हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

शुभ नवरात्र

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

अब प्रतिभा पलायन रोकने की दिशा में उठाएं कदम

अमरीका की ओर से एच-1बी वीजा के लिए किया गया नियमों में बदलाव वहां काम कर रहे भारतीय पेशेवरों की परेशानियां बढ़ाने वाला जरूर है लेकिन दूसरी ओर यह भारत के लिए प्रतिभा पलायन रोकने की दिशा में कदम उठाने का सुनहरा मौका भी है। वीजा नियमों की अस्पष्टता के बीच अमरीकी कंपनियों ने देश से बाहर गए कर्मचारियों को वापस अमरीका लौटने का फरमान जारी किया तो इनमें कार्यरत भारतीय पेशेवरों में भी खलबली मच गई। अब ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बढ़ी वीजा फीस नए आवेदकों के लिए है और एक बारगी ही देय होगी।

ट्रंप प्रशासन की ओर से वीजा के लिए यह भारी भरकम फीस कहने को तो स्थानीय लोगों को रोजगार देने व कुशल विदेशी पेशेवरों को ही अपने यहां काम करने का मौका देने के लिए लागू की गई है। यह भी तर्क दिया जा रहा है कि अमरीकियों को नौकरी से निकालकर कुछ कंपनियां विदेशियों को कम वेतन पर नियुक्तियां दे रहीं थी। लेकिन तथ्य यही है कि एच-1बी वीजा नियमों में बदलाव का सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर ही पड़ने वाला है। भारतीय आईटी व टेक कंपनियां भी हर साल बड़ी संख्या में अपने कार्मिकों को इस वीजा के जरिए अमरीका भेजती है। पेशेवरों के लिए एच-1बी वीजा लंबे समय से एकेडमिक करियर, रिसर्च अवसरों और दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी बाजार में नौकरियों तक पहुंच का साधन रहा है। अमरीका के ही सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच जारी किए गए सभी एच-1बी वीजा में से 70 प्रतिशत से ज्यादा भारतीयों को मिले हैं। ट्रंप सरकार अमरीकियों को रोजगार के अवसर की आड़ लेकर अपने यहां स्किल्ड अप्रवासियों के रास्ते धीरे-धीरे बंद कर रही है। एक तथ्य यह भी है कि अमरीका की कई नामी कंपनियां भारतीय पेशेवरों के भरोसे ही रहती आई हैं। अमरीका में भारी वीजा फीस देनी पड़ी तो ये कंपनियां भी अपने कार्यालय भारत व दूसरे देश में खोलने का विकल्प रख सकती हैं।

अमरीका का यह कदम भारत से प्रतिभा पलायन रोकने की दिशा में अहम हो सकता है, यह कहना अभी आसान नहीं है। क्योंकि वेतन व जीवनशैली से जुड़ी सुविधाओं का इन प्रयासों में खासा योगदान रहने वाला है। अभी हमारे शहरों में ऐसे पेशेवरों के लिए बुनियादी सुविधाओं की दिशा में काफी कुछ करना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि बेंगलूरु, हैदराबाद, पुणे और गुडगांव जैसे आइटी शहरों में पेशेवरों और स्टार्टअप्स को आकर्षित करने का यह बेहतर मौका है। समुचित सुविधाएं देने के साथ अपने ही देश में पेशेवरों को रोक कर 'विकसित भारत' के लक्ष्य की दिशा में कदम तेज किए जा सकते हैं।

टैरिफ के बाद टैलेंट वॉर : अमरीका में हमारे तकनीकी और पेशेवर समुदाय पर भारी पड़ेगी ट्रंप की नीति

एच-1बी वीजा शुल्क से भारतीय सपनों पर चोट

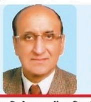

के.एस. तोमर
राजनीतिक विश्लेषक एवं स्तंभकार
@patrika.com

भारतीय तकनीकी पेशेवर अमरीकी तकनीकी, वित्त, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में गहराई से जुड़े हुए हैं। हाल के वर्षों में एच-1बी अनुमोदनों का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा भारतीय नागरिकों का रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी कठोर सीमा का प्रभाव असंगत रूप से भारत पर पड़ेगा।

जब नीति तनावरूपी हो जाती है, तब अर्थव्यवस्थाएं कीमत चुकाती हैं। हाल ही वाइट हाउस की घोषणा ने एच-1बी वीजा प्रायोजन पर चौंकाने वाला 1,00,000 डॉलर शुल्क लगा दिया। इसे प्रशासन ने राजस्व और सुरक्षा के उपाय के रूप में पेश किया, लेकिन इसका असली असर सीधे भारत और अमरीका के बीच प्रतिभा के पुल पर पड़ता है। यह कोई मामूली सुधार नहीं, बल्कि एक कठोर उपाय है, जो भारतीय तकनीकी और पेशेवर समुदाय पर भारी पड़ सकता है।

एच-1बी प्रणाली छोटी नहीं है। वित्तीय वर्ष 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन (यूएससीआइएस) ने लगभग 399,395 एच-1बी याचिकाओं को मंजूरी दी, जिनमें से लगभग 141,205 नई नौकरियों के लिए अनुमोदन थे। कानूनी वार्षिक सीमा 85,000 ही रहती है (65,000 सामान्य स्लॉट और 20,000 उच्च शिक्षा के लिए)। यदि नया शुल्क केवल कानूनी सीमा पर लागू किया जाए तो राजस्व लगभग 8.5 बिलियन डॉलर होगा। यदि इसे सभी नई याचिकाओं पर लगाया जाए तो यह 14.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। यदि यह सभी स्वीकृत याचिकाओं पर लागू किया जाए तो 40 बिलियन डॉलर तक का आंकड़ा बन सकता है। आज के डॉलर-रुपए दर पर 1,00,000 डॉलर लगभग 8.8 लाख रुपए है। लेकिन केवल राजस्व ही पूरा चित्र नहीं है। भारतीय तकनीकी पेशेवर अमरीकी तकनीकी, वित्त, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में गहराई से जुड़े हुए हैं। वे संस्थापक उद्यमी, वरिष्ठ इंजीनियर, अस्पताल विशेषज्ञ और विश्वविद्यालय शोधकर्ता हैं। हाल के वर्षों में एच-1बी अनुमोदनों का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा भारतीय नागरिकों का रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी कठोर सीमा का प्रभाव असंगत रूप से भारत पर पड़ेगा। इनके द्वारा सृजित आर्थिक मूल्य- पेटेंट, स्टार्टअप, वेतन कर, उपभोग और प्रबंधन नेतृत्व- एक बार के शुल्क से नहीं आंका जा सकता। भारतीय प्रवासी और उद्योग अध्ययन बताते हैं कि अमरीका में भारतीयों की आर्थिक छाप दशकों और अरबों डॉलर में है, केवल छात्र ही सालाना 8 बिलियन डॉलर से अधिक का योगदान देते हैं। यदि गतिशीलता और नवाचार की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होती है, तो यह शुल्क इसे नहीं सुधार सकता।

हर वह कंपनी जो विशेषज्ञ और गतिशील श्रम पर निर्भर है प्रभावित होगी- चाहे वह अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट हों या टीसीएस, इंफोसिस जैसी बड़ी भारतीय सेवा कंपनियां- वे सभी महंगे शुल्क और संभावित कॉन्ट्रैक्ट पुनर्मूल्यांकन का सामना करेंगी। छोटे अमेरिकी स्टार्टअप, जो एच-1बी कर्मचारियों पर अपनी वृद्धि का आधार रखते हैं, अधिक दबाव में आएंगे। कितने भारतीय जीवन और कॅरियर तुरंत खतरे में हैं, यह आंकलन पर निर्भर करता है। रिपोर्ट्स 3 लाख से 7 लाख प्रभावित भारतीयों तक का अनुमान देती हैं। इसका राजनीतिक महत्त्व बड़ा है क्योंकि यह केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समुदायों और भारतीय तकनीकी केंद्रों- बेंगलूरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, मुंबई और दिल्ली-एनसीआर- के प्रवाह पर असर डालता है। जिन राज्यों से भारत का प्रमुख सॉफ्टवेयर निर्यात होता है- कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु- वे सीधे और सबसे गंभीर रूप से प्रभावित होंगे।

अमरीकी पक्ष देखें तो तत्काल राजस्व आकर्षक लगता है, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव महंगे होंगे। गतिशीलता में कमी अमरीकी नवाचार को धीमा कर सकती है, स्टार्टअप की स्थापना में देरी, उत्पाद विकास में बाधा और टीम अनुभव के नुकसान की वजह से कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। इधर, भारत को इस चुनौती का सामना करने के लिए बहुस्तरीय प्रतिक्रियाओं की जरूरत है। कूटनीतिक बातचीत और दबाव जरूरी है। स्वास्थ्य, महत्त्वपूर्ण आरएंडडी और अकादमिक आदान-प्रदान में छूट की मांग करनी चाहिए। उद्योग दबाव को अमरीकी कॉर्पोरेट हितधारकों के माध्यम से वहां कांग्रेस तक पहुंचाया जा सकता है। इस कार्यकारी शुल्क की वैधता को अमरीकी अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। भारत और प्रभावित कंपनियों को कानूनी और प्रशासनिक समीक्षा के साथ डब्ल्यूएचओ और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एकतरफा उपायों की हानिकारक प्रभावों को उजागर करना चाहिए। यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ गति बढ़ानी चाहिए और पारस्परिक गतिशीलता तथा तकनीकी सहयोग का आग्रह करना चाहिए।

भारत के लिए चुनौती को रणनीतिक अवसर में बदलना आवश्यक है। व्यवधान को घरेलू क्षमता में तेजी, साझेदार बाजारों में विविधता और अमरीकी कंपनियों तथा वाशिंगटन को यह समझाना कि प्रतिभा गतिशीलता कोई सब्सिडी नहीं, बल्कि 21वीं सदी के नवाचार की ऑक्सीजन है। यदि नई दिल्ली और मुंबई केवल क्रोध में प्रतिक्रिया करती हैं, तो रणनीतिक पहल खो जाएगी।

इस संकट में भारत को केवल नुकसान देखने की बजाय उसे घरेलू नवाचार, स्टार्टअप इकोसिस्टम और वैश्विक साझेदारियों में नए अवसर में बदलने की जरूरत है। उच्च मूल्य वाली नौकरियों और विशेषज्ञता को देश में बनाए रखना, नए निवेश आकर्षित करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे न रहना ही दीर्घकालिक रणनीति हो सकती है।

नेतृत्व

ओएसिस से सीखें विपत्ति में पोषण का महत्त्व

संकट कितना भी विकराल क्यों न हो, जीवन व संभावना बनी रहती है

असीम मरुस्थल के बीच एक ऐसे क्षेत्र में जहां तपन धरती को झुलसा देती है और अभाव हर जीव की परीक्षा लेता है, वहां पर अक्सर एक ओएसिस यानि नखलिस्तान उभरता है- जो जल, छाया और जीवन का आश्रय होता है। पथिकों और जीव-जंतुओं के लिए यह केवल शरणस्थली नहीं, बल्कि आशा, अस्तित्व और पुनर्जीवन का प्रतीक है। श्रेष्ठ नेतृत्व भी इसी ओएसिस की भांति है, जो कठिनतम परिस्थितियों में भी सहारा, दिशा और पोषण प्रदान करता है। भारतीय दर्शन में एक नेतृत्वकर्ता की तुलना अक्सर शीतल छाया और जीवनदायी जल से की गई है और ऐसा ही अनेक शास्त्रों और परंपराओं में भी वर्णित है।

प्रो. हिमांशु राय
निदेशक
आइआइएम इंदौर
@patrika.com

ओएसिस हमें सिखाता है कि संकट चाहे कितना भी विकराल क्यों न हो, उसके बीच भी जीवन और संभावना बनी रहती है। सूनी रेत के विस्तार में अचानक मिल जाने वाला जल यह संदेश देता है कि निराशा शाश्वत नहीं है। महान नेतृत्वकर्ता भी अपने साथियों को यही भरोसा दिलाते हैं। ओएसिस की एक शिक्षा निःस्वार्थ पोषण भी है। उसका जल और छाया बिना किसी भेदभाव के सबको प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार सच्चा नेतृत्व उदारता और करुणा से चिह्नित होता है। एक नेतृत्वकर्ता केवल संसाधन ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहारा भी देता है। ओएसिस का संदेश धैर्य और सहनशीलता है। वह वहीं फलता-फूलता है जहां अधिकांश जीवन हार मान लेता है। उसकी जड़ें गहराई में उतरकर अदृश्य जलस्रोतों से जुड़ जाती हैं। उसी प्रकार, दृढ़ नेतृत्वकर्ता शक्ति और मूल्यों का सहारा लेकर परिस्थितियों का सामना करता है। ओएसिस सिखाता है कि नेतृत्व प्रभुत्व में नहीं, करुणा और पोषण में फलता है। वह थके हुए के लिए संबल है, निराश के लिए आशा है और वहां जीवन का दान करता है जहां सबकुछ शून्य प्रतीत होता है। यही नेतृत्व का सर्वोच्च रूप है- पुनर्जीवन, करुणा और जीवन की सतत नवीनीकरण में आस्था।

Join This Channel:- https://t.me/AllNewsPaperPaid1

आत्म दर्शन

नवरात्र : मानसिक शुद्धि का अवसर

अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि शारदीय नवरात्रि आधुनिक युग में क्यों प्रासंगिक है? तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि इसकी जड़ें वेद-पुराणों में गहराई से जुड़ी हुई हैं। यह पर्व केवल भगवती श्रीदुर्गाजी की पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मानुशासन, आत्मबल और नारीशक्ति के सम्मान का प्रतीक होने के साथ-साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक शुद्धि और अनुशासित जीवनशैली की शुरुआत करने का एक बेहतरीन अवसर भी है। जहां एक ओर यह पर्व धार्मिक परंपराओं से जुड़ा है, वहीं आधुनिक युग में इसकी प्रासंगिकता कहीं अधिक व्यापक और सार्थक हो गई है। अतएव इस पर्व को धर्म, शक्ति, भक्ति और आत्मोत्थान का महायोग कहा जा सकता है। नवरात्रि का मूल भाव "शक्ति की आराधना" है। यह पर्व समाज को नारी को देवी के समान देखने के साथ-साथ, उसे वास्तविक अधिकार और सम्मान देने की प्रेरणा देता है।

स्वामी राजेंद्र दास
@patrika.com

आधुनिक जीवन तनाव, भागदौड़ और अनिश्चितता से भरा है। नवरात्रि के व्रत, ध्यान और संयम की प्रक्रिया मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्रदान करती है। शरीर को डिटॉक्स करने के साथ-साथ मन को भी नकारात्मकता से मुक्त करने में सहायक होती है। नवरात्रि के व्रत, सात्विक आहार और नियमबद्ध जीवनशैली आज की खराब दिनचर्या के लिए एक प्रकार की नेचुरल थेरेपी बन सकती है। डिटॉक्स, सादगी और संयम स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। यह पर्व तन, मन और आत्मा तीनों के लिए रिफ्रेशिंग ब्रेक है।

नवरात्रि के आयोजन- दुर्गा पूजा, रामलीला, गरबा- समुदाय को एक साथ लाते हैं। आज जब एकाकीपन बढ़ रहा है, यह पर्व सामूहिकता और मेल-जोल का अवसर प्रदान करता है। सांस्कृतिक मेलों, भजन-संध्याओं और झांकियों के माध्यम से सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करता है जिससे व्यक्ति खुद को सुरक्षित और मजबूत पाता है, रिश्तों में मिठास और उच्च मनोबल से लबरेज जीवन को बढ़ावा देने का यह एक अनमोल अवसर है। नवरात्रि के पीछे की कथा- मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय- एक प्रतीक है जीवन के संघर्षों पर विजय का। आज का मानव बाहरी चुनौतियों के साथ-साथ आंतरिक डर, तनाव और असुरक्षा से भी लड़ रहा है। नवरात्रि उसे याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक शक्ति है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है और यही इंसान को विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूत बने रहने और जीत के लिए प्रेरित करता है।

शिला-गैलरी : प्राचीन शाटियाल शिलालेखों की अद्भुत विरासत

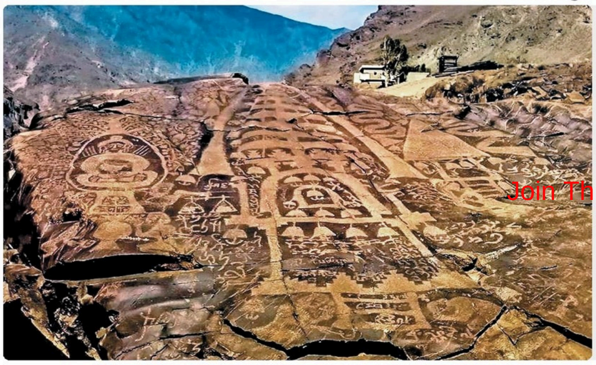

उत्तरी पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में कराकोरम हाईवे के किनारे स्थित शाटियाल शिलालेख प्राचीन मानव सभ्यता की अनमोल धरोहर हैं। शाटियाल से राइकोट ब्रिज तक लगभग 100 किलोमीटर क्षेत्र में फैले इन शिलालेखों को विश्व की सबसे बड़ी खुली शिला-गैलरी माना जाता है। यहां 50,000 से अधिक शिलाचित्र और लगभग 5,000 शिलालेख दर्ज किए गए हैं। ये प्राचीन शिलाचित्र मानव जीवन, आस्था और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की झलक प्रस्तुत करते हैं। कराकोरम की ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित यह स्थल न सिर्फ इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए अनमोल है, बल्कि विश्व सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की आवश्यकता का सशक्त संदेश भी देता है।

सशक्त कदम कम हुई कर दरों का लाभ आम जनता तक पहुंचाने पर भी नजर

अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगा जीएसटी रिफॉर्म

गोपाल कृष्ण अग्रवाल
फैलो मेंबर, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया
@patrika.com

यह सरलीकरण ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक सुधार भी है। सरकार ने रेट ही कम नहीं किए, बल्कि स्लैब भी कम कर दिए हैं।

वर्ष 2017 में जब जीएसटी कर प्रणाली को लागू किया गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के पटल पर कहा था कि यह भारत की आर्थिक आजादी का दिन है। आज भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक 'एक राष्ट्र एक कर' लागू किया गया है। उससे पूर्व यूपीए की सरकार ने कई बार प्रयास किया था कि जीएसटी लागू किया जाए लेकिन वे सफल नहीं हुए। मोदी सरकार आने पर प्रदेशों को आश्वासन दिया गया कि केंद्र हर वर्ष 14% बढ़ोतरी के मापदंड के साथ प्रदेशों को जो कुछ भी कर में क्षति होती है तो उसे केंद्र पूर्ण करेगा। इस पर प्रदेशों और केंद्र के लगभग 16 करों को समाहित करके एक कर प्रणाली देश में लागू करने में केंद्र सफल हुआ।

मोदी सरकार ने शीघ्र जीएसटी लागू ही नहीं किया बल्कि केवल पांच वर्ष में उसे तकनीकी रूप से सरलता से स्थापित भी कर दिया। आज हर महीने सामान्यतया 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की कर आपूर्ति हो रही है, जबकि सरकार लगातार कर घटाती भी जा रही है। जीएसटी के अंतर्गत प्रदेश एवं केंद्र को सीजीएसटी/एसजीएसटी में 50/50 प्रतिशत कर का हिस्सा मिलता है और जो इसके अलावा केंद्र के पास आइजीएसटी के रूप में कर आता है उसका भी लगभग 41 प्रतिशत हिस्सा केंद्र प्रदेशों को दे देता है। इस बार नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफार्म द्वारा सरकार ने रेट ही कम नहीं किया बल्कि स्लैब भी कम कर दिए हैं। अब केवल दो स्लैब ही रखे हैं। आमजन की रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर या तो टैक्स जीरो है या 5 प्रतिशत ही। बाकी चीजों पर 18 प्रतिशत कर है। 99 प्रतिशत सामान इन दो स्लैब में ही आ जाता है। इन रिफार्म द्वारा सरलीकरण की व्यापक प्रक्रिया लागू की गई है। नए व्यापारियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन मात्र तीन दिन में कर दिया जाएगा और कर दाताओं के लगभग 90 प्रतिशत कर वापसी तुरंत कर दिए जाएंगे।

व्यापारी वर्ग इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से परेशान रहते थे। उसकी विसंगतियों को भी खत्म किया गया है। जिन उत्पाद प्रणालियों में इनपुट टैक्स क्रेडिट की समस्या थी, उन विसंगतियों को भी काफी हद तक दूर किया गया है। अब जीएसटी नेक्स्ट जेन सुधार केवल सरलीकरण ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक सुधार भी लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को जीएसटी सुधारों के माध्यम से तोहफा देने की जो घोषणा की थी वह अब 22 सितंबर को नई जीएसटी सुधार प्रणाली लागू होने के साथ पूरी हो जाएगी। इस परिवर्तन के बाद देश विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ और सशक्त कदमों से आगे बढ़ेगा।

सरकार की पैनी नजर इस पर भी रहेगी कि कम हुई कर दरों का लाभ व्यापारी वर्ग आम जनता तक अवश्य पहुंचाए। व्यापार के सरलीकरण में सबसे ज्यादा चुनौती अनुपालन के लिए होती है। देश में वैश्विक व्यापार की चुनौतियों के मद्देनजर, यह कर सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाएगा और प्रधानमंत्री के स्वदेशी के आह्वान को भी पूर्ण गति प्रदान करेगा।

बुक इनसाइट

सर्कल ऑफ डेज

अपनी ऐतिहासिक कहानियों के लिए प्रसिद्ध लेखक केन फॉलेट की नई पुस्तक 'सर्कल ऑफ डेज' पाठकों को प्राचीन सभ्यताओं और रहस्यमयी दुनिया की यात्रा पर ले जाती है।

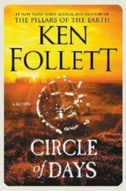

यह उपन्यास एक रहस्यमयी और रोमांचक कहानी प्रस्तुत करता है, जो प्राचीन इतिहास और आधुनिक समय के बीच एक अनोखा ताना-बाना बुनता है। यह उपन्यास इंग्लैंड के ऐतिहासिक स्मारक स्टोनहेंज के इर्द-गिर्द घूमता है। पुस्तक में बताया गया है कि कैसे पत्थरों का यह अद्भुत वृत्त सिर्फ एक स्थापत्य नहीं, बल्कि रहस्य, शक्ति और मानवीय संघर्ष की गाथा भी है। फॉलेट अपने लेखन में उस समय के समाज, राजनीति और धार्मिक मान्यताओं को विस्तार से पिरोते हैं। अंत तक आते-आते उपन्यास एक मजबूत और प्रभावशाली क्लाइमेक्स पर पहुंचता है, जो पाठकों के मन में लंबे समय तक छाप छोड़ जाता है।

आपकी बात

स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण जरूरी

सोशल मीडिया का अंधाधुंध प्रयोग मानसिक तनाव, समय की बर्बादी और रिश्तों में दूरी का कारण बन सकता है। इससे बचने के लिए सबसे पहले स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण जरूरी है। दिन का एक निश्चित समय सोशल मीडिया को दें और शेष समय परिवार, पढ़ाई या रचनात्मक कार्यों में लगाएं। अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद करें और उपयोगी व सकारात्मक सामग्री को ही देखें। **- इशिता पाण्डेय,** कोटा

किसी भी चीज की अति बुरी होती है

ऐसा कहा जाता है कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है। यही हाल सोशल मीडिया के अधिक उपयोग का हो गया है। इनसे बचने के लिए सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले समय में कमी करनी होगी। निरर्थक और उद्देश्यहीन सामग्रियां जो सोशल मीडिया पर दिन-रात चलती रहती हैं, उन्हें देखना और उन्हें फॉलो करना छोड़ना होगा। तभी हम सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। **- नरेश कानूनगो,** देवास, म.प्र.

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

इसे स्कैन करें

पत्रिकायन का सवाल था, 'सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों को देखते हुए इससे दूर रहने के क्या तरीके हो सकते हैं?' प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।
https://shorturl.at/UJSzQ

आज का सवाल

त्यौहारों पर खरीदारी करते समय क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

अग्रसेन जयंती पर विशेष उनका 'एक रुपया एक ईंट' का सिद्धांत कमजोर परिवारों को सुरक्षा प्रदान करता था

महाराजा अग्रसेन का आर्थिक समाजवाद आज भी प्रेरणास्रोत

विजय गर्ग
संस्थापक महासचिव, अग्रसेन अग्रोहा अग्रवाल फाउंडेशन
@patrika.com

महाराजा अग्रसेन की जयंती प्रतिवर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है, जो शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन भी होता है। महाराजा अग्रसेन का जन्म आज से लगभग 5100 वर्ष पूर्व द्वापर और कलियुग के संधिकाल में हुआ था। इतना अधिक समय बीत जाने के बाद भी महाराजा अग्रसेन का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, आर्थिक समरूपता एवं सामाजिक समानता, आर्थिक समाजवाद, मानव आस्था तथा सहयोग का जीवन दर्शन दुनिया के लिए प्रेरणास्रोत बना हुआ है।

महाराजा अग्रसेन केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने अपने राज्य में कुछ अद्भुत नियम बनाए थे, जैसे 'एक ईंट और एक रुपया' का सिद्धांत, जब भी कोई नया परिवार नगर में बसने आता, हर परिवार उसे एक ईंट और एक रुपया देता था, जिससे वह व्यक्ति अपना घर बना ले और रुपए से कारोबार शुरू कर ले। इस प्रकार एक रुपया एक ईंट का सिद्धांत नवागत एवं कमजोर परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता था एवं राज्य में चहूं ओर खुशहाली थी। "शत-हस्त समाहरः सहस्त्र हस्त संकिरः" सौ हाथों से कमाकर हजार हाथों से बांट दो।

अथर्ववेद के इस श्लोक को महाराजा अग्रसेन ने अपना शासनाधार बनाया और एक समूह तथा सुखी समाज की स्थापना की जिसमें समूहजनों ने अभावग्रसितों एवं पीड़ितों की सहायता की तथा सबको समूह बनाया। समाजवाद की इस अभिनव पहल के प्रणेता महाराजा अग्रसेन ने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया और वैदिक सनातन आर्य संस्कृति की मान्यताओं को और विस्तार दिया तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः को साकार किया।

महाराजा अग्रसेन का सिद्धांत किसानों और व्यापारियों के साथ संवाद एवं सहयोग पर आधारित था। उनका आदर्श शासन बताता है कि जनता के विश्वास एवं समान भागीदारी के बिना शासन लंबे समय तक नहीं टिक सकता। शासन यदि सहभागिता, पारदर्शिता एवं परोपकार पर आधारित हो तो जनता का भरोसा बना रहता। बेरोजगारी एवं युवाओं की निराशा को महाराजा अग्रसेन के सिद्धांत सहकारिता और उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर दूर किया जा सकता है।

महाराजा श्री अग्रसेन ने अपने राज्य को 18 गणराज्यों में विभक्त किया एवं शासन का विकेन्द्रीकरण किया, इस प्रकार महाराजा अग्रसेन न सिर्फ समाजवाद के प्रथम प्रर्वतक थे बल्कि विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था एवं सहकारिता के प्रणेता भी थे। उन्होंने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, सामाजिक समानता एवं आर्थिक समरूपता को अपने शासन का आधार बनाया। इस प्रकार अपनी प्रजा की समृद्धि एवं सुख के लिए जरूरी सभी आयामों को यथा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सांस्कृतिक को दृढ़ किया एवं राज्य का नवनिर्माण किया। महाराजा अग्रसेन का समाजवादी दृष्टिकोण युवाओं को स्वावलंबन और सहकारिता की ओर प्रेरित करता है। उनका शासन इस बात का प्रमाण है कि समानता, न्याय, परोपकार एवं सहयोग पर आधारित समाज किसी भी संकट से बच सकता है। जनता के विश्वास एवं समान भागीदारी के बिना शासन लंबे समय तक नहीं टिक सकता। महाराजा अग्रसेन ने समाज को जाति या वर्ग में बांटने के बजाय सभी को बराबरी का दर्जा दिया। महाराजा अग्रसेन का आदर्श समाज इसी राह का पथ-प्रदर्शक है, जहां हर नागरिक को अवसर मिले, हर वर्ग का सम्मान हो और सत्ता का उद्देश्य केवल जनसेवा हो। वे न केवल एक सफल शासक थे, बल्कि ऐसे समाज-सुधारक भी थे, जिन्होंने आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को अपने शासन का मूल आधार बनाया। उनका समाजवादी दृष्टिकोण आधुनिक समय में भी प्रेरणा का स्रोत है। आज जब पूरी दुनिया समानता, आर्थिक न्याय और सामाजिक सहयोग की राह तलाश रही है, तब महाराजा अग्रसेन का समाजवाद और भी प्रासंगिक हो उठता है। उनके जीवन के मूल रूप से तीन आदर्श हैं- "लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था", "आर्थिक समरूपता" एवं "सामाजिक समानता"। यह तीनों आदर्श व्यवस्थाएं अगर वर्तमान में किसी भी देश एवं प्रदेश की चुनी हुई सरकार जनता पर लागू करें या इनको ध्यान में रखकर नीतियां बनाए, तो वर्तमान में समस्याओं का निदान किया जा सकता है।

निशाने पर भारतीय

ट्रंप प्रशासन द्वारा एच-1बी वीजा पर लागू की गयी भारी फीस हैरान करने वाली है. सिर्फ यही नहीं कि अमेरिका द्वारा कुल जारी किये जाने वाले एच-1बी वीजा का 70 फीसदी भारतीय पेशेवरों को मिलने के कारण ट्रंप प्रशासन का यह ताजा कदम भारत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला है, बल्कि भारी टैरिफ और ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह पर लगाये गये प्रतिबंध के बाद अमेरिका द्वारा भारत को दिया गया यह तीसरा जबरदस्त झटका है. अमेरिका हर साल लॉटरी सिस्टम से 85,000 पेशेवरों को एच-1बी वीजा देता है, जिनमें 70 फीसदी भारतीय होते हैं. यह वीजा अमेरिका में भारतीयों के लिए तरक्की का जरिया भी है. अमेरिका में लगभग तीन लाख उच्च कुशल भारतीय कर्मचारी हैं. इनमें से ज्यादातर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में रहते हैं. एच-1बी वीजा की वजह से ही भारतीय-अमेरिकी अमेरिका में सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे और सबसे ज्यादा कमाने वाले लोगों में से हैं. अपने परिवारों के साथ अमेरिका में रहने वाले भारतीय अमेरिकियों की आबादी का एक चौथाई हिस्सा एच-1बी वीजाधारक हैं. इस वीजा से भारतीय कंपनियों को भी फायदा होता रहा है, क्योंकि यह भारतीय कंपनियों को अपने नये इंजीनियरों को अमेरिका भेजने में मदद करता था. अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियां भी ज्यादातर युवा भारतीय टैलेंट को अमेरिका ले जाने के लिए इसी रास्ते का उपयोग करती हैं. पहले एच-1बी वीजा की फीस 215 डॉलर थी. साथ ही, 750 डॉलर और लगते थे. कुछ मामलों में यह फीस 5,000 डॉलर (करीब 4.5 लाख रुपये) से ज्यादा हो जाती थी, लेकिन अब कंपनियों को कुशल विदेशी कर्मियों की नियुक्ति के लिए एक लाख डॉलर यानी 88 लाख रुपये देने होंगे. जाहिर है, नयी फीस कई गुना ज्यादा है. यह फैसला एच-1बी वीजा कार्यक्रम को खत्म कर सकता है, क्योंकि यह शुल्क औसत वेतन से भी ज्यादा है. चूंकि अधिकतर टेक कंपनियां मिड लेवल प्रोफेशनल्स को एक लाख डॉलर से कम वेतन देती हैं, ऐसे में, वीजा पर एक लाख डॉलर खर्च करना कंपनियों पर बोझ बन सकता है. भारतीय कंपनियों और स्टार्टअप्स पर इसका सीधा असर पड़ेगा. हालांकि यह फैसला भारत के लिए अवसर भी बन सकता है. जी-20 के पूर्व शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीइओ अमिताभ कांत का कहना है कि अमेरिका से लौटने वाले उच्च कुशल भारतीयों को नौकरी पर रखकर भारतीय कंपनियां नवाचार को नयी ऊंचाइयों पर ले जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल तो ट्रंप प्रशासन का यह कदम भारतीय पेशेवरों के लिए चिंता का ही कारण है.

चूंकि एच-1बी वीजा के तहत अमेरिका जाने वाले पेशेवरों में भारतीय सबसे ज्यादा होते हैं, ऐसे में ट्रंप प्रशासन द्वारा इसकी फीस बढ़ाकर एक लाख डॉलर कर देने का खामियाजा भी सबसे अधिक भारतीय ही भुगतेंगे.

भारी टैरिफ के बाद अब वीजा का झटका

आनंद कुमार
एसोसिएट फेलो-एमपीआइडीएसए
anandkmrai@gmail.com

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा की फीस में भारी बढ़ोतरी भारतीय पेशेवरों को सीधे-सीधे प्रभावित करने वाली है. भारतीय पेशेवर एच-1 बी वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी हैं और करीब 71 प्रतिशत वीजा भारतीयों को ही जारी होते हैं. इससे भारतीय पेशेवरों के साथ-साथ आइटी कंपनियों पर भी दबाव बढ़ेगा. पहले व्यापार पर शुल्क और अब सेवाओं के क्षेत्र में बाधा, दोनों कदम इस ओर संकेत करते हैं कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में भारत जैसे देशों के साथ आर्थिक रिश्तों को नये सिरे से परिभाषित करने की नीति पर काम कर रहे हैं.

जब भारत अमेरिकी प्रशासन द्वारा लगाये गये भारी-भरकम शुल्क पर बातचीत करने की कोशिश कर ही रहा था, तभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक और झटका देते हुए एच-1बी वीजा की फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी. यह फैसला भारत–अमेरिका के आर्थिक रिश्तों के एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने वाला है. ट्रंप प्रशासन ने 19 सितंबर को एच-1बी वीजा की सालाना फीस 2,000–5,000 डॉलर से बढ़ाकर सीधे 1,00,000 डॉलर कर दी है. यह नियम 21 सितंबर की आधी रात से लागू भी हो गया है. अमेरिकी प्रशासन ने हालांकि बाद में यह स्पष्ट किया कि बढ़ी हुई फीस नये आवेदनों पर लागू होगी, पहले से वीजाधारकों या उनके नवीनीकरण पर नहीं. इसके बावजूद, इस घोषणा ने भारतीय पेशेवरों और आइटी कंपनियों में हड़कंप मचा दिया है. एच-1बी वीजाधारकों और उनके परिवारों में अनिश्चितता का माहौल बन गया है. अनेक लोग अपने बच्चों की पढ़ाई, घर के कर्ज और रोजमर्रा की योजनाओं को लेकर गहरे असमंजस में हैं.

दरअसल भारतीय पेशेवर एच-1बी वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी हैं और लगभग 71 प्रतिशत वीजा भारतीयों को ही जारी होते हैं. नयी फीस कई भारतीय पेशेवरों के वार्षिक वेतन के 60 फीसदी से अधिक है. इस कारण अनेक लोगों ने जल्दी-जल्दी अमेरिका लौटने के लिए उड़ानों की बुकिंग करायी, ताकि वे समय पर पहुंच सकें. नासकॉम ने तो अपने सदस्य संगठनों को सलाह दी है कि वे अपने एच-1बी कर्मचारियों को तुरंत अमेरिका भेजने की तैयारी करें, ताकि संभावित बाधाओं से बचा जा सके. टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल जैसी भारतीय आइटी उद्योग की दिग्गज कंपनियों के साथ-साथ अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल और मेटा जैसी अमेरिकी कंपनियां एच-1बी वीजा पर ही निर्भर हैं. उदाहरण के लिए, 2024 में अमेजन को ही 10,000 से अधिक एच-1बी वीजा अनुमोदन मिले थे. इस तरह की फीस वृद्धि से न केवल भारतीय कंपनियों, बल्कि अमेरिकी कॉरपोरेट जगत की लागत में भी भारी बढ़ोतरी होने की आशंका है. भारत सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम के निहितार्थों का अध्ययन किया जा रहा है और सरकार भारतीय उद्योग जगत से मिलकर सामूहिक रणनीति बनायेगी. भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अमेरिका लौटने की कोशिश कर रहे भारतीय नागरिकों की हरसंभव सहायता करें. डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में नीतिगत अस्थिरता और व्यवधान सामान्य स्थिति बन गये हैं. सबसे पहले यह व्यवधान व्यापार के क्षेत्र में दिखाई दिया, जब ट्रंप ने आयातक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की नीति अपनायी. भारत इस नीति से सबसे बड़ा प्रभावित देश है, क्योंकि रूस से तेल आयात करने पर ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया. ट्रंप का तर्क है कि इन नीतियों से अमेरिका को आर्थिक लाभ होगा. उनका और उनके 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' समर्थकों का मानना है कि आयातित वस्तुओं पर ऊंचा शुल्क लगाकर वे विदेशी कंपनियों को अमेरिका में विनिर्माण के लिए मजबूर कर देंगे, लेकिन इस तरह के बदलाव एक झटके में नहीं होते और इनके लिए अनुकूल परिस्थितियों के साथ समय की भी जरूरत होती है. ट्रंप का यह दांव अपने लक्ष्य तक पहुंचने में विफल साबित हो रहा है. एच-1बी वीजा की फीस को अत्यधिक महंगा कर देने का मकसद यही बताया जा रहा है कि अमेरिकी कंपनियां विदेशी पेशेवरों की जगह स्थानीय अमेरिकी नागरिकों को रोजगार दें, लेकिन यह भी असंभव नहीं, तो कठिन अवश्य है, क्योंकि उच्च तकनीकी क्षेत्र में जिस तरह की विशेषज्ञता भारतीय पेशेवरों के पास है, उसका विकल्प तुरंत उपलब्ध नहीं हो सकता. परिणामस्वरूप यह कदम भी केवल अस्थिरता और व्यवधान ही पैदा करेगा.

उल्लेखनीय है कि खुद अमेरिका के तकनीकी क्षेत्र के कई दिग्गज, जिनमें एलन मस्क जैसे लोग शामिल हैं, एच-1बी वीजा के समर्थक हैं. मस्क के मुताबिक, यह वीजा अमेरिका को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने का अवसर देता है और देश को तकनीकी रूप से अग्रणी बनाये रखता है. अमेरिका के भीतर भी इस फैसले की आलोचना हो रही है. कई सांसदों और उद्योगपतियों ने इसे जल्दबाजी में लिया गया और 'लापरवाह' कदम बताया है. अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने स्वीकार किया कि एच-1बी वीजा प्रणाली में खामियां हैं, पर उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि 1,00,000 डॉलर का शुल्क हर साल वीजा की पूरी अवधि तक लागू रहेगा. अमेरिकी उद्योग जगत को डर है कि इससे उनके प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ेगी, नवाचार की गति धीमी होगी और कंपनियां काम को ऑफशोर यानी भारत जैसे देशों में शिफ्ट करने लगेंगी.

रणनीतिक दृष्टि से भी यह निर्णय केवल भारतीय आइटी क्षेत्र को नहीं, बल्कि दीर्घकाल में खुद अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है. भारतीय कंपनियां पहले ही ऑफशोरिंग को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है, ताकि अमेरिका में ऑन साइट नियुक्तियों की आवश्यकता कम पड़े. इससे अमेरिकी ग्राहकों को महंगे प्रोजेक्ट्स और धीमी तकनीकी प्रगति का सामना करना पड़ेगा. वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल (जीटीआरआइ) की चेतावनी है कि अंततः यह नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारत से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है. ट्रंप प्रशासन दावा कर रहा है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और वीजा प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है, पर वास्तविकता यह है कि यह 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडा को आगे बढ़ाने की एक और कोशिश है. पहले व्यापार पर शुल्क, अब सेवाओं के क्षेत्र में बाधा, दोनों कदम इस ओर संकेत करते हैं कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में भारत जैसे देशों के साथ आर्थिक रिश्तों को नये सिरे से परिभाषित करने की नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वह अमेरिका के उन क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो वैश्विक प्रतिभा और मुक्त व्यापार पर आधारित हैं. एच-1बी वीजा की फीस में की गयी भारी वृद्धि केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि अमेरिका और भारत की अर्थव्यवस्थाओं के लिए दूरगामी परिणामों वाला कदम है. इससे न केवल भारतीय पेशेवरों और आइटी कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा, बल्कि अमेरिकी कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार की क्षमता पर भी चोट पहुंचेगी. दीर्घकाल में यह नीति अमेरिका को वैश्विक सहयोग से और अधिक दूर कर सकती है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

पाकिस्तान-सऊदी रक्षा समझौता और भारत की सतर्कता

विवेक शुक्ला
वरिष्ठ पत्रकार
vivekshukladelhi@gmail.com

पश्चिम और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बदलने वाला यह समझौता भारत के लिए सतर्कता की घंटी है. हालांकि मजबूत नेतृत्व और रणनीतिक स्वायत्तता से भारत इस चुनौती का सामना कर सकता है. यदि यह समझौता क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देता है, तो सभी के लिए लाभदायक होगा.

विगत 17 सितंबर को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रियाद में ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किये. इस 'स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट' में एक प्रमुख धारा यह है कि किसी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जायेगा. यह समझौता नाटो-शैली का है, जहां हमले की स्थिति में दोनों देश एक-दूसरे की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस समझौते की पृष्ठभूमि में हाल की क्षेत्रीय घटनाएं, जैसे इस्राइल का कतर पर हमला और अमेरिका की सुरक्षा गारंटी में आयी कमजोरी जिम्मेदार हैं. भारत के लिए यह समझौता दोधारी तलवार है. एक ओर, भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं. भारत सऊदी से 100 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार करता है और मुख्य रूप से तेल आयात करता है. सऊदी अरब ने स्पष्ट किया है कि भारत के साथ उसके संबंध मजबूत रहेंगे और यह समझौता भारत के खिलाफ नहीं है. विगत अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब यात्रा के बाद दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने की योजना बनायी थी. खाड़ी देशों में 90 लाख से अधिक भारतीय काम करते हैं, जो रेमिटेंस का बड़ा स्रोत है.

अलबत्ता यह समझौता भारत की पश्चिम एशिया की नीति को चुनौती देता है. पाकिस्तान अब मुस्लिम दुनिया में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है, जो कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है. हालांकि, भारत की प्रतिक्रिया संयमित रही है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जयसवाल ने कहा है कि भारत इस समझौते का अध्ययन करेगा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध रहेगा. भारत के लिए हालांकि अवसर भी है. यह समझौता भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का अवसर देता है. क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) जैसे गठबंधनों को मजबूत करना, अंडमान-निकोबार द्वीपों पर रक्षा बुनियादी ढांचा विकसित करना और नौसेना की गश्त बढ़ाना आवश्यक है. ओमान, यूएई और बहरीन जैसे मध्यमार्गी खाड़ी देशों से भी भारत संबंध मजबूत कर सकता है. ऊर्जा विविधीकरण के लिए नवीकरणीय स्रोतों पर भी भारत को जोर देना चाहिए.

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग दशकों पुराना है. बीती सदी के छठे दशक से ही सऊदी अरब को पाकिस्तान सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहायता प्रदान करता आया है. जैसे, 1970-80 के दशक में पाक सैनिक सऊदी अरब में तैनात रहे. यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में भी पाकिस्तान का योगदान रहा है. हालांकि, यह नया समझौता पहले के अनौपचारिक संबंधों को औपचारिक रूप देता है, जो क्षेत्रीय तनावों के कारण आवश्यक हो गया था. हाल ही में इस्राइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया, जो सऊदी अरब की सीमा से सटा है. इस हमले में अमेरिका की चुप्पी ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर संदेह पैदा कर दिया है. अमेरिका के पास पश्चिम एशिया में करीब 40,000-50,000 सैनिक तैनात हैं, लेकिन इस्राइली हमले पर वाशिंगटन की निष्क्रियता ने सऊदी अरब को वैकल्पिक सुरक्षा भागीदारों की तलाश करने पर मजबूर किया. इसी संदर्भ में पाकिस्तान, जो मुस्लिम दुनिया का एकमात्र परमाणु हथियार संपन्न देश है, सऊदी अरब के लिए एक आकर्षक सहयोगी बन गया. समझौते में रक्षा उद्योग सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सैन्य सह-उत्पादन शामिल हैं, जो दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करेंगे. यह समझौता क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदलने वाला है. पश्चिम एशिया में इस्राइल की आक्रामकता और ईरान के साथ तनाव के बीच सऊदी अरब को एक मजबूत सहयोगी की जरूरत थी, जबकि पाकिस्तान के लिए यह आर्थिक और रणनीतिक लाभ का स्रोत है, क्योंकि सऊदी अरब से तेल आपूर्ति और वित्तीय सहायता मिल सकती है. दोनों देशों के लिए यह समझौता अहम है. सऊदी अरब के लिए यह अमेरिकी निर्भरता से मुक्ति का कदम है. कतर पर इस्राइली हमले के बाद सऊदी अरब ने महसूस किया कि अमेरिका हमेशा उसकी रक्षा नहीं करेगा. पाकिस्तान की परमाणु क्षमता इस समझौते को और मजबूत बनाती है, हालांकि समझौता स्पष्ट रूप से परमाणु छत्रछाया का उल्लेख नहीं करता.

पाकिस्तान के लिए यह समझौता आर्थिक संकट से उबरने का अवसर है. पाकिस्तान को सऊदी से तेल आपूर्ति, निवेश और सैन्य सहायता मिल सकती है. इस समझौते से पाकिस्तान को सऊदी की वित्तीय और तेल सहायता मिल सकती है, जो युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान की शक्ति बढ़ाएगी. यदि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है, तो सऊदी अरब की प्रतिक्रिया आ सकती है. इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, क्योंकि सऊदी से तेल आयात पर हमारी निर्भरता है. ऐसे में, भारत को रूस और अन्य स्रोतों से विविधीकरण तेज करना होगा. पश्चिम और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बदलने वाला यह समझौता भारत के लिए सतर्कता की घंटी है. ऐसे में, भारत को अपनी कूटनीति और रक्षा रणनीति को अनुकूलित करना होगा. हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है. मजबूत नेतृत्व और रणनीतिक स्वायत्तता से भारत इस चुनौती का सामना कर सकता है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

Join This Channel:- https://t.me/AllNewsPaperPaid1

देश दुनिया

बाल तस्करी और यौन शोषण से बच्चों को बचाने की जरूरत

बच्चों, विशेषकर लड़कियों, के लिए सुरक्षित बचपन सुनिश्चित करने में हमारे समाज की विफलता लगातार सामने आती रही है. दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीति निर्माता, राजनेता और सार्वजनिक संस्थान ऐसे मामलों में अर्थपूर्ण कार्रवाई करने में विफल रहे हैं. एंटी-स्लेवरी ऑर्गनाइजेशन, इंटरनेशनल जस्टिस मिशन ने हाल ही में बताया कि बांग्लादेश के 20 से 50 प्रतिशत यौन व्यापार में नाबालिग शामिल हैं. बीते वर्ष यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 34 लाख से अधिक बच्चे बेघर हैं, सो उन्हें माता-पिता की देखभाल के बिना रहना पड़ता है. ऐसी स्थिति में रहने वाली लड़कियां जहां यौन व्यापारियों के लिए सहज सुलभ रहती हैं, वहीं माता-पिता की देखरेख में पल रही अनेक लड़कियां भी बाल विवाह के चंगुल में फंस जाती हैं. कई बार खराब शादी से बच निकलने वाली युवतियां भी अक्सर तस्करों का शिकार हो जाती हैं. इनमें से ज्यादातर पीड़ितों के पास इनकार करने का विकल्प नहीं होता और इसके परिणाम अक्सर गंभीर होते हैं, जिनमें शारीरिक, यौन और भावनात्मक हिंसा के साथ-साथ मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित होना भी शामिल है. इन सबके बावजूद, हमारी रणनीतियां निचले स्तर की हैं. गरीबी और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के उद्देश्य से बनायी गयीं व्यापक नीतियां अपर्याप्त हैं. सामाजिक सुरक्षा लाभ अक्सर स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने और सबसे कमजोर लोगों तक पहुंचने में विफल रहते हैं. बाल विवाह कमजोर और हाशिये पर रहने वाले समुदायों के बीच अभी भी एक समस्या बना हुआ है. कानूनी खामियां, प्रणालीगत बाधाएं, तथा महिला एवं बाल उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में कम सजा के कारण यौन व्यापार में शामिल अपराधियों का हौसला बढ़ता है. इतना ही नहीं, तस्करी से बच गये लोगों और बेघर बच्चों के लिए सुरक्षित और साधन संपन्न आश्रय गृहों की कमी के कारण कई बच्चे लगातार शोषण का शिकार होते रहते हैं. इन परिस्थितियों में हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि वर्तमान और आगामी सरकारें बाल सुरक्षा को सर्वोपरि रखेंगी.

The Daily Star

बोधि वृक्ष

नवरात्र और पुनर्जीवन

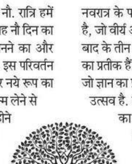

नव के दो अर्थ हैं- नया एवं नौ. रात्रि हमें आराम और शांति देती है. यह नौ दिन का समय है स्वयं के स्वरूप को पहचानने का और अपने स्रोत की ओर वापस जाने का. इस परिवर्तन के काल में प्रकृति पुराने को त्याग कर नये रूप का सृजन करती है. जैसे एक नवजात जन्म लेने से पहले अपनी मां के गर्भ में नौ महीने व्यतीत करता है, उसी तरह एक साधक भी इन नौ दिनों और रातों में उपवास, प्रार्थना, मौन और ध्यान द्वारा अपने सच्चे स्रोत की ओर वापस आता है. रात को रात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि यह जीवन को फिर से उर्जित करती है. नवरात्र तीनों स्तर पर राहत देते हैं- स्थूल, सूक्ष्म और कारण. उपवास शरीर को पवित्र करता है, जबकि मौन वाणी को पवित्र करते हुए बेचैन मन को शांत करता है. ध्यान एक साधक को अपने अस्तित्व की ओर ले जाता है. नवरात्र के इन नौ दिनों के दौरान मन को दिव्य चेतना में लिप्त रखना चाहिए. नवरात्र की नौ रातों और दस दिनों की अवधि में शक्ति की देवी और उसकी चेतना की आराधना होती है. नवरात्र के पहले तीन दिन दुर्गा की आराधना होती है, जो वीर्य और आत्मविश्वास का प्रतीक हैं. उसके बाद के तीन दिन लक्ष्मी के लिए हैं, जो धन-धान्य का प्रतीक हैं. अंत के तीन दिन सरस्वती के लिए हैं जो ज्ञान का प्रतीक हैं. नवरात्र आत्मा और प्राण का उत्सव है. यह असुरों, यानी नकारात्मक शक्तियों का नाश कर सकता है. नवरात्र के तीन-तीन दिनों के तीन खंड तमस, रजस और सत्व के प्रतीक हैं. हमारा जीवन इन्हीं तीन गुणों पर चलता है. फिर भी हम इसके बारे में सजग नहीं रहते. व्रत के माध्यम से हमारी चेतना नवरात्र में तमस और रजत के बीच बहती हुई अंत के तीन दिनों में सत्व में प्रवेश करती है. नवरात्र के दौरान मातृ रूपी दिव्यता की आराधना से हम तीनों गुणों को संतुलित कर वातावरण में सत्व की वृद्धि करते हैं. नवरात्र के अंत पर, दसवें दिन हम विजयादशमी का उत्सव मनाते हैं. विजय दिवस- यह दिन जागी हुई दिव्य चेतना में परिणत होने का है. जब सत्व गुण बढ़ता है, तब विजय की प्राप्ति होती है.

-श्री श्री रवि शंकर

प्रबंध सूत्र

कपट अब रणनीति है

आलोक पुराणिक
स्तंभकार
puranika@gmail.com

जिन्हें आप अपना परम मित्र मानते थे, वे आपके दुश्मनों से हाथ मिलाते दिख सकते हैं. उन्हें लगा कि आप नहीं, आपके दुश्मन उनके हितों के ज्यादा बड़े खैरख्वाह हैं. अपने व्यक्तिगत रिश्तों में कई बार हम स्तब्ध होते हैं कि अरे, वह मेरे बारे में ऐसी बात कैसे कह सकता है! सब संभव है जी. सऊदी अरब और पाकिस्तान का हालिया रक्षा समझौता इस बात को फिर सच साबित करता है. कल तक भारत का करीबी माना जाने वाला सऊदी अरब अब नये साझेदार की तलाश में है. यह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं. रिश्ते हमेशा 'तेल' और 'डॉलर' की नमी से सींचे जाते रहे हैं. यह हमें याद दिलाता है कि दोस्ती की नींव अगर हित पर रखी हो, तो उसका हमेशा टिकना मुश्किल है. व्यक्तिगत रिश्तों में स्वार्थों का तेल काम करता है. कंपनियों में यह अक्सर देखने में आता है कि प्रतिस्पर्धी कंपनी का टॉप ऑफिसर एक जमाने की प्रतिद्वंदी कंपनी ज्वॉइन कर लेता है.

व्यक्तिगत रिश्तों का हाल भी लगभग वैसा ही है. जब तक हित मेल खाते हैं, मित्रता प्रगाढ़ रहती है. जैसे ही प्राथमिकताएं बदलती हैं, वही मित्र विरोधी लगने लगता है. 'रामचरितमानस' में तुलसीदास जी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, 'कलि करि कपट सबै करहीं। मित्रहि कहत विरोधि बरहीं..' कलियुग की यही परिभाषा है- कपट हर रिश्ते में घुस जाता है. कपट अब कूटनीति और रणनीति के कपड़े पहनकर आता है. प्रबंध विज्ञान कहता है बदलाव ही शाश्वत है. कंपनियां बदलते बाजार के अनुसार रणनीति बदलती हैं. देश बदलते हालात के अनुसार नये गठजोड़ करते हैं. और व्यक्ति भी अगर नहीं बदला, तो समय उसे बदल देता है. आपके या आपके किसी करीबी के साथ गुजरा होगा, तो वह किसी पुराने रिश्ते के बदलने से स्तब्ध होगा. उसे अगर मीडिया के अंदाज में सलाह दी जाए, तो ये सलाहें होंगी- फैक्ट चेकिंग : पहले तो अपनी भावनाओं पर 'फैक्ट चेक' लगाइए- किसी को कहीं और फायदा दिख रहा है, तो इस सचाई को स्वीकार कीजिए. 'आज का धोखा, कल का सबक'- ऐसे तगड़े हेडलाइन खुद पर लगाइए. सबक लीजिए कि स्वार्थ से बढ़कर कुछ नहीं है. किसी से उम्मीद न कीजिए कि वह हर हाल में आपके साथ खड़ा रहेगा.

फोटो फीचर-पुरानी यादें, नया फोटोग्राफर. पुरानी तस्वीरों को देखिए, मुस्कराइए...कहीं हंसिए, कहीं चिढ़िए, लेकिन इमेजिन कीजिए- आपने नये फ्रेम लगवा लिये हैं. भावनाओं की दीवार अब नये पोस्टरों से सजी है. कार्टून कटिंग-हल्का व्यंग्य जरूरी. अपने दिल के कॉलम में एक 'कार्टून जोन' खोलिए. सोचिए, वह दोस्त दुश्मन बनकर कैसी हरकतें कर रहा है. पेट पकड़कर हंसिए, आखिर हंसी भी तो मीडिया का अहम हिस्सा है! बस ऐसे ही आप रिश्तों के बदलाव को झेल लेंगे.

आपके पत्र

नवरात्र में पहचानें अपनी शक्ति को

आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है. नौ दिनों तक चलने वाली शक्ति के नौ रूपों की पूजा की समाप्ति विजयादशमी के साथ होगी. ये नौ दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के अवसर हैं. वहीं विजयादशमी का अर्थ अपने भीतर के अंधकार पर विजय पाना और पूरी तरह से एक नया और सकारात्मक मनुष्य बनने का द्योतक है. आइए हम संकल्प लें कि देवी पूजा के इस अवसर पर हम अपने भीतर की बुराइयों को दूर करेंगे और स्वयं को एक नया और सकारात्मक ऊर्जा से लैस मनुष्य बनायेंगे.

अन्विका शेखर, छपरा

मोबाइल फोन का बच्चों पर असर

मोबाइल फोन से निकलने वाला रेडिएशन बच्चों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है. इस रेडिएशन के कारण तंत्रिका संबंधी समस्याएं होने की संभावना तो होती ही है, बच्चों में बोलने, सांस लेने और सीखने की क्षमता में भी कमी आती है. एक शोध से पता चलता है कि कि मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन बच्चों में चिड़चिड़ेपन का कारण भी बन रहा है. इस कारण बच्चे गुस्सैल होते जा रहे हैं. ऐसे में बहुत आवश्यक है कि हम बच्चों के मोबाइल उपयोग की एक समयसीमा तय करें.

निशु झा, धनबाद

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001 ■ **फैक्स करें** : 0651-2544006 ■ **मेल करें** : eletter@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

उम्मीद के 7 मिनट

कोई भी व्यक्ति उससे प्रेम नहीं करता, जिससे वह डरता है। जहां डर है वहां प्रेम संभव नहीं।

-अरस्तु, दार्शनिक

खुशी की गाइड

संतोष व संतुलन से आती है स्थायी खुशी

रिसर्च, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट और हार्वर्ड

धन हमारे जीवन को सुविधाएं देता है। सुंदर घर, अच्छा भोजन, स्वास्थ्य की देखभाल और बच्चों की शिक्षा से लेकर सबकुछ। जरा सोचिए जब जेब में पैसे हों तो बाजार से मनचाही वस्तु खरीदते समय कैसा आत्मविश्वास रहता है। लेकिन जब जेब खाली हो वही बाजार बोझिल लगता है। ये धन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है।

- फिर भी शोध बताते हैं कि धन और खुशी का संबंध सीधा रेखीय नहीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट-2024 कहती है कि एक सीमा तक आय बढ़ने पर संतुष्टि भी बढ़ती है, लेकिन उसके बाद खुशी की वृद्धि रुक जाती है। भारत में उम्रदराज लोगों की संतुष्टि केवल आय से नहीं बल्कि शिक्षा सामाजिक सम्मान, स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर पाई गई।
- यही बात महाराष्ट्र के सांगली जिले के अध्ययन में भी दिखी, जहां आय बढ़ने के बाद भी खुशी सामाजिक संबंधों और मानसिक स्वास्थ्य पर टिक गई।
- हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एडल्ट डेवलपमेंट अध्ययन भी यही कहता है कि जीवन में असल संतोष और स्वास्थ्य का आधार न तो धन है और न ही प्रसिद्धि, बल्कि गहरे रिश्ते, व्यक्तिगत और सामाजिक हैं।
- ईशावास्य उपनिषद् भी कहता है त्याग की भावना से भोग करो और किसी के धन की लालसा मत करो। धन सुरक्षा और साधन तो देता है पर स्थायी खुशी, संतोष संतुलन और संबंधों से ही आती है।

▪ 1 मिनट रीड

सकारात्मक संकल्प

प्रियजनों से रोज बात करें

रोजाना अपने किसी दोस्त या परिजन से आमने-सामने बैठ कर या फोन पर चंद मिनटों की अच्छी-बातें जरूर करें। इसमें ना सिर्फ अपनी बातें बताएं, बल्कि सामने वाले की बातों को भी गौर से सुनें। इसके लिए आप सुबह या शाम को कामकाज समाप्त होने के बाद 10-15 मिनट का समय चुन सकते हैं। ज्यादातर बातें सकारात्मक हों, लेकिन अपनी समस्या भी साझा करें। यह बातचीत ना सिर्फ तनाव और अकेलापन दूर करती है, बल्कि आनंद का भाव बढ़ा कर मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर भी बनाती है। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि नियमित संवाद से गलतफहमियां कम होती हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं।

संकल्प लें कि रोजाना अपने प्रियजनों से बातचीत कर अपने मन की बात और सकारात्मक अनुभव साझा करेंगे।

▪ 1 मिनट रीड

सुने गए शब्दों से होता है संवाद का मूल्यांकन

जीवन-सूत्र

स्वामी मुकुंदानंद
आध्यात्मिक गुरु और लेखक

क्या आपने कभी विचार किया है कि आधुनिक युग में अधिकांश रिश्ते अस्थिर क्यों हो गए हैं? हमारी सर्वश्रेष्ठ मंशाओं के बाद भी गलतफहमियां उभर आती हैं, रिश्तों की डोर कमजोर पड़ जाती है। समस्या न तो भावनाओं की कमी है न ही प्रयासों की। इसका असली कारण यह है कि हम मूलभूत सत्य को अनदेखा कर बैठते हैं। दरअसल वास्तविक संवाद का मूल्यांकन बोले गए शब्दों से नहीं, सुने गए शब्दों से होता है।

जरा सोचिए स्कूल से कॉलेज तक हमें वाद-विवाद भाषण समूह चर्चा एवम् रचनात्मक लेखन जैसी गतिविधियों के माध्यम से बोलने और लिखने की कला को बेहतर बनाने का भरपूर अवसर मिलता है। किंतु हमें शायद ही कभी सुनने की कला सिखाई जाती है। परिणामस्वरूप हममें से अधिकांश निष्क्रिय या चयनात्मक श्रोता बन जाते हैं। हम केवल वही सुनते हैं, जो हम सुनना चाहते हैं। यहां तक कि अपनी धारणाओं पूर्वग्रहों या उस क्षण की मनोदशा के आधार पर बातचीत का निष्कर्ष भी निकालते हैं।

दूसरों को समझने के बजाय हम प्रतिवाद की तैयारी में लग जाते हैं। बातों में तर्क तो होता है, परंतु सहानुभूति का अभाव रह जाता है। प्रसिद्ध कहावत है अधिकतर लोग समझने की मंशा से नहीं सुनते वे प्रत्युत्तर देने की मंशा से सुनते हैं।

आज जब रिश्ते जटिल व तनावपूर्ण हो वास्तविक श्रवण शब्दों को सुनने तक सीमित नहीं होता। इसका अर्थ है संदेश को पूर्ण रूप से आत्मसात करना, गैर मौखिक संकेतों का अवलोकन करना और अभिमत को स्थगित कर स्पष्टता व सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया देना। कई बार इसका तात्पर्य चुप रहना भी होता है क्योंकि अकसर शब्दों से अधिक अर्थपूर्ण मौन होता है।

वास्तविक श्रवण का एक प्रखर उदाहरण महाभारत में देखने को मिलता है। ऋषि वेद व्यास के शिष्य संजय को दिव्य दृष्टि द्वारा कुरुक्षेत्र युद्ध का दर्शन प्राप्त हुआ था। एकात्मता व निष्पक्षता के साथ उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को युद्ध की घटनाओं का वर्णन किया। विशेष रूप से उन्होंने श्रीकृष्ण-अर्जुन के बीच हुए संवाद को ध्यानपूर्वक सुना। संजय की एकाग्रता के कारण भगवद् गीता का ज्ञान हमें उपलब्ध हुआ और आज भी मानवता को प्रेरित करता है। उनका उदाहरण दर्शाता है कि श्रवण निष्क्रिय नहीं होता। यह हृदय की स्वीकृति से संपन्न एक पवित्र कर्म है। श्रवण चुनिंदा लोगों को प्रदत्त वरदान नहीं है। इसे हम सभी विकसित कर सकते हैं। आइए

श्रवण आपके संवाद में तो सुधार लाता ही है बल्कि अंतःक्रिया को सरल व अर्थपूर्ण भी बना देता है।

जानें कुछ सरल एवं प्रभावशाली प्रक्रियाएं...

1. दूसरों को अविभाजित ध्यान दें और उस समय अन्य कार्य न करें ताकि वक्ता को लगे कि उनकी बातें आपके लिए मूल्यवान हैं।
2. जब बातचीत आमने-सामने हो तो आंखों का संपर्क बनाए रखें। वक्ता को बिना टोके बात कहने दें।
3. गैर मौखिक संकेतों को समझना भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि स्वर का उतार-चढ़ाव चेहरे की प्रतिक्रियाएं एवं देहभाषा।
4. व्यक्तिगत पूर्वग्रहों से अलग अन्य के दृष्टिकोण को निष्पक्षता के साथ ग्रहण करें।
5. अनचाहे सुझाव देने से पहले संयम बरतना ही बुद्धिमानी है। कहने को कुछ सार्थक न हो, तब मौन सबसे सम्मानजनक है।

नियमित अभ्यास से ये आदतें संवाद में सुधार लाती हैं बल्कि अंतःक्रिया को सुदृढ़ मधुर एवं अर्थपूर्ण बना देती हैं।

अंततः श्रवण एक दुर्लभ्य उपहार है, जो हम दूसरों को दे सकते हैं। कदाचित यही कारण है कि प्रकृति ने हमें दो कान और एक मुंह दिया ताकि हम सुनें अधिक और बोलें कम।

2 मिनट रीड

संघर्ष की कहानी **मोहम्मद सिराज,** भारतीय क्रिकेटर

उधार के जूते पहने, भूखे पेट प्रैक्टिस की, अब सफल गेंदबाज

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (31) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मंच पर मेहनत, जज्बे और हौसले की मिसाल बन चुके हैं। पिछले माह इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस के चलते आईसीसी ने सिराज को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। हैदराबाद की झोपड़पट्टी से टीम इंडिया तक उनका सफर आसान नहीं रहा। जानते हैं उनकी संघर्ष से सफलता की कहानी...

सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में हुआ था। उनका परिवार बेहद साधारण था। पिता मोहम्मद गौस ऑटो रिक्शा चलाकर गुजारा करते थे। मां घर चलाने के लिए कई घरों में साफ-सफाई का काम करती थीं। आर्थिक तंगी इतनी थी कि बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए सिराज ने कैटरिंग तक में काम किया। वहां वे रूमाली रोटियां बनाते थे। एक साक्षात्कार में सिराज ने बताया कि कई बार तो उनके हाथ जल जाते थे।

संघर्ष: 20 किमी पैदल जाते थे ट्रेनिंग के लिए, पिता के निधन से टूटे

मोहम्मद सिराज का ट्रेनिंग ग्राउंड उनके घर से 20 किलोमीटर दूर था। परिवार के पास साधन नहीं थे। ऐसे में सिराज अकसर पैदल ही ग्राउंड पर जाते थे। सिराज के पास खेलने के लिए जूते भी नहीं थे। ऐसे में वे कई बार अपने दोस्तों से उनके जूते लेकर खेलने जाते थे। बस का किराया बचाने के लिए सिराज खाना नहीं खाते थे। भूखे पेट ही प्रैक्टिस के लिए निकल जाते थे। 2020 में ऑस्ट्रेलिया दौरे से ठीक पहले उनके पिता का

निधन हो गया था। इस दुःख के बीच सिराज ने पिता की कब्र पर जाकर वादा किया था कि वे उनके सपनों को पूरा करेंगे। सोशल मीडिया पर शुरुआती आलोचनाओं और चोटों ने भी सिराज को तोड़ा था। इन सब परिस्थितियों के चलते एक समय ऐसा भी आया, जब सिराज ने क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का भी मन बना लिया था।

शुरुआत: 21 की उम्र में रणजी और आईपीएल में दमदार डेब्यू

सिराज ने 2015 में हैदराबाद की रणजी टीम से शुरुआत की, जहां उन्होंने पहले सीजन में 41 विकेट लेकर सबका ध्यान आकर्षित किया। उनकी मेहनत तब रंग लाई, जब सनराइजर्स हैदराबाद ने 2017 के आईपीएल में उन्हें टीम में जगह दी। उसी वर्ष उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में डेब्यू कर उन्होंने देश के लिए खेलना शुरू किया।

सफलता : आईपीएल में 12.25 करोड़ में बिके, ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्ट में शामिल

2024 में तेलंगाना सरकार ने सिराज को डीएसपी के पद पर नियुक्त किया। बीसीसीआई ने सिराज को 2024-25 के सालाना कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड A खिलाड़ियों में शामिल किया है, जिसके तहत उन्हें सालाना 5 करोड़ रुपए की रिटेनर फीस मिलती है। आईपीएल में भी सिराज की 2025 की नीलामी में गुजरात टाइटंस ने उन्हें 12.25 करोड़ रुपए में खरीदा था।

▪ 2 मिनट रीड

Join This Channel:- https://t.me/AllNewsPaperPaid1

प्रेरक प्रसंग

मित्रता में घमंड ना बने बाधा

नेल्सन मंडेला के जीवन की यह घटना उनकी उदारता और क्षमाशीलता के गुण को बताती है। इससे हमें सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता में पद और हैसियत का घमंड आड़े नहीं आना चाहिए।

यह घटना दक्षिण अफ्रीका की संसद की है। देश का नया संविधान तैयार किया जा रहा था। रॉबेन द्वीप जेल में 18 साल बिताने के बाद मंडेला अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बन चुके थे। वे हेलिकॉप्टर से संसद पहुंचे। मंडेला वहां सांसदों और अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे कि उनकी नजर भीड़ में खड़े क्रिस्टो ब्रांड पर पड़ी। यह शख्स कोई और नहीं, बल्कि मंडेला की कारावास अवधि के दौरान रॉबेन द्वीप जेल के वॉर्डन थे। उन्होंने ब्रांड को बुलाया और सभी से परिचय कराते हुए बोले, 'आप जानते हैं कि यह व्यक्ति कौन है? यह व्यक्ति मेरे जेलर थे, जेल में ये मेरे दोस्त थे।' यह सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जब मंडेला रॉबेन जेल पहुंचे थे तो ब्रांड महज 18 साल के थे। वे मंडेला पर सख्त निगरानी रखते थे। लेकिन धीरे-धीरे वे मंडेला से प्रभावित हुए और दोस्ती ऐसी बनी कि ब्रांड मंडेला के पसंदीदा ब्रेड और पसंद की चीजें छुपाकर अंदर लाने लगे। वे मंडेला की नवजात पोती को भी अंदर ले आए ताकि वे उसे दुलार सकें। राष्ट्रपति जैसे बड़े पद पर होने के बावजूद मंडेला ने अपने और क्रिस्टो के बीच दोस्ती के रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। एक ऐसा रिश्ता, जो रॉबेन द्वीप की जेल में विकसित हुआ था।

आत्मकथा में बताया वाकया

क्रिस्टो ब्रांड ने अपनी आत्मकथा 'मंडेलाः माई प्रिजनर, माई फ्रेंड' में इस पल को याद करते हुए लिखा है कि मंडेला के इस ... ने उन्हें ... और सम्मान से भर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि सच्ची ताकत दूसरों को माफ करने और उनके भीतर इंसानियत को देखने में है, भले ही वे आपके उत्पीड़क ही क्यों न रहे हों।

▪ 1 मिनट रीड

सीनियर सिटीजन

आर्थिक साथी

एफडी पर उच्च ब्याज दरें चाहिए तो यहां खाता खोलें

बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) की वरिष्ठ नागरिक विशेषाधिकार स्कीम आपके लिए काफी उपयोगी हो सकती है। इसमें वरिष्ठ और वरिष्ठतम नागरिकों के लिए एफडी पर खास ब्याज दरें मिल रही हैं। साथ ही इसके तहत खाते खुलवाने पर कई तरह के लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।

▪ बैंक ऑफ बड़ौदा में विशेषाधिकार बचत खाता कौन खुलवा सकता है?

बीओबी विशेषाधिकार बचत खाता उन नागरिकों के लिए है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो गई है। खासकर वे वरिष्ठ नागरिक, जो जमा राशि पर बेहतर दरों के साथ ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा सेवानिवृत्त लोग पेंशन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता बैंक की वेबसाइट या बैंक शाखा के माध्यम से ऑनलाइन खोला जा सकता है।

खाते के साथ ये फायदे मिल रहे

- डेबिट कार्ड से प्रतिदिन 50,000/- रुपए तक नकद निकासी सीमा है।
- वार्षिक लॉकर किराए पर 25% छूट।
- पहले वर्ष निःशुल्क वीसा प्लेटिनम डेबिट कार्ड। निकासी 1 लाख रु. तक।
- स्वीप सुविधा मांगने पर उपलब्ध है।
- निःशुल्क प्राइम क्रेडिट कार्ड। बीओबी एटीएम पर मुफ्त असीमित लेनदेन।
- पहले वर्ष के डीमैट वार्षिक रखरखाव शुल्क पर छूट है।
- रिवर्स मॉर्गेज ऋण पर प्रसंस्करण शुल्क में 50% तक की छूट।
- फ्लेक्सी एफडी पर उच्च ब्याज दरें।
- इस खाते को पेंशन खाते के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- चेकबुक, ई-मेल, स्टेटमेंट और एसएमएस अलर्ट सुविधा भी है।

आपकी योजना **बुढ़ापे में स्वास्थ्य देखभाल जरूरी,** जानिए वे सरकारी सुविधाएं, जो सेहत का सहारा बनेंगी

इन 4 स्कीम में बुजुर्गों को मिलता है निःशुल्क इलाज

डॉ. अशोक कुमार भार्गव
आईएएस, पूर्व कमिश्नर, मप्र

बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य देखभाल बहुत जरूरी है। यदि सेहत बिगड़ जाती है तो बुढ़ापे में सबसे बड़ी चुनौती इलाज पर होने वाला लाखों रुपए का खर्च होता है। चूंकि इस दौरान आय के साधन भी सीमित हो जाते हैं, इसलिए महंगा इलाज बुजुर्गों के लिए भारी पड़ता है। इलाज में आर्थिक स्थिति आड़े नहीं आए, इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ सरकारी योजनाएं हैं, जिनका लाभ लेकर सरकारी के साथ निर्धारित निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज कराया जा सकता है।

स्वास्थ्य से जुड़ी वे कौन सी सरकारी योजनाएं हैं? उनका लाभ कैसे लिया जा सकता है? कितनी राशि तक का इलाज कवरेज इनमें मिल सकता है? कौन-कौन सी बीमारियां इन स्कीम में कवर हो सकती हैं? क्या निजी अस्पताल में इलाज कराने पर भी मदद मिल सकती है? ऐसे सभी सवालों के जवाब यहां जानिए।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य में उम्र का बंधन नहीं, 5 लाख तक का कवरेज

- **कवरेजः** 100 साल की उम्र के बुजुर्ग भी इस स्कीम के दायरे में आते हैं। वे 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं।
- **सुविधाः** सरकारी के अलावा देशभर में 24 हजार से अधिक रजिस्टर्ड निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा।
- **आयु सीमाः** इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है।
- **बीमारीः** यह पॉलिसी पहले से मौजूद बीमारियों के इलाज को भी कवर करती है। हॉस्पिटल में भर्ती होने से 30 दिन पहले व डिस्चार्ज के 60 दिन बाद का खर्च मिलता है।
- **पात्रताः** इस स्कीम के लिए वे ही बुजुर्ग नागरिक पात्र हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। वही आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आयुष्मान वय वंदना योजना

- **कवरेजः** 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग इस योजना में 5 लाख रु. तक का मुफ्त इलाज सरकारी व नेटवर्क अस्पतालों में करा सकते हैं।
- **सुविधाः** देशभर में 24 हजार से अधिक रजिस्टर्ड निजी अस्पतालों में कैशलेस सुविधा।
- **बीमारीः** हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों को भी इसमें कवर किया गया है।
- **आयु सीमाः** 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग। आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनता है।
- **पात्रताः** इस स्कीम का लाभ सभी आय वर्ग के बुजुर्ग ले सकते हैं। चाहे बीपीएल परिवार के हों या फिर उच्च आर्थिक आय में आते हों।

स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम

- **कवरेजः** इस योजना में डिमेंशिया, गठिया और मधुमेह जैसी आयु-संबंधी बीमारियों का इलाज कवर किया जाता है।
- **सुविधाः** सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क या रियायती दर पर उपचार की सुविधा मिलती है।
- **बीमारीः** लंबी देखभाल के लिए वृद्धावस्था क्लिनिक व पुनर्वास केंद्र की सुविधा भी है।
- **आयु सीमाः** 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक लाभ ले सकते हैं।
- **पात्रताः** इसमें गामीण क्षेत्र के बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दिया है। शहरी क्षेत्र के जरूरतमंद बुजुर्ग भी इसके लिए पात्र हैं।

केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना

- **कवरेजः** केंद्रीय सेवाओं से रिटायर कर्मचारी और अधिकारी निःशुल्क इलाज करा सकते हैं।
- **सुविधाः** स्कीम के तहत नेटवर्क में शामिल अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा भी है।
- **बीमारीः** अस्पताल में भर्ती होने से 30 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 60 दिन बाद तक के सभी इलाज खर्च इसमें शामिल होते हैं।
- **आयु सीमाः** इस योजना के तहत केंद्रीय पेंशनर्स को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।
- **पात्रताः** पेंशनर्स व्यक्ति के अलावा उन पर जो भी व्यक्ति आश्रित है उसका इलाज भी इस सीजीएचएस के तहत कराया जा सकता है।

आपके अनुभव **जो जीवन में** आपके सबक बनेंगे

सच्चा सुख परिवार के साथ मिलता है

वृद्ध माता-पिता का अकेलापन दूर करने के लिए आज कल बच्चे कई प्रकार के भौतिक साधन जैसे मोबाइल, टीवी, रेडियो, पत्र-पत्रिकाएं आदि उपलब्ध करा देते हैं। ये चीजें कुछ हद तक उनका टाइम पास कर भी देती हैं, लेकिन उन्हें सच्चा सुख अपनों के साथ, परिवार के बीच रहने से मिलता है। जब बुजुर्ग माता-पिता घर में अपने परिजन को देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। पोते-पोतियों की किलकारियां उनके जीवन में नए उत्साह का संचार करती हैं। जब बच्चे उनके साथ खेलते और वक्त बिताते हैं तो उन्हें असीम आनंद मिलता है।

▪ **ताराचंद मकसाने**
नवी मुंबई (महाराष्ट्र)

बेबस नहीं, सक्रिय बने रहें

बुजुर्ग होने पर बेबस नहीं, सक्रिय रहें। यह स्वस्थ रहने में भी मदद करता है। यदि आप प्रकृति प्रेमी गृहिणी हैं और अपने शौक के साथ आय बढ़ाना चाहती हैं तो बागवानी से जुड़ जाएं। जीरो इन्वेस्ट से आप अपनी बालकनी से यह शुरुआत कर सकती हैं। बेकार पड़े प्लास्टिक के डिब्बों को मनचाहे पेंट कर पौधे लगा सकती हैं। मैं अपने महिला ग्रुप में हर माह एक सदस्य को अपने हाथ से पेंट किया हुआ गमला पौधा लगाकर देती हूं। लेखन कार्य भी जारी है। चार किताबें लिख चुकी हूं।

▪ **मनु वशिष्ठ,** कोटा (राजस्थान)

अपने ऐसे अनुभव, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनें, srcitizen@dbcorp.in पर भेज सकते हैं। चुनिंदा अनुभव प्रकाशित करेंगे।

ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड

हौसला नहीं हारे... चोट से उबरे, फिर मेडल जीते

ये हैं हरियाणा के 76 वर्षीय राम किशोर शर्मा। अब तक दौड़, जैवलिन थ्रो में कई नेशनल-इंटरनेशनल मेडल जीत चुके हैं। 2022 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 100 मीटर की दौड़ में घायल हो गए थे। इसके कारण रेस छोड़नी पड़ी, लेकिन हौसला जिंदा रखा। 2024 में अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैम्पियनशिप सिंगापुर में कांस्य पदक जीता। इसी साल फरवरी में राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में कांस्य पदक, मार्च में थाईलैंड ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में रजत और मई में वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स चाइना में जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता। अब फरवरी 2026 में आबूधावी में होने वाले ओपन वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स की तैयारी में जुटे हुए हैं। रोज दो घंटे पसीना बहा रहे हैं।

सप्ताह का स्वास्थ्य मंत्र

रोज सिर्फ 21 मिनट व्यायाम रखेगा फिट

यदि बढ़ती उम्र में आप सप्ताह में ढाई घंटे व्यायाम के लिए दे रहे हैं तो शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे। शोध बताते हैं कि इस हिसाब से रोजाना औसतन 21-22 मिनट ही आपको व्यायाम करना है। इसमें एरोबिक, ताई ची, एक पैर पर खड़े रहना और स्ट्रेचिंग जैसे व्यायाम कर सकते हैं। इन्हें करने से स्वास्थ्य के साथ आपकी खुशी भी बढ़ती है।

हेल्पलाइन नंबर

एम्बुलेंस चाहिए तो 102 पर कॉल करें

वरिष्ठ नागरिक यदि किसी मेडिकल इमरजेंसी में हैं तो वह तत्काल एम्बुलेंस बुला सकते हैं। देश में कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय 102 नंबर डायल करके यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी को दिल का दौरा पड़ा है, स्ट्रोक आया है या दुर्घटना हुई है तो इस नंबर पर कॉल करते ही आपातकालीन कर्मचारी कुछ ही मिनटों में आपके पास पहुंच जाएंगे।

स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन के लिए 1075 डायल करें

वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिकल इमरजेंसी में हेल्पलाइन 1075 मार्गदर्शन देती है। चाहे दवा के दुष्प्रभावों को समझना हो, मधुमेह, बीपी का प्रबंधन करना हो या छोटी-मोटी बीमारियों के बारे में सलाह लेनी हो। इस हेल्पलाइन नंबर पर प्रशिक्षित पेशेवर मार्गदर्शन देते हैं।

संपादकीय

" कोई स्थायी गठबंधन नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं।
- हेनरी जॉन टेंपल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एच-1बी वीजा नीति में अप्रत्याशित बदलाव की घोषणा से भारतीय पेशेवरों में संशय है। वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में इस तरह का संरक्षणवाद दीर्घकाल में भले अमेरिका के लिए आत्मघाती हो, लेकिन फिलहाल भारत को कूटनीतिक सतर्कता दिखानी होगी।

ट्रंप की मंशा

अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अधिकारियों की नई दिल्ली यात्रा के कुछ ही दिन बाद और भारत के वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अमेरिका यात्रा के ऐन पहले, जब द्विपक्षीय व्यापार वार्ता पटरी पर लौटती दिख रही थी, ठीक तभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा के शुल्क में अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने वैश्विक प्रतिभा बाजार को हिला कर रख दिया है। भारतीय पेशेवरों के लिए तो यह और भी बड़ा धक्का है, जो इस वीजा कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं। दरअसल, एच-1बी वीजा उच्च कुशल पेशेवरों को अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है, जो लंबे समय से भारतीय आईटी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिए सपनों का द्वार रहा है। नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका द्वारा अब तक जारी एच-1बी वीजा में करीब 72 फीसदी भारतीयों के खाते में ही आए हैं। लेकिन 21 सितंबर, 2025 से प्रभावी इस नई नीति के तहत अब नए एच-1बी वीजा आवेदकों को एक लाख डॉलर का शुल्क भरना होगा, जो अब तक महज एक हजार डॉलर था। जाहिर है कि कंपनियां अब नए विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने से पहले दो बार सोचेंगी, क्योंकि एक लाख डॉलर का अतिरिक्त बोझ छोटी-मझोली फर्मों के लिए असहनीय हो सकता है। टीसीएस और इंफोसिस जैसी अमेरिकी बाजारों पर निर्भर भारतीय कंपनियों को भी अपनी रणनीति बदलते हुए अब या तो स्थानीय कर्मचारियों को प्राथमिकता देनी होगी या वे वैकल्पिक बाजारों की तलाश करेंगी। चौंकाने वाले फैसले लेना भले ही ट्रंप की आदत हो, लेकिन सेवा क्षेत्र में पहली बार अपनी संरक्षणवादी नीति के दर्शन करा, वह भूल रहे हैं कि अमेरिका को बनाने में अप्रवासियों की बड़ी भूमिका रही है। सिलिकॉन वैली के करीब एक-तिहाई टेक-कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। फॉर्च्यून 500 की लगभग डेढ़ दर्जन कंपनियों में शीर्ष पर भारतीय बैठे हैं, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के इंजन भी हैं। 2024 में 72 यूनिकॉर्न स्टार्टअप भारतीय मूल के लोगों के थे, जिनका कुल मूल्य करीब 195 अरब डॉलर आंका गया था। इन कंपनियों में अमेरिकी भी काम करते हैं। अमेरिकी आबादी में बमुश्किल डेढ़ फीसदी होने के बावजूद भारतीय पांच से छह फीसदी कर अदा करते हैं। नैसकॉम का यह कहना उचित ही है कि एच-1बी वीजा जैसे फैसलों का नकारात्मक असर अमेरिका में नवाचार के माहौल और रोजगार आधारित अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। रूस से तेल लेने पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ और चाबहार पर छूट को रद्द करने के बाद ट्रंप के एच-1बी वीजा शुल्क में बढ़ोतरी के फैसले के पीछे भारत पर दबाव बनाने की मंशा ही अधिक दिखती है।

रियाद, इस्लामाबाद और भू-राजनीतिक संकेत

सऊदी–पाक रक्षा समझौता याद दिलाता है कि आधुनिक दुनिया में गठबंधन विचारधारा से नहीं, बल्कि तात्कालिक सुरक्षा जरूरतों से तय होते हैं। आने वाले महीने बताएंगे कि नई दिल्ली इस नए सुरक्षा परिदृश्य में कितना संतुलन साध पाती है, जहां दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की सीमाएं धुंधली हो रही हैं।

आनंद कुमार
एसोसिएट फेलो एमपी-आईडीएसए

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए पारस्परिक रक्षा समझौते ने दक्षिण एशिया और खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा संरचना को गहराई से प्रभावित करने की संभावना पैदा कर दी है। समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। यह केवल भाईचारे का प्रतीक नहीं, बल्कि एक ऐसी रणनीतिक पुनर्संरचना है, जो युद्ध, शक्ति शून्यता और बदलते गठबंधनों से जूझ रहे क्षेत्र में नई चुनौतियां उत्पन्न करती है और भारत की सुरक्षा व कूटनीतिक रणनीति के लिए गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

इस समझौते की तात्कालिक पृष्ठभूमि पश्चिम एशिया की उथल-पुथल है। हाल ही में इस्राइल द्वारा कतर की राजधानी दोहा पर किया गया हमला, जिसमें वरिष्ठ हमास नेताओं के ठिकाने को निशाना बनाया गया और छह लोगों की मौत हुई, ने अरब जगत को झकझोर दिया। महत्वपूर्ण यह रहा कि इस हमले पर अमेरिका, जो परंपरागत रूप से खाड़ी क्षेत्र का सुरक्षा प्रदाता माना जाता रहा है, ने लगभग चुप्पी साधे रखी। 2019 में सऊदी तेल ठिकानों पर ईरान समर्थित बलों के हमले के बाद से ही अमेरिकी सुरक्षा गारंटी को लेकर शंकाएं बढ़ रही थीं। इस बार की चुप्पी ने यह संदेश और स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका अब पहले जैसी सुरक्षा छतरी देने में इच्छुक या सक्षम नहीं है। सऊदी अरब के लिए यह एक बड़ा संकेत था कि उसे अपने सुरक्षा विकल्पों का दायरा बढ़ाना होगा और अमेरिकी अनिश्चितता के बीच वैकल्पिक साझेदारों को खोजना होगा।

यहीं पर पाकिस्तान एक स्वाभाविक सहयोगी के रूप में सामने आता है। लंबे समय से रियाद का निकट साझेदार और एकमात्र मुस्लिम बहुल परमाणु शक्ति होने के कारण पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए विशेष महत्व रखता है। समझौता भले ही रक्षात्मक भाषा में प्रस्तुत किया गया हो, पर इसका रणनीतिक अर्थ कहीं अधिक गहरा है। पाकिस्तानी अधिकारी कहते हैं कि यह समझौता किसी विशेष देश के खिलाफ नहीं है और इसकी तुलना नाटो के सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत से की जा सकती है। इसके बावजूद, इसका समय और प्रसंग स्पष्ट रूप से बताता है कि यह इस्राइल की हालिया कार्रवाइयों और बदलते क्षेत्रीय समीकरणों की प्रतिक्रिया है। इस समझौते के प्रभाव अनेक स्तरों पर दिख सकते हैं। खाड़ी में यह पहले से अस्थिर माहौल को और जटिल बनाता है। अमेरिका द्वारा कराए गए अब्राहम समझौते, जिनका उद्देश्य अरब देशों और इस्राइल को ईरान विरोधी मोर्चे में जोड़ना था, गाजा संघर्ष और इस्राइल की आक्रामक कार्रवाइयों से कमजोर पड़ चुके हैं। सऊदी अरब और इस्राइल के बीच संबंध सामान्य करने की योजनाएं अब ठंडी पड़ गई हैं। पाकिस्तान के साथ रक्षा गठबंधन कर रियाद यह संकेत दे रहा है कि वह अमेरिकी और इस्राइली प्रभाव से बाहर अपनी स्वतंत्र सुरक्षा नीति अपनाएगा। इससे अन्य खाड़ी देश भी इसी तरह की व्यवस्थाओं की ओर बढ़ सकते हैं, जिससे पुरानी सुरक्षा संरचना और अधिक ढीली पड़ सकती है।

दक्षिण एशिया के लिए भी यह विकास कम महत्वपूर्ण नहीं है। पाकिस्तान द्वारा सऊदी अरब को परमाणु छतरी देने की पेशकश पहले से तनावपूर्ण परमाणु संतुलन को और जटिल बनाती है। भारत, जिसके पास अनुमानतः लगभग 172 परमाणु हथियार हैं, अब ऐसी स्थिति का सामना करेगा, जिसमें पाकिस्तान की परमाणु क्षमताएं अप्रत्यक्ष रूप से एक बड़े खाड़ी देश की सुरक्षा से जुड़ सकती हैं। यद्यपि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि सऊदी अरब को परमाणु हथियारों तक पहुंच मिलेगी, परंतु पाकिस्तानी परमाणु सुरक्षा की संभावना ही निवारक समीकरण को बदलने के लिए पर्याप्त है। भारत की कूटनीतिक स्थिति अब और संवेदनशील हो गई है। पिछले एक दशक में नई दिल्ली ने सऊदी अरब के साथ ऊर्जा, व्यापार और आतंकवाद निरोध में मजबूत साझेदारी बनाने में काफी निवेश किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह इस समझौते के प्रभावों का अध्ययन करेगा और उम्मीद करता है कि रियाद दोनों देशों के हितों और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखेगा। पर हकीकत यह है कि यह समझौता नई अनिश्चितताओं को जन्म देता है। भारत को अब रियाद के साथ अपने रिश्ते बनाए रखते हुए पाकिस्तान–सऊदी रिश्तों से पैदा हो सकने वाले सुरक्षा जोखिमों से सतर्क रहना होगा।

यह समझौता व्यापक भू-राजनीतिक संकेत भी देता है। यह दर्शाता है कि दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया, दोनों में अमेरिकी प्रभाव धीरे-धीरे घट रहा है। वाशिंगटन की अनिर्णयता ने एक शून्य पैदा किया है, जिसे क्षेत्रीय शक्तियां भरने की कोशिश कर रही हैं। चीन, जो पहले से ही पाकिस्तान और सऊदी अरब, दोनों का करीबी साझेदार है, इन घटनाओं को ध्यान से देखेगा, जबकि ईरान भी सतर्क रहेगा, क्योंकि वह रियाद और इस्लामाबाद, दोनों का प्रतिद्वंद्वी है। एक संभावित परमाणु आयाम वाले सऊदी–पाक सुरक्षा अक्ष का उभार तेहरान के लिए भी चिंता का कारण बनेगा।

भारत के लिए आगे की राह में रणनीतिक धैर्य और संतुलन आवश्यक होगा। वह सऊदी अरब को नाराज नहीं कर सकता, जो ऊर्जा आपूर्ति और आतंकवाद विरोधी सहयोग का अहम भागीदार है। साथ ही, उसे पाकिस्तान की खाड़ी में बढ़ती भूमिका को लेकर सजग रहना होगा। हाल के वर्षों में भारत का इस्राइल के साथ बढ़ता रक्षा सहयोग भी सावधानी से आगे बढ़ाना होगा, ताकि अरब देशों में गलत संदेश न जाए। चुनौती यही है कि भारत इस्राइल और अरब जगत, दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखते हुए अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं से समझौता न करे।

सऊदी–पाक रक्षा समझौता याद दिलाता है कि आधुनिक दुनिया में गठबंधन अक्सर विचारधारा से नहीं, बल्कि तात्कालिक सुरक्षा आवश्यकताओं से तय होते हैं। यह लंबे समय से परदे के पीछे मौजूद रिश्ते को औपचारिक रूप देता है और इसके पीछे की रणनीतिक गणनाओं को उजागर करता है। भारत के लिए यह कोई संकट नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि बदलते क्षेत्रीय परिदृश्य में पुरानी धारणाओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आने वाले महीने बताएंगे कि नई दिल्ली इस नए और अनिश्चित सुरक्षा परिदृश्य में कितनी कुशलता से संतुलन साध पाती है, जहां दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं और दूरस्थ राजधानियों की गतिविधियां तत्काल प्रभाव डाल रही हैं।

Join This Channel:- https://t.me/AllNewsPaperPaid1

जीवन धारा

कार्ल हिल्टी

जीवन का विकास सीधा, एकसमान पथ नहीं है, बल्कि अप्रत्याशित तत्वों और रचनात्मक चुनौतियों वाला पथ है। जीवन के प्रत्येक काल का अपना उद्देश्य और कार्य होता है।

जीवन का अर्थ खाना-पीना और मर जाना नहीं है

हर जीवन में कई चरण होते हैं, और कोई भी जीवन शुरुआत से अंत तक एकसमान सीधा नहीं चलता, जैसे कोई साफ-सुथरी नदी या कृत्रिम रूप से बनाई गई सीधी नहर। कोई दो जीवन बिल्कुल एक-दूसरे जैसे नहीं चलते, और यहां तक कि सबसे प्राकृतिक लगने वाले चरण भी कभी-कभी एक-दूसरे की उल्टी दिशा में होते हैं। इसलिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो अपनी युवावस्था में असाधारण रूप से बुद्धिमान होते हैं, और उनमें युवावस्था के गुण वृद्धावस्था में ही आते हैं। हर जीवन में ऐसी गलतियां होती हैं, जिन्हें टाला जा सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि कोई स्वस्थ जीवन पूरी तरह से स्थिर नहीं होता, न ही कोई पूरी तरह से सामान्य होता है, बल्कि सभी के जीवन में अपरिहार्य गलतियां और छूटे हुए अवसर होते हैं, लेकिन वे किसी की गलत सोच या मूर्खता के कारण नहीं होते, बल्कि किसी बाहरी या आंतरिक वजह से होते हैं, जिसे रोका नहीं जा सकता और यही जीवन को आकार देते हैं। यह बताता है कि जीवन का विकास सीधा, एकसमान नहीं होता है, बल्कि यह अप्रत्याशित तत्वों और रचनात्मक चुनौतियों वाला पथ है। जीवन के प्रत्येक काल का अपना उद्देश्य और कार्य होता है। बसंत ऋतु में पेड़ बढ़ते और फूल खिलते हैं, इसके अलावा आप उसमें फल नहीं देख सकते और उस समय का एक अनोखा आनंद है। पौधों की प्राकृतिक वृद्धि में जानबूझकर बाधा डालकर आधुनिक बौने वृक्षों को केवल शीघ्र फल उत्पादन के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन उन वृक्षों पर उत्पन्न होने वाले फल न तो अच्छी गुणवत्ता के होते हैं और न ही प्राकृतिक वृक्षों पर पके फलों की तरह स्वस्थ होते हैं। एक व्यक्ति, जिसने जीवन की कई परिस्थितियों का अनुभव किया है और उनसे सीखा है, उसके पास जीवन की गहरी समझ और अपनी उपलब्धियों से निर्मित एक मजबूत, अडिग व्यक्तित्व, दोनों होते हैं। इसी प्रकार वृद्धावस्था भी अपने योग्य कार्य कर सकती है, जब व्यक्ति पतन और निराशा के बजाय ज्ञान और दूरदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करे, तभी यह संभव है। जो कोई भी जीवन के ऐसे किसी भी चरण को छोड़ देता है, और उसे जल्दी से पार कर जाता है, उसके विशिष्ट लाभों का कोई उपयोग नहीं करता, वह कभी भी बाद में उसे फिर से पाने की स्थिति में नहीं होगा, बल्कि उसके स्वरूप में हमेशा एक स्पष्ट कमी रहेगी। इस कमी को युवावस्था में रोकना शिक्षा का विषय है। जीवन के वास्तविक लाभ और उपलब्धियां इस आंतरिक, स्व-प्रेरित प्रयास से आती हैं, बाहरी मदद से नहीं। यह आंतरिक ज्ञान, निश्चित रूप से, उन लोगों के लिए नहीं है, जिनके लिए जीवन का अर्थ खाने-पीने और मर जाने के अलावा और कुछ नहीं है। आंतरिक जीवन के चरण उन लोगों के लिए हैं, जो जीवन के सभी चरणों से गुजरते हुए एक वास्तविक आध्यात्मिक जीवन की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं।

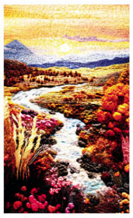

पहले चलना सीखें

सूत्र

जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए हमें चरणबद्ध तरीके से काम करना होगा, चाहे कॅरिअर हो या व्यक्तिगत जीवन। यदि आप चाहेंगे कि छलांग लगाकर सफलता हासिल कर लें, तो जीवन भर निराशा हाथ लगेगी। जीवन के प्रत्येक काल का अपना उद्देश्य और कार्य होता है। पहले चलना सीखें, फिर आगे बढ़ें, तभी जीवन सुंदर होगा।

दूसरा पहलू

आज, लगभग हर चीज इंटरनेट से जुड़ी है। आखिर इंटरनेट हमारे जीवन का हिस्सा कैसे बना?

इंटरनेट के हमारे जीवन का हिस्सा बनने की कहानी

इंटरनेट एक ऐसी व्यवस्था है, जिससे दुनिया भर के कंप्यूटर एक-दूसरे को संदेश भेज सकते हैं। व्यावहारिक रूप से इंटरनेट से जुड़ी हर चीज में एक कंप्यूटर होता है। 1960 के दशक में, कंप्यूटर केवल खास कामों (जैसे वैज्ञानिक शोध) के लिए इस्तेमाल होते थे। उस समय, अगर दो कंप्यूटरों को डाटा शेयर करना होता, तो लोग पहले से समय तय करते और फिर टेलीफोन कॉल के जरिये एक कंप्यूटर को दूसरे से जोड़ते। अमेरिक एक ऐसा नेटवर्क चाहता था, जिससे टेलीफोन लाइन खराब होने के बावजूद कंप्यूटर अपने आप संदेश भेज सकें। 1962 में, अमेरिकी इंजीनियर पॉल बरन रैंड कॉर्प ने 'हॉट पोटैटो नेटवर्किंग' नामक एक नया विचार दिया। इसमें संदेश को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता था। इन टुकड़ों में एक क्रम संख्या होती, ताकि दूसरा कंप्यूटर पूरा संदेश समझ सके। इस विचार को आज के अरपानेट के रूप में लागू किया गया। इन छोटे टुकड़ों को 'पैकेट' और इस प्रणाली को 'पैकेट स्विच्ड नेटवर्किंग' नाम मिला। इंटरनेट के जनक विन्ट सर्फ ने ऐसी व्यवस्था बनाई, जिसमें कोई पैकेट गायब हो जाए, तो उसे प्राप्त करने वाला कंप्यूटर भेजने वाले से उसे दोबारा मांग सके। इसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। 1990 के आसपास टिम बर्नर्स-ली ने सीईआरएन (यूरोपियन ऑर्गनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च) में काम करते हुए वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत की, ताकि उनके सहयोगी आसानी से अपने शोध को एक-दूसरे के साथ साझा कर सकें। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली बनाई, जिसमें एक कंप्यूटर पर कई 'पेज' हो सकते थे। इसके लिए उन्होंने यूआरएल (यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर) का विचार दिया, जो किसी भी कंप्यूटर को इंगित कर सकता था। बर्नर्स-ली ने पहला वेब ब्राउजर और वेब सर्वर बनाया। आज किसी यूआरएल में हम जो 'डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू' देखते हैं, यह उसी वर्ल्ड वाइड वेब से आया है। उन्होंने इसे मुख्य रूप से टेक्स्ट, तस्वीरें और फाइलें साझा करने के लिए बनाया था, लेकिन इंटरनेट ने इसे वीडियो और ऑडियो के लिए भी उपयुक्त बना दिया। यूट्यूब व इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म उसी का पालन करते हैं। कंप्यूटर अब सस्ते हो गए हैं, जिसके चलते लाखों-करोड़ों डिवाइस इंटरनेट से जुड़े हैं। इनमें सेंसर शामिल हैं, जैसे सिक्योरिटी कैमरा। इसके अलावा, स्मार्ट थर्मोस्टेट है, जो आपके घर की हीटिंग या कूलिंग को चालू-बंद करता है। इन सभी स्मार्ट डिवाइस को 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' कहा जाता है। आज, लगभग हर चीज इंटरनेट से जुड़ी है। यह एक ऐसा जाल है, जो न सिर्फ कंप्यूटरों को, बल्कि हमारी जिंदगी को भी जोड़ता है।

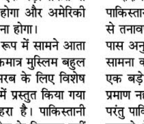

फ्रेड मर्टिन

1960 के दशक में, यदि दो कंप्यूटरों को डाटा शेयर करना होता, तो लोग पहले से समय तय करते थे।

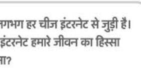

टिम बर्नर्स-ली ने एक ऐसी प्रणाली बनाई, जिसमें एक कंप्यूटर पर कई 'पेज' हो सकते थे। इसके लिए उन्होंने यूआरएल (यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर) का विचार दिया, जो किसी भी कंप्यूटर को इंगित कर सकता था।

आंकड़े

नवोन्मेषी देश

एक नवोन्मेषी देश विश्व के लिए प्रगति का पथ होता है। इस मामले में स्विट्जरलैंड इस वर्ष 100 में से 66 अंकों के साथ शीर्ष पर है।

स्विट्जरलैंड	66.0
स्वीडन	62.6
अमेरिका	61.7
दक्षिण कोरिया	60.0
सिंगापुर	56.6

चीन 56.6 अंकों के साथ वार्षिक रैंकिंग में 10वें स्थान पर है। | स्रोत : WIPO

अंतर्यात्रा

दुर्गम ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसका वध कोई भी पुरुष न कर सके, क्योंकि उसे भ्रम था कि कोई स्त्री उसे मार नहीं सकती, लेकिन उसका वध मां दुर्गा ने किया।

मां भगवती ने निभाया वचन

दुर्गम नाम के दैत्य ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया, जिसमें उसने मांगा कि कोई भी पुरुष उसका वध न कर सके, क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई स्त्री इतनी बलशाली नहीं हो सकती, जो उसे मार सके। इस वरदान के बाद दुर्गमासुर ने वेदों का ज्ञान चुरा लिया और देवताओं को परेशान करने लगा। देवताओं का बल क्षीण हो गया। इसके बाद दुर्गम ने स्वर्ग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। समस्त देवगण एकत्रित हुए और उन्होंने देवी मां भगवती का आह्वान किया। मां को देवताओं ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। इसके बाद मां भगवती ने समस्त देवताओं को दैत्य दुर्गम के प्रकोप से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया।

मां भगवती ने दुर्गम का अंत करने का प्रण लिया है, यह बात जब दुर्गम को पता चली, तो उसने स्वर्ग लोक पर पुनः आक्रमण कर दिया। इसके बाद साक्षात मां भगवती देवताओं और स्वर्ग लोक की रक्षा के लिए प्रकट हुईं और उन्होंने अपने वचन के अनुसार, दैत्य दुर्गम की सेना और उसका संहार कर मृत्यु लोक पहुंचा दिया। मां भगवती ने दुर्गम के साथ जब अंतिम युद्ध किया तब उन्होंने भुवनेश्वरी, काली, तारा, छिन्नमस्ता, भैरवी, बगला तथा दूसरी अन्य महा शक्तियों का आह्वान करके दुर्गम को पराजित किया था। इस भीषण युद्ध में विकट दैत्य दुर्गम को पराजित कर उसका वध करने पर मां भगवती दुर्गा नाम से प्रख्यात हुईं।

अंतर्यात्रा
संकलित

आज का इतिहास

भारत का नक्शा बदलने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पर चर्चा

इस बात को कौन नहीं जानता कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत के साथ कारोबार के लिए की गई थी, लेकिन भारत की धन धान्य से भरपूर रियासतों की आपस की लड़ाई और मजबूत नेतृत्व की कमी को देखते हुए कंपनी की साम्राज्यवादी आकांक्षाएं जाग गईं और उसने भारत का इतिहास और भूगोल सब बदलकर रख दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण में 22 सितंबर का एक खास महत्व है। दरअसल 1599 में वह 22 सितंबर का ही दिन था जब लंदन में 21 कारोबारियों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में भारत के साथ कारोबार करने के लिए एक कंपनी के गठन पर विचार किया गया। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की दिशा में पहला कदम कहा जा सकता है। 1539 - सिख संप्रदाय के पहले गुरु नानक देव जी का करतारपुर में निधन। पाकिस्तान स्थित इस जगह को अब डेरा बाबा नानक के नाम से जाना जाता है। 1599 : लंदन के फाउंडर हॉल में 21 व्यापारियों की बैठक हुई जिसमें भारत के साथ कारोबार के लिए एक नयी कंपनी स्थापित करने के बारे में चर्चा की गई। 1903 - अमेरिकी नागरिक इटालो मार्चिओनी को आइसक्रीम कोन के लिए पेटेंट मिला। 1914 - मद्रास बंदरगाह पर जर्मनी के युद्धपोत इम्देन ने बमबारी की।

मुद्दा

चुनौतियों को अवसर में बदलना होगा

ट्रंप का रवैया दशकों की भारत-अमेरिकी साझेदारी के लिए तो खतरा है ही, यह अमेरिकियों के हितों को भी चोट पहुंचा रहा है।

केएस तोमर

अपने दूसरे कार्यकाल के बमुश्किल नौ महीने पूरे होने पर ट्रंप ने ऐसे तीन फैसले लिए हैं, जो अदूरदर्शी राष्ट्रवाद और घरेलू दिखावे से प्रेरित नीति-निर्माण को उजागर करते हैं। एच-1बी वीजा शुल्क को बढ़ाकर, चाबहार बंदरगाह पर भारतीय संचालन की छूट को रद्द कर, और सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौते को मौन स्वीकृति देकर ट्रंप घरेलू मतदाताओं को आकर्षित कर राष्ट्रवादी रुख का संकेत दे रहे हैं, पर वह अमेरिकियों के हितों को ठेस भी पहुंचा रहे हैं। ये कार्रवाइयां दशकों की रणनीतिक योजना, क्षेत्रीय प्रभाव और भारत-अमेरिका साझेदारी के लिए खतरा हैं।

हरेक एच-1बी आवेदन पर एक लाख डॉलर शुल्क लगाने का ट्रंप का फैसला हथौड़े जैसा है। इसे 'अमेरिकी कामगारों की सुरक्षा' कहकर प्रचारित किया जा रहा है, पर इससे अमेरिकी नवाचारों के नष्ट होने और भारत-अमेरिका संबंधों के निचले स्तर पर जाने का खतरा है। भारत पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। अमेरिका में लगभग तीन लाख भारतीय पेशेवर हैं, जिनके सामने रोजगार का खतरा पैदा हो सकता है। अमेरिका में नौकरी की योजना बना रहे लोगों को अपने कॅरिअर में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भारत स्वास्थ्य और अनुसंधान एवं विकास में छूट पर बातचीत करने, वाशिंगटन में कॉर्पोरेट लॉबिंग का लाभ उठाने तथा यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया से साझेदारी करने का विकल्प चुन सकता है। भारत को स्टार्ट-अप्स का विस्तार, अनुसंधान और विकास को मजबूत करने, और वहां से वापस लौटने वाली प्रतिभाओं के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। एच-1बी शुल्क भले ही अमेरिका को वित्तीयम लाभ प्रदान करे, लेकिन वैश्विक प्रतिभाओं पर कर लगाकर अमेरिका अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। भारत को इस झटके को रणनीतिक आत्मनिर्भरता के अवसर में बदलना होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रियाद में हुए रक्षा समझौते ने दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था को झटका दिया है। इससे पाकिस्तान की जर्जर अर्थव्यवस्था और सैन्य स्थिति को मजबूती मिलेगी, साथ ही यह चीन की पश्चिम एशियाई रणनीति से मेल खाता है। नई दिल्ली ने सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए माना है कि उसे इस समझौते के बारे में पता था। यह संयम भारत के संतुलनकारी रवैये को दर्शाता है। सऊदी अरब भारत का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्तिकर्ता होने के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार भी है। इस समझौते के बाद सऊदी अरब का समर्थन पाकिस्तान को सीमा पार से प्रायोजित आतंकवादी समूहों को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए उकसा सकता है, जबकि इस्लामी एकजुटता का दिखावा चरमपंथी नेटवर्क को सक्रिय कर सकता है।

यह समझौता पिछले पांच वर्षों में सऊदी अरब के साथ विकसित हुए भारत के संबंधों को और जटिल बना देता है। चीन को इससे चुपचाप लाभ मिल रहा है, क्योंकि यह समझौता सीपीईसी को मजबूत कर रहा है और खाड़ी क्षेत्र में उसकी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ा रहा है, जिससे यह क्षेत्र अमेरिकी प्रभुत्व से दूर हो रहा है। भारत के सामने खाड़ी देशों के साथ अपनी साझेदारी बनाए रखने, आतंकवाद-रोधी समन्वय को मजबूत करने और अमेरिका, रूस और इस्राइल के साथ बहुध्रुवीय कूटनीति का लाभ उठाने की चुनौती है। चाबहार बंदरगाह पर भारत के संचालन के लिए अमेरिकी छूट को रद्द करने का ट्रंप का फैसला हमारी क्षेत्रीय रणनीति के लिए एक गंभीर झटका है। तेहरान पर 'अधिकतम दबाव' बनाने के तहत उठाए गए इस कदम से भारत के 12 करोड़ डॉलर का निवेश खतरे में पड़ गया है और भारत को अफगानिस्तान, रूस और मध्य एशिया से जोड़ने वाला गलियारा भी ठप हो गया है। चाबहार महज एक बंदरगाह ही नहीं, बल्कि यह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए एक जीवनरेखा है, चीन के ग्वादर का प्रतिकार है, और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे में एक महत्वपूर्ण स्थल है।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 66 ■ अंक 119 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2025-27 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

भारत बनाम अमेरिका, रिश्तो की नई इबारत, बनते-बिगड़ते वैश्विक समीकरण

संजीव ठाकुर

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के शुरुआती दिनों में 1947 से 1964 तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू और अमेरिकी राष्ट्रपतियों के बीच संबंध कभी गर्मजोशी से भरे तो कभी अविश्वास से ग्रस्त रहे। भारत और अमेरिका के बीच समानांतर स्थाई मित्रता कभी कभार ही देखने को मिली है। भारत की शांतिपूर्ण गुटनिरपेक्ष नीति और अमेरिका की पाकिस्तान-समर्थक रणनीति इस रिश्ते की सबसे बड़ी बाधाएँ थीं,फिर भी लोकतंत्र के साझा मूल्यों और खाद्यान्न व सैन्य सहयोग ने संवाद को जीवित रखा। 1962 का भारत-चीन युद्ध एक ऐसा मोड़ साबित हुआ जिसने दिखा दिया कि जब हित टकराएँ तो दूरी रहती है, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो दोनों साथ भी खड़े हो सकते हैं। 1947 से 1953 भारत की स्वतंत्रता के समय व्हाइट हाउस में हैरी एस. ट्रूमैन थे। उनका ध्यान यूरोप के पुनर्निर्माण और सोवियत संघ को रोकने पर था। अमेरिका चाहता था कि भारत अमेरिका के साथ रूस के विरोधी खेमे में शामिल हो जाए किन्तु नेहरू जी ने रूस के विरुद्ध किसी भी सैन्य गठबंधन और किसी भी समझौते से दूरी बनाये रखी थी जिससे अमेरिका भारत के संबंधों में निराशा हुई और जिसके कारण भारत और अमेरिका दोनों देशों के रिश्ते शुरुआती वर्षों में औपचारिक ही रहे। 1953 से 1963 ड्वाइट डी. आइज़नहावर के कार्यकाल में भारत अमेरिकी रिश्तों में कुछ गर्माहट आई थी, 1959 में वे भारत आए और संसद को संबोधित करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। खाद्यान्न संकट के दौरान पीएल 480 योजना के अंतर्गत अमेरिका ने भारत को बड़ी मात्रा में गेहूँ उपलब्ध करा कर खाद्यान्न संकट में मदद की थी। लेकिन दूसरी तरफ इसी दौर में अमेरिका पाकिस्तान को भरपूर सैन्य और आर्थिक मदद भी दे रहा था। जिसके फलस्वरुप पाकिस्तान भारत पर आक्रमण की तैयारी में लग गया था यह भारत के लिए गहरी चिंता और सैनिक परेशानियों का का कारण बन गया था। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद 2014 से अब तक अमेरिका में राष्ट्रपति बराक ओबामा,जो बाईडेन और फिर दोबारा डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने तक भारत के संबंध अमेरिका से काफी मधुर रहे हैं। किंतु डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के कुछ समय पश्चात डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए अविश्वसनीय राष्ट्रपति बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव अचानक पाकिस्तान की तरफ अपने निजी हितों के कारण ज्यादा होने लगा है, जिसके कारण भारत पर भारत से अमेरिका में आयातित आवश्यक सामग्रियों पर 50% टैरिफ आरोपित कर दिया है, जिसका बड़ा कारण भारत द्वारा रुस से कच्चा तेल खरीद कर उसे परिष्कृत कर यूरोपीय राष्ट्रों को बेचना बताया गया है। जिससे भारत तथा अमेरिका के रिश्ते मैं काफी खटास आ गई है और भारत के लिए एक आर्थिक संकट उभर कर सामने आ गया है।इधर चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की महत्वपूर्ण बैठक में भारत,रूस और चीन एक ही मंच पर नए गठबंधन में खड़े दिखाई दिए इस नई साझेदारी से डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय देशों में बेचैनी काफी बढ़ गई है।

पूर्व में पिछले दो दशकों से भारत एवं अमेरिका वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा रहे थे । पिछले कुछ दशकों में यह संबंध केवल कूटनीति और सुरक्षा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति तक विस्तारित हुए हैं। यही कारण है कि इन रिश्तों के भविष्य को लेकर लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बहस और विश्लेषण होता रहा है। वर्तमान में भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार समझता एवं मानता है। अमेरिका ने भारत को "मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया है। दोनों देशों के बीच रक्षा सौदे, सैन्य अभ्यास और तकनीकी हस्तांतरण जैसे मुद्दों पर सहयोग लगातार गहराता और आगे बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भी दोनों तत्परता से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका और भारत शिक्षा और संस्कृति भी रिश्तों की अहम कड़ी बने हैं। भारतीय छात्रों की सबसे बड़ी संख्या अमेरिका में पढ़ाई करतें है, जो दोनों समाजों के बीच मानवीय और सांस्कृतिक पुल का काम करती है। परंतु ताजा खबरों के हिसाब से शिक्षा के लिए भारत से जाने वाले छात्रों पर बड़ी रकम आवर्जन के लिए तय कर दी है जिससे छात्रों को और भारत सरकार को बड़ी आर्थिक हानि होने का अंदेशा भी है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध लगातार प्रगति तथा उन्नती पर हैं। अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है। वहीं, अमेरिका की कंपनियाँ भारत को उसकी विशाल जनसंख्या को मद्देनजर रख एक उभरते हुए विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में देखती हैं। चीन पर भारत की निर्भरता कम करने की वैश्विक रणनीति में अमेरिका तथा यूरोपीय देश भारत को विशेष स्थान देने लगे हैं । हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता दबदबा भारत और अमेरिका को करीब ला रहा है। संयुक्त अभ्यास, हथियार निर्माण और साइबर सुरक्षा में सहयोग इस दिशा को और मज़बूत बना सकता है।एआई, क्वांटम कम्प्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग नए अवसरों के द्वार खोल रहा है। "डिजिटल इंडिया" और "सिलिकॉन वैली" का मेल इनोवेशन को नई दिशा दे सकता है।ग्रीन टेक्नोलॉजी और स्वच्छ ऊर्जा निवेश आने वाले वर्षों में दोनों देशों की साझेदारी को वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका में ला सकते हैं। नेट-ज़ीरो लक्ष्यों की ओर बढ़ते कदम इसमें महत्वपूर्ण रहेंगे।हालाँकि रिश्तों में चुनौतियों की कमी नहीं है। टैरिफ, बौद्धिक संपदा अधिकार और बाजार पहुँच को लेकर मतभेद बने हुए हैं। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि नई दिल्ली की सरकार रूस और अन्य देशों से अपने संबंध और मजबूत बनाए रखना चाहती है।मानवाधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों के सवाल पर अमेरिका की समय-समय पर की जाने वाली आलोचना भी रिश्तों को जटिल और भारतीय लोकतंत्र को परेशान करने वाला बनाती है।

बॉर्डर राज्यों में बढ़ती घुसपैठ : सरकार की जवाबदेही पर सवाल

आरती कुमारी

अनुत्तरित सवालों को नए ढंग से राजनीतिक मुद्दों में बदलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विलक्षण शैली रही है। इस परिप्रेक्ष्य में जम्मू-कश्मीर को विशेश दर्जा देने वाली धारा-370, 35-ए, तीन तलाक और राम मंदिर जैसे आजादी के बाद से अनुत्तरित चले आ रहे प्रश्नों के समाधान के बाद मोदी ने असम की धरती से घुसपैठ करने और कराने वालों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने दरांग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठियों की मदद से जनसांख्यिकीय घनत्व बदलने की साजिश चल रही है, जो राश्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। हमारी सरकार घुसपैठियों को देश के साधन-संसाधन पर कब्जा नहीं करने देगी।' घुसपैठियों को मदद देने वालों को सीधी चुनौती देते हुए मोदी ने कहा, 'घुसपैठियों को हटाने में हम अपना जीवन लगा देंगे। घुसपैठियों को पनाह देने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस जब सत्ता में थी, तब इन्हें संरक्षण देती रही, जिससे घुसपैठिए हमेशा भारत में बस जाएं और भारत का राजनीतिक भविश्य तय करें। कांग्रेस के लिए देशहित से बड़ा, अपने वोट-बैंक का हित रहा है। किंतु अब यह नहीं चलेगा।' बंगाल, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानीय बनाम विदेशी नागरिकों का मसला एक बड़ी समस्या बन गया है। जो यहां के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को लंबे समय से झकझोर रहा है। असम के लोगों की शिकायत है कि बांग्लादेश म्यांमार से बड़ी संख्या में घुसपैठ करके आए मुस्लिमों ने उनके न केवल आजीविका के संसाधनों को हथिया लिया है, बल्कि कृषि भूमि पर भी काबिज हो गए हैं। इस कारण राज्य का जनसंख्यात्मक घनत्व बिगड़ रहा है। लिहाजा यहां के मूल निवासी बोडो आदिवासी और घुसपैठियों के बीच जानलेवा हिंसक झड़पें भी होती रहती हैं। नतीजतन अवैध और स्थाई नागरिकों की पहचान के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता पत्रक बनाने की पहल हुई। इस निर्देश के मुताबिक 1971 से पहले असम में रह रहे लोगों को मूल नागरिक माना गया है। इसके बाद के लोगों को अवैध नागरिकों की सूची में दर्ज किया गया है। इस सूची के अनुसार 3.29 करोड़ नागरिकों में से 2.89 करोड़ लोगों के पास नागरिकता के वैध दस्तावेज हैं। शेष रह गए 40 लाख लोग फिलहाल अवैध नागरिकों की श्रेणी में रखे गए हैं। इस तरह के संवेदनशील मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दरअसल घुसपैठिए अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो यह उन राजनीतिक दलों को वजूद बचाए रखने की दृष्टि से खतरे की घंटी है, जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए घुसपैठ को बढ़ावा देकर अवैध नागरिकता को वैधता देने के उपाय करते रहे हैं। असम में अवैध घुसपैठ का मामला नया नहीं है। 1951 से 1971 के बीच राज्य में मतदाताओं की संख्या अचानक 51 प्रतिशत बढ़ गई। 1971 से 1991 के बीच यह संख्या बढ़कर 89 फीसदी हो गई। 1991 से 2011 के बीच मतदाताओं की तादात 53 प्रतिशत बढ़ी। 2001 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से यह भी देखने में आया कि असम में हिंदू आबादी तेजी से घटी है और मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। 2011 की जनगणना में मुस्लिमों की आबादी और तेजी से बढ़ी। 2001 में जहां यह बढ़ोत्तरी 30.9 प्रतिशत थी, वहीं 2011 में बढ़कर 34.2 प्रतिशत हो गई। जबकि देश के अन्य हिस्सों में मुस्लिमों की आबादी में बढ़ोत्तरी 13.4 प्रतिशत से 14.2 फीसदी तक ही हुई। असम में 35 प्रतिशत से अधिक मुस्लिमों वाली 2001 में विधानसभा सीटें 36 थी, जो 2011 में बढ़कर 39 हो गईं। गौरतलब है कि 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के बाद से 1991 तक हिंदुओं की जनसंख्या में 41.89 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि इसी दौरान मुस्लिमों की जनसंख्या में 77.42 फीसदी की बेलगाम वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह 1991 से 2001 के बीच असम में हिंदुओं की जनसंख्या 14.95 प्रतिशत बढ़ी, जबकि मुस्लिमों की 29.3 फीसदी बढ़ी। इस घुसपैठ के कारण असम में जनसंख्यात्मक घनत्व गड़बड़ा गया और सांप्रदायिक दंगों का सिलसिला षुरू हो गया। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा बोडो आदिवासियों ने भुगता। इसी के दुष्फल स्वरूप कई बोडो उग्रवादी संगठन अस्तित्व में आ गए। बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद बक्सा, चिरांग, धुबरी और कोकराझार जिलों में सबसे ज्यादा है। इन्हीं जिलों में बोडो आदिवासी हजारों साल से रहते चले आ रहे हैं। लिहाजा बोडो और मुस्लिमों के बीच रह-रहकर हिंसक वारदातें होती रही हैं। पिछले 18 साल में ही हिंसा की 15 बड़ी घटनाएं घटी हैं। जिनमें 600 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। घटनाएं घटने के बावजूद इस हिंसा का संतोशजनक पहलू यह रहा है कि हिंसा के मूल में हिंदू, ईसाई, बोडो आदिवासी और आजादी के पहले से रह रहे पुश्तैनी मुसलमान नहीं हैं। विवाद की जड़ में स्थानीय आदिवासी और घुसपैठी मुसलमान हैं। इन धुसपैठियों को भारतीय नागरिकता देने के काम में असम राज्य कांग्रेस की राश्ट्र विरोधी भूमिका रही है। घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए कांग्रेसियों ने इन्हें बड़ी संख्या में मतदाता पहचान पत्र एवं राशन कार्ड तक हासिल कराए। नागरिकता दिलाने की इसी पहल के चलते घुसपैठिए कांग्रेस को झोली भर-भर के वोट देते रहे हैं। कांग्रेस की तरूण गोगाई सरकार इसी बूते 15 साल सत्ता में रही। लेकिन लगातार घुसपैठ ने कांग्रेस की हालत पतली कर दी थी। फलस्वरूप भाजपा सत्ता में आ गई। इस अवैध घुसपैठ के दुश्प्रभाव पहले अलगाववाद के रूप में देखने में आ रहे थे, लेकिन बाद में राजनीति में प्रभावी हस्तक्षेप के रूप में बदल गए। इन दुश्प्रभावो को पूर्व में सत्तारूढ़ रहा कांग्रेस का केंद्रीय व प्रांतीय नेतृत्व जानबूझकर वोट बैंक बनाए रखने की दृश्टि से अनदेखा करता रहा है। लिहाजा धुबरी जिले से सटी बांग्लादेश की जो 134 किलोमीटर लंबी सीमा-रेखा है उस पर कोई चौकसी नहीं है। नतीजतन घुसपैठ आसानी से जारी है। असम को बांग्लादेश से अलग ब्रह्मपुत्र नदी करती है। इस नदी का पाट इतना चौड़ा और दलदली है कि इस पर बाड़ लगाना या दीवार बनाना नामुमकिन है। केवल नावों पर सशस्त्र पहरेदारी के जरिए घुसपैठ को रोका जाता है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा के घुसपैठियों के विरुद्ध कड़े रुख के चलते इनकी वापसी भी षुरू हुई है। दरअसल 1971 से ही एक सुनियोजित योजना के तहत पूर्वोत्तर भारत, बंगाल, बिहार और दूसरे प्रांतों में घुसपैठ का सिलसिला जारी है। म्यांमार से आए 60,000 घुसपैठिए रोहिंग्या मुस्लिम भी कश्मीर, बेंगलुरु और हैदराबाद में गलत तरीकों से भारतीय नागरिक बनते जा रहे हैं। जबकि कश्मीर से हिंदू, सिख और बौद्धों को धकिया कर पिछले 3 दशक से शरणार्थी बने रहने को विवश कर दिया है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार ने तत्कालीन असम सरकार के साथ मिलकर फैसला लिया था कि 1971 तक जो भी बांग्लादेशी असम में घुसे हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी और बाकी को भारत की जमीन से निर्वासित किया जाएगा। इस फैसले के तहत ही अब तक सात बार एनआरसी ने नागरिकों की वैध सूची जारी करने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम वोट-बैंक की राजनीति के चलते कांग्रेस, वामपंथी और तृणमूल एनआरसी का विरोध करते रहे हैं। बांग्लादेश के साथ भारत की कुल 4097 किलोमीटर लंबी सीमा-पट्टी है, जिस पर जरूरत के मुताबिक सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं। इस कारण गरीबी और भुखमरी के मारे बांग्लादेशी असम में घुसे चले आते हैं। क्योंकि यहां इन्हें कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अपने-अपने वोट बैंक बनाने के लालच में भारतीय नागरिकता का सुगम आधार उपलब्ध करा देते हैं। मतदाता पहचान पत्र जहां इन्हें भारतीय नागरिकता का सम्मान हासिल करा देता है, वहीं राशन कार्ड की उपलब्धता इन्हें बीपीएल के दायरे में होने के कारण मुफ्त अनाज की सुविधा दिला देती हैं। आसानी से बन जाने वाले बहुउद्देश्यीय पहचान वाले आधार कार्ड भी इन घुसपैठियों ने बड़ी मात्रा में हासिल कर लिए हैं। इन सुविधाओं की आसान उपलब्धता के चलते देश में घुसपैठियों की तादाद चार करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। दरअसल बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठीये शरणार्थी बने रहते, तब तक तो ठीक था, अलबत्ता भारतीय गुप्तचर संस्थाओं को जो जानकारियां मिल रही हैं, उनके मुताबिक, पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था इन्हें प्रोत्साहित कर भारत के विरुद्ध उकसा रही है। सऊदी अरब से धन की आमद इन्हें धार्मिक कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाकर आत्मघाती जिहादियों की नस्ल बनाने में लगी है। बांग्लादेश इन्हें हथियारों का जखीरा उपलब्ध करा रहा है। जाहिर है, ये जिहादी उपाय भारत के लिए किसी भी दृष्टि से शुभ नहीं हैं। लिहाजा समय आ गया है कि जो आतंकवादी देश की एकता अखंडता और संप्रभुता को सांगठनिक चुनौती के रूप में पेश आ रहे हैं, उन्हें देश से बेदखल किया जाए।

अमृत भारत एक्सप्रेसः जन-जन की ट्रेन, कनेक्टिविटी के नए युग की शुरुआत

ओम प्रकाश

भारतीय रेल को देश की जीवनरेखा कहा जाता है। यह हर दिन 2.3 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों को सफ़र कराती है। यह केवल एक परिवहन साधन ही नहीं बल्कि देश की सामाजिक और आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने वाली शक्ति है। अमृत भारत एक्सप्रेस इस बड़े तंत्र में एक गेम-चेंजर बनकर उभरी है। कम-लागत, आधुनिक और समावेशी पहल जो भारतीयों की यात्रा करने की शैली को बदल रही है। यद्यपि यह पूरे देश की आशाओं को पूरा करती है, इसके परिवर्तनकारी प्रभाव विशेष रूप से बिहार में उल्लेखनीय हैं। एक ऐसा प्रदेश जहाँ निवासियों का भाग्य हमेशा से रेल कनेक्शन पर बहुत अधिक निर्भर रहा है। यह ट्रेन वाकई में जन-जन की रेल है। जहाँ प्रीमियम ट्रेनों से केवल चुनिंदा लोगों को सुविधा हासिल होती हैं, वहीं अमृत भारत आम यात्रियों के लिए है। ये नॉन-एसी सुपरफास्ट ट्रेनें हैं जिनका किराया पारंपरिक मेल-एक्सप्रेस के करीब है, लेकिन सुविधाएँ आधुनिक हैं। उदाहरण के लिए, पटना-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस की स्लीपर टिकट लगभग 560 रुपये में मिलती है। सफ़र झटकों से मुक्त है, सीटें आरामदायक हैं, बायो-वैक्यूम टॉयलेट, एलईडी लाइटिंग और मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट जैसी सुविधाएँ मौजूद हैं। सुरक्षा के लिए फायर डिटेक्शन सिस्टम, सेमी-ऑटोमैटिक कपलर और ऑनबोर्ड मॉनिटरिंग जैसी तकनीकें भी लगी हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस का नेटवर्क देशभर में तेज़ी से बढ़ रहा है। दर्जन भर से अधिक मार्गों पर ट्रेनें चल रही हैं और अगले कुछ वर्षों में 200 नई अमृत भारत ट्रेनों की योजना है। सभी ट्रेनें मेक इन इंडिया के तहत देश में ही बन रही हैं। एक-एक रेक की लागत लगभग 65 करोड़ रुपये है, जिससे निर्माण इकाइयों, आपूर्ति श्रृंखला और रखरखाव केंद्रों में रोज़गार भी बढ़ रहा है। यह न सिर्फ़ यात्री सेवा में, बल्कि औद्योगिक दृष्टि से भी आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में इन ट्रेनों का असर सबसे ज़्यादा दिखता है। पहले शुरू की गई 14 सेवाओं में से 10 सीधे तौर पर बिहार से जुड़ी हैं। दरभंगा, पटना, सहरसा, मोतिहारी, सीतामढ़ी और गया से अब दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अमृतसर और बेंगलुरु तक सीधी कनेक्टिविटी है। 3,129 किलोमीटर लंबी जोगबनी–इरोड अमृत भारत एक्सप्रेस बिहार के उत्तर-पूर्वी छोर को दक्षिण भारत (तमिलनाडु) से जोड़ती है। छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और परिवारों के लिए इसका मतलब है कम यात्रा समय, आसान सफ़र और महानगरों तक सीधी पहुँच। इसका सीधा आर्थिक असर भी हो रहा है। किसान और छोटे व्यापारी अब इन ट्रेनों के पार्सल वैन के ज़रिए जल्दी और सस्ते में अपना सामान बड़े बाज़ारों तक पहुँचा पा रहे हैं। स्टेशनों के आसपास रिक्शा चालकों, चाय विक्रेताओं, होटल व्यवसायियों और हस्तशिल्पियों को भी रोज़गार के नए अवसर मिल रहे हैं। इसके साथ ही सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना भी इन लाभों को बढ़ा रही है। जिसके अंतर्गत 1300 से अधिक स्टेशनों (केवल बिहार में 98) का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। जहाँ स्थानीय कलाकार जैसे मधुबनी पेंटिंग बनाने वाले या मिठाई बेचने वाले सीधे यात्रियों तक अपनी चीज़ें पहुँचा सकते हैं। पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिला है। बिहार के बोधगया, नालंदा और पटना साहिब जैसे धरोहर स्थल पहले पहुँच की कमी से जूझते थे। अब गया, सीतामढ़ी और पटना तक सस्ती और सीधी ट्रेनों की वजह से तीर्थयात्रियों और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आना आसान हो गया है। दूसरी ओर, बिहारवासियों के लिए भी अमृतसर का स्वर्ण मंदिर या हरिद्वार जैसे पर्यटन स्थलों तक जाना सुगम हो गया है। इससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान और अंतरराज्यीय पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। अंततः अमृत भारत केवल पटरियों पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी नहीं है, बल्कि समावेशी विकास का प्रतीक भी है। यह लाखों लोगों की यात्रा को आरामदायक और किफ़ायती बनाते हुए उद्योग, पर्यटन और रोज़गार को आगे बढ़ा रही है। यह भविष्य के लिए तैयार भारतीय रेल की ओर एक कदम है। यह एक नया अध्याय है जहाँ कनेक्टिविटी आकांक्षाओं, अवसरों और गर्व को आगे बढ़ाने वाली शक्ति बनेगी, विशेषकर बिहार के लिए।

आईआरटीएस
(सेवानिवृत्त)
पूर्व पीसीसीएम, उत्तरी रेलवे
एवं पश्चिम मध्य रेलवे

Join This Channel:- https://t.me/AllNewsPaperPaid1

स्वर्णिम साबित हुआ 14 सितम्बर

भारतीय खेलों के लिए बीता रविवार यानी 14 सितम्बर का दिन स्वर्णिम साबित हुआ। दिन की शुरुआत महिला बॉक्सर जेस्मीन लंबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा के स्वर्णिम पंच से हुई। इसके बाद देश में खुशी का माहौल बनाने वाली खबर दुबई से आई। भारत ने वहां चल रहे क्रिकेट एशिया कप में अपनी परंपरागत प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को फतह ही नहीं किया, बल्कि यों कहें कि एकदम से ध्वस्त कर दिया। वैसे तो पहलगाम घटना की वजह से देश में एक वर्ग पाकिस्तान से खेलने का विरोध कर रहा था। पर सरकार ने आईसीसी टूर्नामेंटों में खेलने की नीति की वजह से इसमें खेलना स्वीकार किया। पर भारतीय टीम ने एकतरफा अंदाज में जीत पाकर देश के क्रिकेटप्रेमियों को खुश कर दिया। वहीं जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करके अपना विरोध भी जता दिया। भारत और पाकिस्तान के इस मुकाबले के लिए स्टेडियम के खचाखच भरे होने से यह बात तो समझ में आती है कि इस मुकाबले को लेकर लोगों में अभी भी दीवानगी बनी हुई है। इस मुकाबले से एक बात यह भी साफ हो गई कि भारतीय टीम में भले ही रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज शामिल नहीं हैं। पर वे पाकिस्तान टीम से बहुत आगे निकल चुके हैं। यह सही है कि देश में क्रिकेट की दीवानगी के आगे सभी खेल बौने नजर आते हैं। पर बॉक्सिंग में आए दोहरे गोल्ड के भी बहुत मायने हैं। भारतीय बॉक्सिंग में पिछले काफी समय से सफलताएं आना कम हो गई थीं, लेकिन जेस्मीन और मीनाक्षी ने गोल्डन पंच लगाकर यह अहसास करा दिया है कि आने वाला समय उनका है। इस तरह के प्रदर्शनों से यह संकेत भी मिलता है कि भारत का ओलंपिक खेलों की बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल से दूरी जल्द खत्म हो सकती है।

बिहार चुनाव के चुनावी रण में निकलेंगे उपलब्धियों के तरकश से विकास के बाण

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना

बिहार की राजनीति एक बार फिर उस मुहाने पर खड़ी है, जहां से भविष्य की दिशा तय होगी। 2025 का विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार के दो दशकों के 'सुशासन' के दावों और जनता की आकांक्षाओं के बीच का संवाद होगा। यह एक ऐसा चुनाव होगा, जहां अतीत के कार्यों का लेखा-जोखा भविष्य के वादों पर भारी पड़ेगा। इस चुनावी महासमर में नीतीश कुमार और उनके सहयोगी दल, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, जनता के सामने उन उपलब्धियों को रखने की तैयारी में हैं, जिन्होंने पिछले डेढ़ दशक से अधिक समय में बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। यह कहानी है उस बिहार की, जो कभी सड़कों में गड्ढों या गड्ढों में सड़कों के लिए जाना जाता था। यह कहानी है उस प्रदेश की, जहां शाम ढलते ही बेटियां घरों में कैद हो जाती थी। यह कहानी है उस राज्य की, जहां विकास की धारा कुछ गिने-चुने शहरों तक सिमटी हुई थी। नीतीश कुमार की सरकार इन कहानियों को बदलने का दावा करती है। उनका चुनावी अभियान सिर्फ आंकड़ों और योजनाओं का पुलिंदा नहीं होगा, बल्कि यह एक भावनात्मक अपील होगा 'वापसी का भरोसा' दिलाने की, 'फिर से विकास की रेलगाड़ी' को गति देने की। यह इस बात पर केंद्रित होगा कि कैसे एक बीमारू राज्य की छवि से निकलकर बिहार आज देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर अग्रसर है। किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त उसकी उन्नत कनेक्टिविटी होती है। सड़कें महज रास्ते नहीं, बल्कि प्रगति की वे धमनियां होती है, जो गांवों को शहरों से, खेतों को बाजारों से और लोगों को अवसरों से जोड़ती हैं। नीतीश कुमार ने जब 2005 में बिहार की बागडोर संभाली थी, तो प्रदेश की सड़कें जर्जर अवस्था में थी। राजधानी पटना से राज्य के किसी भी कोने में पहुंचने में 10 से 12 घंटे लगना आम बात थी। आज सरकार का दावा है कि राज्य के किसी भी कोने से 5-6 घंटे में पटना पहुंचा जा सकता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है, बल्कि यह एक सोची-समझी रणनीति और अथक प्रयासों का परिणाम है। नीतीश सरकार ने सत्ता में आते ही सड़क निर्माण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा। पिछले करीब 20 वर्षों में बिहार के सड़क नेटवर्क में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2005 से 2025 के बीच सड़कों की लंबाई दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। सरकार ने न केवल नई सड़कें बनाईं है, बल्कि मौजूदा सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण भी किया है। राजकीय उच्च पथों की लंबाई 2,382 किलोमीटर से बढ़कर 3,638 किलोमीटर हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में भी केंद्र सरकार के सहयोग से तेजी आई है। 'मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना' और 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के तहत दूर-दराज के गांवों और टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। मार्च 2025 तक 1,360 किलोमीटर और 2026 तक 8,283 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है। पिछले 10 वर्षों में ही लगभग 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान की है। कनेक्टिविटी के लिए पुलों का महत्व भी सर्वोपरि है। बिहार सरकार ने गंगा, कोसी, गंडक जैसी बड़ी नदियों पर कई महासेतुओं का निर्माण कर उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी को पाट दिया है। छोटे-बड़े हजारों पुल-पुलियों ने आवागमन को सुगम बनाया है। बिहार अब एक्सप्रेसवे के युग में प्रवेश कर रहा है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति को नए पंख लगाएगा। कई महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं या प्रस्तावित हैं, जो बिहार को पूर्वी भारत का एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब बनाने की क्षमता रखता है। रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे (408 किमी) उत्तर बिहार को सीधे हल्दिया बंदरगाह से जोड़ेगा, जिससे आयात-निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे (417 किमी) बिहार के उत्तरी जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे (250 किमी) राजधानी को सीमांचल के इलाके से जोड़ेगा। बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे (300 किमी) बिहार के दो प्रमुख शहरों को जोड़ेगा और गंगा के किनारे एक नया विकास गलियारा बनाएगा। वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे (161 किमी) का एक बड़ा हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा, जो राज्य को देश के दो प्रमुख आर्थिक केंद्रों से सीधे जोड़ेगा। यह सिर्फ सड़कों का जाल नहीं है, बल्कि यह विकास का वह ताना-बाना है जो किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाएगा, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और बिहार के समग्र विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार इन सड़कों को 'विकास के पथ' के रूप में पेश करेंगे, जिस पर चलकर बिहार समृद्धि की मंजिल तक पहुंचेगा। नीतीश कुमार की राजनीतिक विचारधारा का एक केंद्रीय तत्व हमेशा से महिला सशक्तीकरण और सामाजिक समावेशन रहा है। उन्होंने बार-बार यह कहा है कि जब तक महिलाएं और समाज के वंचित वर्ग का विकास नहीं होगा, तब तक राज्य का समग्र विकास संभव नहीं है। उनके कार्यकाल में उठाए गए कदमों ने न केवल महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत किया है, बल्कि उनमें एक नया आत्मविश्वास भी पैदा किया है। नीतीश कुमार के सबसे क्रांतिकारी फैसलों में से एक पंचायती राज संस्थाओं (2006) और नगर निकाय चुनावों (2007) में महिलाओं को 50% आरक्षण देना था। इस एक कदम ने बिहार की हजारों महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व की मुख्यधारा में ला खड़ा किया है। इसके बाद 2016 में सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया, जिसने उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मार्ग प्रशस्त किया। विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई 'जीविका' योजना आज महिला सशक्तीकरण का पर्याय बन चुकी है। 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1.40 करोड़ से अधिक 'जीविका दीदियां' जुड़ी हुई हैं। इन समूहों ने न केवल महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा है, बल्कि सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा और शराबबंदी के खिलाफ एक मजबूत आवाज भी बुलंद की है। सरकार ने 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' का ऐलान किया है। इस योजना के तहत, हर परिवार की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। छह महीने के प्रदर्शन के आधार पर बाद में 2 लाख तक की अतिरिक्त मदद का भी प्रावधान है। यह योजना सीधे तौर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक बड़ा माध्यम बनेगी। सरकार ने आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 और सहायिकाओं का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 4,500 करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य की 2.10 लाख से अधिक आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को सीधा लाभ मिलेगा, जो जमीनी स्तर पर महिला एवं बाल पोषण की रीढ़ हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने 'न्याय के साथ विकास' के अपने नारे को चरितार्थ करने का प्रयास किया है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अति पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, छात्रावासों का निर्माण और उद्यमिता के लिए विशेष योजनाओं ने इन वर्गों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने में मदद की है। 2025 के चुनाव में, नीतीश कुमार इन उपलब्धियों को केवल योजनाओं के रूप में नहीं, बल्कि 'बदलते बिहार में महिलाओं और वंचितों के बढ़ते स्वाभिमान' की कहानी के रूप में पेश करेंगे। यह एक भावनात्मक अपील होगी कि जिस सरकार ने आधी आबादी को सम्मान और अवसर दिया, उसे एक बार फिर सेवा का मौका मिलना चाहिए। विकास का पैमाना केवल राजमार्गों और बड़ी योजनाओं से ही नहीं, बल्कि शहरों की स्वच्छता और गांवों की आत्मनिर्भरता से भी मापा जाता है। नीतीश सरकार ने शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करने का दावा किया है। उनका तर्क है कि जब तक गांव और शहर कंधे से कंधा मिलाकर विकास नहीं करेंगे, तब तक एक 'विकसित बिहार' का सपना साकार नहीं हो सकता। स्मार्ट सिटी मिशन और अन्य शहरी विकास योजनाओं के तहत बिहार के शहरों की तस्वीर बदल रही है। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, और नए संपर्क मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में पटना में 355 करोड़ रुपये से अधिक की तीन सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिससे ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। शहरों में कूड़ा प्रबंधन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पार्कों के सौंदर्यीकरण पर जोर दिया जा रहा है। 'नमामि गंगे' परियोजना के तहत गंगा किनारे के शहरों में घाटों का जीर्णोद्धार और रिवरफ्रंट का विकास किया गया है। सरकार ने हर जिला की जरूरतों के अनुसार, विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उदाहरण के लिए, हाल ही में सीवान जिले में लगभग 558 करोड़ रुपये की नौ विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इनमें ग्रिड सबस्टेशन, रेल ओवरब्रिज और सड़कों का चौड़ीकरण शामिल है। इसी तरह गया में पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार का मानना है कि बिहार की आत्मा गांवों में बसती है। इसलिए ग्रामीण विकास हमेशा से उनकी प्राथमिकता में रहा है। 'सात निश्चय' कार्यक्रम के तहत 'हर घर नल का जल' योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की है। यह न केवल एक सुविधा है, बल्कि इसने महिलाओं को दूर-दराज से पानी लाने के श्रम से भी मुक्ति दिलाई है और जल-जनित बीमारियों में कमी लाई है। इस योजना के तहत गांवों की गलियों को पक्का किया गया है और नालियों का निर्माण किया गया है, जिससे गांवों में स्वच्छता का स्तर बेहतर हुआ है और बरसात के दिनों में होने वाली कीचड़ की समस्या से निजात मिली है। केंद्र सरकार के सहयोग से 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत बिहार में 57 लाख से अधिक पक्के घर बनाए गए हैं, जिससे लाखों गरीब परिवारों का अपने घर का सपना साकार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में 45,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं, जो ग्रामीणों को डिजिटल सेवाएं और सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच प्रदान कर रहे हैं। 2025 के चुनाव में, जदयू-भाजपा गठबंधन शहरी और ग्रामीण विकास की इन दोहरी उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगा। यह संदेश देने का प्रयास होगा कि उनकी सरकार 'सर्वसमावेशी विकास' में विश्वास रखती है, जहां शहर की चमक भी हो और गांव की मजबूती भी। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधना एक बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 'जल-जीवन-हरियाली' जैसी दूरदर्शी योजना की शुरुआत की। यह अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से बिहार के भविष्य को सुरक्षित करने का एक संकल्प है।

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 22-09-2025 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMPG12 User: cci Time: 09-21-2025 22:06 Color:

नवभारत टाइम्स • विचार

नवभारत टाइम्स । मुंबई । सोमवार, 22 सितंबर 2025

> किसी शॉर्टकर्ट से जीत नहीं मिलती। विदेश नीति को लेकर काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए दिन-ब-दिन और साल-दर-साल प्रतिबद्धता दिखानी होगी
> *-रिचर्ड लुगर, अमेरिकी राजनेता*

विदेश नीति में चुनौतियां

अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस में अचानक 50 गुना इजाफा करने का जो फैसला किया है, उसकी मार सबसे ज्यादा भारतीयों पर ही पड़ने वाली है। लेकिन यह अपने आप में ऐसी कोई इकलौती घटना नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुईं जो भारतीय विदेश नीति के लिए चुनौती की तरह आई हैं।

टैरिफ से वीजा तक । भारत से भेजे जाने वाले सामानों पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने के जो भी तर्क दिए गए हों, सचाई यही है कि यह फैसला ट्रेड रिलेशन के ग्रामर में फिट नहीं बैठता। यह बात भी सही है कि न तो भारत रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश है और न ही उसके साथ व्यापार करने वाला इकलौता देश। बहरहाल, टैरिफ का मसला सुलझाने के लिए प्रयास भी दोनों तरफ से जारी हैं। लेकिन, जब इन प्रयासों के मद्देनजर ट्रेड डील पर कोई नतीजा निकलने की उम्मीद बढ़ रही थी, तब अचानक वीजा-फीस बढ़ाने का यह फैसला आ गया जिससे आम लोगों के स्तर पर द्विपक्षीय रिश्तों का व्याकरण गड़बड़ाता दिखने लगा।

बुनियादी मानकों पर फोकस

रूस से ईरान तक । रूस पर दबाव बढ़ाने के बहाने भारत पर टैरिफ लादने का मामला अभी सुलझा भी नहीं कि ईरान पर दबाव बढ़ाने की जरूरत बताते हुए चाबहार पोर्ट तक हमारी पहुंच रोकने की कोशिश की गई। इस पोर्ट के इस्तेमाल को लेकर जो छूट हमें दी गई थी, उसे ट्रंप प्रशासन ने समाप्त कर दिया। इस पोर्ट को विकसित करने में भारत अपना काफी संसाधन लगा चुका है।

पाक-यूएई समझौता । पिछले दिनों सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ सामरिक समझौता भी कम गंभीर मसला नहीं है। इस समझौते के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान ने तय किया है कि किसी भी एक देश पर हुए हमले को दोनों देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में देखें तो भारत इस क्षेत्र में बन रहे इन नए समीकरणों की किसी भी रूप में अनदेखी नहीं कर सकता।

बुनियादी मानक । इन तमाम घटनाओं को समग्रता में देखें तो ऐसा लगता है कि भारत को अपनी विदेश नीति की बारीकियों पर दोबारा गौर करने की जरूरत है। विदेश नीति में लचीलापन (फ्लेक्सिबिलिटी) जितना आवश्यक है, उससे कम अहमियत निरंतरता (कंटिन्यूटी) की नहीं है। बदलते अंतरराष्ट्रीय समीकरणों को संबोधित करते हुए भी यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि विदेश नीति के बुनियादी मानकों पर फोकस बना रहे।

नश्तर

मूर्खता का मश्क़

सौरभ श्रीवास्तव

मूर्ख होना आसान काम नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुबह सोकर उठें, घर की छत पर खड़े होकर सिकंदरनुमा पोज बनाएं और कह दें, 'आज से मैं मूर्ख हूं, समाज मुझसे समझदारी की उम्मीद न करे।' क्या लगता है, ऐसी घोषणा के बाद माता-पिता, अड़ोसी-पड़ोसी आपसे यह कहना बंद कर देंगे कि तुम तो समझदार हो, तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए था? आप के व्यक्तित्व पर जो समझदारी का तमगा लगा है, वह इतनी आसानी से नहीं हटने वाला।

मूर्ख बनने की प्रक्रिया बड़ी ही मुश्किल है। लंबी साधना चाहिए। बेवकूफी भरी एक-दो बातों से काम नहीं चलेगा। आपको लंबे समय तक मूर्खताभरी बातें कहनी और लिखनी होंगी। जैसा कि मैं कर रहा हूं- मूर्खता पर लिखकर। हालांकि अभी फैसला नहीं हो सका है कि ऐसा करना समझदारी है या मूर्खता। फिर भी कोशिश तो जारी ही रखनी चाहिए। जहां भी मंच मिले, मूर्खता से भरपूर बातें कह या लिख मारिए। अपने लिखे हुए या कहे हुए का खूब प्रचार कीजिए।

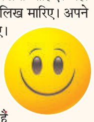

प्रचार के लिए अपने से ज्यादा मूर्खों के बीच जाइए। उनसे सोशल मीडिया पर जुड़िए। आप उन्हें सूर (सूरदास) कहिए तो वे आपको तुलसी कह ही देंगे। भले ही आप अपने से ज्यादा मूर्ख को 'सूरदास' कह रहे हैं जो समाज में दृष्टिहीन होने के प्रतीक के तौर पर प्रचलित है, पर इस उपमा को वे तारीफ की तरह लेंगे। मैंने पहले ही कहा था, मूर्ख होना आसान नहीं है, देखिए बीच में समझदारी भरी पंक्ति आ ही गई, क्षमा करें। आप खुद को तुलसी कहे जाने पर फोकस कीजिए। यूं आपका और आपकी मूर्खता का एक इकोसिस्टम बन जाएगा। अब सवाल है कि इस दायरे में आपको कोई मूर्ख तो कहेगा नहीं। हताश मत होइए। इस दायरे के बाहर भी लोग हैं, जो गंभीरता से पढ़-लिख रहे हैं। वे आपको मूर्ख मानेंगे, पर ऐसे लोगों की फिक्र मत कीजिए। ज्यादा पढ़ने-लिखने वाले हर बात पर शक करते हैं। आज नहीं तो कल वे आपके मूर्ख होने पर भी शक करने लगेंगे, ऐसी स्थिति में वे खुद के समझदार होने पर भी शक करेंगे। आपको जुटे रहना है। मेरी शुभकामनाएं।

एकदा

संकलन : रेनू सैनी

पुरातत्व की जादूगर

वर्ष 1925 में बांग्लादेश के खुलना शहर में देबाला मित्रा का जन्म हुआ। बचपन से ही बौद्ध गुफाएं और मठ उनके आकर्षण का केंद्र रहे। उन्होंने कलकत्ता और खुलना से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की व वर्ष 1946 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति में एमए की डिग्री हासिल की। बाद में पेरिस में कंबोडिया की कला का अध्ययन भी किया। वर्ष 1975 में उन्होंने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित तेलकुपी मंदिर पर अपना पीएचडी शोधपत्र प्रस्तुत कर कलकत्ता विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्राप्त की। उनकी रुचि पुरातत्व में इतनी अधिक जागी कि उन्होंने उन्होंने हिमालयी क्षेत्रों और लद्दाख में बौद्ध गुफाओं व मठों का सर्वेक्षण किया। ऊंचाई पर ऑक्सिजन कम होने और मौसम खराब होने से कई बार विपरीत परिस्थितियां खड़ी हो गईं, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने अपने हाथों से गुफाओं की नक्काशी का मापन और चित्रांकन किया। उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक बनने का गौरव प्राप्त हुआ। डेबला मित्रा ने पुरातत्व से संबंधित अनेक रोचक और गहन खोज की। उन्हें पुरातत्व की जादूगर कहा जाता है।

H-1B वीजा की भारी-भरकम फ़ीस अमेरिकी इकॉनमी पर भारी पड़ेगी

ट्रंप लिख रहे बर्बादी की दास्तान

मृत्युंजय राय

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर सालाना एक लाख डॉलर यानी 88 लाख रुपये की भारी-भरकम फीस लगाई है। ट्रंप ने यह फीस इसलिए लगाई है ताकि अमेरिकी कंपनियां H-1B वीजा पर स्किल्ड विदेशी वर्कर्स को काम पर रखने की बजाय अमेरिकी लोगों को काम पर रखें। इसकी मार भारतीयों पर पड़ेगी, जिन्हें H-1B का सबसे अधिक फायदा मिलता आ रहा है। यह भी तय है कि ट्रंप के इस कदम को वहां की अदालत में चुनौती दी जाएगी।

ट्रंप ने मारी पलटी । ट्रंप के समर्थक भी H-1B प्रोग्राम को लेकर बंटे रहे हैं। टेस्ला के संस्थापक इलॉन मस्क इनमें से एक हैं। इस वीजा पर जब पहले विवाद हुआ था, तब मस्क ने इसका बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि वह अमेरिकी नागरिक बनने से पहले H-1B वीजा होल्डर थे। खुद ट्रंप भी H-1B वीजा को लेकर रुख बदलते रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि वह स्किल्ड लोगों के अमेरिका आने के पक्षधर हैं, बाद में इस बात से पलट गए।

चीन का फायदा । H-1B वीजा से खासतौर पर अमेरिकी टेक्नॉलजी कंपनियों को दूसरे देशों से प्रतिभाशाली लोगों को अपने यहां काम पर रखने में मदद मिलती है। आज चीन के साथ अमेरिका प्रतिस्पर्धा में उलझा है। दोनों के बीच टेक्नॉलजी वॉर चल रही है। ऐसे में H-1B प्रोग्राम पर अंकुश लगाना अमेरिका को भारी पड़ सकता है।

AI Image

इसमें US का घाटा
- टेक इंडस्ट्री की हायरिंग अप्रोच बदलेगी
- चीन से AI वॉर में पिछड़ सकता है US
- L-1 वीजा का कंपनियां बढ़ाएंगी इस्तेमाल

उलझन में कंपनियां । ट्रंप के H-1B वीजा पर इस फैसले से अमेरिकी कंपनियों में भी हड़कंप है। उन्हें लगता है कि इससे अहम पदों पर नियुक्तियां भी प्रभावित होंगी। US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि वह ट्रंप सरकार के साथ इस कदम के असर को समझने और आगे की राह के बारे में बात कर रहा है।

AI रिसर्च पर असर । अमेरिकी कंपनियों को अब H-1B वीजा प्रोग्राम को लेकर अपने अप्रोच में बदलाव करना होगा। AI जैसे क्षेत्र में उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर पड़ सकती है। असर सिर्फ टेक्नॉलजी कंपनियों पर ही नहीं होगा। इससे मेडिकल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ यूनिवर्सिटीज भी प्रभावित हो सकती हैं, जिन्हें H-1B वीजा जारी किए जाते हैं।

लंबी अवधि में नुकसान । वीजा नीतियों में इस बदलाव का अमेरिकी इकॉनमी और कॉरपोरेट अमेरिका को लंबी अवधि में भी नुकसान होगा। खासतौर पर स्टार्टअप्स को। स्टार्टअप्स को डर है कि बड़ी कंपनियां जहां इतनी फीस चुकाने में सक्षम हैं, वहीं उभरती हुई कंपनियों के लिए ऐसा करना मुश्किल होगा।

सैलरी से ज्यादा फीस । H-1B प्रोग्राम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा भारतीय करते हैं, इसलिए उनकी मुसीबत भी बड़ी है। इनमें से कइयों की तो सैलरी भी उतनी नहीं है, जितनी इस वीजा की फीस तय की गई है। ऐसे में जो कंपनियां H-1B वीजा को स्पॉन्सर करती हैं, उनकी दिलचस्पी इस रास्ते से हायरिंग में घट सकती है। संभव है कि वे इसका इस्तेमाल हाई स्किल्ड पेशेवरों के लिए ही करें।

L-1 का रास्ता । माना यह भी जा रहा है कि कंपनियां अब विदेशी वर्कर्स के लिए L-1 वीजा का ज्यादा इस्तेमाल करेंगी। जहां अमेरिका ने साल में 85000 H-1B वीजा की लिमिट तय की हुई है, वहीं L-1 वीजा को लेकर कोई ऐसी सीमा नहीं है। हालांकि, इस वीजा का इस्तेमाल कंपनी के अंदर ट्रांसफर के लिए किया जाता है, न कि नई हायरिंग के लिए। फिर इस पर भी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की नजर है। दरअसल, H-1B वीजा की तरह ग्लोबल IT और आउटसोर्सिंग कंपनियां L-1 वीजा का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं। इसलिए इसे भी ट्रंप सरकार निशाना बना सकती है।

जल्द सुलझे विवाद । वहीं, पिछले कुछ वर्षों से भारत में मल्टीनैशनल कंपनियां ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर (GCC) में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं। अमेरिका के H-1B वीजा पर सख्ती से ये कंपनियां यहां और भी अधिक हायरिंग कर सकती हैं। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका जा रहे हैं। आशा है कि व्यापार समझौते पर बातचीत के साथ वह H-1B वीजा का मुद्दा भी अमेरिकी प्रतिनिधियों के सामने उठाएंगे। दोनों देशों के बीच ऐसे विवाद जितनी जल्द खत्म हों, यह दोनों के लिए उतना ही बेहतर होगा।

ख़ुशियों के मेसेज पढ़ने को आवाज़ ज़रूरी नहीं

AI Image

जीवन आनंद
शैलेंद्र पांडेय

एशिया कप चल रहा है। इस दौरान वायरल एक विडियो क्लिप ने हंगामा मचा रखा है। इसमें बस चेहरे हैं, आवाज नहीं। इसका मूक होना भी एक वजह बन गई है विवाद की। लेकिन, मौन हमेशा विवादित नहीं होता और मूक फिल्में तो बिल्कुल नहीं। टेक्नॉलजी ने आज जब हर दृश्य में कृत्रिम रंग और आवाज भर दी है, तब मूक फिल्मों को देखना टाइम मशीन की यात्रा है। इनका सबसे बड़ा आनंद यही है कि इनमें शब्दों की जगह भावनाएं बोलती हैं।

मूक फिल्में किसी भाषा की मोहताज नहीं - न कहने के लिए और न समझने के लिए। जीवन में भी मौन का असर ऐसा ही है। कई बार शब्दों की जरूरत नहीं होती, कुछ न कहना ही सबकुछ कह देता है। बहुत ताकत है मौन की भाषा में - किसी का स्नेहिल स्पर्श, किसी की आंखों का इशारा - संवाद से ज्यादा गहरा असर होता है इनका। व्यस्त और शोरगुल भरे जीवन में मूक फिल्में हमें यह याद दिलाती हैं कि कभी-कभी चुप रहना भी जरूरी है। मौन के क्षण हमें भीतर झांकने का मौका देते हैं। जैसे मूक फिल्मों में हम खुद कहानी गढ़ते हैं, वैसे ही जीवन में भी कई बार हमें अपनी कल्पना और संवेदना से ही अर्थ निकालना पड़ता है।

फ्रांस के लुई ले प्रिंस ने 1888 में बगीचे में टहलते लोगों को चंद सेकंड फिल्माया - Roundhay Garden Scene। लुमिएर ब्रदर्स ने 1895 में बनाई - Workers Leaving the Factory। दुनिया ने पहली बार अपने आसपास घटने [illegible] चलते देखा। यह जादू था, और यह भी जादू था कि रोजमर्रा की वे चीजें कितनी चमत्कारिक लग रही थीं। यह असर था सादगी का। शोर-शराबे और चमक-धमक में कई बार असली मकसद खो जाता है। अगर लुई प्रिंस के विडियो में मौजूद लोगों की आवाज सुनाई पड़ती, तो किसका ध्यान जाता पेड़ों की छांव में टहलने के आनंद पर - या, लुमिएर ब्रदर्स के वर्कर्स का शोर सुनाई पड़ने लगता, तो काम से घर लौटने के उत्साह से खिले चेहरों पर कौन गौर करता। और तब शायद चार्ली चैपलिन की दर्द भरी मुस्कान भी हमारे ख्यालों में दर्ज न हो पाती। वेदों में भी बताया गया है कि मौन मदद करता है एकाग्रता बनाने और ऊर्जा बचाने में। मौन बचाता है नकारात्मक बातों से।

अमेरिकी निर्देशक और लेखक Walter Scott Murch [illegible] कि वह अपनी फिल्मों के सीन को किसी मूक फिल्म की तरह ही बनाते हैं - 'कोई डायलॉग वाला सीन होता है, तब भी मैं उसे साइलेंट मूवी की तरह ट्रीट करता हूं। कलाकारों के होंठ पढ़कर समझता हूं कि वे क्या कह रहे हैं।' स्कॉट भावनाओं को पकड़ना चाहते हैं और मूक फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि इसके लिए आवाज की जरूरत नहीं। बातें तो तब भी कह दी जाती थीं, जब भाषा नहीं थी।

Join This Channel:- https://t.me/AllNewsPaperPaid1

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

हमारे भीतर है बुराइयों पर विजय पाने की शक्ति

ब्रह्माकुमारी शिवानी

आज से नवरात्रि शुरू हो रही है। यह पर्व हमारे जीवन और वातावरण में उमंग व उत्साह की नई ऊर्जा भरने वाला, दिव्यता और पवित्रता का एक अनोखा उत्सव है। विशेषकर यह परिवार के साथ मिलकर खुशियां मनाने का पर्व है। हर प्रांत भले ही इसे अलग-अलग तरीकों से मनाता हो, लेकिन भावना सबकी एक ही होती है - देवी उपासना के माध्यम से अपने भीतर की दैवी शक्तियों और गुणों को जागृत करना, ताकि अंदर छिपी बुराइयों और कमजोरियों से मुक्ति मिल सके।

जब संसार में नकारात्मकता की अधिकता हो जाती है, तो उसका अंत करने के लिए कोई न कोई दैवी शक्ति प्रकट होती है। इन शक्तियों की आसुरी तत्वों पर विजय को मूर्तियों और चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। नवरात्रि के इन दिनों में इसका आत्मचिंतन जरूरी है। असल में, हमारे मन के विकार ही वास्तविक असुर हैं, जो अशुद्धता और नकारात्मकता का प्रतीक हैं। और हमारे अंदर के शुद्ध, सकारात्मक और दिव्य गुण ही सच्ची दैवी शक्ति हैं, जिन्हें देवी दुर्गा के रूप में दर्शाया जाता है।

देवी के हाथों में दिखाए गए अस्त्र-शस्त्र वास्तव में बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सूक्ष्म शक्तियां हैं, जैसे सहन करने की, अपने अंदर सद्गुणों को समाने की, परखने की, निर्णय लेने की, सामना करने की और सहयोग देने की क्षमता। पुराणों में कहा गया है कि देवताओं ने असुरों से बचने के लिए भगवत शक्तियों का आह्वान किया। ये शक्तियां कोई बाहर से आने वाली नहीं थीं, बल्कि हमारे भीतर की आत्मिक शक्तियां हैं - पवित्रता, प्रेम, करुणा, दया, सुख-शांति, [illegible] काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे आसुरी स्वभाव भी हमारे अंदर ही होते हैं। दैवी गुणों की रक्षा के लिए हमें अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करना होता है।

दुर्भाग्यवश, हम नौ दिन उपासना करते हैं और दशमी के दिन मूर्ति विसर्जन के साथ सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन सच्ची नवरात्रि का अर्थ है - नियमित आत्मचिंतन, उपासना और अपने भीतर की दैवी शक्तियों को जागृत रखना है।

कांटे की बात

विकसित भारत के लिए हमारा जुडिशल सिस्टम सबसे बड़ी बाधा है। कई कानून समस्या को आसान की बजाय जटिल बना देते हैं। कोर्ट में मी लॉर्ड जैसे शब्द अंग्रेजों के जमाने के हैं। इन्हें बदलना चाहिए।

संजीव सान्याल, एडवाइजर, PMEAC

डेटा Window

H-1B वीजा की फीस ट्रंप ने 1 लाख डॉलर कर दी है। इसका अमेरिकी कंपनियों और भारतीय प्रतिभाओं पर बुरा असर पड़ेगा।

भारतीय H-1B पर नहीं जाएंगे, तो कैसे काम करेगा US

शीर्ष नियोक्ता- 2025

एमेजॉन	10,004
TCS	5,505
माइक्रोसॉफ्ट	5,189
मेटा	5,123
ऐपल	4,202
गूगल	4,181

भारत के लिए वीजा

FY24-2,19,659

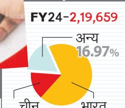

FY23-2,65,777

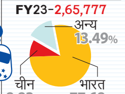

7,00,000 वर्तमान सक्रिय H-1B वीजा

63,717 टॉप 20 नियोक्ताओं ने FY25 में H-1B वीजा स्पॉन्सर किए

12,567 भारतीय कंपनियों ने जारी किए

अमेरिकी हैं 9 में से 10 शीर्ष H-1B नियोक्ता

FY24 में जारी वीजा

भारत	1,50,647
चीन	31,735
फिलिपींस	3,562
द.कोरिया	2,289
मेक्सिको	1,954
कुल	2,19,659

मीम बहार

अब फोन ही घर है, घर ही फोन है, फोन में ही घर है और ईएमआई है, लोन है। ये Gen Z का जोन है।

विरोधियों की हत्या करने का काला इतिहास

7 अक्टूबर 2023 को इस्राइल पर हमास के हमले के बाद गाजा ने भयानक तबाही देखी है। तबाही ऐसी कि गाजा को पहचानना मुश्किल हो गया है। इस बीच, इस्राइल ने ईरान, सीरिया, लेबनान और कतर तक पर हमला किया। उसने पेजर ब्लास्ट के जरिये हिज्बुल्लाह विद्रोहियों को निशाना बनाया, जिसमें इस्राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताया गया। जो लोग मोसाद के काम करने के तरीके से वाकिफ हैं, वे भी इससे हैरान रह गए थे।

पश्चिम में हत्याएं । रोनेन बर्गमैन (Ronen Bergman) ने कुछ समय पहले 'Rise and Kill First,' नाम की किताब लिखी थी। वह इस्राइल में पत्रकार रहे हैं। इस किताब को लिखने के लिए उन्होंने हजारों इंटरव्यू किए ताकि मोसाद की हकीकत समझी जा सके। इनमें नेताओं से लेकर खुफिया एजेंसियों में काम कर चुके लोग शामिल थे। रोनेन लिखते हैं, 'दूसरे विश्वयुद्ध के बाद से पश्चिमी दुनिया में सबसे अधिक हत्याएं इस्राइल ने की हैं।'

नैतिक पहलू । रोनेन की किताब में इतिहास के साथ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी दिखती है। उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि जब कोई स्टेट अपने सर्वाइवल के लिए हत्या का रास्ता चुनता है तो इससे कई नैतिक सवाल भी खड़े होते हैं। मसलन, एक ऐसा देश, जो शरणार्थियों के लिए बना। ऐसे शरणार्थियों के लिए, जो जर्मनी में नरसंहार का सामना कर रहे थे। क्या ऐसे देश के लिए विरोधियों की हत्या करवाना ठीक है?

दशकों पुराना सिलसिला । किताब में इस्राइल के लिए हत्याएं करने वालों से भी बात की गई है। ऐसे ही एक हत्यारे ने रोनेन को बताया, '1944 में (इस्राइल 1948 में अलग देश बना) मैंने एक ब्रिटिश ऑफिसर की येरूशलम की सड़कों पर हत्या की थी। मुझे इसका जरा भी अफसोस नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। हमें लगता था कि जितने अंग्रेजों के शव लंदन पहुंचेंगे, हमारी आजादी का दिन उतना करीब आएगा।' उस वक्त फलस्तीन पर अंग्रेजों का कब्जा था।

विचार विंडो

वजूद मिटने का डर । रोनेन बताते हैं कि इस्राइल के अलग देश बनने से पहले जो यहूदी अंडरग्राउंड मूवमेंट में शामिल थे, बाद में उनमें से कई सत्ता में शीर्ष पदों पर पहुंचे। इनमें यित्जाक शमीर जैसे लोग भी शामिल थे। हिटलर ने यहूदियों पर जो जुल्म ढाए थे और जिस बड़े पैमाने पर उनकी हत्याएं की थीं, उसे देखते हुए इस्राइल के मन में तब यह डर बैठा हुआ था कि उन्हें हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है।

होलोकॉस्ट का साया । Meir Dagan 2002 से 2011 तक मोसाद के चीफ थे। उनके दफ्तर में एक तस्वीर टंगी थी। इसमें शॉल ओढ़कर प्रार्थना करते हुए एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को दिखाया गया था, जो जर्मन फौज के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है। जब भी मोसाद के लोग किसी बेहद खास मिशन पर जाते थे, वह उन्हें अपने ऑफिस बुलाते और बताते कि तस्वीर में जो व्यक्ति घुटनों के बल बैठा हुआ है, वह उनके ग्रैंडफादर हैं, जिनकी नाजियों ने हत्या कर दी थी। Meir ने रोनेन को बताया- हिटलर के होलोकॉस्ट में जो भी यहूदी मारे गए, उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया। इस्राइल अब कभी भी उस स्थिति में नहीं जाएगा, हम अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे।

इस किताब में कई चौंकाने वाली घटनाएं दर्ज हैं। कई ऐसे वाकये हैं, जिन पर यकीन करना मुश्किल है। बहरहाल, आज इस्राइल-फलस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उसके कई पहलुओं को समझने में इससे मदद मिल सकती है।

रीडर्स मेल
www.edit.nbt.in

नेपाल से सबक

पिछले दिनों भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के बाद नेपाल में भी युवाओं का जन आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। वहां आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा में कई जानें चली गईं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। प्रश्न यह है कि नेपाल में युवा अचानक इतना अधिक आक्रामक कैसे हो गया है? क्या सरकार को इस बात का इल्म नहीं था कि हालात इस कदर बिगड़ सकते हैं। लगता है कि सरकार के आकलन में वाकई कोई न कोई चूक अवश्य हुई है। हमारे देश में युवा देश के खिलाफ जाने की कतई आवश्यकता नहीं समझता है। हमारे यहां हमेशा ही एक मजबूत लोकतंत्र है।

-मनमोहन राजावतराज, ईमेल से

readersmail.nbt@gmail.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः(022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

Machine Translated by Google

एच-1बी, शायद

भारत के तकनीकी कर्मचारियों को अमेरिकी नौकरियों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। डोनाल्ड

पी ट्रम्प के एच-1बी अत्यधिक कुशल गैर-आप्रवासी वीजा के लिए नए आवेदकों से $100,000 वसूलने के फैसले, जो वर्तमान शुल्क का लगभग छह गुना है, ने व्यापक चिंता पैदा कर दी है कि न केवल तकनीकी क्षेत्र के हजारों संभावित वीजा आवेदकों का जीवन प्रभावित हो सकता है, जिससे परिवारों के लिए "मानवीय परिणाम" हो सकते हैं, जैसा कि भारत के विदेश मंत्रालय ने उल्लेख किया है, बल्कि अमेरिका में प्रमुख तकनीकी कंपनियों के बीच भी व्यापक व्यवधान होगा जो इस वीजा के तहत कुशल श्रमिकों को काम पर रखने पर निर्भर हैं। जबकि इस श्रेणी में जारी किए गए वीजा की संख्या 2004 से प्रति वर्ष 85,000 पर सीमित है, और आवंटन लॉटरी के माध्यम से तय किए जाते हैं, अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट बताती है कि आगामी स्केल वर्ष के लिए आवेदन लगभग 3,59,000 के चार साल के निचले स्तर पर आ गए हैं। इन वीज़ा में आम तौर पर 71% हिस्सा भारतीय नागरिकों का होता है, फिर भी आँकड़े यह भी बताते हैं कि इन वीज़ा प्राप्तकर्ताओं में से लगभग 60% की कमाई $100,000 से कम है, जिसका अर्थ है कि लंबी अवधि में, उनके नियोक्ताओं के लिए विदेश से ऐसे विशेषज्ञ कर्मचारियों को नियुक्त करना उचित ठहराना मुश्किल हो सकता है। व्हाइट हाउस की कार्रवाई पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया में इस तथ्य की पुनरावृत्ति शामिल थी कि "कुशल प्रतिभाओं की गतिशीलता और आदान-प्रदान ने अमेरिका और भारत में प्रौद्योगिकी विकास, नवाचार, आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता और धन सृजन में बहुत बड़ा योगदान दिया है", फिर भी दक्षिण ब्लॉक के लिए इस नीति को उलटने के लिए राजनयिक या राजनीतिक दबाव डालने की सीमित गुंजाइश है।

हालांकि, भारतीय नागरिकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रोका जा सकता है, अगर सरकार भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और भारतीय तकनीकी उद्योग की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सुधार करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाए, ताकि यह अब तक की तुलना में और भी अधिक प्रगति कर सके। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नई क्षमताओं को विकसित करने के अवसरों का लाभ उठाकर और चीन और रूस सहित पूरे एशिया में नए बाजारों की खोज करके और यूरोप के उन हिस्सों में, जहाँ स्वदेशी संरक्षणवाद के ट्रान्साटलांटिक संक्रमण को अभी तक इच्छुक खरीदार नहीं मिले हैं, हासिल किया जा सकता है। हालाँकि ट्रम्प का आदेश एक साल के भीतर समाप्त होने वाला है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, जिससे भारत के नीति निर्माताओं के लिए यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में घटते रोज़गार के अवसरों पर भारतीय तकनीकी कर्मचारियों की निर्भरता कम करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना तैयार करें। जैसे-जैसे भारत और अन्य देश ट्रम्प व्हाइट हाउस की भावी नवप्रवर्तकों, रोजगार सृजनकर्ताओं और करदाताओं का अपने यहां स्वागत करने की शत्रुता की इस नई वास्तविकता के साथ तालमेल बिठा रहे हैं, वैसे-वैसे अन्य देशों की बजाय अमेरिका को ही आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कौशल की कमी का सामना करना पड़ेगा।

यूरेनियम अशांति

संसाधन निष्कर्षण परियोजनाओं में लोगों की सहमति होनी चाहिए

टी स्थानीय नेताओं के साथ विचार-विमर्श के निरर्थक साबित होने के बाद, मेघालय से किसी भी कीमत पर यूरेनियम खनन का केंद्र का निर्णय, भारत के संसाधन निष्कर्षण के इतिहास में एक चिंताजनक मानदंड है। खासी समूह 1980 के दशक से डोमियासियाट और वाहकाजी में बड़े भंडारों की खोज और निष्कर्षण का विरोध करते रहे हैं। हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) जारी किया है, जिसमें परमाणु, महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के निष्कर्षण को सार्वजनिक परामर्श से छूट दी गई है। स्थानीय समूहों ने पहले ही ओएम-आधारित मार्ग की निंदा की है; सत्तारूढ़ दल से जुड़े एक समूह ने खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद से आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी छठी अनुसूची की शक्तियों का उपयोग करने का आह्वान किया है।

ओएम कार्यकारी उपकरण होते हैं जो प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों को कमज़ोर करते हैं और स्वतंत्र जाँच के बिना जारी किए जाते हैं। इस मामले में, ओएम, देखरेख करने वाले समुदायों को उन फैसलों में मूकदर्शक बना देता है जिनके उनके लिए गंभीर परिणाम होते हैं।

यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने यूरेनियम के मामले में इतनी सख्ती से कदम उठाया हो। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दशकों से झारखंड के सिंहभूम ज़िले में काम कर रहा है। जहाँ एक ओर विस्तार या नई खदानों की स्थापना से जुड़ी सुनवाई में विकिरण जोखिम और आजीविका के नुकसान को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, वहीं ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि कॉर्पोरेशन ने अपरिचित भाषाओं में नोटिस जारी किए और आपत्तियों की अनदेखी की। आदिवासी समुदायों के लिए, इस अनुभव ने इस धारणा को और पुष्ट किया है कि उनकी ज़मीन 'शेष भारत' के लिए एक 'संसाधन सीमा' बनी हुई है।

स्थानीय नेताओं के साथ अपनी बातचीत में, राज्य को उनके इनकार का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसने संकेत दिया है कि 'नहीं' अब स्वीकार्य उत्तर नहीं है। यूरेनियम खनन अत्यधिक प्रदूषणकारी है और परिदृश्य को अपरिवर्तनीय रूप से बदल सकता है। यही कारण है कि वैश्विक मानदंडों के तहत स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति आवश्यक है। यदि ऐसी सहमति उपलब्ध नहीं है, तो यह उसी राज्य का कर्तव्य है जिसने लोकतांत्रिक सुरक्षा स्थापित की है कि वह यूरेनियम को राष्ट्रीय सुरक्षा या विकास का एकमात्र मार्ग मानना बंद करे और अन्य भंडारों, विकल्पों या यहां तक कि बिजली उत्पादन रणनीतियों पर भी विचार करे। अब, समुदाय नियमगिरि (2013) जैसे उदाहरणों का हवाला देते हुए, और पांचवीं और छठी अनुसूची के तहत संरक्षण का आह्वान करते हुए, अदालतों में ओएम की वैधता को चुनौती देने पर विचार कर सकते हैं। अंत में, अगर स्थानीय विरोध प्रदर्शन तेज़ होते हैं, तो केंद्र को एक बार फिर बातचीत के ज़रिए जवाब देना चाहिए: ज़बरदस्ती, भले ही अल्पावधि में अपना लक्ष्य हासिल कर ले, लेकिन बाद में सिर्फ़ असंतोष ही पैदा करेगी। केंद्र का दायित्व न केवल व्यवस्था बनाए रखना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि संवैधानिक सुरक्षाएँ व्यवहार में लागू हों।

श्रीलंका में अभिजात वर्ग की दंडमुक्ति को 'समाप्त' करने से परे का संदेश

एंड्रयू फिदेल फर्नांडो

श्रीलंका में स्थित एक पुरस्कार विजेता लेखक और पत्रकार हैं

सितंबर 2023 में , इसके तुरंत बाद जी-77+चीन शिखर सम्मेलन हवाना में संपन्न हुआ। क्यूबा, श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने एक पड़ाव का चयन किया कोलंबो लौटते समय वे यूनाइटेड किंगडम में थे। उन्होंने एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भाग लेने का फैसला किया था, जिसमें उनकी पत्नी, प्रोफ़ेसर मैत्री विक्रमसिंघे को सम्मानित किया जा रहा था।

इस संबंध में, उन पर 16.2 मिलियन श्रीलंकाई रुपये या लगभग 50,000 डॉलर की सार्वजनिक धनराशि का दुरुपयोग करने का आरोप है, जिसके वे हकदार नहीं थे। श्री विक्रमसिंघे को अगस्त 2025 में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया, चार दिनों की हिरासत में रखा गया और बाद में एक श्रीलंकाई अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया।

गिरफ्तारी के बाद श्री सिंह को दोषी ठहराने का प्रयास किया गया है।

विक्रमसिंघे की गिरफ्तारी को राजनीतिक बदला लेने के तौर पर देखा जा रहा है। श्री विक्रमसिंघे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने सितंबर 2024 में होने वाले चुनावों में वर्तमान राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के खिलाफ चुनाव लड़ा था।

घरेलू स्तर पर, श्री विक्रमसिंघे के समर्थक मुखर थे, यहां तक कि वे 26 अगस्त, 2025 को उनकी अदालती सुनवाई की तिथि पर उनकी रिहाई की मांग करने के लिए एकत्र हुए थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सहयोगियों ने सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन किया है, यहां तक कि भारत और मालदीव के राजनेताओं ने भी उनकी गिरफ्तारी पर अपनी चिंता व्यक्त की है।

श्री विक्रमसिंघे के समर्थक उनके खिलाफ लगे आरोपों की तुच्छता पर ज़ोर दे रहे हैं। उनका दावा है कि निश्चित रूप से एक राष्ट्राध्यक्ष को निजी यात्राओं पर भी राष्ट्रपति पद के भत्ते पाने का अधिकार है। श्री विक्रमसिंघे की कानूनी टीम भी इस बात से इनकार नहीं करती कि इस यात्रा पर खर्च किया गया पैसा करदाताओं का था; वे सिर्फ़ यही तर्क देते हैं कि उन्हें इसे खर्च करने की अनुमति थी।

शायद ये दावे अदालत में टिक पाएँ और श्री विक्रमसिंघे बरी हो जाएँ। लेकिन सिर्फ़ यह कहना कि एक राष्ट्रपति को अपनी निजी यात्रा पर 1.62 करोड़ श्रीलंकाई रुपये खर्च करने का अधिकार है, इस द्वीपीय देश के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए, शर्मनाक है। कथित राशि से कई लोगों के लिए घर खरीदा जा सकता है, कई लोगों की शिक्षा का खर्च उठाया जा सकता है, आस-पड़ोस में हार्डवेयर की दुकानें खोली जा सकती हैं, गिरवी और कर्ज़ चुकाए जा सकते हैं, या नावें खरीदी जा सकती हैं।

श्री में आम आदमी

श्रीलंका की नज़र इस बात पर रहेगी कि क्या सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, जो 2022 के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का मुख्य आकर्षण थी, को राजनीतिक स्पेक्ट्रम में स्वीकार किया गया है।

शिंग। आँकड़ों के अनुसार, श्री विक्रमसिंघे पर जिस राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है, उसे कमाने में एक औसत श्रीलंकाई परिवार को लगभग 18 साल लगेंगे। श्रीलंका की जनता अब इन खर्चों को अपनी शर्तों पर समझती है। अभिजात वर्ग को कम रियायतें दी जाती हैं।

जवाबदेही की माँग ये वे राजनीतिक मूल्य हैं जो जुलाई 2022 में श्रीलंका में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान अभिव्यक्त हुए थे। 13 जुलाई को जब प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो के मध्य में उनके कार्यालय पर धावा बोला था, तब श्री विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री थे। हालाँकि इमारत पर कब्ज़ा करने के कुछ ही मिनटों बाद ज़ोरदार जश्न मनाया गया, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करने की भी ज़ोरदार अपील की गई। प्रदर्शनकारियों के नेताओं को बार-बार यह कहते सुना गया, "अगर हम यहाँ कुछ भी तोड़ते हैं, तो हमें ही इसकी कीमत चुकानी होगी।" उस हफ़्ते, श्री विक्रमसिंघे ने कहा, "अगर हम यहाँ कुछ भी तोड़ते हैं, तो हमें ही इसकी कीमत चुकानी होगी।"

विक्रमसिंघे इन प्रदर्शनकारियों को “फासीवादी” कहते थे।

श्री विक्रमसिंघे जानते होंगे कि श्रीलंकाई जनता राजनेताओं की ज्यादतियों के प्रति गहरी नाराज़गी रखती है। 2015 में, उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी लहर पर सवार होकर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए एक अप्रत्याशित गठबंधन बनाया था। हालाँकि वह ' सुशासन ' सरकार विफल रही, फिर भी अधिक जवाबदेही की माँग जारी रही। 2019 में, गोटाबाया राजपक्षे को श्रीलंका का राष्ट्रपति चुना गया, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उनसे सरकार के भीतर भ्रष्टाचार को खत्म करने की उम्मीद की जा रही थी, हालाँकि उनका मुख्य मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा था। जब गोटाबाया राजपक्षे की विफलताएँ आर्थिक संकट में बदल गईं, तो जनता ने उन्हें ज़ोरदार तरीके से बेदखल कर दिया।

श्री. विक्रमसिंघे की गिरफ्तारी के बाद श्रीलंका की जनता ने संकेत दिया है कि राजनेताओं द्वारा किए गए व्यय पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

शायद श्री मोदी के बारे में विवाद चल रहा है।

विक्रमसिंघे की यह लापरवाही श्री विक्रमसिंघे की एक लापरवाही मात्र थी, जिनके कोलंबो के मध्य में स्थित घर की कीमत उन 16.6 मिलियन श्रीलंकाई रुपयों से कहीं ज़्यादा है, जिन्हें उन पर अवैध रूप से खर्च करने का आरोप है। लेकिन जनता अब ऐसी 'लापरवाही' बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है।

श्री विक्रमसिंघे की गिरफ्तारी से बहुत कम जानकारी मिलती है मौजूदा नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) सरकार के लिए राजनीतिक ज़मीन तैयार करने के अलावा, यह ताकतवर लोगों को भी जवाबदेह ठहराने की इच्छाशक्ति दिखाने का भी एक बड़ा उदाहरण है। 2024 के श्रीलंकाई राष्ट्रपति चुनाव में श्री विक्रमसिंघे तीसरे स्थान पर रहे। श्रीलंका की 225 सदस्यीय संसद में उनकी पार्टी और उसके सहयोगियों के पास सिर्फ़ छह सीटें हैं। सच कहें तो, गिरफ्तारी के समय वे श्रीलंका की राजनीति से काफ़ी हद तक अप्रासंगिक थे, हालाँकि उनके मुखर समर्थक मौजूद थे।

और फिर भी, इस दावे में भी सच्चाई है कि श्री विक्रमसिंघे के खिलाफ आरोप तुच्छ हैं। श्रीलंका की अदालतों में और भी गंभीर आरोप हैं, जैसे कि एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पर एक दवा घोटाले का आरोप, जिससे सरकार को 144 मिलियन श्रीलंकाई रुपये का नुकसान हुआ। 2022 में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान, यह दावा भी ज़ोर पकड़ गया कि राजनेताओं ने विदेशों में विमानों में भरकर विदेशी मुद्रा जमा कर रखी है।

इसी पैमाने पर एनपीपी सरकार श्री विक्रमसिंघे की गिरफ़्तारी में एक बड़ा जोखिम उठा रही है। सबसे पहले, इससे पुराने राजनीतिक प्रतिष्ठान, पूर्व राष्ट्रपतियों, राजपक्षे परिवार के सदस्यों और विपक्षी सदस्यों, जो श्री विक्रमसिंघे के साथ जुड़े हुए हैं, के और अधिक विरोधी होने का ख़तरा है।

विक्रमसिंघे की गिरफ़्तारी के बाद। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एनपीपी ख़ुद पर भी सुर्ख़ियाँ बटोर रही है। अगर सरकार 1.66 करोड़ श्रीलंकाई रुपये की राशि पर इतना बड़ा आरोप लगाती है, तो पहली बार संसद में आए सदस्यों—एनपीपी के 150 से ज़्यादा सदस्य हैं—को हर खर्च के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, वरना उन पर पाखंड का आरोप लगने का ख़तरा है। अगर यह श्रीलंका के राजनेताओं के लिए एक नई लकीर है, तो यह सबसे ज़्यादा एनपीपी पर लागू होती है।

जहां तक अधिकांश मतदाताओं का सवाल है, एनपीपी अपनी संख्या के बावजूद अभी भी एक राजनीतिक प्रयोग है। सरकार को पहले ही अपने दो मंत्रियों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू करनी पड़ी है।

विकासशील देशों पर अक्सर 'कम-परिपक्व' लोकतंत्र होने का आरोप लगाया जाता है। श्रीलंका में, जनता ने राजनीतिक सत्ता के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह से बदल दिया है। किस्मत अच्छी रही तो, वह अपने सरकारी कर्मचारियों पर लगाम कसता रहेगा।

एक ऐसा नेता जिसने सत्ता को जनता से जोड़ा है

Shivraj Singh चौहान

केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास, भारत सरकार

एन भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का उदय विशेषाधिकार के पारंपरिक चश्मे से नहीं समझा जा सकता। राजनीतिक वंशों में पले-बढ़े कई नेताओं के विपरीत, श्री मोदी और उनकी नेतृत्व शैली ज़मीन से उभरी है, उनके संघर्ष, ज़मीनी स्तर पर वर्षों के काम और सरकार के विभिन्न स्तरों पर अनुभव से आकार लेती है। उनका करियर न केवल एक व्यक्ति के उत्थान का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि भारत में अभिजात वर्ग द्वारा संचालित राजनीति की नींव के लिए एक चुनौती भी है।

नेतृत्व के प्रारंभिक लक्षण वडनगर के एक साधारण परिवार में जन्मे श्री. मोदी का बचपन ज़िम्मेदारी और सादगी से भरा रहा। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चैरिटी स्टॉल लगाने से लेकर स्कूली बच्चे के रूप में जातिगत भेदभाव पर नाटक लिखने तक, उन्होंने कम उम्र में ही संगठनात्मक कौशल और सामाजिक सरोकार का अद्भुत मिश्रण दिखाया। उन्होंने वंचित सहपाठियों के लिए पुरानी किताबें और वर्दियाँ इकट्ठा करने के अभियान भी चलाए - यह इस बात का एक प्रारंभिक संकेत था कि वे नेतृत्व को सेवा के रूप में देखते थे, न कि किसी विशेषाधिकार के रूप में। इन छोटे-छोटे प्रयासों ने उनके सार्वजनिक जीवन में आने वाले दृष्टिकोण का पूर्वाभास करा दिया।

उनकी जमीनी स्तर की प्रवृत्तियाँ तीव्र हो गईं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में, जहाँ आम कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों से मेलजोल बढ़ाने, उनके जैसा जीवन जीने और अपने आचरण से विश्वास अर्जित करने का निर्देश दिया गया था। एक युवा प्रचारक के रूप में, श्री मोदी ने ठीक यही किया। अक्सर बस या स्कूटर से गुजरात भर में यात्रा करते हुए, और भोजन व आश्रय के लिए ग्रामीणों पर निर्भर रहते हुए, उन्होंने साझा कठिनाइयों और संघर्षों के माध्यम से सभी का विश्वास जीता। इस अनुशासन ने उन्हें उन लोगों की रोज़मर्रा की चिंताओं से जुड़े रहने में मदद की जिनकी वे सेवा करना चाहते थे, और इसने उन्हें संकटों के समय संगठित, बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया की माँग करते हुए प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने के लिए तैयार किया।

ऐसा ही एक संकट 1979 में मच्छू बांध के टूटने से आया था, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे।

प्रधान मंत्री महोदय ने भारतीय राजनीति को नया रूप दिया है, इसे संघर्षों और स्वतंत्रता की भावना में स्थापित किया है।

आम आदमी

श्री मोदी ने तुरंत स्वयंसेवकों को पाली में तैनात किया, राहत सामग्री का प्रबंध किया, शवों को निकाला और परिवारों को सांत्वना दी। कुछ साल बाद, गुजरात में सूखे के दौरान, उन्होंने सूखी अभियान का नेतृत्व किया, जो पूरे राज्य में फैल गया और लगभग 25 करोड़ रुपया का भोजन वितरित किया गया। दोनों आपदाओं में, उन्होंने बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किए, जिससे उनके उद्देश्य की स्पष्टता, उनके सैन्य-शैली के संगठन और इस बात पर उनके आग्रह का परिचय मिला कि नेतृत्व का अर्थ केवल प्रतीकात्मकता नहीं, बल्कि सेवा है।

जबकि इन शुरुआती प्रकरणों ने उनकी क्षमता का परीक्षण किया लोगों को संगठित करने के लिए, आपातकाल ने दमन के दौर में उनके साहस की परीक्षा ली। मात्र 25 वर्ष की आयु में, एक सिख के वेश में, उन्होंने पुलिस निगरानी से बचने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच संवाद कायम रखा। इस ज़मीनी नेटवर्क ने क्रूर शासन के विरुद्ध प्रतिरोध को जीवित रखा, जिससे उन्हें एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में ख्याति मिली।

चुनावी राजनीति में अनुप्रयोग: यही कौशल जल्द ही चुनावी राजनीति में भी इस्तेमाल होने लगे। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात संगठन मंत्री के रूप में, उन्होंने पार्टी का विस्तार नए समुदायों तक किया, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जो राजनीतिक विमर्श में हाशिए पर थे। उन्होंने विविध पृष्ठभूमियों के नेताओं को तैयार किया, ज़मीनी स्तर पर समर्थन जुटाया और लालकृष्ण आडवाणी की सोमनाथ-अयोध्या रथ यात्रा जैसे बड़े आयोजनों की योजना बनाने में मदद की। बाद में, विभिन्न राज्यों में प्रभारी के रूप में , उन्होंने बूथ स्तर तक मज़बूत पार्टी तंत्र का निर्माण किया।

जब वे 1962 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 2001 में, श्री मोदी ने इन सबकों को शासन में लागू किया। उदाहरण के लिए, पदभार ग्रहण करने के कुछ ही घंटों बाद, उन्होंने साबरमती तक नर्मदा का पानी लाने पर एक बैठक बुलाई थी, जिससे यह संकेत मिलता था कि उनके प्रशासन को निर्णायक कदम उठाने होंगे।

उनका दृष्टिकोण शासन को एक ऐसा रूप देना था

यह एक जन आंदोलन था, जहां प्रवेशोत्सव ने स्कूल में नामांकन को प्रोत्साहित किया, कन्या केलवणी ने लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया, गरीब कल्याण मेलों ने कल्याण को नागरिकों तक पहुंचाया, और कृषि महोत्सवों ने किसानों के खेतों तक कृषि सहायता पहुंचाई।

Join This Channel: https://t.me/AllNewsPaperPaid1

नौकरशाहों को कार्यालयों से निकालकर कस्बों और गाँवों में धकेल दिया गया। उनका मानना है कि शासन को लोगों तक वहीं पहुँचना चाहिए जहाँ वे रहते हैं, न कि सम्मेलन कक्षों तक सीमित रहना चाहिए।

साझेदारी के रूप में नीति: गुजरात में किए गए ये प्रयोग उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्रीय आदर्श बन गए। स्वच्छता अभियानों के साथ उनका अनुभव स्वच्छ भारत मिशन के रूप में विकसित हुआ, जहाँ उन्होंने प्रतीकात्मकता को सामूहिक कार्य में बदलने के लिए स्वयं झाड़ू उठाई।

डिजिटल इंडिया, जन-धन योजना और अन्य पहल ऊपर से शुरू किए गए कार्यक्रम नहीं थे, बल्कि जमीनी स्तर पर बिताए उनके वर्षों से मिली सीख पर आधारित जन आंदोलन थे। ये उनके जनभागीदारी के दर्शन को मूर्त रूप देते थे, जहाँ शासन तभी कारगर होता है जब नागरिक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के बजाय भागीदार बनें। श्री मोदी जैसे नेता और जनता के बीच दशकों से पनपा यह विश्वास ही आज के भारत में नीति को साझेदारी में बदल पाया है।

दशकों से, श्री मोदी ने लोगों की ज़रूरतों को समझने और उन्हें कैसे पूरा किया जाए, यह जानने की एक दुर्लभ सहज प्रवृत्ति दिखाई है, न कि बैठक-कक्ष की बहसों से, बल्कि ज़मीनी स्तर पर जीवंत जुड़ाव से। यह सहज प्रवृत्ति, कठोर प्रशासनिक अनुभव के साथ मिलकर, उनकी राजनीति की पहचान बन गई है।

अंततः, उनका जीवन और नेतृत्व इस धारणा को पुनः परिभाषित करता है कि भारतीय राजनीति केवल अभिजात वर्ग की है। वे योग्यता और परिश्रम के प्रतीक बन गए हैं और शासन को आम लोगों के और करीब ले आए हैं। उनकी राजनीतिक शक्ति सत्ता को जनता से जोड़ने में निहित है। ऐसा करके, उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नया रूप दिया है, जो आम नागरिक के संघर्षों और भावनाओं पर आधारित है।

द टटर्सटूदएडिटर

अमेरिका की ओर से एक और कदम: नए एच-1बी वीज़ा आवेदनों पर $100,000 का भारी-भरकम शुल्क लगाने की ट्रंप प्रशासन की अचानक घोषणा, अमेरिका की आव्रजन नीति में एक अभूतपूर्व कदम है। कार्यक्रम के "दुरुपयोग" पर अंकुश लगाने के नाम पर, जल्दबाजी में उठाया गया यह कदम, हज़ारों कुशल भारतीय पेशेवरों की आजीविका को खतरे में डालने और भारत के आईटी क्षेत्र को पंगु बनाने का खतरा पैदा करता है।

इस नीति के भयावह प्रभावों से इनकार नहीं किया जा सकता। यह महज़ सुधार नहीं, बल्कि संरक्षणवाद के नाम पर आर्थिक युद्ध है।

इस तरह का दोहरा रवैया अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी को कमज़ोर करता है। इस कमज़ोरी के लिए भारत सरकार भी बराबर की ज़िम्मेदारी लेती है।

वर्षों की चेतावनियों के बावजूद, नई दिल्ली द्विपक्षीय गतिशीलता समझौता या दीर्घकालिक एच-1बी ढांचा हासिल करने में विफल रही।

सक्रिय कूटनीति, संभवतः वीज़ा सुधारों को रक्षा सौदों या व्यापार रियायतों से जोड़कर, इस आघात को कम किया जा सकता था।

इस नीति के व्यापक परिणाम होने का खतरा है - अमेरिकी तकनीकी प्रतिभाओं की उपलब्धता में बाधा, अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए लागत में वृद्धि, तथा भू-राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण मोड़ पर द्विपक्षीय संबंधों में तनाव।

केजे हारून बाशा, वानीयंबाडी, तमिलनाडु

भारत को डरना नहीं चाहिए

इस तरह की ब्लैकमेलिंग से बचें और इसे तकनीकी रूप से दक्ष लोगों के कौशल का लाभ उठाने के अवसर के रूप में उपयोग करें। साथ ही, अगर अमेरिका भारत को इसी तरह निशाना बनाना जारी रखता है, तो चल रही व्यापार वार्ताएँ निरर्थक हो सकती हैं।

ज़हर।

बालकृष्णन एमके, नई दिल्ली

तारी हथियार के बाद, अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ 'वीज़ा मिसाइल' का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर कर्मचारी अपनी योग्यता के लिए जाने जाते हैं और उन्हें नियुक्त करना कम खर्चीला होता है। अंततः, किसी भी उद्यमी या दिग्गज कंपनी के लिए आर्थिक लाभ और मुनाफा ही मायने रखता है। ऐसा लगता है कि ट्रंप बाजार अर्थव्यवस्था की गतिशीलता के खिलाफ जा रहे हैं और उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है।

साथ ही, यह भारत के लिए एक सबक है और उसे श्री ट्रम्प की नीतियों को भारत की नीतियों और कार्यक्रमों को नया रूप देने वाले उत्प्रेरक के रूप में देखना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभी निरंतर प्रगति की आवश्यकता है।

एजी राजमोहन, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश

भारत को हजारों की हानि

प्रत्येक वर्ष कुशल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होगी।

इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्र अपना सामान बांधकर बेहतर नौकरियों के लिए विदेश चले जाते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उन्हें मोटी तनख्वाह का लालच देती हैं। घरेलू कंपनियाँ उनकी बराबरी नहीं कर सकतीं। ये प्रतिभाशाली भारतीय अपने नए कार्यस्थलों में विकास को गति देते हैं। वे अन्यत्र मज़बूत अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण में भी योगदान देते हैं। अपने देश में, देश उनके कौशल से वंचित रह जाता है।

भारत सरकार को आगे आकर प्रतिभाओं को यहीं बनाए रखने के लिए करों में छूट या अनुदान देना चाहिए। वीज़ा शुल्क का मुद्दा कोई झटका नहीं है। यह भारत को आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका है।

चंद्रन चैथराम, चेरुकुन्नु, कन्नूर, केरल

अभिनेता के लिए पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय Dadasaheb Phalke Award on actor Mohanlal is सुविचारित। दशकों से, लालेटन की उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा ने भाषाई सीमाओं को पार करते हुए उन्हें भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता का प्रतीक बना दिया है। थनमथ्रा जैसे गहन नाटक से लेकर दृश्यम जैसे मनोरंजक थ्रिलर तक , अपने परिवर्तनकारी अभिनय में, उन्होंने एक ऐसी गहराई दिखाई है जो बहुत कम अभिनेताओं में होती है।

वेद चिदानंद, बेंगलुरु

परीक्षा और मूल्यांकन: मैं NEET PG 2025 के इच्छुक समुदाय की ओर से हाल ही में हुई NEET PG परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित चिंताओं को उजागर करने के लिए लिख रहा हूँ। प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं: कई

उम्मीदवारों ने अपने NEET PG 2025 परिणामों में महत्वपूर्ण विसंगतियों की सूचना दी है, उच्च अंतर के साथ, बड़ी संख्या में हल किए गए प्रश्नों और सही उत्तरों के बावजूद। एनबीईएमएस ने व्यक्तिगत उत्तर पुस्तिकाएँ या आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी नहीं की है, जिससे उम्मीदवारों के लिए अपने अंकों की पुष्टि करना या यह समझना असंभव हो गया है कि अंक कैसे दिए गए। समान संख्या में हल किए गए प्रश्नों और समान उत्तर पैटर्न वाले कई उम्मीदवारों को व्यापक रूप से भिन्न अंक मिले हैं, जिससे मूल्यांकन की सटीकता को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। स्पष्टीकरण, पुनर्मूल्यांकन या उत्तर पुस्तिकाएँ जारी करने के बार-बार अनुरोधों पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

Dr. Jay K. Sen, Visnagar, Gujarat

letters@thehindu.co.in पर भेजे गए पत्रों में डाक पता अवश्य होना चाहिए।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली ● सोमवार ● 22 सितम्बर ● 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

जिस प्रकार मैले दर्पण में सूरज का प्रतिबिंब नहीं पड़ता उसी प्रकार मलिन अंतःकरण में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता।

-रामकृष्ण परमहंस

ट्रंप का वीजा बम

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोजाना कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं, जिससे भारत सरकार और भारतीय निशाने पर आ जाते हैं। ट्रंप आड़ तो अपने देश के युवाओं के रोजगार बढ़ाने की ले रहे हैं, लेकिन हमला भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं पर कर रहे हैं। अभी अमेरिका से भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क का मामला सुलझा भी नहीं है कि ट्रंप ने एच1बी वीजा का बम गिरा दिया है। एच1बी वीजा शुल्क को सालाना 100,000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया है। इस कदम से अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों, जिनमें बड़ी संख्या में आईटी से जुड़े हैं, पर गंभीर असर पड़ेगा। भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट ने असर की झांकी दिखा दी है। अमेरिका का दावा है कि एच1बी वीजा का बहुत दुरुपयोग होता है। इसकी शुरुआत उन उच्च कुशल कामगारों को अमेरिका में आने की अनुमति देने के लिए की गई थी, जो उन क्षेत्रों में काम करते हैं, जहां अमेरिकी काम नहीं करते। 100,000 डॉलर के शुल्क के बाद सुनिश्चित होगा कि वास्तव में कुशल लोग ही अमेरिका आएं और अमेरिकी कामगारों का स्थान नहीं लें। ट्रंप का तर्क है कि रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड कार्यक्रम के तहत प्रति वर्ष 281,000 लोगों को अमेरिका में प्रवेश मिलता है, तथा ये लोग औसतन प्रति वर्ष 66,000 अमेरिकी डॉलर कमाते हैं तथा सरकारी सहायता कार्यक्रमों का भारी लाभ उठाते हैं। हम इसे बंद करने जा रहे हैं। इस कदम का उन भारतीय कर्मचारियों पर गहरा असर पड़ेगा जिन्हें प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां और अन्य कंपनियां एच1बी वीजा पर नियुक्त करती हैं। ये वीजा तीन साल के लिए वैध होते हैं, जिन्हें तीन साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। आदेश के कुछ घंटों बाद शनिवार को अमेरिका में एच1बी वीजा पर रह रहे भारतीयों में भ्रम व चिंता व्याप गई। कई भारतीयों ने भारत यात्रा की अपनी योजना रद्द कर दी। जो भारत आए हुए थे उनमें जल्द से जल्द लौटने की मारामारी मच गई। हालांकि बाद में कहा गया कि यह शुल्क नये आवेदकों पर ही लागू होगा। पुराने वीजा धारक प्रभावित नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी अमेरिका के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने तल्ख टिप्पणी की कि आपके जन्मदिन पर फोन कॉल के बाद आपको जो जवाबी तोहफा मिला है, उससे भारतीय नागरिकों को दुख हुआ है। गले मिलना, खोखले नारे लगवाना और संगीत कार्यक्रम करवाना कोई विदेश नीति नहीं है। हमें अपने हितों के लिए गंभीर होना होगा।

बहुविवाह में भत्ता

कोई मुसलमान पुरुष अपनी बीवी का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, तो उसे दूसरी या तीसरी शादी करने का हक नहीं है। केरल हाई कोर्ट ने 39 साल की महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह कहा। पीड़िता ने भीख मांग कर गुजारा कर रहे पति से दस हजार रुपये मासिक गुजारा भत्ता मांगा है। 46 वर्षीय नेत्रहीन पति उसे छोड़कर पहली पत्नी के साथ रह रहा है, और तीसरा निकाह करने की धमकी दे रहा है। परिवार न्यायालय ने यह कह कर याचिका ठुकरा दी थी कि जो खुद भीख मांग कर गुजर कर रहा है, उसे गुजारा भत्ता देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। चूंकि प्रतिवादी मुसलमान है और पारंपरिक कानून का लाभ उठा रहा है, जो पुरुषों को चार शादियों का अधिकार देता है। हालांकि इस्लाम में जो शख्स दूसरी/तीसरी बीवी का भरण-पोषण नहीं कर सकता है, वह भी प्रथागत कानून के अनुसार दोबारा निकाह नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि मुसलमानों में इस तरह की शादियां शिक्षा की कमी, धार्मिक कानूनों की जानकारी के अभाव के कारण होती हैं। कोई भी अदालत किसी मुसलमान पुरुष की दूसरी/तीसरी शादी को मान्यता नहीं दे सकती, जब वह अपनी पत्नियों के भरण-पोषण में असमर्थ हो। अदलत ने मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान की आयतों की दलील देते हुए कहा कि बहुविवाह अपवाद है। पहली पत्नी, दूसरी, तीसरी और चौथी पत्नी को जो मुसलमान पति न्याय दे सकता है, तो एक बार से ज्यादा शादी जायज है। बेशक, मुसलमानों में बहुत छोटा सा तबका बहुविवाह करता है। इस मामले में अदालत ने भीख मांगने वाले को उचित परामर्श देने को कहा। बहुविवाह की शिकार बेसहारा पत्नियों की रक्षा करने को राज्य सरकार का कर्त्तव्य भी बताया। यह कहना भी गलत नहीं कहा जा सकता कि उसका पति विवाह के वक्त भी भिक्षावृत्ति ही करता रहा होगा। याचिकाकर्ता सब जानते-बूझते इस वैवाहिक बंधन में गई। तलाकयाफ्ता पत्नी का अधिकार है गुजारा-भत्ता मांगना। मगर महिलाओं को श्रम करके भी दो जून की रोटी कमाने का प्रयास करने में हिचकना नहीं चाहिए। राज्य सरकारों को निराश्रितों के खाने-जीने की सुविधा का जिम्मा उठाने की ठोस व्यवस्था करनी चाहिए। मस्जिदों, मौलवियों, समाज और न्यायपालिका को भी बहुविवाह पर उचित परामर्श देने का प्रयास करना चाहिए।

परिधि/ राजीव मंडल

दवा-जिंदगी दोनों फेल

देश में मीडिया से लेकर आमजन के बीच एच1 बी वीजा, भारत पर अमेरिका का लगाया गया तगड़ा टैरिफ और कुछ हद तक नेपाल में सत्ता के उखड़ने पर बहस और चर्चाओं का अंतहीन सिलसिला जारी है। स्वाभाविक रूप से ऐसे विषयों पर गंभीरता कम मिर्च-मसाला को छौंका लगाया जाता है। मगर एक खबर जिसपर मीडिया को भी सीना तानकर आगे आना चाहिए और आम जनता को भी अपना आक्रोश जगजाहिर करना चाहिए जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा।

खबर है कि हृदय रोग और हाई बीपी की दवाओं सहित 94 के सैंपल फेल पाए गए हैं। तीन दवा तो नकली पाए गए हैं। आश्चर्य की बात है कि इस हाहाकारी खबर पर जनता खामोश है। मतलब जिस भरोसे के साथ लोग दिल की बीमारी और बीपी की दवा सेहतमंद होने के लिए खा रहे थे, वह तो 'दिल्लगी' जैसी थी। नकली दवा का इतना बड़ा कारोबार सरकार की नाक के नीचे हो और इसका पता भी तब चला है जब दवाइयां बाजार में पसर चुकी हों तो इसे क्या कहा जाए? यह सारा धत् कर्म हिमाचल प्रदेश में स्थापित दवा फैक्टरियों में ज्यादा हो रहा है और काफी अरसे से हो रहा है। हालांकि अन्य राज्यों की फैक्टरियों में बनी 56 दवाओं के सैंपल भी फेल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बद्दी, सिरमौर, पांवटा साहिब, नालागढ़ में बनी कई जीवनरक्षक दवा बेकार पाए गए हैं। उसी तरह उत्तराखंड और पंजाब में भी बनी दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। दरअसल, नामचीन ब्रांड की दवा कंपनियों के समानांतर नकली दवा बनाने वाला सिंडिकेट भी बाजार में मौजूद है और बेहद साफगोई और भरोसे के साथ काम करता है। हालांकि भारत में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) है जो दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के लिए मानक निर्धारित करती है और उनकी देखरेख करती है। पिछले वर्ष इसी सितम्बर माह में पैरासिटामॉल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई थी। इसमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाएं भी शामिल थी। सीडीएससीओ की लिस्ट में कैल्शियम और विटामिन डी3 सप्लीमेंटस और एंटी डायबिटीज सहित हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं भी शामिल थी। उस मामले में किसे दंडित किया गया, किस फैक्टरी को ब्लैक लिस्ट किया गया; किसी को पता नहीं। दुनिया की खबरों पर मगजमारी करने वालों को असल में ऐसी खबरों पर सजग रहने की जरूरत है।

चीन की बढ़ती हनक

स्वच्छ ऊर्जा

विनीत नारायण

आज की दुनिया में ऊर्जा नीतियां सिर्फ आर्थिक निर्णय नहीं हैं, बल्कि वैश्विक वर्चस्व की कुंजी हैं। जब अमेरिका तेल और गैस पर दांव लगा कर पुरानी राह पर लौट रहा है, वहीं चीन स्वच्छ ऊर्जा क्रांति को गति दे रहा है। यह विरोधाभास न केवल आर्थिक असंतुलन पैदा कर रहा है, बल्कि भविष्य की तकनीकी दिग्गजों-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)-के लिए बुनियादी ढांचे को भी प्रभावित कर रहा है। साइरस जेन्सेन की हालिया वीडियो 'अमेरिका जस्ट मेड द ग्रेटेस्ट मिस्टेक ऑफ द 21वीं सेंचुरी' इस मुद्दे को बेबाकी से उजागर करती है।

अमेरिका, जो कभी नवाचार का प्रतीक था, अब अपनी ऊर्जा नीतियों में उल्टा चढ़ाव दिखा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में, अमेरिका ने अलास्का में 44 अरब डॉलर का प्राकृतिक गैस प्रोजेक्ट शुरू किया था। जनरल मोटर्स जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की योजनाओं को रद्द कर रही हैं, और वी8 गैस इंजनों पर लौट रही हैं। यहां तक कि ईवी खरीद पर टैक्स क्रेडिट भी समाप्त कर दिए गए हैं। यह सब तब हो रहा है, जब दुनिया जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है, और नवीकरणीय ऊर्जा ही भविष्य का रास्ता दिख रही है।

जेन्सेन की वीडियो में साफ कहा गया है कि अमेरिका की यह रणनीति अल्पकालिक लाभ के लिए है। तेल और गैस निर्यात बढ़ाने से तत्काल आर्थिक फायदा तो मिलेगा, लेकिन लंबे समय में यह वैश्विक बाजारों में पीछे धकेल देगा। अमेरिका ने 1950 के दशक में सोलर पैनल विकसित किए थे, 1970 के दशक में लिथियम-आयन बैटरी का आविष्कार किया, लेकिन रोनाल्ड रीगन जैसे नेताओं ने जिमी कार्टर के व्हाइट हाउस सोलर पैनल हटाकर इसकी उपेक्षा की। आज भी वही पुरानी सोच हावी है। परिणामस्वरूप, अमेरिका ईवी निर्यात में मात्र 12 अरब डॉलर और बैटरी निर्यात में 3 अरब डॉलर पर सिमट गया है, जबकि सोलर पैनल निर्यात तो महज 69 मिलियन डॉलर का है। यह भूल सिर्फ आर्थिक नहीं, भू-राजनीतिक भी है। वैश्विक दक्षिण-जो सौर और पवन ऊर्जा के 70 प्रतिशत स्रोतों और महत्त्वपूर्ण खनिजों के 50 प्रतिशत का नियंत्रण रखता है-अब नवीकरणीय ऊर्जा की ओर मुड़ रहा है। अमेरिका का जीवाश्म ईंधन पर फोकस इन देशों को अलग-थलग कर देगा जबकि चीन इनके साथ साझेदारी कर रहा है। वहीं, चीन ने स्वच्छ ऊर्जा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना लिया है। 2024 में चीन ने दुनिया के बाकी देशों से ज्यादा विंड टर्बाइन और सोलर पैनल लगाए। ईवी और बैटरी स्टोरेज में निवेश ने इसे वैश्विक नेता बना दिया है। पिछले साल चीन ने 38 अरब डॉलर के ईवी निर्यात किए, 65 अरब डॉलर की बैटरी बेचीं, और सोलर पैनल के 40

अरब डॉलर के निर्यात किए। स्वच्छ ऊर्जा पेटेंट में चीन के पास 7 लाख से ज्यादा हैं, जो दुनिया के आधे से अधिक हैं। जेन्सेन उद्धृत करते हुए बताते हैं कि चीन की सफलता का राज समन्वित प्रयास है। सीएल के सह-अध्यक्ष शिएन पैन कहते हैं, 'चीन को लंबे लक्ष्य पर प्रतिबद्ध करना मुश्किल है, लेकिन जब हम प्रतिबद्ध होते हैं, तो समाज के हर पहलू-सरकार, नीति, निजी क्षेत्र, इंजीनियरिंग-सभी एक ही लक्ष्य की ओर कड़ी मेहनत करते हैं।' यह दृष्टिकोण अमेरिका की छिटपुट नीतियों से बिल्कुल अलग है।

चीन अब वैश्विक बाजारों में फैल रहा है। ब्राजील, थाईलैंड, मोरक्को और हंगरी में ईवी और बैटरी फैक्टरियां बना रहा है। हंगरी में 8 अरब डॉलर का कारखाना, इंडोनेशिया में 11 अरब डॉलर का सोलर प्लांट-ये निवेश न केवल आर्थिक, बल्कि भू-राजनीतिक लाभ भी दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से जेन्सेन कहते हैं, 'ईवी बैटरी बनाने वाले देश दशकों तक आर्थिक और भू-राजनीतिक फायदे काटेंगे। अभी तक का एकमात्र विजेता चीन है।' पिछले 15 वर्षों में चीन ने बिजली उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। यह आंकड़ा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि एआई जैसी उभरती तकनीकें बिजली पर निर्भर हैं। चीन का स्वच्छ ऊर्जा निवेश न केवल पर्यावरण बचाएगा, बल्कि एआई क्रांति में भी नेतृत्व देगा। आरएमआई की 'पावरिंग अप द ग्लोबल साउथ' रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक दक्षिण के 70 प्रतिशत सौर-पवन संसाधन चीन की रणनीति से जुड़ रहे हैं। यह संघर्ष सिर्फ दो महाशक्तियों का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का है। वैश्विक दक्षिण-अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण एशिया-अब सस्ती और सतत ऊर्जा की तलाश में है। चीन ने इन देशों में सस्ते सोलर पैनल और ईवी तकनीक पहुंचाई है, जबकि अमेरिका के महंगे गैस प्रोजेक्ट इनके लिए बोझ साबित हो रहे हैं। परिणाम? ये देश चीन की ओर झुक रहे हैं।

भारत के संदर्भ में देखें तो यह चेतावनी स्पष्ट है। हमारी 'मेक इन इंडिया' और 'प्लेड्ज फॉर क्लाइमेट' पहलें स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित हैं, लेकिन चीन का वर्चस्व चुनौती है। भारत सोलर और विंड में प्रगति कर रहा है, लेकिन बैटरी और ईवी चिप्स में आयात पर निर्भरता बनी हुई है। यदि हम चीन की तरह समन्वित नीति नहीं अपनाते, तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में पीछे रह जाएंगे। अमेरिका की गलती से सबक लेते हुए, भारत को स्वदेशी नवाचार पर जोर देना चाहिए-जैसे लिथियम खनन और बैटरी रिसाइक्लिंग में निवेश। अमेरिका की यह भूल नई नहीं है। 20वीं सदी में जापान ने इलेक्ट्रॉनिक्स में अमेरिका को पीछे छोड़ा था क्योंकि अमेरिका ने अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता दी। आज चीन स्वच्छ ऊर्जा में वही कर रहा है। जेन्सेन की वीडियो एक चेतावनी है: जो देश बिजली उत्पादन में आगे होगा वही एआई और अगली औद्योगिक क्रांति जीतेगा। अमेरिका को अपनी नीतियां पलटनी होंगी-ईवी सब्सिडी बहाल करनी होंगी, नवीकरणीय अनुसंधान में निवेश बढ़ाना होगा। लेकिन समय कम है।

चीन का बढ़त 10 वर्षों का नहीं, बल्कि दशकों का हो सकता है। अमेरिका ने 21वीं सदी की सबसे बड़ी गलती कर दी है-जीवाश्म ईंधन पर दांव लगा कर स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य को गंवा दिया। चीन का उदय एक सबक है: समन्वित, दूरदर्शी नीतियां ही विजेता बनाती हैं। भारत जैसे देशों को इस दौड़ में शामिल होना चाहिए ताकि हम न केवल पर्यावरण बचाएं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता भी हासिल करें। समय आ गया है कि दुनिया एकजुट होकर स्वच्छ ऊर्जा को अपनाए, अन्यथा इतिहास हमें माफ नहीं करेगा।

(लेख में विचार निजी हैं)

हमारी 'मेक इन इंडिया' और 'प्लेड्ज फॉर क्लाइमेट' पहल स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित हैं, लेकिन चीन का वर्चस्व चुनौती है। भारत सोलर और विंड में प्रगति कर रहा है, लेकिन बैटरी और ईवी चिप्स में आयात पर निर्भर है। यदि हम चीन की तरह समन्वित नीति नहीं अपनाते, तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में पीछे रह जाएंगे। अमेरिका की गलती से सबक लेते हुए, भारत को स्वदेशी नवाचार पर जोर देना चाहिए-जैसे लिथियम खनन और बैटरी रिसाइक्लिंग में निवेश

Join This Channel:- https://t.me/AllNewsPaperPaid1

एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर पान का पत्ता

- भारतीय संस्कृति में पान का पत्ता शुभता, औषधीय गुणों और हमारी परंपरा का प्रतीक है। चाहे पूजा-पाठ हो, शादी-ब्याह या फिर धार्मिक आयोजन...हर शुभ मौके पर पान का पत्ता अहम होता है
- अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, पान के पत्ते में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। शोधों में पाया गया है कि पान का पत्ता शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है
- पान के पत्तों में पाए जाने वाले विटामिन सी और अन्य एंटी-ऑक्सिडेंट्स उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं

(मीडिया इनपुट्स)

प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए कि ग्यारह वर्षों में उनकी सरकार ने चीन से भारी मात्रा में दवाओं के आयात के अलावा रेयर अर्थ मैग्नेट्स, सेमीकॉन चिप्स के साथ ही खाद्यान्नों और सब्जियों के उत्पादन में जरूरी रसायनों और उर्वरकों के आयात पर निर्भरता कितनी कम की है...?

एम.के. वेणु, पत्रकार
@mkvenu1

सामाजिक सुधार का महापर्व

नवरात्र | डॉ. घनश्याम बादल

हिन्दू धर्म के सबसे बड़े पर्वों में से एक माने जाने वाले नवरात्र शुरू हो गए हैं। नौ दिन तक तन-मन की शुद्धि के लिए किए जाने वाले नवरात्र व्रत धार्मिक कर्मकांड मात्र नहीं हैं अपितु वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखते हैं, और प्रतीक रूप में गहरा संदेश देते हैं। नवरात्र का शाब्दिक अर्थ है 'नौ रातें' और यह देवी-शक्ति की उपासना का पर्व है। यह पर्व वर्ष में दो बार चैत्र और शारदीय नवरात्रि मनाया जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह शक्ति की आराधना और असुर शक्तियों पर विजय का प्रतीक है, परंतु यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि स्त्री-शक्ति, नैतिक मूल्यों और सामाजिक उत्थान का उत्सव भी है।

आज के समय में जब समाज महिला असमानता, सामाजिक भेदभाव, पर्यावरण संकट, नैतिक पतन आदि अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है, तब नवरात्र हमें अवसर देते हैं कि इन समस्याओं पर सामूहिक रूप से विचार करें और समाधान खोजें। नवरात्र की कथा के अनुसार, दुर्गा देवी ने महिषासुर जैसे राक्षस का वध कर देवताओं और मानवता को अत्याचार से मुक्ति दिलाई। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर लेते हैं, तो समाज में सकारात्मक शक्ति का उदय होता है। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। चाहे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष हो, अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना हो या व्यक्तिगत जीवन में नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय पाना। ये नौ देवियां धार्मिक प्रतिमाएं मात्र नहीं अपितु आधुनिक प्रतीक भी हैं। यदि इन्हें आधुनिक दृष्टि से देखें तो प्रत्येक देवी एक मानवीय मूल्य और सामाजिक आदर्श का प्रतीक है। एक नई दृष्टि के साथ इन देवियों के आधुनिक प्रतीको एवं अर्थों पर दृष्टि डालते हैं। **शैलपुत्री**-पर्वतपुत्री शैलपुत्री धरती और प्रकृति से जुड़ाव की प्रेरणा देती हैं। आज जब पर्यावरण संकट बढ़ रहा है, यह देवी हमें बताती हैं कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और टिकाऊ जीवन शैली अपनानी चाहिए। **देवी ब्रह्मचारिणी**-तपस्या और अनुशासन की प्रतीक हैं, जो संदेश देती हैं कि शिक्षा, आत्मसंयम और स्पष्ट जीवन-दृष्टि से ही प्रगति संभव है। **चंद्रघंटा**-साहस और वीरता की देवी हैं, जो सिखाती हैं कि समाज में अन्याय, अपराध और

शोषण के खिलाफ निडर होकर खड़ा होना चाहिए। **कुष्मांडा**-सृष्टि की रचयिता कुष्मांडा आधुनिक युग में रचनात्मकता, नवाचार और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। **स्कंदमाता**-मातृत्व और पालन-पोषण की प्रतीक हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि अगली पीढ़ी को अच्छे संस्कार देना हमारा कर्त्तव्य है। **कात्यायनी**-दमन और अन्याय के अंत की प्रतीक हैं, जो महिला सशक्तिकरण और न्यायपूर्ण समाज के लिए संघर्ष की प्रेरणा देती हैं। **कालरात्रि**-अंधकार का नाश करने वाली देवी कालरात्रि हमें अज्ञान, अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता फैलाने का संदेश देती हैं। **मां महागौरी**-पवित्रता और शांति की प्रतीक हैं, और समाज में स्वच्छता, समानता और मानसिक शांति का आदर्श प्रस्तुत करती हैं। **सिद्धिदात्री** जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ज्ञान, उपलब्धि और परिपूर्णता की प्रतीक देवी हैं, जो प्रेरित करती हैं कि हम कौशल और ज्ञान से आत्मनिर्भर और समर्थ बनें। इन नौ देवियों को यदि हम नौ सामाजिक स्तंभ मानें तो नवरात्रि हमें आत्म सुधार और समाज सुधार की एक पूरी रूपरेखा प्रदान करती है।

सामाजिक सुधार की दृष्टि से भी नवरात्र का महत्त्व कम नहीं है। नवरात्रि का मूल ही स्त्री-शक्ति की उपासना है। नवरात्र में हम संकल्प लें कि बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना है, यह संकल्प ही इस पर्व को सार्थक बना सकता है। नवरात्रि आत्म शुद्धि का समय है। अवसर है कि हम अंधविश्वास, जातिवाद, छुआछूत, नशाखोरी और सामाजिक भेदभाव जैसी बुराइयों को समाप्त करने की प्रतिज्ञा लें। प्रकृति अपने आप में देवी का स्वरूप है। अतः नवरात्र में वृक्षारोपण, प्लास्टिक-मुक्त अभियान और जल-संरक्षण का संदेश समाज को दिया जा सकता है। पूजा में इको-फ्रेंडली सामग्री का प्रयोग करके यह पर्व पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकता है। नवरात्रि में सामूहिक आयोजन जाति, धर्म और वर्ग भेद मिटाने के अवसर होते हैं। ऐसे में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा सकते हैं, जो समाज को जोड़ने का काम करें। नवरात्रि में व्रत-उपवास का अपना ही महत्त्व है। इसे केवल धार्मिक नियम न मान कर स्वस्थ जीवन शैली, नशा-मुक्ति और मानसिक शांति का अभ्यास बनाया जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि नवरात्रि धार्मिक पर्व मात्र नहीं है, बल्कि आत्म-संयम, सामाजिक जागरूकता और परिवर्तन का अवसर है। यदि हम नवरात्रि को सामाजिक सुधार की दृष्टि से मनाएं तो यह पर्व महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता का सशक्त माध्यम बन सकता है।

मौन | श्रीराम शर्मा आचार्य

मनुष्य जो कुछ सोचता और विचारता है, उसे वाणी के माध्यम से व्यक्त करता है। मनुष्य ने अपने विचारों और भावों को सर्वप्रथम वाणी के माध्यम से व्यक्त करना सीखा। वाणी और मस्तिष्क का सीधा संबंध है, विशेषतः अभिव्यक्ति के लिए तो सबके लिए वही सर्वाधिक सुलभ है। इसलिए मानसिक शक्तियों का बहिर्गमन मुख्यतः वाणी द्वारा होता है। अहंता, मोह-तृष्णा, वासना आदि द्वारा तो मानसिक शक्तियां अंदर-अंदर ही जलती रहती हैं। वाणी के माध्यम से उनकी ज्वालाएं बाहर भी धधकने लगती हैं। इसलिए वाणी के संयम को मानसिक संयम के साथ भी जोड़े रखा गया है। विचारों पर संयम कर लिया जाए और वाणी को असंयमित ही रहने दिया जाए तो विचार संयम का आधार भी लड़खड़ा उठता है। हमेशा कुछ न कुछ कहते रहने की आदत व्यक्ति को कोई विषय ढूंढ़ने के लिए भी बाध्य करती है। इसलिए विचार संयम के साथ-साथ वाणी का संयम भी अनिवार्य है। वरन वाणी का संयम-मानसिक संयम का ही अंग है। मानसिक संयम के साथ वाणी के संयम की महत्ता को भी समझना चाहिए और उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। बोलने में बड़ी शक्ति खर्च होती है। एक घंटे लगातार बोलने पर व्यक्ति इतना अधिक थक जाता है कि आठ घंटे तक शारीरिक श्रम किया जाता तो थकान नहीं आती। कारण वाणी का सीधा संबंध मस्तिष्क से है, और काम तो हाथ-पैर से भी किए जा सकते हैं, उन्हें करते समय ध्यान कहीं और भी रह सकता है, पर बोलते समय सारा ध्यान बोलने पर ही रखना पड़ता है। बेहोश होने अथवा मरने से पूर्व अन्य अंग बाद में निष्क्रिय होते हैं, सबसे पहले वाणी ही अवरुद्ध होती है, क्योंकि मस्तिष्क जैसे-जैसे शिथिल या अचेत होता जाता है, वाक इंद्रिय वैसे-वैसे असमर्थ होती जाती है। शरीर में जो शक्ति और मस्तिष्क में जो चेतना बची रहती है, वह इतनी अपर्याप्त रहती है कि कुछ शब्द भी नहीं बोले जा सकते। यद्यपि वह शक्ति अन्य अंगों को हिलाने-डुलाने के लिए पर्याप्त रहती है। मरते हुए कोई बात सुन कर उत्तर सिर हिला कर ही दे पाते हैं-कुछ कह पाना अधिकांश लोगों के लिए कठिन ही होता है। शारीरिक क्रिया-कलाप में जिन कार्यों में सर्वाधिक मानसिक शक्ति खर्च होती है, वह वाणी ही है। इसीलिए मौन की गणना मानसिक तप से की गई है।

रीडर्स मेल

Join This Channel:- https://t.me/AllNewsPaperPaid1

फ्रीलांसिंग का बढ़ता चलन

आजकल फ्रीलांसिंग युवाओं के बीच बहुत पसंदीदा तरीका बन गया है पैसे कमाने का। पहले लोग नौकरी पर ही भरोसा करते थे, लेकिन अब कई युवा पारंपरिक नौकरी छोड़ कर फ्रीलांसिंग अपना रहे हैं। इसको अपनाने की सबसे बड़ी वजह है कि इसमें ऑफिस जाना नहीं पड़ता और आप अपनी स्किल के अनुसार काम करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग युवाओं को इसलिए ज्यादा पसंद कि अपनी मर्जी से काम करते हैं। चाहे सुबह करें या शाम को, जितना चाहे उतना काम करें। युवा अपनी पढ़ाई और अन्य कामों के साथ फ्रीलांसिंग को आसानी से जोड़ रहे हैं। इंटरनेट की वजह से काम ढूंढ़ना पहले से आसान हो गया है। कई वेबसाइट्स और ऐप्स हैं, जहां युवा अपने हुनर के मुताबिक काम पा सकते हैं। चाहे लेख लिखना हो, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो या वेबसाइट बनाना हो, हर तरह के काम ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कहा जा सकता है कि युवा फ्रीलांसिंग को कमाई और करियर बनाने का नया जरिया मान रहे हैं। यह सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं, बल्कि अपना हुनर निखारने और भविष्य को मजबूत करने का भी मौका है।

महेश चमोला, देहरादून

आदेश की धज्जियां उड़ाई

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए देश की राजधानी में सुप्रीम कोर्ट के सामने ही बिना सुरक्षा उपक्रमों के मैनुअल तरीके से गटर की सफाई का मामला सामने आया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है, और भविष्य के लिए चेतावनी दी है। राज्यों से ऐसी घटनाएं आती रही हैं जिन पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हाल के एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में देश की राजधानी में 16 सितम्बर को न्यू अशोक विहार में सीवर लाइन में एक सफाईकर्मी मृत और तीन बेहोशी की हालत में पाए गए थे। सरकार एवं संस्थाओं को सोचना चाहिए कि इस कार्य के लिए मनुष्य का प्रयोग न किया जाए जबकि वैकल्पिक साधन मौजूद हैं। मेरा मानना है कि सफाईकर्मियों में जागरूकता भी जरूरी है।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

आलोचना से सबक लेना जरूरी

मनुष्य का जीवन ऐसी यात्रा है, जिसमें हर कदम पर कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। जन्म से मृत्यु तक हमारा सीखना कभी रुकता नहीं। नई चीजें सीखने के लिए समय, धैर्य और खुले मन की जरूरत होती है। जीवन में कई बार हमें दूसरों की सलाह, आलोचना या प्रतिक्रिया मिलती है। यदि हम इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करें तो यह हमारे व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का मौका देती है, लेकिन अक्सर लोग प्रतिक्रिया को गलत समझ लेते हैं, जिससे रिश्तों में दरार आ जाती है। घर-परिवार में भी छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो जाता है। इसका मुख्य कारण है कि हम सलाह को अपने खिलाफ समझ लेते हैं। हमें सोचना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारा भला चाहता है। सलाह को खुले मन से स्वीकारने से हम बेहतर इंसान बनते हैं। कमियों को स्वीकार कर सुधारने से काम में सफलता मिलती है। मनुष्य पूर्ण नहीं होता। हर किसी में कुछ कमियां होती हैं। इन्हें पहचान कर सुधार करना ही जीवन का सही रास्ता है। जो व्यक्ति हर पल नया सीखने के लिए तैयार रहता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है।

दर्शन सिंह, मेरठ

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा ● राष्ट्रीयता ● कर्त्तव्य ● समर्पण

वर्ष-35, अंक 39

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **जिया कादरी** द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित। । **स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र*** ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, **दूरभाष - नोएडा प्रेस** 0120-2444755, 2444756 **फैक्स** - 2550750

आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

एच-1 बी वीजा का खौफ

भारत के लिए अब यह सोच पाना बहुत मुश्किल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी नीतियां उसके हक में हैं अथवा विरोध में? श्री ट्रम्प हर दूसरे दिन भारत के बारे में अपने विचार जिस तरह बदलते रहते हैं उससे यही लगता है कि वह भारत के साथ अपने देश के सम्बन्धों में मित्र भाव को दूसरे पायदान पर रखते हैं। उनकी नीतियां बताती हैं कि अमेरिका के आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय स्थानीय अमेरिकी नागरिकों के रोजगार के लिए नुक्सानदेह साबित हो रहे हैं। वास्तव में अमेरिका उनके पुन: सत्तारूढ़ होने के बाद जिस तरह की आर्थिक नीतियां अपना रहा है वे पूरी तरह अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के विरुद्ध हैं और संरक्षणवादी हैं जिन्हें कथित अमेरिकी राष्ट्रवाद की चाशनी में भीगो कर परोसा जा रहा है। भारत के आयात पर शुल्क दर 50 प्रतिशत बढ़ाने के बाद श्री ट्रम्प ने एच-1बी वीजा की फीस को बढ़ाकर सीधे ही एक लाख डॉलर (88 लाख रुपये) वार्षिक कर दिया है जिसका सबसे प्रतिकूल असर भारत से नौकरी के लिए जाने वाले आईटी क्षेत्र के तकनीकी युवाओं पर पड़ेगा। यह कदम ट्रम्प ने तब उठाया है जब एक दिन बाद ही भारत के वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयल शुल्क दरों के बारे में बातचीत करने अमेरिका जा रहे हैं।

वीजा फीस बढ़ाने का मतलब यह होगा कि जो कम्पनियां अमेरिका में विदेशी आईटी इंजीनियरों व अन्य तकनीकी कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं उन्हें प्रति कर्मचारी के हिसाब से यह धनराशि अमेरिकी सरकार को देनी पड़ेगी। फिलहाल वीजा फीस दो हजार डॉलर से लेकर छह हजार डॉलर वार्षिक की है। वीजा तीन साल के लिए वैध रहता है जिसकी इतनी ही अवधि तीन साल बाद और बढ़ाई जा सकती है। इस वीजा के तहत अमेरिका में नौकरी करने जाने वालों में सबसे ज्यादा भारतीय 72 प्रतिशत होते हैं। अक्तूबर 2022 और सितम्बर 2023 के दरम्यान चार लाख से अधिक भारतीयों को यह वीजा मिला था। भारत की आईटी क्षेत्र की टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो व एचसीएल कम्पनियों ने लगभग 20 हजार कर्मचारियों के लिए यह वीजा लिया हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका सरकार का कहना है कि नई वीजा फीस के लागू होने से अमेरिकी नागरिकों को लाभ होगा और उनके लिए नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। तकनीकी क्षेत्र में विदेशों से आने वाले युवा अपेक्षाकृत कम वेतन पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं जबकि अमेरिकी नागरिकों का वेतन अधिक होता है। सामान्यत: विदेशों या भारत से गये मध्यम क्षेणी के कर्मचारियों की तनख्वाह 66 हजार डॉलर वार्षिक की होती है जबकि आम अमेरिकी का वेतन 75 हजार डॉलर वार्षिक होता है।

> **अमेरिकी सरकार के अनुसार विज्ञान व टैक्नोलॉजी सम्बन्धित क्षेत्र में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों की संख्या में पिछले दो दशकों में भारी इजाफा हुआ जबकि इस क्षेत्र की विकास दर इतनी अधिक नहीं रही। वर्ष 2000 से 2019 के बीच विदेशी टेक-कर्मचारियों की संख्या बढ़कर दुगनी से भी अधिक हो गई जबकि इस क्षेत्र की विकास दर 44 प्रतिशत के आसपास रही। 2000 में जहां इनकी संख्या 12 लाख थी वहीं 2019 में बढ़कर 25 लाख हो गई। इस दौरान विदेशी कर्मचारियों की इस क्षेत्र में भागीदारी 17.7 प्रतिशत से बढ़कर 26.1 प्रतिशत हो गई।**

अमेरिकी सरकार के अनुसार विज्ञान व टैक्नोलॉजी सम्बन्धित क्षेत्र में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों की संख्या में पिछले दो दशकों में भारी इजाफा हुआ जबकि इस क्षेत्र की विकास दर इतनी अधिक नहीं रही। वर्ष 2000 से 2019 के बीच विदेशी टेक-कर्मचारियों की संख्या बढ़कर दुगनी से भी अधिक हो गई जबकि इस क्षेत्र की विकास दर 44 प्रतिशत के आसपास रही। 2000 में जहां इनकी संख्या 12 लाख थी वहीं 2019 में बढ़कर 25 लाख हो गई। इस दौरान विदेशी कर्मचारियों की इस क्षेत्र में भागीदारी 17.7 प्रतिशत से बढ़कर 26.1 प्रतिशत हो गई। इसके अनुसार यह संख्या बढ़ने की असली वजह एच-1बी वीजा का दुरुपयोग है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि अकेले आईटी क्षेत्र में कार्यरत कम्पनियों ने इस वीजा सुविधा का सर्वाधिक दुरुपयोग किया जिससे इस क्षेत्र के अमेरिकी कर्मचारियों को सबसे ज्यादा नुक्सान उठाना पड़ा और उन्हें पर्याप्त नौकरियां नहीं मिलीं। सरकार के अनुसार इस वीजा प्रणाली के तहत अमेरिका आने वाले विदेशी कर्मचारियों की संख्या में पिछले कुछ सालों में भारी इजाफा हुआ। 2003 में जहां इस क्षेत्र में कुल विदेशी कर्मचारी 32 प्रतिशत के लगभग थे वहीं पिछले पांच सालों में इनकी संख्या बढ़कर 65 प्रतिशत हो गई।

यह सर्वविदित तथ्य है कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक भारतीय युवा इंजीनियर तकनीशियन ही लगे हुए हैं। इसके साथ ही आईटी आउटसोर्सिंग कम्पनियां वीजा का उपयोग अपना मुनाफा या बचत बढ़ाने में करती हैं। इससे अमेरिकी कर्मचारियों के रोजगार को नुक्सान हो रहा है क्योंकि उन्हें कम वेतन पर काम करने वाले विदेशी कर्मचारी मिल जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस के सचिव विल शार्ट के अनुसार यह वीजा कार्यक्रम विदेशों से उच्चतम स्तर की प्रतिभा को अमेरिका में लाने के लिए शुरू किया गया था परन्तु इसका लाभ दूसरे तरीकों से लिया जाने लगा। अत: वीजा की फीस एक लाख डॉलर करने का मूल लक्ष्य यह है कि केवल ऊंची प्रतिभा के विशेषज्ञ ही अमेरिका में काम करने के लिए आयें जिससे सामान्य अमेरिकी कर्मचारियों का नुक्सान न हो लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यदि भारत के सन्दर्भ में देखें तो बहुत निराशाजनक स्थिति उभरती है। अमेरिका में सामान्य मध्यम श्रेणी भारतीय कर्मचारी की वार्षिक तनख्वाह 66 हजार डॉलर वार्षिक होगी। अत: उसके लिए एक लाख डालर वार्षिक की फीस नियोजक कम्पनियां देना क्यों पसन्द करेंगी? इससे जाहिराना तौर पर नियोजक भारतीयों को नौकरियां देने से परहेज करेंगे। ट्रम्प के सिद्धान्त के अनुसार इस कदम से अमेरिकियों को प्रत्यक्षत: लाभ होगा।

अब सवाल यह है कि क्या ट्रम्प यह सब अमेरिकी मतदाताओं को रिझाने के लिए कर रहे हैं? उनकी रिपब्लिकन पार्टी रूढ़ीवादी राष्ट्रवादी पार्टी मानी जाती है। वह अपने कार्यकाल की पूर्व अवधि 2016 में भी एच-1बी वीजा स्कीम की कटु आलोचना कर चुके हैं। वह शुरू से ही इसे अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध मानते रहे हैं। अत: इस मुद्दे पर उनके साथ अमेरिका का जन समर्थन हो सकता है। परन्तु अमेरिका आर्थिक वैश्वीकरण का अलम्बरदार भी रहा है अत: उसकी जिम्मेदारी है कि वह संरक्षणवादी कदमों से बचे। क्योंकि ऐसा करके इस क्षेत्र में वह अपनी अग्रणी भूमिका से हाथ धो बैठेगा। मगर ट्रम्प का ऐसा रुख भारत के हित में किसी भी दृष्टि से नहीं है। अत: भारत को अपने राष्ट्रीय हित सुरक्षित रखते हुए ही इस मुद्दे पर अपनी ठोस प्रतिक्रिया देनी होगी।

राम और श्रवण के देश में ...

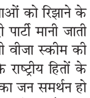
गीता पाढा

"हम अपने बच्चों को आगे बढ़ना तो सीखा रहे हैं,
पर अफसोस घर, परिवार और
रिश्तेदारों से नाते टूटते जा रहे हैं,,
आज की पीढ़ी को इतना मतलबी और महत्वाकांक्षी बना रहे हैं,
कि एक वक्त आने पर उन्हें माता पिता भी अपनी तरक्की में बाधा नजर आ रहे हैं,,
इसलिए राम और श्रवण के देश में भी वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं,
और जीवन की संध्या में लाखों बुजुर्ग स्वयं को असहाय पा रहे हैं...।।"

अब टूट चुका है छज्जू का चौबारा

डा. चन्द्र त्रिखा
chandertrikha@gmail.com

कभी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक कहावत हर भारतीय की विरासत होती थी।

'जो सुख छज्जू के चौबारे
ओह बलख न बुखारे'

जी हां, वही छज्जू का चौबारा अब टूट चुका है और उसके खण्डहर ही शेष बचे हैं। यह लाहौर के मेयो अस्पताल के पास स्थित था और इसे लाहौर का एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता रहा है। यह चौबारा छज्जू भगत नामक व्यक्ति का था जो मुगल बादशाह शाहजहां के समय में रहते थे। उन्होंने अपना व्यापारिक जीवन छोड़कर भक्ति और वैराग्य का जीवन अपना लिया था। बाद में उनके अनुयायियों ने लाहौर में उनकी समाधि स्थल को चौबारे के नाम से प्रसिद्ध किया जो पूरे लाहौर में चर्चित हुआ। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में चौबारे के महत्व को समझते हुए छज्जू भगत का मंदिर, यात्रियों के लिए कमरे, तालाब और सुंदर बाग बनवाकर इसकी शोभा बढ़ाई थी। आज भी छज्जू का चौबारा एक चर्चित स्थल तो है मगर अब इसके खण्डहर ही बचे हैं जो लाहौर के मेयो अस्पताल के पास स्थित है।

एक तरफ हो जाओ !

लाहौर में यह चौबारा था। उसका नाम था 'छज्जू का चौबारा'। पंजाबी जीवनशैली में लोकोक्ति चर्चित हुई कहावत थी- 'जो सुख छज्जू दे चौबारे, न बलख न बुखारे' अर्थात छज्जू के चौबारे के सुख के आगे बल्क व बुखारे का सुख भी फीका पड़ जाता हे। छज्जू भगत का असली नाम छज्जू राम भाटिया था। वे लाहौर के रहने वाले थे। मुगल बादशाह जहांगीर के समय वे सोने का व्यापार किया करते थे। सन् 1640 में उनके निधन के बाद जब भंगी मिसल के सरदारों का वक्त आया तो उनकी दुकान और विशाल डेरे की जगह पर मंदिर व धर्मशाला बनवाई गई। इस समय निर्माण को नाम मिला 'छज्जू का चौबारा' महाराजा रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में यहां पर यात्रियों के लिए नए कमरे, तालाब और सुंदर बगीचे बनवाकर उसकी शोभा में चार चांद लगा दिए।

छज्जू भगत की कहानी भी बेमिसाल है। वह व्यापारी थे। मगर उनका व्यापार में मन अधिक नहीं लगता था। वैराग्य प्रवृत्ति के थे। एक दिन गली में से जा रहे थे। मेहतर गली साफ करती हुई चलने वालों से कह रही थी 'एक तरफ हो जाओ' उनका कहना ठीक था। अन्यथा कूड़े में पैर पड़ जाएगा। उनकी बात सुनकर छज्जू को आत्मबोध हुआ। एक वैराग्यवान के लिए व्यापार और ईश्वर भक्ति एक साथ नहीं चल सकती। उसने अपना कारोबार बेटों को सौंपा और चौबारे पर बैठकर भक्ति करने लग गया। दूर-दूर से लोग उसके सत्संग में आने लगे। उसका चौबारा पूरे लाहौर में प्रसिद्ध हो गया। इसका मुख्य कारण एक ही था। छज्जू सांसारिक मोह त्याग कर एक

तरफ हो गया था। सांसारिक मोह के चक्कर में फंस कर वह अपने आत्मा के साथ न्याय नहीं कर पा रहा था। आज भी छज्जू के यह जीवनी संदेश हम आर्यों के लिए इतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उस काल में थे।

लाला छज्जू राम का चौबारा पूरे महानगर की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बन गया था। यह चौबारा, इधर-उधर से आने व जाने वाले सूफी फकीरों की आरामगाह बन गया था। यह एक दो मंजिला मकान था। नीचे की मंजिल पर एक हिस्से में छज्जू राम की स्वर्णकारी की दुकान थी। दूसरे हिस्से में परिवार रहता था। छज्जू राम नाम का स्वर्णकार था, मगर उस काम में कुछ ज्यादा ही ईमानदारी की वजह से ज्यादा ग्राहक नहीं आ पाते थे लेकिन छज्जू राम भाटिया अपने सीमित काम से ही बेहद संतुष्ट था। लाहौर के बहुत से ऐसे परिवार थे, जो सोने के जेवरों व खरीद-बिक्री के मामले में उसी पर भरोसा करते। भरोसा करने वालों में बड़े-बड़े घरों की बेगमें भी शामिल थीं। बुर्का पहनकर आतीं थीं, मगर छज्जू राम की दुकान में प्रवेश करते ही बुर्का उतार देतीं। छज्जू राम का एक सेवक सबको सबसे पहले शरबत पेश करता और फिर पानदान उनके आगे सरका देता।

'छज्जू का चौबारा' इन दिनों एक बार फिर चर्चा में है। लाहौर के अनारकली बाज़ार के एक कोने में स्थित यह 'चौबारा' जो अब तक एक कहावत तक ही सीमित था, अब उस पर बाकायदा शोध कार्य हो रहे हैं। अब इसे वहां का पुरातत्व विभाग संरक्षित स्थल घोषित करने जा रहा है। कहावत इतनी ही थी, जो सुख छज्जू दे चौबारे ओह न बलख, न बुखारे, अब नए शोध ने उस कहावत को जीवित कर दिखाया है।

पड़ौसी देश के चंद बुद्धिजीवियों की बदौलत लाहौर स्थित 'छज्जू का चौबारा' नए संदर्भ में ध्वस्त होने से बच गया है। मगर अब यह खण्डहरों में बदल चुका है। अब अनारकली बाजार लाहौर के अधिकांश लोग इस बात पर यकीन करने लगे हैं कि जिस शख्स ने शाहजहां के वक्त में सूफी फकीरों और दरवेशों की पूरे दिल से खिदमत की हो, उसके ऐतिहासिक 'चौबारे' को कैसे कुछ सनकी लोगों के विरोध के मद्देनज़र नष्ट किया जा सकता है। एक मुद्दत से पश्चिमी व पूर्वी पंजाब के लोग अक्सर यह कहावत दोहराते रहे हैं कि 'जो सुख छज्जू दे चौबारे, ओह न बलख न बखारे। नई नस्ल के दोस्तों के लिए यह दोहरा देना ज़रूरी है कि छज्जू राम कौन था?

छज्जू मूल रूप से एक जौहरी था। पूरा नाम था छज्जू राम भाटिया। उसका एक विशाल आवास था। यह अनारकली बाज़ार लाहौर के एक कोने पर उस हिस्से में था जहां अब एक मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का निर्माण चल रहा है। विशाल हृदय वाला और अध्यात्म प्रवृत्ति वाला छज्जू राम भाटिया, अपनी दुकान के मुनाफे का दसवां भाग नियमित रूप से अलग रख देता था। इस दशमांश से छज्जू का चौबारा फकीरों, दरवेशों और संतों की टोलियों से बारौनक बना रहता था। अलग-अलग दरगाहों और दूरदराज़ के मंदिरों-गुरुओं के यात्री वही विश्राम करते थे।

लाहौर के अनारकली रोड पर इसी 'छज्जू का चौबारा' था। छज्जू उन दिनों लाहौर का एक प्रमुख जौहरी था। पूरा नाम था लाला छज्जू राम भाटिया। दो मंज़िले-आवास की पहली मंज़िल पर उसका कारोबार था। दूसरी मंज़िल पर परिवार। उसी की छत पर उसने बनाया था 'छज्जू का चौबारा'। इस चौबारे को फकीरों के डेरे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस चौबारे पर फकीरों की धूनी भी रमती थी और भजन-कीर्तन व सूफियों का सेमा-नृत्य भी चलता था। छज्जू को अध्यात्म से ऐसी 'लौ' लगी कि धीरे-धीरे ज़्यादा वक्त जप-तप में बिताने लगा। उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा फकीरों, भक्तों व ज़रूरतमंद लोगों पर खर्च करना शुरू किया। शीघ्र ही उसे 'छज्जू-भगत' कहा जाने लगा। लोग अक्सर कहते, इस चौबारे पर आकर रूहानी सुकून मिलता था। सभी सुख मिल जाते। भूखे को रोटी, नंगे को कपड़ा और अगले सफर पर रवाना होने से पहले खाने-पीने की रसद और कुछ सिक्के ताकि 'बवक्ते ज़रूरत' काम आएं।

मन में जिज्ञासा थी। उस चौबारे को ढूंढा जाए। पुराने रिकार्ड, किताबें व पुराने लोगों को खंगाला तो दिलचस्प ऐतिहासिक गवाहियां खुल गईं। लाहौर में बहुत कुछ है जो हमें विरासत से जोड़ता है। शहर के मेयो अस्पताल के साथ ही मौजूद है इस चौबारे के खण्डहर।

छज्जू राम भाटिया उर्फ छज्जू भगत, दरअसल शाहजहां के समय में हुआ था। उसकी उम्र व जन्म वर्ष का तो पता नहीं चलता, लेकिन उसने आखिरी सांस 1696 में ली थी। उसकी मृत्यु भी रहस्यमय रही थी। किंवदंती यही है कि मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व वह चौबारे के कोने में स्थित अपनी तप-गुफा में चला गया था और बाद में उसका कोई अता पता नहीं चला। उसका 'चौबारा' फकीरों का डेरा बन गया। फकीर दिन में वहां धमाल नृत्य करते और तालियों के बीच गाते, 'जो सुख छज्जू दे चौबारे, ओह बलख न बुखारे।'

प्राप्त ऐतिहासिक दस्तावेज़ों के अनुसार महाराजा रणजीत सिंह अपने शासनकाल में यहां अक्सर फकीरों से मिलने आ जाया करते थे। वहां उन्होंने 'छज्जू भगत' की स्मृति में एक मंदिर भी बनवा दिया था और मंदिर के लिए व फकीरों के लिए हर माह एक निश्चित राशि भी 'दरबार' से भिजवाते रहे। अब भी उन बचे-खुचे खंडहरों के सामने शीश नवाने लोग हर मंगलवार और वीरवार आ जाते हैं।

लाहौर के मेयो अस्पताल के साथ ही बना है 'शम्स शहाबुद्दीन तीमारदारी घर'। खण्डहर कायम हैं। मेयो अस्पताल वालों ने फैसला किया कि इस खंडहर को तोड़ दिया जाए ताकि अस्पताल का विस्तार हो सके। मगर लोगों के विरोध और इतिहास व मीडिया से जुड़े लोगों की कड़ी आपत्तियों के बाद तोड़ने का फैसला स्थगित कर दिया गया। हालांकि अब जो भी प्रयास हो रहे हैं, सिर्फ खण्डहरों को बचाने के लिए हो रहे हैं। इस संबंध में एक इतिहासकार सुरेंद्र कोछड़ ने भारत सरकार से भी दखल देने की अपील की थी। उसकी दलील है कि यह 'विरासत की सम्पदा' है और इसे कानूनी रूप में भी तोड़ा नहीं जा सकता। पुराने लाहौर में इस जगह के खंडहर भी अब बोलने लगे हैं। अब पुराने चौबारे के काल्पनिक चित्र भी बनाए जाने लगे हैं और एक मुस्लिम इतिहासकार लतीफ ने इन चित्रों को पुरानी जानकारी के आधार पर छपाया भी है।

इस मंदिर बनाम दरगाह के साथ ही उदासीन सम्प्रदाय के एक संत बाबा प्रीतम दास का छोटा सा मंदिर भी था। बाबा प्रीतम दास वही संत थे, जिन्होंने अपने समय के चर्चित संत बाबा भुम्मन शाह को दीक्षा दी थी। बाबा भुम्मन शाह आज भी सिरसा, फाज़िल्का, अबोहर, फतेहाबाद आदि में पूरे कम्बोज समुदाय में पूजे जाते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि औरंगजेब के शासन में दो स्थानों को विशेष महत्व दिया जाता था। एक स्थान था 'पीर ऐन-उल-कमाल' का मकबरा और दूसरा 'छज्जू भगत का मंदिर'। अब इस विलक्षण स्थान के आसपास अस्पताल के कर्मचारियों के आवास भी बन गए हैं। वहां तक पहुंचने के लिए इन क्वार्टरों के बीच संकरे रास्तों से गुज़रना होता है। मगर निस्बत रोड व रेलवे रोड के मध्य में स्थित इन खंडहरों पर अब इबादत होती रहती है। हालांकि वे दिन गए जब बात-बात पर कह दिया जाता था-

'जो सुख छज्जू दे चौबारे
ओह, बलख न बुखारे'

एक सुखद बात है कि छज्जू का नाम व 'कल्चर' बचाने के लिए पाकिस्तान का सोशल मीडिया व वहां के कुछ बुद्धिजीवी पूरी तरह सतर्क रहे हैं और मोर्चे पर डटे रहे हैं, यह कहते हुए कि यह हमारा विरसा है।

स्वच्छ ऊर्जा की दौड़ में चीन का बढ़ता वर्चस्व!

Join This Channel:- https://t.me/AllNewsPaperPaid1

विनीत नारायण
www.vineetnarain.net

आज की दुनिया में ऊर्जा नीतियां सिर्फ आर्थिक निर्णय नहीं हैं, बल्कि वैश्विक वर्चस्व की कुंजी हैं। जब अमेरिका तेल और गैस पर दांव लगाकर पुरानी राह पर लौट रहा है, वहीं चीन स्वच्छ ऊर्जा क्रांति को गति दे रहा है। यह विरोधाभास न केवल आर्थिक असंतुलन पैदा कर रहा है, बल्कि भविष्य की तकनीकी दिग्गजों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के लिए बुनियादी ढांचे को भी प्रभावित कर रहा है। साइरस जेन्सेन की हालिया वीडियो 'अमेरिका जस्ट मेड द ग्रेटेस्ट मिस्टेक ऑफ द 21वीं सेंचुरी' इस मुद्दे को बेबाकी से उजागर करती है। अमेरिका, जो कभी नवाचार का प्रतीक था, अब अपनी ऊर्जा नीतियों में उल्टा चढ़ाव दिखा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में, अमेरिका ने अलास्का में 44 अरब डॉलर का प्राकृतिक गैस प्रोजेक्ट शुरू किया था। जनरल मोटर्स जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की योजनाओं को रद्द कर रही हैं और वी8 गैस इंजनों पर लौट रही हैं। यहां तक कि ईवी खरीद पर टैक्स क्रेडिट भी समाप्त कर दिए गए हैं। यह सब तब हो रहा है जब दुनिया जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है और नवीकरणीय ऊर्जा ही भविष्य का रास्ता दिख रही है।

जेन्सेन की वीडियो में साफ कहा गया है कि अमेरिका की यह रणनीति अल्पकालिक लाभ के लिए है। तेल और गैस निर्यात बढ़ाने से तत्काल आर्थिक फायदा तो मिलेगा, लेकिन लंबे समय में यह वैश्विक बाजारों में पीछे धकेल देगा। अमेरिका ने 1950 के दशक में सोलर पैनल विकसित किए थे, 1970 के दशक में लिथियम-आयन बैटरी का आविष्कार किया, लेकिन रोनाल्ड रीगन जैसे नेताओं ने जिमी कार्टर के व्हाइट हाउस सोलर पैनल हटाकर इसकी उपेक्षा की। आज भी वही पुरानी सोच हावी है। परिणामस्वरूप, अमेरिका ईवी निर्यात में मात्र 12 अरब डॉलर और बैटरी निर्यात में 3 अरब डॉलर पर सिमट गया है, जबकि सोलर पैनल निर्यात तो महज 69 मिलियन डॉलर का है।

यह भूल सिर्फ आर्थिक नहीं, भू-राजनीतिक भी है। वैश्विक दक्षिण जो सौर और पवन ऊर्जा के 70 प्रतिशत स्रोतों और महत्वपूर्ण खनिजों के 50 प्रतिशत का नियंत्रण रखता है अब नवीकरणीय ऊर्जा की ओर मुड़ रहा है। अमेरिका का जीवाश्म ईंधन पर फोकस इन देशों को अलग-थलग कर देगा, जबकि चीन इनके साथ साझेदारी कर रहा है। वहीं, चीन ने स्वच्छ ऊर्जा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना लिया है। 2024 में चीन ने दुनिया के बाकी देशों से ज्यादा विंड टर्बाइन और सोलर पैनल लगाए। ईवी और बैटरी स्टोरेज में निवेश ने इसे वैश्विक नेता बना दिया है। पिछले साल चीन ने 38 अरब डॉलर के ईवी निर्यात किए, 65 अरब डॉलर की बैटरी बेचीं, और सोलर पैनल के 40 अरब डॉलर के निर्यात किए। स्वच्छ ऊर्जा पेटेंट में चीन के पास 7 लाख से ज्यादा हैं, जो दुनिया के आधे से अधिक हैं।

जेन्सेन उद्धृत करते हुए बताते हैं कि चीन की सफलता का राज समन्वित प्रयास है। सीएल के सह-अध्यक्ष शिएन पैन कहते हैं, "चीन को लंबे लक्ष्य पर प्रतिबद्ध करना मुश्किल है, लेकिन जब हम प्रतिबद्ध होते हैं, तो समाज के हर पहलू सरकार, नीति, निजी क्षेत्र, इंजीनियरिंग सभी एक ही लक्ष्य की ओर कड़ी मेहनत करते हैं।" यह दृष्टिकोण अमेरिका की छिटपुट नीतियों से बिल्कुल अलग है।

चीन अब वैश्विक बाजारों में फैल रहा है। ब्राजील, थाईलैंड, मोरक्को और हंगरी में ईवी और बैटरी फैक्टरियां बना रहा है। हंगरी में 8 अरब डॉलर का कारखाना, इंडोनेशिया में 11 अरब डॉलर का सोलर प्लांट, ये निवेश न केवल आर्थिक, बल्कि भू-राजनीतिक लाभ भी दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से जेन्सेन कहते हैं, "ईवी बैटरी बनाने वाले देश दशकों तक आर्थिक और भू-राजनीतिक फायदे काटेंगे। अभी तक का एकमात्र विजेता चीन है।"

पिछले 15 वर्षों में चीन ने बिजली उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि एआई जैसी उभरती तकनीकें बिजली पर निर्भर हैं। चीन का स्वच्छ ऊर्जा निवेश न केवल पर्यावरण बचाएगा, बल्कि एआई क्रांति में भी नेतृत्व देगा। आरएमआई की 'पावरिंग अप द ग्लोबल साउथ' रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक दक्षिण के 70 प्रतिशत सौर-पवन संसाधन चीन की रणनीति से जुड़ रहे हैं।

यह संघर्ष सिर्फ दो महाशक्तियों का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का है। वैश्विक दक्षिण अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण एशिया, अब सस्ती और सतत ऊर्जा की तलाश में हैं। चीन ने इन देशों में सस्ते सोलर पैनल और ईवी तकनीक पहुंचाई है, जबकि अमेरिका के महंगे गैस प्रोजेक्ट इनके लिए बोझ साबित हो रहे हैं। परिणाम? ये देश चीन की ओर झुक रहे हैं।

भारत के संदर्भ में देखें तो यह चेतावनी स्पष्ट है। हमारी 'मेक इन इंडिया' और 'प्लेड्ज फॉर क्लाइमेट' पहलें स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित हैं, लेकिन चीन का वर्चस्व चुनौती है। भारत सोलर और विंड में प्रगति कर रहा है, लेकिन बैटरी और ईवी चिप्स में आयात पर निर्भरता बनी हुई है। यदि हम चीन की तरह समन्वित नीति नहीं अपनाते, तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में पीछे रह जाएंगे। अमेरिका की गलती से सबक लेते हुए, भारत को स्वदेशी नवाचार पर जोर देना चाहिए जैसे लिथियम खनन और बैटरी रिसाइकिंलग में निवेश। अमेरिका की यह भूल नई नहीं है। 20वीं सदी में जापान ने इलेक्ट्रॉनिक्स में अमेरिका को पीछे छोड़ा था, क्योंकि अमेरिका ने अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता दी। आज चीन स्वच्छ ऊर्जा में वही कर रहा है। जेन्सेन की वीडियो एक चेतावनी है, जो देश बिजली उत्पादन में आगे होगा, वही एआई और अगली औद्योगिक क्रांति जीतेगा।

अमेरिका को अपनी नीतियां पलटनी होंगी, ईवी सब्सिडी बहाल करनी होंगी, नवीकरणीय अनुसंधान में निवेश बढ़ाना होगा। लेकिन समय कम है। चीन का बढ़त 10 वर्षों का नहीं, बल्कि दशकों का हो सकता है। अमेरिका ने 21वीं सदी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, जीवाश्म ईंधन पर दांव लगाकर स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य को गंवा दिया। चीन का उदय एक सबक है/ समन्वित, दूरदर्शी नीतियां ही विजेता बनाती हैं।

भारत जैसे देशों को इस दौड़ में शामिल होना चाहिए, ताकि हम न केवल पर्यावरण बचाएं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता भी हासिल करें। समय आ गया है कि दुनिया एकजुट होकर स्वच्छ ऊर्जा को अपनाए। अन्यथा, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा।

एच-1 बी वीजा : भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किया

- **आपातकालीन सहायता चाहने वाले भारतीय नागरिक +1-202-550-9931 पर संपर्क कर सकते हैं**

वाशिंगटन, (एजेंसी): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा आवेदनों पर हर साल 1,00,000 डॉलर का शुल्क लगाने की घोषणा की है, जिससे भारतीय पेशेवरों में चिंता बढ़ गई है। इस घोषणा के बाद, वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने शनिवार को भारतीय नागरिकों के लिए तत्काल सहायता के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किया दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आपातकालीन सहायता चाहने वाले भारतीय नागरिक +1-202-550-9931 पर संपर्क कर सकते हैं। यह नंबर केवल तत्काल आपातकालीन सहायता चाहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए है, सामान्य कांसुलर पूछताछ के लिए नहीं।

इस कदम से भारतीय तकनीकी पेशेवरों और विदेशों से भेजे जाने वाले धन पर इसके प्रभाव को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं, क्योंकि लगभग 71 प्रतिशत एच-1बी वीजा भारतीय नागरिकों को ही जारी किए जाते हैं।

स्थिति को शांत करने के उद्देश्य से अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह भारी शुल्क केवल नए एच-1बी वीजा आवेदनों पर लागू होगा, न कि मौजूदा वीजा धारकों या नवीनीकरण चाहने वालों पर। दिए गए एक विशेष बयान में व्हाइट हाउस ने शनिवार को कहा कि यह एक-बार की फीस है जो केवल नए वीजा पर लागू होती है, वीजा नवीनीकरण या मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं।

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि एच-1बी वीजा के लिए नया शुल्क लागू होगा, जो केवल नई वीजा याचिकाओं पर लगेगा, न कि नवीनीकरण या मौजूदा वीजा धारकों पर। इस बीच, भारतीय सरकार ने अपने सभी दूतावासों और मिशनों को निर्देश दिया है कि वे अगले 24 घंटों में अमेरिका लौटने वाले भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करें।

विदेश मंत्रालय ने भी इस घटनाक्रम पर ध्यान दिया और कहा कि वह एच-1बी वीजा कार्यक्रम में किए गए व्यापक बदलावों, खासकर नई वार्षिक फीस के बारे में सावधानीपूर्वक समीक्षा कर रहा है।

मंत्रालय ने चिंता व्यक्त की कि इस कदम के वित्तीय नुकसान के अलावा, परिवारों के सामने मानवीय संकट भी पैदा हो सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, सरकार ने अमेरिका के एच-1बी वीजा कार्यक्रम पर प्रस्तावित प्रतिबंधों से संबंधित रिपोर्टें देखी हैं। इस कदम के सभी संभावित प्रभावों का अध्ययन सभी संबंधित पक्षों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भारतीय उद्योग भी शामिल है। भारतीय उद्योग ने पहले ही एच-1बी कार्यक्रम से संबंधित कुछ धारणाओं को स्पष्ट करते हुए एक प्रारंभिक विश्लेषण जारी कर दिया है।

उन्होंने आगे चेतावनी दी कि ट्रंप का यह कदम व्यापारिक क्षेत्र से बाहर भी असर डाल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि सभी संबंधित पक्ष, जिसमें भारतीय उद्योग भी शामिल है, इसके सभी पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं और इस कदम से परिवारों में होने वाली परेशानियों के कारण मानवीय संकट भी पैदा हो सकता है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com
स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

प्रवाह
77 साल बेमिसाल
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

कोई स्थायी गठबंधन नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं।
- हेनरी जॉन टेंपल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एच-1बी वीजा नीति में अप्रत्याशित बदलाव की घोषणा से भारतीय पेशेवरों में संशय है। वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में इस तरह का संरक्षणवाद दीर्घकाल में भले अमेरिका के लिए आत्मघाती हो, लेकिन फिलहाल भारत को कूटनीतिक सतर्कता दिखानी होगी।

ट्रंप की मंशा

अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अधिकारियों की नई दिल्ली यात्रा के कुछ ही दिन बाद और भारत के वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अमेरिका यात्रा के ऐन पहले, जब द्विपक्षीय व्यापार वार्ता पटरी पर लौटती दिख रही थी, ठीक तभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा के शुल्क में अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने वैश्विक प्रतिभा बाजार को हिला कर रख दिया है। भारतीय पेशेवरों के लिए तो यह और भी बड़ा धक्का है, जो इस वीजा कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं। दरअसल, एच-1बी वीजा उच्च कुशल पेशेवरों को अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है, जो लंबे समय से भारतीय आईटी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिए सपनों का द्वार रहा है। नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका द्वारा अब तक जारी एच-1बी वीजा में करीब 72 फीसदी भारतीयों के खाते में ही आए हैं। लेकिन 21 सितंबर, 2025 से प्रभावी इस नई नीति के तहत अब नए एच-1बी वीजा आवेदकों को एक लाख डॉलर का शुल्क भरना होगा, जो अब तक महज एक हजार डॉलर था। जाहिर है कि कंपनियां अब नए विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने से पहले दो बार सोचेंगी, क्योंकि एक लाख डॉलर का अतिरिक्त बोझ छोटी-मझोली फर्मों के लिए असहनीय हो सकता है। टीसीएस और इंफोसिस जैसी अमेरिकी बाजारों पर निर्भर भारतीय कंपनियों को भी अपनी रणनीति बदलते हुए अब या तो स्थानीय कर्मचारियों को प्राथमिकता देनी होगी या वे वैकल्पिक बाजारों की तलाश करेंगी। चौंकाने वाले फैसले लेना भले ही ट्रंप की आदत हो, लेकिन सेवा क्षेत्र में पहली बार अपनी संरक्षणवादी नीति के दर्शन करा, वह भूल रहे हैं कि अमेरिका को बनाने में अप्रवासियों की बड़ी भूमिका रही है। सिलिकॉन वैली के करीब एक-तिहाई टेक-कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। फॉर्च्यून 500 की लगभग डेढ़ दर्जन कंपनियों में शीर्ष पर भारतीय बैठे हैं, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के इंजन भी हैं। 2024 में 72 यूनिकॉर्न स्टार्टअप भारतीय मूल के लोगों के थे, जिनका कुल मूल्य करीब 195 अरब डॉलर आंका गया था। इन कंपनियों में अमेरिकी भी काम करते हैं। अमेरिकी आबादी में बमुश्किल डेढ़ फीसदी होने के बावजूद भारतीय पांच से छह फीसदी कर अदा करते हैं। नैसकॉम का यह कहना उचित ही है कि एच-1बी वीजा जैसे फैसलों का नकारात्मक असर अमेरिका में नवाचार के माहौल और रोजगार आधारित अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। रूस से तेल लेने पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ और चाबहार पर छूट को रद्द करने के बाद ट्रंप के एच-1बी वीजा शुल्क में बढ़ोतरी के फैसले के पीछे भारत पर दबाव बनाने की मंशा ही अधिक दिखती है।

रियाद, इस्लामाबाद और भू-राजनीतिक संकेत

सऊदी–पाक रक्षा समझौता याद दिलाता है कि आधुनिक दुनिया में गठबंधन विचारधारा से नहीं, बल्कि तात्कालिक सुरक्षा जरूरतों से तय होते हैं। आने वाले महीने बताएंगे कि नई दिल्ली इस नए सुरक्षा परिदृश्य में कितना संतुलन साध पाती है, जहां दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की सीमाएं धुंधली हो रही हैं।

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए पारस्परिक रक्षा समझौते ने दक्षिण एशिया और खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा संरचना को गहराई से प्रभावित करने की संभावना पैदा कर दी है। समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। यह केवल भाईचारे का प्रतीक नहीं, बल्कि एक ऐसी रणनीतिक पुनर्संरचना है, जो युद्ध, शक्ति शून्यता और बदलते गठबंधनों से जूझ रहे क्षेत्र में नई चुनौतियां उत्पन्न करती है और भारत की सुरक्षा व कूटनीतिक रणनीति के लिए गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

इस समझौते की तात्कालिक पृष्ठभूमि पश्चिम एशिया की उथल-पुथल है। हाल ही में इस्राइल द्वारा कतर की राजधानी दोहा पर किया गया हमला, जिसमें वरिष्ठ हमास नेताओं के ठिकाने को निशाना बनाया गया और छह लोगों की मौत हुई, ने अरब जगत को झकझोर दिया। महत्वपूर्ण यह रहा कि इस हमले पर अमेरिका, जो परंपरागत रूप से खाड़ी क्षेत्र का सुरक्षा प्रदाता माना जाता रहा है, ने लगभग चुप्पी साधे रखी। 2019 में सऊदी तेल ठिकानों पर ईरान समर्थित बलों के हमले के बाद से ही अमेरिकी सुरक्षा गारंटी को लेकर शंकाएं बढ़ रही थीं। इस बार की चुप्पी ने यह संदेश और स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका अब पहले जैसी सुरक्षा छतरी देने में इच्छुक या सक्षम नहीं है। सऊदी अरब के लिए यह एक बड़ा संकेत था कि उसे अपने सुरक्षा विकल्पों का दायरा बढ़ाना होगा और अमेरिकी अनिश्चितता के बीच वैकल्पिक साझेदारों को खोजना होगा।

आनंद कुमार
एसोसिएट फेलो एमपी-आईडीएसए

यहीं पर पाकिस्तान एक स्वाभाविक सहयोगी के रूप में सामने आता है। लंबे समय से रियाद का निकट साझेदार और एकमात्र मुस्लिम बहुल परमाणु शक्ति होने के कारण पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए विशेष महत्व रखता है। समझौता भले ही रक्षात्मक भाषा में प्रस्तुत किया गया हो, पर इसका रणनीतिक अर्थ कहीं अधिक गहरा है। पाकिस्तानी अधिकारी कहते हैं कि यह समझौता किसी विशेष देश के खिलाफ नहीं है और इसकी तुलना नाटो के सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत से की जा सकती है। इसके बावजूद, इसका समय और प्रसंग स्पष्ट रूप से बताता है कि यह इस्राइल की हालिया कार्रवाइयों और बदलते क्षेत्रीय समीकरणों की प्रतिक्रिया है। इस समझौते के प्रभाव अनेक स्तरों पर दिख सकते हैं। खाड़ी में यह पहले से अस्थिर माहौल को और जटिल बनाता है। अमेरिका द्वारा कराए गए अब्राहम समझौते, जिनका उद्देश्य अरब देशों और इस्राइल को ईरान विरोधी मोर्चे में जोड़ना था, गाजा संघर्ष और इस्राइल की आक्रामक कार्रवाइयों से कमजोर पड़ चुके हैं। सऊदी अरब और इस्राइल के बीच संबंध सामान्य करने की योजनाएं अब ठंडी पड़ गई हैं। पाकिस्तान के साथ रक्षा गठबंधन कर रियाद यह संकेत दे रहा है कि वह अमेरिकी और इस्राइली प्रभाव से बाहर अपनी स्वतंत्र सुरक्षा नीति अपनाएगा। इससे अन्य खाड़ी देश भी इसी तरह की व्यवस्थाओं की ओर बढ़ सकते हैं, जिससे पुरानी सुरक्षा संरचना और अधिक ढीली पड़ सकती है।

दक्षिण एशिया के लिए भी यह विकास कम महत्वपूर्ण नहीं है। पाकिस्तान द्वारा सऊदी अरब को परमाणु छतरी देने की पेशकश पहले से तनावपूर्ण परमाणु संतुलन को और जटिल बनाती है। भारत, जिसके पास अनुमानतः लगभग 172 परमाणु हथियार हैं, अब ऐसी स्थिति का सामना करेगा, जिसमें पाकिस्तान की परमाणु क्षमताएं अप्रत्यक्ष रूप से एक बड़े खाड़ी देश की सुरक्षा से जुड़ सकती हैं। यद्यपि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि सऊदी अरब को परमाणु हथियारों तक पहुंच मिलेगी, परंतु पाकिस्तानी परमाणु सुरक्षा की संभावना ही निवारक समीकरण को बदलने के लिए पर्याप्त है। भारत की कूटनीतिक स्थिति अब और संवेदनशील हो गई है। पिछले एक दशक में नई दिल्ली ने सऊदी अरब के साथ ऊर्जा, व्यापार और आतंकवाद निरोध में मजबूत साझेदारी बनाने में काफी निवेश किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह इस समझौते के प्रभावों का अध्ययन करेगा और उम्मीद करता है कि रियाद दोनों देशों के हितों और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखेगा। पर हकीकत यह है कि यह समझौता नई अनिश्चितताओं को जन्म देता है। भारत को अब रियाद के साथ अपने रिश्ते बनाए रखते हुए पाकिस्तान–सऊदी रिश्तों से पैदा हो सकने वाले सुरक्षा जोखिमों से सतर्क रहना होगा।

यह समझौता व्यापक भू-राजनीतिक संकेत भी देता है। यह दर्शाता है कि दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया, दोनों में अमेरिकी प्रभाव धीरे-धीरे घट रहा है। वाशिंगटन की अनिर्णयता ने एक शून्य पैदा किया है, जिसे क्षेत्रीय शक्तियां भरने की कोशिश कर रही हैं। चीन, जो पहले से ही पाकिस्तान और सऊदी अरब, दोनों का करीबी साझेदार है, इन घटनाओं को ध्यान से देखेगा, जबकि ईरान भी सतर्क रहेगा, क्योंकि वह रियाद और इस्लामाबाद, दोनों का प्रतिद्वंद्वी है। एक संभावित परमाणु आयाम वाले सऊदी–पाक सुरक्षा अक्ष का उभार तेहरान के लिए भी चिंता का कारण बनेगा।

भारत के लिए आगे की राह में रणनीतिक धैर्य और संतुलन आवश्यक होगा। वह सऊदी अरब को नाराज नहीं कर सकता, जो ऊर्जा आपूर्ति और आतंकवाद विरोधी सहयोग का अहम भागीदार है। साथ ही, उसे पाकिस्तान की खाड़ी में बढ़ती भूमिका को लेकर सजग रहना होगा। हाल के वर्षों में भारत का इस्राइल के साथ बढ़ता रक्षा सहयोग भी सावधानी से आगे बढ़ाना होगा, ताकि अरब देशों में गलत संदेश न जाए। चुनौती यही है कि भारत इस्राइल और अरब जगत, दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखते हुए अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं से समझौता न करे।

Join This Channel:- https://t.me/AllNewsPaperPaid1

सऊदी–पाक रक्षा समझौता याद दिलाता है कि आधुनिक दुनिया में गठबंधन अक्सर विचारधारा से नहीं, बल्कि तात्कालिक सुरक्षा आवश्यकताओं से तय होते हैं। यह लंबे समय से परदे के पीछे मौजूद रिश्ते को औपचारिक रूप देता है और इसके पीछे की रणनीतिक गणनाओं को उजागर करता है। भारत के लिए यह कोई संकट नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि बदलते क्षेत्रीय परिदृश्य में पुरानी धारणाओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आने वाले महीने बताएंगे कि नई दिल्ली इस नए और अनिश्चित सुरक्षा परिदृश्य में कितनी कुशलता से संतुलन साध पाती है, जहां दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं और दूरस्थ राजधानियों की गतिविधियां तत्काल प्रभाव डाल रही हैं।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

कार्ल हिल्टी

जीवन का विकास सीधा, एकसमान पथ नहीं है, बल्कि अप्रत्याशित तत्वों और रचनात्मक चुनौतियों वाला पथ है। जीवन के प्रत्येक काल का अपना उद्देश्य और कार्य होता है।

जीवन का अर्थ खाना-पीना और मर जाना नहीं है

हर जीवन में कई चरण होते हैं, और कोई भी जीवन शुरुआत से अंत तक एकसमान सीधा नहीं चलता, जैसे कोई साफ-सुथरी नदी या कृत्रिम रूप से बनाई गई सीधी नहर। कोई दो जीवन बिल्कुल एक-दूसरे जैसे नहीं चलते, और यहां तक कि सबसे प्राकृतिक लगने वाले चरण भी कभी-कभी एक-दूसरे की उल्टी दिशा में होते हैं। इसलिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो अपनी युवावस्था में असाधारण रूप से बुद्धिमान होते हैं, और उनमें युवावस्था के गुण वृद्धावस्था में ही आते हैं। हर जीवन में ऐसी गलतियां होती हैं, जिन्हें टाला जा सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि कोई स्वस्थ जीवन पूरी तरह से स्थिर नहीं होता, न ही कोई पूरी तरह से सामान्य होता है, बल्कि सभी के जीवन में अपरिहार्य गलतियां और छूटे हुए अवसर होते हैं, लेकिन वे किसी की गलत सोच या मूर्खता के कारण नहीं होते, बल्कि किसी बाहरी या आंतरिक वजह से होते हैं, जिसे रोका नहीं जा सकता और यही जीवन को आकार देते हैं। यह बताता है कि जीवन का विकास सीधा, एकसमान नहीं होता है, बल्कि यह अप्रत्याशित तत्वों और रचनात्मक चुनौतियों वाला पथ है। जीवन के प्रत्येक काल का अपना उद्देश्य और कार्य होता है। बसंत ऋतु में पेड़ बढ़ते और फूल खिलते हैं, इसके अलावा आप उसमें फल नहीं देख सकते और उस समय का एक अनोखा आनंद है। पौधों की प्राकृतिक वृद्धि में जानबूझकर बाधा डालकर आधुनिक बौने वृक्षों को केवल शीघ्र फल उत्पादन के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन उन वृक्षों पर उत्पन्न होने वाले फल न तो अच्छी गुणवत्ता के होते हैं और न ही प्राकृतिक वृक्षों पर पके फलों की तरह स्वस्थ होते हैं। एक व्यक्ति, जिसने जीवन की कई परिस्थितियों का अनुभव किया है और उनसे सीखा है, उसके पास जीवन की गहरी समझ और अपनी उपलब्धियों से निर्मित एक मजबूत, अडिग व्यक्तित्व, दोनों होते हैं। इसी प्रकार वृद्धावस्था भी अपने योग्य कार्य कर सकती है, जब व्यक्ति पतन और निराशा के बजाय ज्ञान और दूरदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करे, तभी यह संभव है। जो कोई भी जीवन के ऐसे किसी भी चरण को छोड़ देता है, और उसे जल्दी से पार कर जाता है, उसके विशिष्ट लाभों का कोई उपयोग नहीं करता, वह कभी भी बाद में उसे फिर से पाने की स्थिति में नहीं होगा, बल्कि उसके स्वरूप में हमेशा एक स्पष्ट कमी रहेगी। इस कमी को युवावस्था में रोकना शिक्षा का विषय है। जीवन के वास्तविक लाभ और उपलब्धियां इस आंतरिक, स्व-प्रेरित प्रयास से आती हैं, बाहरी मदद से नहीं। यह आंतरिक ज्ञान, निश्चित रूप से, उन लोगों के लिए नहीं है, जिनके लिए जीवन का अर्थ खाने-पीने और मर जाने के अलावा और कुछ नहीं है। आंतरिक जीवन के चरण उन लोगों के लिए हैं, जो जीवन के सभी [illegible] और दृढ़ता से अग्रसर होते हैं।

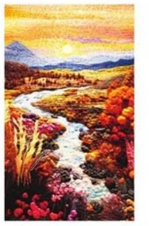

Join This Channel:- https://t.me/AllNewsPaperPaid1

पहले चलना सीखें

सूत्र

जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए हमें चरणबद्ध तरीके से काम करना होगा,चाहे कॅरिअर हो या व्यक्तिगत जीवन। यदि आप चाहेंगे कि छलांग लगाकर सफलता हासिल कर लें, तो जीवन भर निराशा हाथ लगेगी। जीवन के प्रत्येक काल का अपना उद्देश्य और कार्य होता है। पहले चलना सीखें, फिर आगे बढ़ें, तभी जीवन सुंदर होगा।

दूसरा पहलू

आज, लगभग हर चीज इंटरनेट से जुड़ी है। आखिर इंटरनेट हमारे जीवन का हिस्सा कैसे बना?

इंटरनेट के हमारे जीवन का हिस्सा बनने की कहानी

इंटरनेट एक ऐसी व्यवस्था है, जिससे दुनिया भर के कंप्यूटर एक-दूसरे को संदेश भेज सकते हैं। व्यावहारिक रूप से इंटरनेट से जुड़ी हर चीज में एक कंप्यूटर होता है। 1960 के दशक में, कंप्यूटर केवल खास कामों (जैसे वैज्ञानिक शोध) के लिए इस्तेमाल होते थे। उस समय, अगर दो कंप्यूटरों को डाटा शेयर करना होता, तो लोग पहले से समय तय करते और फिर टेलीफोन कॉल के जरिये एक कंप्यूटर को दूसरे से जोड़ते। अमेरिक एक ऐसा नेटवर्क चाहता था, जिससे टेलीफोन लाइन खराब होने के बावजूद कंप्यूटर अपने आप संदेश भेज सकें। 1962 में, अमेरिकी इंजीनियर पॉल बरन रैंड कॉर्प ने 'हॉट पोटैटो नेटवर्किंग' नामक एक नया विचार दिया। इसमें संदेश को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता था। इन टुकड़ों में एक क्रम संख्या होती, ताकि दूसरा कंप्यूटर पूरा संदेश समझ सके। इस विचार को आज के अरपानेट के रूप में लागू किया गया। इन छोटे टुकड़ों को 'पैकेट' और इस प्रणाली को 'पैकेट स्विच्ड नेटवर्किंग' नाम मिला।

फ्रेड मर्टिन

1960 के दशक में, यदि दो कंप्यूटरों को डाटा शेयर करना होता, तो लोग पहले से समय तय करते थे।

इंटरनेट के जनक विन्ट सर्फ ने ऐसी व्यवस्था बनाई, जिसमें कोई पैकेट गायब हो जाए, तो उसे प्राप्त करने वाला कंप्यूटर भेजने वाले से उसे दोबारा मांग सके। इसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। 1990 के आसपास टिम बर्नर्स-ली ने सीईआरएन (यूरोपियन ऑर्गनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च) में काम करते हुए वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत की, ताकि उनके सहयोगी आसानी से अपने शोध को एक-दूसरे के साथ साझा कर सकें। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली बनाई, जिसमें एक कंप्यूटर पर कई 'पेज' हो सकते थे। इसके लिए उन्होंने यूआरएल (यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर) का विचार दिया, जो किसी भी कंप्यूटर को इंगित कर सकता था। बर्नर्स-ली ने पहला वेब ब्राउजर और वेब सर्वर बनाया। आज किसी यूआरएल में हम जो 'डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू' देखते हैं, यह उसी वर्ल्ड वाइड वेब से आया है। उन्होंने इसे मुख्य रूप से टेक्स्ट, तस्वीरें और फाइलें साझा करने के लिए बनाया था, लेकिन इंटरनेट ने इसे वीडियो और ऑडियो के लिए भी उपयुक्त बना दिया। यूट्यूब व इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म उसी का पालन करते हैं। कंप्यूटर अब सस्ते हो गए हैं, जिसके चलते लाखों-करोड़ों डिवाइस इंटरनेट से जुड़े हैं। इनमें सेंसर शामिल हैं, जैसे सिक्योरिटी कैमरा। इसके अलावा, स्मार्ट थर्मोस्टेट है, जो आपके घर की हीटिंग या कूलिंग को चालू-बंद करता है। इन सभी स्मार्ट डिवाइस को 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' कहा जाता है। आज, लगभग हर चीज इंटरनेट से जुड़ी है। यह एक ऐसा जाल है, जो न सिर्फ कंप्यूटरों को, बल्कि हमारी जिंदगी को भी जोड़ता है।

टिम बर्नर्स-ली ने एक ऐसी प्रणाली बनाई, जिसमें एक कंप्यूटर पर कई 'पेज' हो सकते थे। इसके लिए उन्होंने यूआरएल (यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर) का विचार दिया, जो किसी भी कंप्यूटर को इंगित कर सकता था।

- द कन्वर्सेशन से

आंकड़े

नवोन्मेषी देश

एक नवोन्मेषी देश विश्व के लिए प्रगति का पथ होता है। इस मामले में स्विट्जरलैंड इस वर्ष 100 में से 66 अंकों के साथ शीर्ष पर है।

स्विट्जरलैंड	66.0
स्वीडन	62.6
अमेरिका	61.7
दक्षिण कोरिया	60.0
सिंगापुर	56.6

चीन 56.6 अंकों के साथ वार्षिक रैंकिंग में 10वें स्थान पर है। | स्रोत : WIPO

दुर्गम ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसका वध कोई भी पुरुष न कर सके, क्योंकि उसे भ्रम था कि कोई स्त्री उसे मार नहीं सकती, लेकिन उसका वध मां दुर्गा ने किया।

मां भगवती ने निभाया वचन

दुर्गम नाम के दैत्य ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया, जिसमें उसने मांगा कि कोई भी पुरुष उसका वध न कर सके, क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई स्त्री इतनी बलशाली नहीं हो सकती, जो उसे मार सके। इस वरदान के बाद दुर्गमासुर ने वेदों का ज्ञान चुरा लिया और देवताओं को परेशान करने लगा। देवताओं का बल क्षीण हो गया। इसके बाद दुर्गम ने स्वर्ग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। समस्त देवगण एकत्रित हुए और उन्होंने देवी मां भगवती का आह्वान किया। मां को देवताओं ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। इसके बाद मां भगवती ने समस्त देवताओं को दैत्य दुर्गम के प्रकोप से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया।

मां भगवती ने दुर्गम का अंत करने का प्रण लिया है, यह बात जब दुर्गम को पता चली, तो उसने स्वर्ग लोक पर पुनः आक्रमण कर दिया। इसके बाद साक्षात मां भगवती देवताओं और स्वर्ग लोक की रक्षा के लिए प्रकट हुईं और उन्होंने अपने वचन के अनुसार, दैत्य दुर्गम की सेना और उसका संहार कर मृत्यु लोक पहुंचा दिया। मां भगवती ने दुर्गम के साथ जब अंतिम युद्ध किया तब उन्होंने भुवनेश्वरी, काली, तारा, छिन्नमस्ता, भैरवी, बगला तथा दूसरी अन्य महा शक्तियों का आह्वान करके दुर्गम को पराजित किया था। इस भीषण युद्ध में विकट दैत्य दुर्गम को पराजित कर उसका वध करने पर मां भगवती दुर्गा नाम से प्रख्यात हुईं।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 22 सितंबर, 1949

'इंडिया' के साथ देश को 'भारत' भी कहा जाएगा

देश का नाम 'इंडिया' व '

देश के भावी नाम के बारे में फैसला हो गया है। 'इंडिया' के साथ देश को 'भारत' भी कहा जाएगा। भारत राज्यों का संघ होगा, जिसे भारतीय संघ कहा जाएगा। सदस्यों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए।

चुनौतियों को अवसर में बदलना होगा

ट्रंप का रवैया दशकों की भारत-अमेरिकी साझेदारी के लिए तो खतरा है ही, यह अमेरिकियों के हितों को भी चोट पहुंचा रहा है।

केएस तोमर | मुद्दा

अपने दूसरे कार्यकाल के बमुश्किल नौ महीने पूरे होने पर ट्रंप ने ऐसे तीन फैसले लिए हैं, जो अदूरदर्शी राष्ट्रवाद और घरेलू दिखावे से प्रेरित नीति-निर्माण को उजागर करते हैं। एच-1बी वीजा शुल्क को बढ़ाकर, चाबहार बंदरगाह पर भारतीय संचालन की छूट को रद्द कर, और सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौते को मौन स्वीकृति देकर ट्रंप घरेलू मतदाताओं को आकर्षित कर राष्ट्रवादी रुख का संकेत दे रहे हैं, पर वह अमेरिकियों के हितों को ठेस भी पहुंचा रहे हैं। ये कार्रवाइयां दशकों की रणनीतिक योजना, क्षेत्रीय प्रभाव और भारत-अमेरिका साझेदारी के लिए खतरा हैं।

हरेक एच-1बी आवेदन पर एक लाख डॉलर शुल्क लगाने का ट्रंप का फैसला हथौड़े जैसा है। इसे 'अमेरिकी कामगारों की सुरक्षा' कहकर प्रचारित किया जा रहा है, पर इससे अमेरिकी नवाचारों के नष्ट होने और भारत-अमेरिका संबंधों के निचले स्तर पर जाने का खतरा है। भारत पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। अमेरिका में लगभग तीन लाख भारतीय पेशेवर हैं, जिनके सामने रोजगार का खतरा पैदा हो सकता है। अमेरिका में नौकरी की योजना बना रहे लोगों को अपने कॅरिअर में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भारत स्वास्थ्य और अनुसंधान एवं विकास में छूट पर बातचीत करने, वाशिंगटन में कॉर्पोरेट लॉबिंग का लाभ उठाने तथा यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया से साझेदारी करने का विकल्प चुन सकता है। भारत को स्टार्ट-अप्स का विस्तार, अनुसंधान और विकास को मजबूत करने, और वहां से वापस लौटने वाली प्रतिभाओं के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

एच-1बी शुल्क भले ही अमेरिका को वित्तीयम लाभ प्रदान करे, लेकिन वैश्विक प्रतिभाओं पर कर लगाकर अमेरिका अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। भारत को इस झटके को रणनीतिक आत्मनिर्भरता के अवसर में बदलना होगा।

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रियाद में हुए रक्षा समझौते ने दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था को झटका दिया है। इससे पाकिस्तान की जर्जर अर्थव्यवस्था और सैन्य स्थिति को मजबूती मिलेगी, साथ ही यह चीन की पश्चिम एशियाई रणनीति से मेल खाता है।

नई दिल्ली ने सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए माना है कि उसे इस समझौते के बारे में पता था। यह संयम भारत के संतुलनकारी रवैये को दर्शाता है। सऊदी अरब भारत का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्तिकर्ता होने के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार भी है। इस समझौते के बाद सऊदी अरब का समर्थन पाकिस्तान को सीमा पार से प्रायोजित आतंकवादी समूहों को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए उकसा सकता है, जबकि इस्लामी एकजुटता का दिखावा चरमपंथी नेटवर्क को सक्रिय कर सकता है।

यह समझौता पिछले पांच वर्षों में सऊदी अरब के साथ विकसित हुए भारत के संबंधों को और जटिल बना देता है। चीन को इससे चुपचाप लाभ मिल रहा है, क्योंकि यह समझौता सीपीईसी को मजबूत कर रहा है और खाड़ी क्षेत्र में उसकी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ा रहा है, जिससे यह क्षेत्र अमेरिकी प्रभुत्व से दूर हो रहा है। भारत के सामने खाड़ी देशों के साथ अपनी साझेदारी बनाए रखने, आतंकवाद-रोधी समन्वय को मजबूत करने और अमेरिका, रूस और इस्राइल के साथ बहुध्रुवीय कूटनीति का लाभ उठाने की चुनौती है।

चाबहार बंदरगाह पर भारत के संचालन के लिए अमेरिकी छूट को रद्द करने का ट्रंप का फैसला हमारी क्षेत्रीय रणनीति के लिए एक गंभीर झटका है। तेहरान पर 'अधिकतम दबाव' बनाने के तहत उठाए गए इस कदम से भारत के 12 करोड़ डॉलर का निवेश खतरे में पड़ गया है और भारत को अफगानिस्तान, रूस और मध्य एशिया से जोड़ने वाला गलियारा भी ठप हो गया है। चाबहार महज एक बंदरगाह ही नहीं, बल्कि यह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए एक जीवनरेखा है, चीन के ग्वादर का प्रतिकार है, और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे में एक महत्वपूर्ण स्थल है। यानी चाबहार का रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। बीजिंग ईरान के साथ अपने 400 अरब डॉलर के रणनीतिक समझौते और मध्य एशियाई गलियारों में प्रभुत्व का लाभ उठाकर इस शून्य को भरने के लिए तैयार है। भारत को इस झटके को एक अधिक लचीली क्षेत्रीय रणनीति के अवसर के रूप में बदलना चाहिए।

भारत के सामने तिहरी चुनौती है-अमेरिका में अपनी प्रतिभा और आर्थिक हितों की रक्षा करना, प्रतिबंधों और चीनी अतिक्रमण से क्षेत्रीय संपर्क को सुरक्षित रखना, तथा पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव के बीच खाड़ी संबंधों का प्रबंधन करना। रणनीतिक धैर्य, सक्रिय कूटनीति और घरेलू लचीलापन इससे निपटने की कुंजी हैं। भारत को इन चुनौतियों को अवसरों में बदलना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि ट्रंप के फैसले अंततः उसकी क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति को कमजोर करने के बजाय मजबूत करें।

नागरिक देवो भवः

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर की शाम राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में देश के नागरिकों से स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने की जो अपील की, वह स्वागत योग्य तो है ही, अनुकरणीय भी है। स्वदेशी की वकालत का इससे उपयुक्त समय कोई और नहीं हो सकता था। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ देश में त्योहारों व उत्सवों का एक लंबा सिलसिला भी आरंभ हो रहा है। आज से ही देश में जीएसटी की नई दरें भी लागू हो रही हैं, जिससे रोजमर्रा की जरूरत की कई चीजों के दाम घटने की उम्मीद है। कई कंपनियों ने तो अपने उत्पादों के घटे दामों का विज्ञापन देना भी शुरू कर दिया है। अगले डेढ़ महीने में दुर्गापूजा, दिवाली, छठ पूजा के अलावा पचास से भी अधिक छोटे-बड़े पर्व-त्योहार होने जा रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं कि यह त्योहारी सीजन सदियों से भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा देता रहा है। इन्हीं दिनों में किसानों की जेब में नई खरीदारी करने के लिए पैसे होते हैं। इसलिए जीएसटी में सुधार का यह माकूल समय तो था ही, प्रधानमंत्री द्वारा अपने भावनात्मक संवाद के जरिये नागरिकों को उनके कर्तव्य का स्मरण कराना भी उचित था।

अमेरिकी टैरिफ, ट्रंप प्रशासन के अनिश्चित रुख-रवैये और तेजी से बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के मद्देनजर भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त न पड़े, इसके लिए नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को स्वदेशी की याद दिलाई है। देश की आजादी में स्वदेशी आंदोलन का योगदान एक स्थापित तथ्य है। इसका स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों व कारोबारियों से कहा है कि वे ज्यादा से ज्यादा देश में बनी चीजों की बिक्री व खरीदारी करें, ताकि इससे हमारे लघु एवं मध्यम उद्योगों को मजबूती मिल सके। जाहिर है, यही सेक्टर सबसे अधिक रोजगार सृजित करता है। इसमें नौजवानों की हित-चिंता भी छिपी है। पिछले कई वर्षों, खासकर कोरोना महामारी के बाद से ही अर्थशास्त्री लगातार घरेलू मांग में वृद्धि के उपायों को अपनाने पर जोर देते रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 12 लाख रुपये तक की आय पर कर रियायत देने और जीएसटी दरों में कटौती जैसे कदम इसी मंशा से प्रेरित हैं। इसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को तो मिले ही, स्थानीय उत्पादकों को भी मिलना चाहिए।

स्वदेशी की वकालत का इससे उपयुक्त समय कोई और नहीं हो सकता था। आज से शारदीय नवरात्रि के साथ देश में त्योहारों व उत्सवों का सिलसिला भी आरंभ हो रहा है।

वैश्वीकरण के दौर में संरक्षणवादी नीतियों की एक सीमा है, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने आयात शुल्क बढ़ाकर जिस तरह अमेरिकी कंपनियों, किसानों व उत्पादकों के लिए संरक्षणवादी रुख अपनाया और वैश्विक अर्थजगत में भूचाल पैदा किया है, उसने दूसरे देशों को भी बाध्य किया है कि वे अपने किसानों, कारोबारियों के हितों की रक्षा के लिए आगे आएं। भारत-अमेरिकी व्यापार वार्ता में जो गतिरोध पैदा हुआ, उसके मूल में भी यही चिंता है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि अमेरिका भारतीय बाजार में अपने कृषि उत्पादों को उतारना चाहता है, जिनसे लाखों भारतीय किसानों-कारोबारियों के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। स्वाभाविक ही भारत सरकार ने इससे इनकार कर दिया। ट्रंप प्रशासन अब बौनी हरकतों पर उतर आया है और भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के हथकंडे अपनाने लगा है। ऐसे में, प्रधानमंत्री ने देशवासियों से जो अपील की है, वह दरअसल भारत राष्ट्र की अपने नागरिकों से अपेक्षा है। आजादी की जंग के समय स्वदेशी को लेकर जो जुनून था, उसका आधा भी अभी पैदा हो जाए, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार रोकने की सारी कुचालें निरर्थक हो जाएंगी।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 22 सितंबर, 1950

कांग्रेस की आर्थिक योजना

नासिक कांग्रेस के महत्वपूर्ण प्रस्तावों में एक प्रस्ताव आर्थिक कार्यक्रम से संबंध रखता है। इस प्रस्ताव में कांग्रेस ने देश के लिए आर्थिक कार्यक्रम के मोटे सिद्धांत निर्धारित कर दिये हैं। उनमें नवीनता कुछ नहीं है। कांग्रेस ने पहले भी इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है और देश के स्वतंत्र होने के बाद से ही सरकार उस पर चलने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने जन-कल्याणकारी राज्य की स्थापना को अपना ध्येय स्वीकार किया है।

जन-कल्याणकारी राज्य का अर्थ यह कि राज्य केवल आन्तरिक अशान्ति और बाहरी आक्रमण से ही देश की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि वह यह चिन्ता भी करेगा कि उसके नागरिकों की भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकतायें भी पूरी हों। वह देखेगा कि लोगों को जीवन धारण करने के लिए पर्याप्त पौष्टिक आहार प्राप्त हो, रहने के लिए स्वच्छ हवा और प्रकाशयुक्त मकान मिले, उनके लिए चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो और उनकी सन्तान को शिक्षित और संस्कारवान बनाया जाये। जन-कल्याणकारी राज्य जनता के लिए जिन कामों को करने की अपनी जिम्मेदारी समझेगा, उनकी सूची बहुत लम्बी बनायी जा सकती है। संक्षेप में, वह जन-जीवन को हर तरह से सुखी और समृद्ध बनाने का प्रयास करेगा।

जन-कल्याणकारी राज्य की कुछ विशेषताओं का कांग्रेस के प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है। जन-कल्याणकारी राज्य में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जायेगी। राजनीतिक लोकतंत्र प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार देता है। आर्थिक लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यक भौतिक और सामाजिक आवश्यकताएं पूरी की जायेंगी। भौतिक और सामाजिक आवश्यकताओं का एक न्यूनतम मापदण्ड निर्धारित होगा और देश में किसी भी व्यक्ति को उस मापदण्ड से नीचे स्तर पर नहीं रहने दिया जायेगा। दूसरे शब्दों में वे सड़कों पर अथवा गन्दी और अंधेरी कोठरियों में रहने को बाध्य न होंगे और न अधपेट रह कर अपनी जिन्दगी के दिन पूरे करेंगे। उसमें बेकार कोई नहीं रहेगा, हरेक को उपयोगी काम के जरिये आजीविका कमाने का अवसर दिया जायेगा। कोई किसी का शोषण नहीं कर पायेगा, हमारा संविधान कहता है कि हरेक को उन्नति करने के समान अवसर दिये जायेंगे।

सर्ववत्सला अशिव-विनाशिनी मां

यहां स्कैन करें

विद्यानिवास मिश्र | प्रसिद्ध साहित्यकार, संपादक

शक्ति कहीं बाहर नहीं है, भीतर है। उसे पूरी प्राणवत्ता के साथ पुकार लगाने की जरूरत पड़ती है; हम कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, तुम जागो। शारदीय नवरात्रि पर विशेष :

मैं प्रतिदिन *श्री दुर्गा सप्तशती* का यह श्लोक सात बार दुहराता हूं- *सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥*

इसके अर्थ पर ध्यान करता हूं, मां तुम सबके मंगल का मंगल हो, मंगलमय की केंद्रभूत शक्ति हो, शिवा हो, शिव-तत्व को सक्रिय करने वाली हो, समस्त पुरुषार्थों की साधिका हो, तुमसे सभी को जीवन के समस्त चरम मूल्यों को साधने की शक्ति मिलती है, इसलिए तुम सबकी आश्रयदात्री हो। तुम्हारे तीन नेत्र हैं। दो से बाहर और तीसरे से भीतर देखती हो, पूरा देखती हो, सबको देखती हो। तुम गौरी हो, समस्त सात्विक शुभता का सारभूत रूप, तुम विश्वात्मा की आत्मा हो, तुम्हें नमन है।

ध्यान करते हुए मन में यह संशय भी कभी होता है- सबका मंगल क्यों? मंगल हो उसका, जो अच्छा है; जो बुरा है, दूसरों को सताता है, उत्पीड़ित करता है, उसका मंगल क्यों? जगदंबा भी तो असुरों का नाश करती हैं। फिर ये सर्वमंगलमांगल्या कैसे? यह संशय आज की परिस्थिति में और गहरे रूप में उठता है। इतनी निरुद्देश्य हिंसा, इतना दूसरों को क्षति पहुंचाकर सुख-सुविधा के सरंजाम जुटाने का उतावलापन, मासूम जानवरों की मुलायम रोएंदार खाल ओढ़ने के लिए इतनी नृशंस हत्या, पेड़ों को लुगदी में परिवर्तित करने का निर्मोही संकल्प और सुंदर, सुशील वधू को दहेज के लोभ में जलाने का ऐसा पैशाचिक व्यापार, संसार में है। कहां है सबका मंगल? मंगल तो लगता है, थोड़े से लोगों की संपत्ति बन गया है। कहां हैं सर्वेश्वरी? कहां हैं सर्वमंगला?

एक ओर यह संशय घेरता है, तो दूसरी ओर बच्चा खिलखिलाकर हंसता है, मां को मैंने बेवकूफ बना दिया। बड़ी निर्व्याज हंसी हंसता है और मां बेवकूफ बनाए जाने का मजा लेती है। एक लड़की दुष्ट अभिप्राय वाले गुंडे को जान पर खेलकर पकड़वा देती है, उसे अपने प्राणों की चिंता नहीं होती, गरीब रिक्शेवाला सवारी को पर्स वापस करने के लिए दो घंटे दौड़ लगाता है और पर्स वापस करके इनाम भी नहीं लेता, वापस करना अपना फर्ज समझता है। दस-बारह संतान एक के बाद दूसरी मरती रहीं और मां दूसरों की संतानों को खिलाकर मातृत्व की आपूर्ति करती है और परितृप्ति पाती है, तब लगता है कि मां कहीं गई नहीं हैं। सर्ववत्सला अशिव-विनाशिनी मां यहीं आसपास हैं। ये हैं, तभी तो कुछ मानवीय स्नेह-सूत्र बचे हुए हैं।

मां दुष्ट का निकंदन (संहार) करती हैं, तब भी उसका अमंगल नहीं चाहतीं, वह उसे मुक्ति देती हैं, मोह और मद के पाश से। वह पशु की बलि नहीं लेतीं, पशुत्व की बलि स्वीकार करती हैं। पशुत्व, जो हम सबमें कभी न कभी जाग उठता है। तब हम अपने को भूल जाते हैं, अपनी उस मानवीय प्रकृति को भूल जाते हैं, जो मां की ही प्रतिछवि है और जो उत्सर्ग में प्राप्ति ढूंढ़ती है, दूसरों में अपनापन पाती है। मां उसी आत्म-विस्मृति के अंधकार को चीरती हैं, बड़ी निमर्मता से चीरती हैं। मां की, जगत की मां की, समस्त सृष्टि की मां की, समस्त स्पंदनों की आद्या शक्ति की अवधारणा बड़ी अद्भुत है। मा धातु का संस्कृत में अर्थ है, आकार देना, मापना (कोई कितना है, कहां तक है, कब तक है, इसका निर्धारण करना), मूल्यवत्ता देना, आदर देना, प्रामाणिकता देना, वास्तविकता की पहचान कराना। जगदंबा की अवधारणा में ये सभी अर्थ समाए हुए हैं।

मां जगत में समाई रहती हैं और जगत मां में समाया रहता है। मां छिपी भी रहती हैं और हर वस्तु की निजता में प्रकट भी होती रहती हैं। हर नई कली की मुस्कान में, लहर की हर नई थिरकन में, हर मंत्र की नई गूंज में, हर शब्द के नए अर्थ में, हर ध्वनि के अनंत-विस्तारी नए आकाश में मां प्रकट होती रहती हैं। वह सृष्टि की रचना का रहस्य भी हैं। इसीलिए मां का जब हम आह्वान करते हैं, तो बाह्य सृष्टि के नए स्पंदन का आह्वान करते हैं और अपने भीतर के अन-उकसे आंसुओं का भी आह्वान करते हैं। तभी हम जो अब तक अपने को मानते-समझते रहे हैं, वह सब छोटा पड़ जाता है, एक नई आकांक्षा के आगे अपने को न्योछावर करके अपने को दूसरों तक पहुंचाने की आकांक्षा के आगे। यह आकांक्षा ही परम मंगल है।

जगदंबा के आविर्भाव की कथाएं एक ही सत्य उजागर करती हैं कि शक्ति कहीं बाहर नहीं है, भीतर है। उसे पूरी प्राणवत्ता के साथ पुकार लगाने की जरूरत पड़ती है; हम कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, तुम जागो। विष्णु की चिरनिद्रा से, विष्णु के ही शरीर से कान में मैल भरी, वे ही असुर हो गए, अर्थात विष्णु के पालक धर्म को बहरेपन ने सताया, विष्णु के भीतर ही सुषुप्त शक्ति जागती है, तो स्रष्टा ब्रह्मा की रक्षा के लिए विष्णु को तो प्रेरित करती ही है, आसुरी शक्ति को सम्मोहित भी करती है। वे अपने विनाश का उपाय स्वयं बतलाते हैं, मारे जाते हैं और शक्ति का महाकाली रूप अपना काम कर तिरोहित हो जाता है।

देवी मंगल की अधिष्ठात्री इसलिए हैं कि वह मद, मोह, अज्ञान के घेरों से मुक्ति देती हैं और जीवन के सही योग की (दूसरों को भोग चढ़ाकर योग की) तृप्ति देती हैं। देवी के मंदिर में आते ही जो गीत लोकजीवन को आपूरित करते हैं, उनका एक ही भाव है कि जहां-जहां अभाव है, वहां भाव रूप होकर आओ। कंगले के लिए माल, अंधे के लिए आंख, बच्चे के लिए विद्या, बंध्या के लिए संतान, बांझ पेड़ के लिए फल, अंधे कुएं के लिए जल, कोढ़ी के लिए निर्मल काया बनकर आओ। उस देवी को प्रसन्न करने में ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है, जो पीड़ा हरती है समस्त जगत की, जो विश्व की समान भाव से हित-चिंता करती है। वही भूमि है, वही भूमि को चारों ओर से घेरने वाली जलराशि है, वही इस सृष्टि का बीज है, वही विस्तार है और वही सबका पुनः अविभाज्य निराकार में विलयन है।

उसे प्रसन्न करना है, तो जीवन को, आस-पास को भरने वाली सुरभि बनना होना, फूल की तरह हलका और कमनीय बनना होगा, धूप की तरह अपनी जलन से वातावरण की शुद्धि बनना होगा, दीये की तरह अपने को जलाकर दूसरे की रोशनी बनना होगा और अपने को पूरी तरह निचोड़कर मृत्यु का इनकार करने वाला अमृत रूप नैवेद्य बनना होगा। यही जीवन सर्वमंगलमांगल्या का फूलों का बना धूप से गमकता, दीये से रोशन और प्रसाद वितरित करता रथ बन सकता है।

(प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित *विद्यानिवास मिश्र रचनावली* में संकलित निबंध-अंश)

पाकिस्तान की कितनी मदद कर पाएगा सऊदी अरब

यहां स्कैन करें

टीसीए रंगाचारी | पूर्व राजनयिक

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए सुरक्षा समझौते के निहितार्थ बेशक दोनों देशों के लिए अहम हो सकते हैं, मगर ऐसा कोई सुबूत नहीं, जिसके आधार पर यह कहा जाए कि भारत के प्रति जो नकारात्मक रुख पाकिस्तान का है, वही सऊदी अरब का भी है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रक्षा संबंध काफी पुराने हैं। वर्ष 1979 में जब मक्का की ग्रैंड मस्जिद पर हमला हुआ था, तब पाक सैनिकों ने सऊदी अरब की भरपूर मदद की थी। करीब दस हजार सऊदी सैनिकों को पाकिस्तानी फौज ने प्रशिक्षित भी किया था। सऊदी अरब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहा है और इजरायल की हालिया सैन्य कार्रवाइयों ने इस क्षेत्र में अनिश्चितताएं बढ़ाई हैं।

दरअसल, जब से मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्क की कमान संभाली है, तब से सऊदी अरब की सोच में काफी बदलाव आया है। वह आधुनिकता को जीने लगा है। आर्थिक विविधीकरण, सामाजिक सुधार, दुनिया भर की प्रतिभाओं और कौशल को आकर्षित करने और साथी अरब देशों के साथ संबंधों का विस्तार करके यह मुल्क खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, तो वह भारत को दुश्मन समझता है। इस पृष्ठभूमि में सऊदी अरब और पाकिस्तान, दोनों के हित बुनियादी तौर पर एक-दूसरे से अलग हैं। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान शायद ही ईरान से टकराना चाहेगा, इसी तरह रियाद भी भारत को खो देने की कीमत पर पाकिस्तान का साथ देने से रहा।

सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान शायद ही ईरान से टकराना चाहेगा, तो वहीं रियाद भी भारत को खो देने की कीमत पर इस्लामाबाद का साथ देने से रहा।

ऐसा इसलिए भी कि सऊदी अरब और भारत में कोई मतभेद नहीं है। दोनों में न कोई सीमा को लेकर विवाद है, न वैचारिक तनाव और न ही आर्थिक संघर्ष है। दोनों का आपसी व्यापार लगभग 50 अरब डॉलर का है। सऊदी अरब में सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में भारतीयों की गिनती होती है, जिससे दोनों देशों को लाभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन बार वहां का दौरा कर चुके हैं, तो मोहम्मद बिन सलमान भी 2023 में भारत आ चुके हैं। पहलगाम हमले की सऊदी अरब ने भी निंदा की थी। जाहिर है, अपने-अपने हितों को सभी राष्ट्र तवज्जो देते हैं।

इन परिस्थितियों में किसी एक पर हमला, दोनों देशों के खिलाफ कार्रवाई मानने जैसे प्रावधान की अत्यधिक व्याख्या बेमतलब है। मसलन, पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग के बावजूद अमेरिका 1965 के भारत-पाक युद्ध में उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। 1971 की जंग में भी उसने पाकिस्तान का साथ देने का प्रयास जरूर किया, लेकिन बांग्लादेश के वजूद में आने के बाद उसे तुरंत मान्यता भी दे दी। तो फिर उस समझौते का क्या महत्व रहा? दरअसल, इस्लामाबाद के हुक्मरां अपने अवाम को बताना चाहते हैं कि वे दुनिया में अलग-थलग नहीं हैं और अमेरिका के बाद सऊदी अरब भी उसके साथ है। उसकी नजर में सऊदी अरब सबसे महत्वपूर्ण इस्लामी देश है। दरअसल, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात का जो मकसद इस्लामाबाद की अंदरूनी राजनीति के लिए था, वही इस समझौते का है।

हां, एक चर्चा और जरूर चल रही है कि कहीं सऊदी अरब इस समझौते की आड़ में परमाणु ताकत तो नहीं बनना चाहता? मगर हमें यह जान लेना चाहिए कि 1945 के बाद से अब तक परमाणु हमले की धमकियां तो खूब दी गईं, लेकिन किसी देश ने इसकी हिमाकत नहीं की। अव्वल तो सहमति इसी पर है कि मध्य-पूर्व क्षेत्र में परमाणु बम होना नहीं चाहिए, और अगर ईरान या इजरायल के पास यह ताकत है, तो वे यही चाहेंगे कि सऊदी अरब इससे लैस न हो। अमेरिका भी, जो इस क्षेत्र का प्रमुख रखवाला है, ऐसा नहीं चाहेगा और ऐसी किसी भी स्थिति को रोकने का हरसंभव प्रयास करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सऊदी अरब ने परमाणु हथियार हासिल करने की किसी भी इच्छा से स्वयं इनकार किया है। बेशक, इस्लामाबाद परमाणु प्रौद्योगिकी साझा करने की मंशा रखता है, लेकिन ऐसी किसी भी कोशिश पर उसे कड़े प्रतिरोध और अमेरिकी दबाव का सामना करना होगा।

जाहिर है, यह समझौता पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से चले आ रहे आपसी सहयोग का नतीजा है। इस बात का कोई ठोस सुबूत नहीं है कि सऊदी अरब का रुख भारत विरोधी है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

जहां सृजन वहां शक्ति

स्त्री तत्व अस्तित्व का अभिन्न अंग है। यह अस्तित्व इसीलिए बन सका, क्योंकि यहां दो विपरीत ध्रुव एक साथ रहते हैं : स्त्री तत्व और पुरुष तत्व, अंधकार और प्रकाश, जीवन और मृत्यु। इन दोनों के बीच के संतुलन से सृष्टि की रचना हुई है। जहां-जहां सृजन होता है, वहां-वहां स्त्री होती है। स्त्री तत्व के बगैर सृजन हो ही नहीं सकता।

Join This Channel:- https://t.me/AllNewsPaperPaid1

स्त्री की क्षमता सिर्फ जनन-शक्ति नहीं है, इसके अलावा भी कितनी ही तरह की ऊर्जाएं हैं, जो शांत, सौम्य, रचनात्मक होती हैं। वे सभी स्त्रैण गुणों से ओत-प्रोत हैं। वे अस्तित्व का आधा हिस्सा हैं। इस स्त्री तत्व का आदर करने के लिए, उसके प्रति अनुग्रह के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए ही भारत में शक्ति-पूजा शुरू की गई। विश्व की सभी पुरा-कथाओं में देवियां पाई जाती हैं। ये किसी न किसी शक्ति की संचालक होती हैं। लेकिन देवियों की सारी मूर्तियां केवल प्रतीक हैं। पुराने लोग प्रतीकों में बात करते थे; आज इन प्रतीकों को समझने के लिए पासवर्ड जरूरी होंगे।

देवी-पूजा के मंत्र देखें, तो सरलता से समझ में आ जाएगा कि देवी का क्या मतलब है? मंत्रों में कहा गया है कि जो देवी सर्व-भूतों में किसी न किसी गुणवत्ता के रूप में बसती है, उसे प्रणाम करते हैं। ये कौन सी गुणवत्ताएं हैं? वे हैं- शक्ति, बुद्धि, निद्रा, शांति, मातृत्व, लज्जा, भ्रांति, क्षुधा, स्मृति, दया, तृष्णा, लक्ष्मी, चेतना। ये सभी मन की वृत्तियां हैं, जीवन के अलग-अलग पहलू हैं। इनको अगर मानवीय आकार दें, तो देवी जैसी मूर्ति बन जाएगी। जैसे सृजन एक शक्ति है, वैसे ही संहार भी एक शक्ति है। दोनों जरूरी हैं। लेकिन इन्हें देवी बनाकर रखेंगे, तो अपनी जिंदगी में उन्हें कैसे उतार पाएंगे? इनका मर्म यह है कि आपके भीतर ये गुण होने चाहिए। इनको अपनाएं, अपने भीतर गहराई से देखें कि क्या मेरे भीतर दया, क्षमा, शांति, बुद्धि इत्यादि गुण हैं? क्या निद्रा मेरे ऊपर प्रसन्न है?

हमारे पूर्वजों ने बहुत काव्यात्मक ढंग से देवी की [illegible] यह बीते युग की बात हुई, आज देवी को मानवीय बनाने का समय आ गया है। जो बच्चों को जन्म देकर पालती है, पैसे भी कमाती है और ऊपर से पति द्वारा पीटी जाती है; जो समाज में अकेली रहकर पुरुष के बराबर अपना स्थान बनाना चाहती है, दुराचार की शिकार बनती है; जो जन्म से पहले ही कोख में नष्ट कर दी जाती है, ये सब भी तो उसी शक्ति के रूप हैं! जिस पुरुष ने दुर्गा और काली के रूप रचे, जो देवी के लिए उपवास रखते हैं, क्या नारी के इन रूपों की पूजा कर पाएंगे? उसके लिए सिर्फ नौ दिन काफी नहीं हैं, बल्कि हर दिन, हर नारी को पूजनीय मानकर जीना होगा।

जहां-जहां सृजन होता है, वहां-वहां स्त्री होती है। स्त्री तत्व के बगैर सृजन हो ही नहीं सकता। स्त्री की क्षमता सिर्फ जनन-शक्ति नहीं है, इसके अलावा भी कितनी ही तरह की ऊर्जाएं हैं।

अमृत साधना

केर स्टार्मर | ब्रिटिश प्रधानमंत्री

सच्चे देशभक्त अपने समुदायों को तोड़ते नहीं, उनका निर्माण करते हैं। आप अपने देश से प्यार करने का दावा करते हुए उसकी बुराई नहीं कर सकते। हर जगह ऐसे लोग हैं, जो अपने पड़ोसियों की मदद कर हालात बेहतर बनाते हैं, मैं उनके साथ हूं।

श्रमिकों को नहीं मिल रही उचित पहचान

यह सच है कि भारत आज वैश्विक मंच पर एक उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा है। मोबाइल फोन के निर्माण में दूसरा सबसे बड़ा देश बनने से लेकर सेमीकंडक्टर उद्योग में कदम रखने तक हमारी उपलब्धियां गौरवपूर्ण हैं। मगर प्रश्न यह है कि 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में क्या केवल उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग ही पर्याप्त माने जाएंगे? नहीं, हमें श्रम-आधारित उद्योगों और श्रमिकों के सम्मान पर उतना ही ध्यान देना होगा, जितना बड़े उद्यमियों व निवेशकों पर दिया जा रहा है।

पिछले दो दशकों से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 15-17 प्रतिशत पर ठहरी हुई है। इसके विपरीत चीन ने लंबे समय तक 25-30 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखी। यह अंतर केवल नीतियों से नहीं, बल्कि कार्य-संस्कृति से भी पैदा हुआ है। भारत में श्रम को अपेक्षित सम्मान न मिलना सबसे बड़ी बाधा है। हमारे समाज में कुर्सी-मेज पर बैठकर की जाने वाली नौकरी को प्रतिष्ठा की नजरों से देखा जाता है, जबकि मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर जैसे कौशल-आधारित कार्यों को अक्सर हीन दृष्टि से। यही कारण है कि युवा वर्ग उद्यमशीलता और श्रम-प्रधान कार्यों से विमुख होकर कॉरपोरेट नौकरी या विदेश जाने को मजबूर है। विडंबना यह है कि जिन घरेलू कार्यों को लोग तुच्छ समझते हैं, वही काम करने वाले श्रमिक आराम से 40 से 50 हजार रुपये प्रतिमाह कमा रहे हैं। इसके बावजूद देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। इसका अर्थ है कि असल समस्या रोजगार की कमी नहीं, बल्कि मानसिकता की जकड़न है।

इस स्थिति को और जटिल बना रही है सरकार की मुफ्त योजनाएं। जब बिना परिश्रम के सुविधाएं मिलती हैं, तो श्रम का आकर्षण घटता है। यही कारण है कि बाजार से श्रमिक गायब हो रहे हैं। यदि हम चीन से मुकाबला करना चाहते हैं, तो हमें अपनी कार्य-संस्कृति को सख्त और अनुशासन की ओर मोड़ना होगा। हम चाहें, तो जर्मनी जैसे देशों से भी सीख सकते हैं, जहां श्रमिकों को अधिकारियों के समकक्ष सम्मान और वेतन दिया जाता है। यानी, जब तक कठोर परिश्रम करने वाले हाथों को उचित सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक विकास अधूरा ही रहेगा। वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम उद्यमशीलता के साथ-साथ श्रमिकों के सम्मान और कौशल को भी केंद्र में रखें। विकास का मंत्र तभी सार्थक होगा। हमें श्रम को पवित्र कर्तव्य और श्रमिकों को सम्मानित नागरिक मानना ही होगा। जरूरी यह भी है कि इस तरह की नीतियां व्यावहारिक हों। आत्मनिर्भर भारत की यही सच्ची पहचान होगी!

सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
श्रम का महत्व

कामगारों को सरकारों से मिलता प्रोत्साहन

पिछले हफ्ते की ही खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत की। कहना गलत नहीं होगा कि इस योजना से लाखों लोगों की उम्मीदों को पंख लगे हैं। इसमें जरूरतमंदों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज देने की व्यवस्था तो की ही गई है, जरूरत के उपकरण भी मुफ्त में मुहैया कराए जाएंगे और उनको अपना कारोबार आगे बढ़ाने में भरपूर मदद की जाएगी। यह सब इसलिए किया गया है, ताकि उनका श्रम बेजा न जाए। ठीक इसी तरह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से आह्वान किया है कि वे स्वदेशी उत्पादों का प्रयोग करें, ताकि घरेलू उद्योगों को नव-जीवन मिल सके। ये घरेलू उद्योग निस्संदेह सूक्ष्म व लघु उद्योग ही हैं।

इन सबसे समझा जा सकता है कि सरकारें छोटे-छोटे उद्यमियों की मदद के लिए कितनी तत्पर हैं। हमने अपने आस-पास कई ऐसे लोगों को देखा भी है, जो छोटे-छोटे व्यवसाय करके आगे बढ़े हैं। वे अपने उन उद्योगों के बूते ही आज बेहतर जीवन-यापन कर रहे हैं। इसी तरह, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत बढ़ई, दर्जी, बुनकर, नाई, सुनार समेत 20 तरह के काम-धंधे वालों को लाभ दिया जा रहा है। जाहिर है, ये ऐसे लोग हैं, जो पूरी तरह से अपने श्रम पर निर्भर हैं और अब उनको केंद्र व राज्य समर्थित योजनाओं से काफी राहत मिलने लगी है।

इन सबसे यही स्पष्ट होता है कि सरकारें श्रमिकों का पूरा ध्यान रखती हैं। कई मामलों में ज्यादा ध्यान रखा जाता है और उनके श्रम को सम्मानित तक किया जाता है। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार इसकी तस्दीक करता है, जिसका मकसद है, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के कामगारों को उनके विशिष्ट योगदानों के लिए सम्मानित करना। यह पुरस्कार उन श्रमिकों को मिलता है, जो जिम्मेदारीपूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। देश में परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ही नतीजा है कि अब लोग स्वरोजगार को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। मुद्रा जैसी योजनाओं से कर्ज पाकर वे न सिर्फ अपना कारोबार शुरू करते हैं, बल्कि आसपास के लोगों को भी उससे जोड़कर चौतरफा लाभ बांटते हैं। पहले के वर्षों में ऐसा कहां दिखता था? पहले तो लोग सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में आमतौर पर नौकरी ही अधिक ढूंढ़ा करते थे। इसीलिए, कुछ लोग यदि हमारी श्रम-शक्ति की तुलना चीन से करते हैं, तो वह सही नहीं है। श्रम-शक्ति ने ही इस देश को गढ़ा है और इसी शक्ति के भरोसे देश शीर्ष की तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा।

प्रभात कुमार, टिप्पणीकार

दैनिक जागरण

सज्जन की शक्ति सदैव जगत कल्याण के लिए होती है

चुनाव आयोग का सही फैसला

यह अच्छा हुआ कि चुनाव आयोग देश भर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआइआर को लेकर न केवल प्रतिबद्ध है, बल्कि उसने राज्यों के चुनाव अधिकारियों को यह निर्देश भी दे दिया कि वे 30 सितंबर तक इस प्रक्रिया के लिए तैयार रहें। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अक्टूबर के अंत अथवा नवंबर के आरंभ में देश भर में मतदाता सूचियों के सत्यापन का काम शुरू कर सकता है। यह कार्य होना ही चाहिए। एक तो इसलिए, क्योंकि पिछली बार अधिकांश राज्यों में मतदाता सूचियों का सत्यापन 2002 और 2004 के बीच हुआ था। अच्छा यह होगा कि चुनाव आयोग एक निश्चित अंतराल के बाद मतदाता सूचियों के सत्यापन की प्रक्रिया नियमित रूप से पूरी करे। इसकी आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि अब एक बड़ी संख्या में लोग रोजगार-व्यापार के सिलसिले में अपने मूल निवास स्थान से अन्यत्र चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी किसी से छिपा नहीं कि अनेक स्थानों पर मृत लोगों के नाम मतदाता सूचियों में दर्ज बने रहते हैं। बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया ने तो इस आशंका को भी बल दे दिया है कि अवांछित लोग और विशेष रूप से बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल आदि के नागरिक फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे भारतीय मतदाता बन बैठे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सीमावर्ती राज्यों और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में ऐसा होने की प्रबल आशंका है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बांग्लादेशी घुसपैठिये किस तरह देश के विभिन्न हिस्सों में जा बसे हैं। उन्होंने फर्जी दस्तावेजों से राशन कार्ड, आधार और उनके जरिये मतदाता पहचान पत्र भी हासिल कर लिए हैं।

अब जब चुनाव आयोग देश भर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा है तो उसे इसके लिए हरसंभव प्रयत्न करने होंगे कि इस प्रक्रिया में किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। निःसंदेह इतने बड़े देश में मतदाता सूचियों में सुधार करने की प्रक्रिया में कहीं न कहीं कुछ न कुछ खामी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मतदाता सूचियों का सत्यापन ही न किया जाए। दुर्भाग्य से विपक्षी दल यही चाहते हैं। उन्होंने बिहार में मतदाता सूचियों के सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर जिस तरह आसमान सिर पर उठा लिया, उसे देखते हुए इसका अंदेशा है कि वे देशव्यापी एसआइआर पर भी हायतौबा मचाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग को विपक्षी दलों के दुष्प्रचार की काट के लिए तैयार रहना होगा। इसकी भरी-पूरी आशंका है कि बंगाल जैसे राज्यों में उसे दुष्प्रचार के साथ राज्य सरकारों के असहयोग का भी सामना करना पड़ सकता है।

दवाओं में खोट

बीमारी के उपचार के लिए लोग दवाओं का सेवन करते हैं, लेकिन जब दवाओं की गुणवत्ता पर प्रश्न उठते हैं, तो लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है। केंद्रीय दवा नियंत्रक मानक संगठन (सीडीएससीओ) और राज्य दवा नियामकों की जांच में हिमाचल प्रदेश के 31 दवा उद्योगों में बनी 38 दवाएं गुणवत्ता के मानकों पर खरी नहीं उतरी हैं, जबकि देशभर में बनी कुल 94 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं। तीन दवाएं नकली भी निकलीं। चिंताजनक है कि ये दवाएं हृदय रोग, हाई बीपी, प्रसव, संक्रमण और आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार में उपयोग की जाती हैं। हिमाचल प्रदेश के बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, कालाअंब और पांवटा साहिब को फार्मा हब माना जाता है। यहां पर सैकड़ों दवा उद्योग हैं जहां से विदेशों में भी दवाओं की आपूर्ति की जाती है, लेकिन यहां की दवाएं बार-बार मानकों पर खरा नहीं उतर रही हैं, जो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है और हिमाचल के दवा उद्योग की छवि को भी प्रभावित कर रहा है। जरूरी दवाओं के सैंपल फेल होने से निर्माण में लापरवाही का संकेत मिलता है। नकली दवाओं का मामला गंभीर है, क्योंकि इससे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। दवा निर्माण में सख्त नियम बनाए जाने चाहिए और लापरवाही पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन उद्योगों के सैंपल बार-बार फेल हो रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। दवाओं की गुणवत्ता में किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता।

> दवाएं बार-बार मानकों पर खरा नहीं उतर रही हैं, यह लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है

सतही विमर्श सफलता की गारंटी नहीं

डा. एके वर्मा

राजनीति में फेक नैरेटिव और आक्रामक आरोपों को केंद्र में रखकर अहम मुद्दों को जैसे किनारे किया जा रहा है, उससे लोकतंत्र की गुणवत्ता प्रभावित होती है

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक खेमे अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। इस कड़ी में लोकसभा में नेता-प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ 'वोट-चोरी' का नैरेटिव चलाया हुआ है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के संदर्भ में भी विपक्ष की यह मुहिम जारी है। जबकि संविधान के अनुसार यह चुनाव आयोग का दायित्व है कि वह मतदाता सूचियों में केवल भारतीय नागरिकों के नाम सुनिश्चित करे और मृत, स्थायी रूप से अन्यत्र निवास करने वालों या डुप्लीकेट नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएं और 18 वर्ष वाले नए मतदाताओं को जोड़ा जाए। नागरिकता की पहचान हेतु मान्य दस्तावेजों में आधार कार्ड को सम्मिलित करने की मांग को स्वीकार करने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि चुनाव आयोग ने एसआइआर में कोई गैर-कानूनी प्रक्रिया अपनाई तो वह पूरी प्रक्रिया ही निरस्त कर देगा।

राहुल ने 'चोरी' को अपने चुनावी-नैरेटिव का आधार बना लिया है। 2019 लोकसभा चुनावों में उन्होंने 'चौकीदार चोर है' का नैरेटिव चलाया, 2024 लोकसभा चुनावों में 'संविधान और आरक्षण चोरी' का नैरेटिव चलाया और अब वे चुनाव-आयोग द्वारा 'वोट-चोरी' का नैरेटिव चला रहे हैं। उनके विरुद्ध हाइड्रोजन-बम फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे नैरेटिव से तात्कालिक लाभ भले हो जाए, जैसा 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन को मिला भी, लेकिन फेक नैरेटिव किसी फुलझड़ी की तरह बहुत जल्दी बुझ भी जाता है। चोरी के आरोप लगाने से पहले राहुल को नहीं भूलना चाहिए कि जिस चुनाव आयोग पर वे 'वोट चोरी' का आरोप लगा रहे है, उसी की चुनावी प्रक्रिया के जरिये उनकी पार्टी हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की सत्ता में है। तमिलनाडु और झारखंड में द्रुमक और झामुमो के साथ सत्ता साझा कर रही है। उसी के द्वारा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल, पुडुचेरी, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में गैर-भाजपा सरकारें बनी हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राहुल के 'वोट-चोरी' नैरेटिव को खारिज करते हुए कहा कि 'यदि चुनाव आयोग से हमें तब कोई समस्या नहीं जब हम चुनाव जीतते हैं, तो निश्चित ही हमें उससे तब भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जब हम चुनाव हारते हैं।' उन्होंने कहा कि 'अक्टूबर 2024 विधानसभा चुनावों में वे इतनी सीटों की उम्मीद नहीं कर रहे थे, यदि वोट चोरी करके उनकी कुछ सीटें किसी विपक्षी दल को दे दी जातीं, तो भी वे उसे स्वाभाविक जनादेश ही मानते।' ऐसी स्वीकारोक्तियां किसी नेता का कद बढ़ा देती हैं। राहुल को उनसे कुछ सीखना चाहिए।

अवधेश राजपूत

लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, लेकिन सरकार के विरुद्ध केवल आरोप, आक्षेप, उपहास, निंदा एवं अपशब्द से कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा करने वालों की छवि ही खराब होती है, जिसका खमियाजा उन्हें चुनावों में भुगतना पड़ता है। कांग्रेस एक दशक से सत्ता से बाहर होने के बाद उतावली हो रही है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रधानमंत्री को गाली दे, उन्हें 'चोर' कहे, प्रधानमंत्री की स्वर्गवासी मां को अपशब्द कहे या एआइ द्वारा उनका अभद्र 'मीम' बनाए। स्पष्ट है कि कांग्रेस ने चुनावी स्पर्धाओं में एक रणनीतिक परिवर्तन किया है। वह आरोपात्मक एवं आक्रामक 'फेक-नैरेटिव' को केंद्रीय मुद्दा बनाकर अन्य मुद्दों को गौण रखती है। बिहार में कांग्रेस एसआइआर द्वारा वोट-चोरी को आक्रामक 'नैरेटिव' के रूप में भुनाना चाहती है। फेक-नैरेटिव इंटरनेट मीडिया पर आग की तरह फैलता है और युवा मतदाताओं को सबसे ज्यादा अपनी चपेट में लेता है। शत्रु देश भी उसका फायदा उठाते हैं और देश की राजनीतिक प्रक्रिया में अवांछनीय हस्तक्षेप करते हैं। ऐसे में यह उचित ही है कि चुनाव आयोग ने एआइ-डीपफेक और फेक नैरेटिव से निपटने के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रशिक्षण दिया है और प्रत्येक जिले में 'सेल' बनाकर फेक-नैरेटिव का प्रतिकार करने का आदेश दिया है, ताकि बिहार जैसे माहौल की पुनरावृत्ति न हो। इसके बावजूद, बीते दिनों नेपाल में 'जेन जी' आंदोलन ने जिस तरह अप्रत्याशित हिंसा द्वारा सत्ता-परिवर्तन किया, उससे चुनाव आयोग, केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही राजनीतिक दलों एवं जनता सभी को और सतर्क हो जाना चाहिए।

क्या चुनावों में नैरेटिव फायदेमंद होता है? 2024 में मोदी ने चार-सौ पार के नैरेटिव का दांव चला। राहुल-अखिलेश के नेतृत्व में आइएनडीआइए ने लोकसभा चुनाव में 'संविधान-बचाओ, आरक्षण बचाओ' के नैरेटिव पर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता, लेकिन दिल्ली, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम, बिहार, हिमाचल और उत्तराखंड आदि में उनका नैरेटिव बुरी तरह पिट गया। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने 'गरीबी-हटाओ, देश-बचाओ' के नैरेटिव पर चुनाव जीता था, पर 2004 में वाजपेयी सरकार 'इंडिया शाइनिंग' के नैरेटिव पर चुनाव हार गई। 2007 में उत्तर प्रदेश में मायावती 'ब्राह्मण-दलित भाईचारा' नैरेटिव पर चुनाव जीतीं, पर 2012 में उसी नैरेटिव पर वे चुनाव हार गईं। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने 2024 मे 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' के नैरेटिव पर चुनाव जीता, पर आज उनकी साख बहुत गिर गई है।

स्पष्ट है कि एक नैरेटिव को चुनाव प्रचार के केंद्र में रखना चुनाव जीतने की कोई गारंटी नहीं, पर ऐसा करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। फर्क इतना है कि पहले नैरेटिव सकारात्मक होते थे, लेकिन इधर नैरेटिव का स्वरूप नकारात्मक एवं आक्रामक हुआ है। उसकी यह बदलती प्रवृत्ति राजनीतिक दलों में आंतरिक-लोकतंत्र के अभाव, संगठनात्मक कमजोरी, विचारधारा से दूरी, वैकल्पिक नीतियों का अभाव, नेतृत्व की अपरिपक्वता और दल की जनता से असंबद्धता को दर्शाता है, जिससे भारतीय लोकतंत्र के भविष्य पर एक प्रश्नचिह्न लगता है।

(लेखक सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

नई आपदा में छिपे नए अवसर

डा. जयंतीलाल भंडारी

ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा शुल्क हमारे पेशेवरों के लिए एक आपदा तो है, पर हम चाहें तो यह एक अवसर भी बन सकता है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा शुल्क को बढ़ाकर एक लाख डालर यानी करीब 88 लाख रुपये कर दिया है। हालांकि यह नया नियम केवल नए वीजा आवेदकों पर ही लागू होगा। यह कोई वार्षिक शुल्क नहीं है। जिन लोगों के पास पहले से ही एच-1बी वीजा है और जो इस समय अमेरिका से बाहर हैं, उनसे पुनः प्रवेश के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। जहां ट्रंप ने इस फैसले का बचाव अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा के लिए एक उपाय बताते हुए किया है। साथ ही तर्क दिया है कि आउटसोर्सिंग कंपनियों ने इस कार्यक्रम का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह सस्ते विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए किया है। वहीं कई अमेरिकी सांसदों और सामुदायिक नेताओं ने ट्रंप के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और निरर्थक बताते हुए कहा है कि इससे अमेरिकी आइटी उद्योग पर बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा। यह अमेरिका को उच्चकोटि के कुशल कामगारों से वंचित करने वाला फैसला है। अमेरिका हर साल 65,000 एच-1बी वीजा और 20,000 अतिरिक्त वीजा देता है। इनमें से लगभग 70 प्रतिशत वीजा भारतीयों को मिलते हैं। एमेजोन, माइक्रोसाफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों के हजारों कर्मचारी एच-1बी पर वहां काम करते हैं। वहीं कई भारतीय कंपनियां जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल और काग्निजेंट भी अमेरिका में काम करने के लिए इसी वीजा पर काफी निर्भर हैं। ऐसे में कुशल कामगारों को नियुक्त करने वाली छोटी कंपनियां और स्टार्टअप्स ट्रंप के फैसले से मुश्किल में आ जाएंगी। वीजा शुल्क में इस बदलाव से अमेरिका में भारतीय आइटी इंजीनियरों की नौकरियों पर भी खतरा बढ़ेगा।

निश्चित रूप से ट्रंप का यह फैसला भारत के आइटी क्षेत्र और भारतीय प्रतिभाओं के लिए एक आपदा की तरह है, लेकिन यह कई मायनों में अवसर भी बन सकता है। ऐसे आसार हैं कि भारी वीजा शुल्क से अमेरिकी कंपनियां अपनी नौकरियां विदेश यानी भारत जैसे देशों में शिफ्ट करने पर मजबूर हो जाएंगी। ऐसा होने पर ट्रंप की यह नीति अमेरिका के बजाय भारत और दूसरे देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) की स्थापना भी की जा सकती है और इसमें भारत की प्रतिभाओं को अधिक मौके मिलेंगे। जीसीसी जाब मार्केट में नया चलन है। यह आइटी सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, फाइनेंस, एचआर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करती हैं। हाईस्किल युवाओं के होने के कारण भारत जीसीसी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा हब बनता हुआ दिखा रहा है। दुनिया के 50 प्रतिशत जीसीसी सिर्फ भारत में हैं। अभी देश में 1700 जीसीसी हैं जिनसे 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। देश में जीसीसी बाजार का आकार 5.4 लाख करोड़ रुपये का है। 2030 तक इसके 8.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जीडीपी में भारत के जीसीसी का योगदान एक प्रतिशत है और 2030 तक यह 3.5 प्रतिशत हो जाएगा।

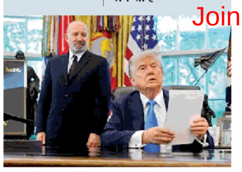

ट्रंप ने की एच-1 बी वीजा शुल्क में भारी वृद्धि। रायटर

एच-1बी वीजा शुल्क बढ़ने से दुनिया की प्रतिभाएं अमेरिका नहीं जा पाएंगी। इससे वहां इनोवेशन भी घट सकती है और भारत के इनोवेशन में नई जान आ सकती है। उम्मीद है पेटेंट, इनोवेशन और स्टार्टअप्स की अगली लहर भारत में तेजी से बढ़ेगी। भारत की प्रतिभाओं के भारत में ही रहने से भारत में शोध एवं विकास की स्थिति मजबूत होगी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआइआइ), 2024 में भारत अभी 39वें स्थान पर है। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट, 2024 के मुताबिक भारत ने तीन प्रमुख बौद्धिक संपदा अधिकारों (आइपी)-पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइनों के लिए विश्व के शीर्ष 10 देशों में स्थान प्राप्त किया है। अब अमेरिकी आइटी कंपनियां भारतीय कंपनियों को [illegible] आउटसोर्सिंग का काम दे सकती हैं। इससे भारत से अमेरिका के लिए काम बढ़ेंगे। भारत ग्लोबल आउटसोर्सिंग का नया हब बनने की डगर पर आगे बढ़ सकेगा। पिछले कई वर्षों से आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में भारत की प्रगति के पीछे देश में संचार का मजबूत ढांचा होना एक प्रमुख कारण है। दूरसंचार उद्योग के निजीकरण से नई कंपनियों के अस्तित्व में आने से दूरसंचार की दरों में भारी गिरावट आई है। उच्च कोटि की त्वरित सेवा, आइटी एक्सपर्ट और अंग्रेजी में पारंगत युवाओं की बड़ी संख्या ऐसे अन्य कारण हैं, जिनकी बदौलत भारत पूरे विश्व में आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है।

निश्चित रूप से अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों के लिए वापस लौटने और अपनी स्किल एवं आइडिया से स्वदेश में योगदान देने का मौका है। इससे 'आत्मनिर्भर भारत' मुहिम को भी गति मिलेगी। ट्रंप द्वारा लगाई गई ऊंची फीस की आपदा को अवसर में बदलने के लिए हमें अन्य कई बातों पर भी ध्यान देना होगा। जैसे कि आउटसोर्सिंग के लिए अमेरिकी बाजार के साथ-साथ यूरोप और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में नई व्यापक संभावनाओं को मुट्ठियों में लेना होगा। इसके लिए हमें देश में आउटसोर्सिंग के चमकीले भविष्य के लिए प्रतिभा निर्माण पर जोर देना होगा। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि साफ्टवेयर उद्योग में हमारी अगुआई की मुख्य वजह हमारी सेवाओं और प्रोग्राम का सस्ता होना है। अतः इस स्थिति को बरकरार रखने के लिए हमें तकनीकी दक्ष लोगों की उपलब्धता बनाए रखनी होगी।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

Join This Channel:- https://t.me/AllNewsPaperPaid1

ऊर्जा

नवरात्र का संदेश

शारदीय नवरात्र का यह अवसर हमें सतर्क, साहसी और विजयी मानसिकता तैयार करना सिखाता है। नवरात्र न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि भारत के कई हिस्सों में इसके आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक [illegible] और फसल की शुरुआत का प्रतीक है। कई किसान नवरात्र को देवी दुर्गा से भरपूर फसल के लिए आशीर्वाद लेने के अवसर के रूप में मनाते हैं, जिसमें आध्यात्मिकता को कृषि कैलेंडर के साथ जोड़ा जाता है। नवरात्र की एक विशिष्ट विशेषता इसकी क्षेत्रीय विविधता है। बंगाल में यह उत्सव दुर्गा पूजा के साथ संपन्न होता है, जो देवी दुर्गा का एक विस्तृत और भव्य उत्सव है। गुजरात में यह त्योहार गरबा और डांडिया रास से जुड़ा है। ये दो ऊर्जावान नृत्य परंपराएं हैं, जो उत्सव का केंद्र हैं। तमिलनाडु में नवरात्र गोलू या गुड़ियों की कलात्मक व्यवस्था की प्रस्तुति के साथ मनाया जाता है। नवरात्र विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व भी करता है, जो भारत को परिभाषित करती है। यद्यपि यह पर्व अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन इसका सार एक ही रहता है। यह विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को उत्सव मनाने के लिए एक साथ लाता है। यह सांस्कृतिक परंपरा भारत के बड़े सामाजिक तानेबाने का प्रतिनिधित्व करती है। यह परंपरा पूरे देश को एकसूत्र में बांधने का माध्यम बनती है।

नवरात्र विभिन्न देवियों से संबंधित है। ये नौ दिन और नौ देवियां हमें प्रतिदिन सतर्क रहने और परिवार, समाज और राष्ट्र की रक्षा उन आंतरिक एवं बाह्य दुष्ट शक्तियों से करने का एक मूल्यवान पाठ पढ़ाती हैं, जो हमारी सुंदर संस्कृति और राष्ट्र को नष्ट करना चाहती हैं। शांति, समृद्धि, विकास और जीवन का उत्सव तभी संभव है जब समाज का प्रत्येक अंग भारत को तोड़ने वाली शक्तियों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त हो।

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

दिल का मामला

देवेंद्रराज सुथार

> हृदय रोग आज भारत में मृत्यु का एक बड़ा कारण बन चुका है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है

हाल में पंजीयन नमूना सर्वेक्षण (एसआरएस) के आंकड़ों में यह बात सामने आई कि देश में होने वाली तीन में से एक मौत दिल से जुड़ी होती है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि हृदय रोग आज भारत में मृत्यु का एक बड़ा कारण बन चुका है। वर्ष 2021 से 2023 के बीच हुए अध्ययन के अनुसार देश में गैर-संक्रामक रोग यानी नान-कम्युनिकेबल डिजीज कुल मौतों का 56.7 प्रतिशत कारण बने। वहीं संक्रामक रोग, मातृत्व, नवजात और पोषण संबंधी स्थितियों से होने वाली मौतों का आंकड़ा 23.4 प्रतिशत दर्ज किया गया। गैर-संक्रामक रोगों में हृदय रोग सबसे अधिक खतरनाक साबित हो रहे हैं। कुल मौतों में से 31 प्रतिशत की वजह हृदय रोग पाए गए। यह संख्या आत्महत्या, सड़क दुर्घटना और अन्य कई बड़े कारणों से कहीं अधिक है। खासकर 30 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों में हृदय रोग एक गंभीर चुनौती बन गया है। 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच आत्महत्या मृत्यु की प्रमुख वजह मानी जाती है, लेकिन 30 वर्ष से ऊपर के लोगों में हृदय रोग मौत का सबसे बड़ा कारण है। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि हृदय रोग और जीवनशैली से जुड़े रोग किस तरह धीरे-धीरे भारत की आबादी पर गहरी चोट कर रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि बदलती जीवनशैली, असंतुलित खानपान, शारीरिक श्रम की कमी और तनाव जैसी स्थितियां इस गंभीर समस्या को बढ़ा रही हैं। तेजी से शहरीकरण और तकनीक पर बढ़ती निर्भरता के कारण लोगों के दैनिक जीवन में सक्रियता कम होती जा रही है, जिससे मोटापा, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसे रोग तेजी से फैल रहे हैं। ये सभी बीमारियां हृदय रोग के प्रमुख कारण बनती हैं। इसके अलावा धूमपान और शराब जैसे नशे भी हृदय संबंधी बीमारियों को और गंभीर बना रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देश में यह स्थिति और भी भयावह है, क्योंकि यहां स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सभी तक समान नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और समय पर इलाज न मिल पाने की वजह से स्थिति और बिगड़ जाती है। शहरों में जहां सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां भी तनावपूर्ण जीवनशैली और व्यस्त दिनचर्या के कारण लोग स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दे पाते। नतीजतन हृदय रोग जैसी बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं और मौत का सबसे बड़ा कारण बन रही हैं।

अगर गंभीर कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में स्थिति और भयावह हो सकती है। लोगों को अपनी जीवनशैली में बदलाव करना होगा, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, नशे से दूरी और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियों को भी हृदय रोगों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने होंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और हृदय रोग से संबंधित जांच एवं इलाज को सुलभ बनाना जरूरी है।

(लेखक लोकनीति विश्लेषक हैं)

लोकतंत्र की ताकत

संजय गुप्त द्वारा लिखित आलेख 'लोकतंत्र के खतरे में होने का हौवा' पढ़ा। इसमें यह बात सही रूप से सामने आई है कि लोकतंत्र पर संकट की बातें प्रायः राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाती हैं। चुनावी माहौल में विपक्ष लोकतंत्र की बुनियादी संस्थाओं पर प्रश्न उठाता है, जबकि सत्ता पक्ष इन्हें निराधार बताकर आलोचना को नकार देता है। इस स्थिति में आम नागरिक के मन में संस्थाओं की विश्वसनीयता को लेकर संशय उत्पन्न होता है। लोकतंत्र का अर्थ केवल मतदान या सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। यह मजबूत और निष्पक्ष संस्थाओं, पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के भरोसे पर टिका है। यदि विपक्ष लगातार बिना ठोस प्रमाण के चुनाव आयोग या न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है तो इससे संस्थाओं की साख कमजोर होती है। दूसरी ओर, यदि सत्ता पक्ष आलोचनात्मक आवाजों को दबाने की कोशिश करता है तो यह भी लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति इसी में है कि सत्ता और विपक्ष, दोनों अपनी भूमिकाएं जिम्मेदारी से निभाएं। चुनाव आयोग और न्यायपालिका जैसी संस्थाएं अपनी पारदर्शिता और निष्पक्षता को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करें, ताकि जनता का विश्वास मजबूत हो। वहीं विपक्ष को तथ्यों पर आधारित और रचनात्मक आलोचना करनी चाहिए, जिससे राजनीतिक विमर्श की गुणवत्ता बढ़े। लोकतंत्र हमारी आचरण-पद्धति और दृष्टिकोण से मजबूत या कमजोर होता है। जनता की सजगता और संस्थाओं की ईमानदारी ही इसे जीवंत बनाए रख सकती है। आयुष्मान पांडेय, लखनऊ विश्वविद्यालय

मेलबाक्स

ट्रंप ले रहे अविवेकपूर्ण निर्णय

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा की फीस बढ़ाने का निर्णय, पहली दृष्टि में भले ही अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए प्रतीत हो, परंतु इसके दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से प्रतिकूल ही होंगे। भारतीय आइटी कंपनियां वर्षों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका निभाती रही हैं। उनके योगदान से न केवल तकनीकी क्षेत्र को नई ऊंचाइयां मिली हैं, बल्कि लाखों अमेरिकी युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर बने हैं। ऐसे में फीस वृद्धि से इन कंपनियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और अमेरिका की प्रतिस्पर्धी क्षमता भी प्रभावित होगी। विडंबना यह है कि इस निर्णय से अमेरिकी नागरिक भी प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने कुछ सलाहकारों की गुमराह करने वाली नीतियों का शिकार हो रहे हैं। जब पूरा विश्व आपसी सहयोग और परस्पर निर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब इस प्रकार के आत्मघाती कदम अमेरिका को ही अलग-थलग करने का काम करेंगे। दरअसल किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके खुलेपन और वैश्विक साझेदारी में निहित होता है। यदि अमेरिका इस दिशा में पीछे हटता है तो नुकसान केवल भारतीय आइटी कंपनियों का नहीं, बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और प्रतिष्ठा का भी होगा। भविष्य की राह तभी सुरक्षित होगी जब अमेरिका सहयोग की भावना को अपनाएगा, न कि संरक्षणवाद की। सुरेश गोयल धूप वाला, हरियाणा

आफलाइन रहना आवश्यक है

एआइ आधारित साधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण एक नई मानसिक स्थिति पर चर्चा शुरू हुई है। इसे ''एआइ साइकोसिस'' कहा जाता है। एआइ साइकोसिस ऐसी मानसिक अवस्था है, जिसमें व्यक्ति एआइ आधारित चैटबाट्स या वर्चुअल असिस्टेंट से इतना अधिक जुड़ जाता है कि वास्तविकता और कल्पना के बीच की सीमा रेखा धुंधली होने लगती है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि एआइ उसकी निर्णय क्षमता को प्रभावित कर रहा है। लोग घंटों तक एआइ से संवाद करते रहते हैं, जिसके कारण भावनात्मक निर्भरता बढ़ जाती है। एआइ के उत्तर इतने वास्तविक लगते हैं कि लोग उन पर आंख मूंदकर भरोसा करने लगते हैं। जिनके पास भावनात्मक सहारा नहीं होता, वे एआइ को अपना वर्चुअल साथी मानने लगते हैं। असली और आभासी संवाद में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। एआइ साइकोसिस से बचने के लिए निश्चित समय पर आफलाइन रहना ज्यादा हितकारी है। दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

संपादकीय जागरण

(10) सोमवार, 22 सितंबर, 2025 : आश्विन शुक्ल प्रतिपदा वि. 2082

सज्जन की शक्ति सदैव जगत कल्याण के लिए होती है

चुनाव आयोग का सही फैसला

यह अच्छा हुआ कि चुनाव आयोग देश भर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआइआर को लेकर न केवल प्रतिबद्ध है, बल्कि उसने राज्यों के चुनाव अधिकारियों को यह निर्देश भी दे दिया कि वे 30 सितंबर तक इस प्रक्रिया के लिए तैयार रहें। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अक्टूबर के अंत अथवा नवंबर के आरंभ में देश भर में मतदाता सूचियों के सत्यापन का काम शुरू कर सकता है। यह कार्य होना ही चाहिए। एक तो इसलिए, क्योंकि पिछली बार अधिकांश राज्यों में मतदाता सूचियों का सत्यापन 2002 और 2004 के बीच हुआ था। अच्छा यह होगा कि चुनाव आयोग एक निश्चित अंतराल के बाद मतदाता सूचियों के सत्यापन की प्रक्रिया नियमित रूप से पूरी करे। इसकी आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि अब एक बड़ी संख्या में लोग रोजगार-व्यापार के सिलसिले में अपने मूल निवास स्थान से अन्यत्र चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी किसी से छिपा नहीं कि अनेक स्थानों पर मृत लोगों के नाम मतदाता सूचियों में दर्ज बने रहते हैं। बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया ने तो इस आशंका को भी बल दे दिया है कि अवांछित लोग और विशेष रूप से बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल आदि के नागरिक फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे भारतीय मतदाता बन बैठे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सीमावर्ती राज्यों और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में ऐसा होने की प्रबल आशंका है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बांग्लादेशी घुसपैठिये किस तरह देश के विभिन्न हिस्सों में जा बसे हैं। उन्होंने फर्जी दस्तावेजों से राशन कार्ड, आधार और उनके जरिये मतदाता पहचान पत्र भी हासिल कर लिए हैं। अब जब चुनाव आयोग देश भर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा है तो उसे इसके लिए हरसंभव प्रयत्न करने होंगे कि इस प्रक्रिया में किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। निःसंदेह इतने बड़े देश में मतदाता सूचियों में सुधार करने की प्रक्रिया में कहीं न कहीं कुछ न कुछ खामी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मतदाता सूचियों का सत्यापन ही न किया जाए। दुर्भाग्य से विपक्षी दल यही चाहते हैं। उन्होंने बिहार में मतदाता सूचियों के सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर जिस तरह आसमान सिर पर उठा लिया, उसे देखते हुए इसका अंदेशा है कि वे देशव्यापी एसआइआर पर भी हायतौबा मचाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग को विपक्षी दलों के दुष्प्रचार की काट के लिए तैयार रहना होगा। इसकी भरी-पूरी आशंका है कि बंगाल जैसे राज्यों में उसे दुष्प्रचार के साथ राज्य सरकारों के असहयोग का भी सामना करना पड़ सकता है।

बच्चों की सुरक्षा

सारण जिले में रविवार को आटो रिक्शा से स्कूल जा रहे दो बच्चों की सड़क दुर्घटना में हुई मौत ने सुरक्षा पर पुनः प्रश्न खड़े कर दिए हैं। बच्चे आटो रिक्शा पर सवार थे, जिसमें एक हाइवा ने टक्कर मार दी। गया में भी बच्चों को ले जा रहा आटो रिक्शा दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कई बच्चे घायल हो गए। सप्ताह भर पहले ही एक स्कूल बस में एक टैंकर ने टक्कर मार दी थी। कुछ दिनों पहले जहानाबाद में एक बच्चे की मौत स्कूल बस से गिरकर हो गई। जर्जर फर्श पर प्लाइवुड का टुकड़ा रख दिया गया था, जिसके खिसक जाने के कारण चलती बस से बच्चा गिरा और टायर से कुचल गया। हर दिन गांव से लेकर शहर तक लाखों की संख्या में बच्चे स्कूल आते-जाते हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। केवल दिशा-निर्देश और बैठकों से काम नहीं चलेगा। व्यावहारिक रूप से यह देखना होगा कि उसका अनुपालन हो भी रहा है या नहीं। बच्चों को जिन वाहनों से ले जाया जा रहा है, वे मानक के अनुरूप हैं या नहीं। उसके चालक का कोई रिकार्ड प्रशासन के पास है या नहीं, यह सारी जानकारी होनी चाहिए। स्कूल के समय सड़कों पर तेज गति से वाहन चलाने पर भी रोक लगानी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़े दंड देने होंगे। अभिभावकों को भी बच्चों की चिंता करनी होगी। उनकी सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए।

> बच्चों को यदि ठूंस-ठूंस कर ले जाया जाता है तो अभिभावक ऐसे वाहनों से भेजने से मना करें और प्रशासन से इसकी शिकायत करें।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या ट्रंप द्वारा एच-1 बी वीजा पर शुल्क बढ़ाना भारत के लिए आपदा के साथ एक अवसर भी है?

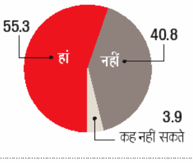

आज का सवाल

क्या घटी हुई जीएसटी दरें उपभोग को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

सतही विमर्श सफलता की गारंटी नहीं

डा. एके वर्मा

राजनीति में फेक नैरेटिव और आक्रामक आरोपों को केंद्र में रखकर अहम मुद्दों को जैसे किनारे किया जा रहा है, उससे लोकतंत्र की गुणवत्ता प्रभावित होती है

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक खेमे अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। इस कड़ी में लोकसभा में नेता-प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ 'वोट-चोरी' का नैरेटिव चलाया हुआ है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के संदर्भ में भी विपक्ष की यह मुहिम जारी है। जबकि संविधान के अनुसार यह चुनाव आयोग का दायित्व है कि वह मतदाता सूचियों में केवल भारतीय नागरिकों के नाम सुनिश्चित करे और मृत, स्थायी रूप से अन्यत्र निवास करने वालों या डुप्लीकेट नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएं और 18 वर्ष वाले नए मतदाताओं को जोड़ा जाए। नागरिकता की पहचान हेतु मान्य दस्तावेजों में आधार कार्ड को सम्मिलित करने की मांग को स्वीकार करने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि चुनाव आयोग ने एसआइआर में कोई गैर-कानूनी प्रक्रिया अपनाई तो वह पूरी प्रक्रिया ही निरस्त कर देगा।

राहुल ने 'चोरी' को अपने चुनावी-नैरेटिव का आधार बना लिया है। 2019 लोकसभा चुनावों में उन्होंने 'चौकीदार चोर है' का नैरेटिव चलाया, 2024 लोकसभा चुनावों में 'संविधान और आरक्षण चोरी' का नैरेटिव चलाया और अब वे चुनाव-आयोग द्वारा 'वोट-चोरी' का नैरेटिव चला रहे हैं। उनके विरुद्ध हाइड्रोजन-बम फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे नैरेटिव से तात्कालिक लाभ भले हो जाए, जैसा 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन को मिला भी, लेकिन फेक नैरेटिव किसी फुलझड़ी की तरह बहुत जल्दी बुझ भी जाता है। चोरी के आरोप लगाने से पहले राहुल को नहीं भूलना चाहिए कि जिस चुनाव आयोग पर वे 'वोट चोरी' का आरोप लगा रहे है, उसी की चुनावी प्रक्रिया के जरिये उनकी पार्टी हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की सत्ता में है। तमिलनाडु और झारखंड में द्रुमक और झामुमो के साथ सत्ता साझा कर रही है। उसी के द्वारा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल, पुडुचेरी, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में गैर-भाजपा सरकारें बनी हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राहुल के 'वोट-चोरी' नैरेटिव को खारिज करते हुए कहा कि 'यदि चुनाव आयोग से हमें तब कोई समस्या नहीं जब हम चुनाव जीतते हैं, तो निश्चित ही हमें उससे तब भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जब हम चुनाव हारते हैं।' उन्होंने कहा कि 'अक्टूबर 2024 विधानसभा चुनावों में वे इतनी सीटों की उम्मीद नहीं कर रहे थे, यदि वोट चोरी करके उनकी कुछ सीटें किसी विपक्षी दल को दे दी जातीं, तो भी वे उसे स्वाभाविक जनादेश ही मानते।' ऐसी स्वीकारोक्तियां किसी नेता का कद बढ़ा देती हैं। राहुल को उनसे कुछ सीखना चाहिए। क्या कांग्रेस स्वतंत्रता के बाद स्वयं द्वारा की गई चोरियों का इतिहास भूल गई है?

अवधेश राजपूत

लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, लेकिन सरकार के विरुद्ध केवल आरोप, आक्षेप, उपहास, निंदा एवं अपशब्द से कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा करने वालों की छवि ही खराब होती है, जिसका खमियाजा उन्हें चुनावों में भुगतना पड़ता है। कांग्रेस एक दशक से सत्ता से बाहर होने के बाद उतावली हो रही है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रधानमंत्री को गाली दे, उन्हें 'चोर' कहे, प्रधानमंत्री की स्वर्गवासी मां को अपशब्द कहे या एआइ द्वारा उनका अभद्र 'मीम' बनाए। स्पष्ट है कि कांग्रेस ने चुनावी स्पर्धाओं में एक रणनीतिक परिवर्तन किया है। वह आरोपात्मक एवं आक्रामक 'फेक-नैरेटिव' को केंद्रीय मुद्दा बनाकर अन्य मुद्दों को गौण रखती है। बिहार में कांग्रेस एसआइआर द्वारा वोट-चोरी को आक्रामक 'नैरेटिव' के रूप में भुनाना चाहती है। फेक-नैरेटिव इंटरनेट मीडिया पर आग की तरह फैलता है और युवा मतदाताओं को सबसे ज्यादा अपनी चपेट में लेता है। शत्रु देश भी उसका फायदा उठाते हैं और देश की राजनीतिक प्रक्रिया में अवांछनीय हस्तक्षेप करते हैं। ऐसे में यह उचित ही है कि चुनाव आयोग ने एआइ-डीपफेक और फेक नैरेटिव से निपटने के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रशिक्षण दिया है और प्रत्येक जिले में 'सेल' बनाकर फेक-नैरेटिव का प्रतिकार करने का आदेश दिया है, ताकि बिहार जैसे माहौल की पुनरावृत्ति न हो। इसके बावजूद, बीते दिनों नेपाल में 'जेन जी' आंदोलन ने जिस तरह अप्रत्याशित हिंसा द्वारा सत्ता-परिवर्तन किया, उससे चुनाव आयोग, केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही राजनीतिक दलों एवं जनता सभी को और सतर्क हो जाना चाहिए।

क्या चुनावों में नैरेटिव फायदेमंद होता है? 2024 में मोदी ने चार-सौ पार के नैरेटिव का दांव चला। राहुल-अखिलेश के नेतृत्व में आइएनडीआइए ने लोकसभा चुनाव में 'संविधान-बचाओ, आरक्षण बचाओ' के नैरेटिव पर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता, लेकिन दिल्ली, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम, बिहार, हिमाचल और उत्तराखंड आदि में उनका नैरेटिव बुरी तरह पिट गया। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने 'गरीबी-हटाओ, देश-बचाओ' के नैरेटिव पर चुनाव जीता था, पर 2004 में वाजपेयी सरकार 'इंडिया शाइनिंग' के नैरेटिव पर चुनाव हार गई। 2007 में उत्तर प्रदेश में मायावती 'ब्राह्मण-दलित भाईचारा' नैरेटिव पर चुनाव जीतीं, पर 2012 में उसी नैरेटिव पर वे चुनाव हार गईं। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने 2024 मे 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' के नैरेटिव पर चुनाव जीता, लेकिन आज उनकी साख बहुत गिर गई है।

स्पष्ट है कि एक नैरेटिव को चुनाव प्रचार के केंद्र में रखना चुनाव जीतने की कोई गारंटी नहीं, पर ऐसा करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। फर्क इतना है कि पहले नैरेटिव सकारात्मक होते थे, लेकिन इधर नैरेटिव का स्वरूप नकारात्मक एवं आक्रामक हुआ है। उसकी यह बदलती प्रवृत्ति राजनीतिक दलों में आंतरिक-लोकतंत्र के अभाव, संगठनात्मक कमजोरी, विचारधारा से दूरी, वैकल्पिक नीतियों का अभाव, नेतृत्व की अपरिपक्वता और दल की जनता से असंबद्धता को दर्शाता है, जिससे भारतीय लोकतंत्र के भविष्य पर एक प्रश्नचिह्न लगता है।

(लेखक सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

नई आपदा में छिपे नए अवसर

डा. जयंतीलाल भंडारी

ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा शुल्क हमारे पेशेवरों के लिए एक आपदा तो है, पर हम चाहें तो यह एक अवसर भी बन सकता है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा शुल्क को बढ़ाकर एक लाख डालर यानी करीब 88 लाख रुपये कर दिया है। हालांकि यह नया नियम केवल नए वीजा आवेदकों पर ही लागू होगा। यह कोई वार्षिक शुल्क नहीं है। जिन लोगों के पास पहले से ही एच-1बी वीजा है और जो इस समय अमेरिका से बाहर हैं, उनसे पुनः प्रवेश के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। जहां ट्रंप ने इस फैसले का बचाव अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा के लिए एक उपाय बताते हुए किया है। साथ ही तर्क दिया है कि आउटसोर्सिंग कंपनियों ने इस कार्यक्रम का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह सस्ते विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए किया है। वहीं कई अमेरिकी सांसदों और सामुदायिक नेताओं ने ट्रंप के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और निरर्थक बताते हुए कहा है कि इससे अमेरिकी आइटी उद्योग पर बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा। यह अमेरिका को उच्चकोटि के कुशल कामगारों से वंचित करने वाला फैसला है। अमेरिका हर साल 65,000 एच-1बी वीजा और 20,000 अतिरिक्त वीजा देता है। इनमें से लगभग 70 प्रतिशत वीजा भारतीयों को मिलते हैं। एमेजोन, माइक्रोसाफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों के हजारों कर्मचारी एच-1बी पर वहां काम करते हैं। वहीं कई भारतीय कंपनियां जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल और काग्निजेंट भी अमेरिका में काम करने के लिए इसी वीजा पर काफी निर्भर हैं। ऐसे में कुशल कामगारों को नियुक्त करने वाली छोटी कंपनियां और स्टार्टअप्स ट्रंप के फैसले से मुश्किल में आ जाएंगी। वीजा शुल्क में इस बदलाव से अमेरिका में भारतीय आइटी इंजीनियरों की नौकरियों पर भी खतरा बढ़ेगा।

निश्चित रूप से ट्रंप का यह फैसला भारत के आइटी क्षेत्र और भारतीय प्रतिभाओं के लिए एक आपदा की तरह है, लेकिन यह कई मायनों में अवसर भी बन सकता है। ऐसे आसार हैं कि भारी वीजा शुल्क से अमेरिकी कंपनियां अपनी नौकरियां विदेश यानी भारत जैसे देशों में शिफ्ट करने पर मजबूर हो जाएंगी। ऐसा होने पर ट्रंप की यह नीति अमेरिका के बजाय भारत और दूसरे देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) की स्थापना भी की जा सकती है और इसमें भारत की प्रतिभाओं को अधिक मौके मिलेंगे। जीसीसी जाब मार्केट में नया चलन है। यह आइटी सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, फाइनेंस, एचआर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करती हैं। हाईस्किल युवाओं के होने के कारण भारत जीसीसी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा हब बनता हुआ दिखा रहा है। दुनिया के 50 प्रतिशत जीसीसी सिर्फ भारत में हैं। अभी देश में 1700 जीसीसी हैं जिनसे 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। देश में जीसीसी बाजार का आकार 5.4 लाख करोड़ रुपये का है। 2030 तक इसके 8.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जीडीपी में भारत के जीसीसी का योगदान एक प्रतिशत है और 2030 तक यह 3.5 प्रतिशत हो जाएगा।

ट्रंप ने की एच-1 बी वीजा शुल्क में भारी वृद्धि ● रायटर

एच-1बी वीजा शुल्क बढ़ने से दुनिया की प्रतिभाएं अमेरिका नहीं जा पाएंगी। इससे वहां इनोवेशन भी घट सकती है और भारत के इनोवेशन में नई जान आ सकती है। उम्मीद है पेटेंट, इनोवेशन और स्टार्टअप्स की अगली लहर भारत में तेजी से बढ़ेगी। भारत की प्रतिभाओं के भारत में ही रहने से भारत में शोध एवं विकास की स्थिति मजबूत होगी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआइआइ), 2024 में भारत अभी 39वें स्थान पर है। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट, 2024 के मुताबिक भारत ने तीन प्रमुख बौद्धिक संपदा अधिकारों (आइपी)-पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइनों के लिए विश्व के शीर्ष 10 देशों में स्थान प्राप्त किया है। अब अमेरिकी आइटी कंपनियां भारतीय कंपनियों को ज्यादा आउटसोर्सिंग का काम दे सकती हैं। इससे भारत से अमेरिका के लिए काम बढ़ेंगे। भारत ग्लोबल आउटसोर्सिंग का नया हब बनने की [illegible] आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में भारत की प्रगति के पीछे देश में संचार का मजबूत ढांचा होना एक प्रमुख कारण है। दूरसंचार उद्योग के निजीकरण से नई कंपनियों के अस्तित्व में आने से दूरसंचार की दरों में भारी गिरावट आई है। उच्च कोटि की त्वरित सेवा, आइटी एक्सपर्ट और अंग्रेजी में पारंगत युवाओं की बड़ी संख्या ऐसे अन्य कारण हैं, जिनकी बदौलत भारत पूरे विश्व में आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है।

निश्चित रूप से अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों के लिए वापस लौटने और अपनी स्किल एवं आइडिया से स्वदेश में योगदान देने का मौका है। इससे 'आत्मनिर्भर भारत' मुहिम को भी गति मिलेगी। ट्रंप द्वारा लगाई गई ऊंची फीस की आपदा को अवसर में बदलने के लिए हमें अन्य कई बातों पर भी ध्यान देना होगा। जैसे कि आउटसोर्सिंग के लिए अमेरिकी बाजार के साथ-साथ यूरोप और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में नई व्यापक संभावनाओं को मुट्ठियों में लेना होगा। इसके लिए हमें देश में आउटसोर्सिंग के चमकीले भविष्य के लिए प्रतिभा निर्माण पर जोर देना होगा। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि साफ्टवेयर उद्योग में हमारी अगुआई की मुख्य वजह हमारी सेवाओं और प्रोग्राम का सस्ता होना है। अतः इस स्थिति को बरकरार रखने के लिए हमें तकनीकी दक्ष लोगों की उपलब्धता बनाए रखनी होगी।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

Join This Channel:- https://t.me/AllNewsPaperPaid1

ऊर्जा

नवरात्र का संदेश

शारदीय नवरात्र का यह अवसर हमें सतर्क, साहसी और विजयी मानसिकता तैयार करना सिखाता है। नवरात्र न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि भारत के कई हिस्सों में इसके आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक निहितार्थ भी हैं। यह मानसून के समापन और फसल की शुरुआत का प्रतीक है। कई किसान नवरात्र को देवी दुर्गा से भरपूर फसल के लिए आशीर्वाद लेने के अवसर के रूप में मनाते हैं, जिसमें आध्यात्मिकता को [illegible]

नवरात्र की एक विशिष्ट विशेषता इसकी क्षेत्रीय विविधता है। बंगाल में यह उत्सव दुर्गा पूजा के साथ संपन्न होता है, जो देवी दुर्गा का एक विस्तृत और भव्य उत्सव है। गुजरात में यह त्योहार गरबा और डांडिया रास से जुड़ा है। ये दो ऊर्जावान नृत्य परंपराएं हैं, जो उत्सव का केंद्र हैं। तमिलनाडु में नवरात्र गोलू या गुड़ियों की कलात्मक व्यवस्था की प्रस्तुति के साथ मनाया जाता है। नवरात्र विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व भी करता है, जो भारत को परिभाषित करती है। यद्यपि यह पर्व अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन इसका सार एक ही रहता है। यह विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को उत्सव मनाने के लिए एक साथ लाता है। यह सांस्कृतिक परंपरा भारत के बड़े सामाजिक तानेबाने का प्रतिनिधित्व करती है। यह परंपरा पूरे देश को एकसूत्र में बांधने का माध्यम बनती है।

नवरात्र विभिन्न देवियों से संबंधित है। ये नौ दिन और नौ देवियां हमें प्रतिदिन सतर्क रहने और परिवार, समाज और राष्ट्र की रक्षा उन आंतरिक एवं बाह्य दुष्ट शक्तियों से करने का एक मूल्यवान पाठ पढ़ाती हैं, जो हमारी सुंदर संस्कृति और राष्ट्र को नष्ट करना चाहती हैं। शांति, समृद्धि, विकास और जीवन का उत्सव तभी संभव है जब समाज का प्रत्येक अंग भारत को तोड़ने वाली शक्तियों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त हो।

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

पाठकनामा

pathaknama@pat .jagran.com

लोकतंत्र की ताकत

संजय गुप्त द्वारा लिखित आलेख 'लोकतंत्र के खतरे में होने का हौवा' पढ़ा। इसमें यह बात सही रूप से सामने आई है कि लोकतंत्र पर संकट की बातें प्रायः राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाती हैं। चुनावी माहौल में विपक्ष लोकतंत्र की बुनियादी संस्थाओं पर प्रश्न उठाता है, जबकि सत्ता पक्ष इन्हें निराधार बताकर आलोचना को नकार देता है। इस स्थिति में आम नागरिक के मन में संस्थाओं की विश्वसनीयता को लेकर संशय उत्पन्न होता है। लोकतंत्र का अर्थ केवल मतदान या सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। यह मजबूत और निष्पक्ष संस्थाओं, पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के भरोसे पर टिका है। यदि विपक्ष लगातार बिना ठोस प्रमाण के चुनाव आयोग या न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है तो इससे संस्थाओं की साख कमजोर होती है। दूसरी ओर, यदि सत्ता पक्ष आलोचनात्मक आवाजों को दबाने की कोशिश करता है तो यह भी लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति इसी में है कि सत्ता और विपक्ष, दोनों अपनी भूमिकाएं जिम्मेदारी से निभाएं। चुनाव आयोग और न्यायपालिका जैसी संस्थाएं अपनी पारदर्शिता और निष्पक्षता को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करें, ताकि जनता का विश्वास मजबूत हो। वहीं विपक्ष को तथ्यों पर आधारित और रचनात्मक आलोचना करनी चाहिए, जिससे राजनीतिक विमर्श की गुणवत्ता बढ़े। लोकतंत्र किसी 'हौवे' से नहीं, बल्कि हमारी आचरण-पद्धति और दृष्टिकोण से मजबूत या कमजोर होता है। जनता की सजगता और संस्थाओं की ईमानदारी ही इसे जीवंत बनाए रख सकती है।

आयुष्मान पांडेय, लखनऊ विश्वविद्यालय

भारत के धनी अमेरिकियों से अपेक्षा

भारत अमेरिका संबंधों में कटुता बढ़ाने की दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चाल चल दी है। एच वन वीजा को लेकर जो नए नियम अमेरिका ने बनाए हैं और जिस तरह से शुल्क में वृद्धि की है, वह बिल्कुल अनुचित है। भारतीयों को पहले वीजा के लिए 88 हजार रुपये लगते थे, लेकिन अब 88 लाख देने होंगे। जाहिर है, ऐसे में भारत से वहां जाने वाले निम्न व मध्यवर्गीय कामगारों को कठिनाई होगी। ये कामगार अमेरिका की बड़ी-बड़ी कंपनियों की उत्पादकता तो बढ़ाते ही हैं, स्वयं भी डालर में कमाई कर घर भेजते हैं। अमेरिका की माइक्रोसाफ्ट, अमेजन, मेटा व अन्य कंपनियों में काम कर उनके मुनाफे में वृद्धि कराते हैं और देश को भी लाभ पहुंचाते हैं। अमेरिकी एच वन वीजा का सबसे अधिक लाभ भारतीय ही लेते हैं, ऐसे में इससे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इन सबके बीच अफसोसजनक पहलू यह है कि अमेरिका में रहने वाले लाखों भारतीय इस संदर्भ में प्रभावी भूमिका में नहीं दिख रहे हैं। भारतीय मूल के धनी अमेरिकियों पर भारतीय भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे में उन धनी मूल भारतीयों से संवेदनशील बनकर भारत के प्रति भी चिंता करने की अपेक्षा तो हम कर ही सकते हैं।

मिथिलेश कुमार, भागलपुर, बिहार

गहरी सामरिक चिंता

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ रक्षा समझौता भारत के लिए गहरी सामरिक चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें यह प्रविधान है कि किसी एक पर हमला दोनों पर माना जाएगा। यदि भारत भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद-रोधी कार्रवाई करता है तो सऊदी अरब इसे स्वयं पर हमला मान सकता है। यह स्थिति भारत की सैन्य स्वतंत्रता और रणनीतिक विकल्पों को सीमित करती है और भारत के लिए नई चुनौती खड़ी करती है। पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में सऊदी अरब का पाकिस्तान की ओर झुकाव भारत की कूटनीतिक चिंताओं को बढ़ाता है। इस परिस्थिति में भारत को आर्थिक, ऊर्जा और तकनीकी सहयोग के माध्यम से सऊदी अरब से अपने संबंध और गहरे करने चाहिए। यदि भारत इस क्षेत्र में रचनात्मक प्रभाव स्थापित करता है तो संभावित तनाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए भारत को कठोर रणनीति और लचीले संवाद का संयोजन अपनाना होगा। सऊदी अरब का यह कदम अमेरिका पर घटते भरोसे और क्षेत्रीय अस्थिरता का परिणाम है। भारत को जी-20, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर सऊदी अरब से संवाद बढ़ाना चाहिए। ईरान, कतर, यूएई जैसे देशों से भी संतुलित संबंध बनाना अनिवार्य है।

अवनीश कुमार गुप्ता, पटना

पोस्ट

सैम पित्रोदा पहले विवादास्पद बयान देते हैं, फिर उस बयान पर सफाई देने में उनका और पार्टी का समय निकल जाता है। पिछले 10-12 साल से उन्होंने इसी तरीके से खुद को और पार्टी को व्यस्त रखा है।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

प्रधानमंत्री मोदी नवरात्र में स्वदेशी का संकल्प दिला रहे हैं। यह मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। अमेरिका ने एक ऐसी आर्थिक लड़ाई शुरू की है कि जब तक भारत के हर घर से इस लड़ाई को नहीं लड़ा जाएगा, तब तक जीत नहीं मिलेगी।

मीनाक्षी जोशी@IMinakshiJoshi

भारत के प्रतिभाशाली लोगों ने वैश्विक इनोवेशन को गति प्रदान की है। सिलिकान वैली से लेकर वाल स्ट्रीट तक अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। एच-1 बी वीजा पर एक लाख डालर का शुल्क लगाकर अमेरिका को ही नुकसान होगा और इससे भारतीय प्रतिभाओं की आभा कमजोर नहीं होगी। हमारे युवा विदेश में ही नौकरी के उत्सुक नहीं, बल्कि वे देश में भी रोजगार सृजन में लगे हैं।

अभिषेक सिंघवी@DrAMSinghvi

जनपथ

मां दुर्गा के आगमन से फैले उल्लास,
दैत्य वंश का कीजिए आकर समूल नाश।
आकर समूल नाश बचे ना इक आतंकी,
मां तू लीजै थाम ट्रंप की भी नौटंकी!
'आधा दुश्मन' रोज बांग दे बनकर मुर्गा,
भारत पर आशीष हस्त फेरो मां दुर्गा!!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर. बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 161

****

कल्पमेधा

किसी देश को इससे नहीं परखना चाहिए कि वह अपने उच्च वर्ग के नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि निम्न वर्ग के नागरिकों के साथ उसका व्यवहार कैसा है।

– नेल्सन मंडेला

बाजार की संवेदना

पिछले कुछ दशकों में भारत में एक बड़ा उपभोक्ता वर्ग ऐसा खड़ा हुआ है, जिसकी जरूरतें कई बार बाजार से संचालित होती हैं। भारत में आइफोन-17 की बिक्री शुरू होने के साथ ही बीते शुक्रवार को जैसा माहौल देखा गया, वह देश की अर्थव्यवस्था में दिनोंदिन विकास के दावे के समांतर किसी वस्तु की जरूरत और उसके उपभोग के पहलू पर विचार के तकाजे को रेखांकित करता है। गौरतलब है कि आइफोन-17 की बिक्री शुरू होने की घोषणा के साथ ही दिल्ली और मुंबई सहित कई शहरों में एप्पल के स्टोर के सामने युवाओं की भारी भीड़ जमा हो गई। उनमें से बहुत सारे लोग वहां रात में ही पहुंच गए थे। मुंबई स्थित स्टोर के सामने लोगों के बीच आपस में मारपीट की भी खबरें आईं। कहा जा सकता है कि बाजार में किसी नई चीज के आने पर उसके प्रति युवाओं के बीच ऐसा आकर्षण और उत्साह सामान्य है। लेकिन जिस दौर में दुनिया भर में रोज खड़ी हो रही नई चुनौतियों और राजनीतिक-सामाजिक स्तर पर जड़ता के समांतर उपजे एक संक्रमणकाल के बीच युवाओं की बेहद महत्त्वपूर्ण भूमिका सामने आ रही है, उसमें आइफोन के नए संस्करण को लेकर ऐसे आकर्षण को कैसे देखा जाएगा।

जिस दिन आइफोन-17 खरीदने के लिए हजारों युवा एप्पल के स्टोर के सामने उमड़ पड़े, उसी दिन यह भी खबर आई कि राजस्थान में करीब चौबीस लाख युवा चपरासी के पद पर नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल थे। इनमें बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की थी, जिनके पास उच्च शिक्षा की डिग्री है। रोजगार के अवसर से संबंधित ऐसी खबरें अक्सर आती रहती हैं। बढ़ती बेरोजगारी की चुनौतियों के अलावा भी अमीरी-गरीबी के बीच तेजी से बढ़ती खाई और शिक्षा से लेकर आर्थिक मोर्चे पर देश जिस तरह की जटिलताओं से जूझ रहा है, उसमें यह सवाल स्वाभाविक है कि देश के सक्षम तबकों के युवाओं का सरोकार और उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। ऐसे दृश्य आम हैं, जिनमें अपने आसपास हो रही किसी त्रासद घटना पर युवाओं के बीच जरूरी संवेदना और सक्रियता का अभाव दिखता है। ऐसे में राष्ट्र और समाज के हित से जुड़े बड़े सवालों पर उनकी ठोस प्रतिक्रिया की बस उम्मीद ही की जा सकती है। हालांकि राजनीतिक अभियानों में युवाओं का एक बड़ा वर्ग अक्सर सक्रिय दिखता है, लेकिन तयशुदा पक्षधरता की अपनी सीमा होती है।

हालांकि यह भी सच है कि एक बड़ी आबादी का कोई हिस्सा अगर बाजार में सक्रिय उपभोक्ता के रूप में दिखता है, तो इसे समूचे समाज का प्रतिनिधि चरित्र नहीं माना जाना चाहिए। मगर जिस आइफोन-17 को लेने के लिए मची होड़ चर्चा का विषय बनी, उसकी कीमत लगभग डेढ़ लाख रुपए है। कई युवाओं ने उसकी पूरी कीमत चुकाई होगी तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे, जिन्होंने उसके लिए कर्ज या मासिक किस्त का सहारा लिया होगा। दरअसल, बाजार कई बार जरूरतों को परिभाषित करता है और इस क्रम में लोग गैरजरूरी चीजें भी अपने लिए अनिवार्य मान कर खरीद लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी के संदर्भ में इसे एक मजबूत सहायक कारक माना गया है। मगर इस क्रम में ऐसे मौके भी सामने आते हैं, जब इस पहलू पर विचार करने की जरूरत महसूस होती है कि उपभोग आधारित मानसिकता से लैस लोगों और तबकों के बीच जरूरतों और संवेदनाओं में तालमेल की दिशा क्या है और इससे भविष्य के कैसे समाज की रूपरेखा बन रही है।

शांति का समर्थन

मणिपुर में कुछ दिनों की शांति के बाद हिंसक घटनाओं को फिर से हवा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में कुकी जो संगठनों और केंद्र सरकार के बीच पिछले दिनों हुए समझौते तथा उसके बाद प्रधानमंत्री के मणिपुर दौरे के बाद से उम्मीद की जा रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर, शुक्रवार शाम को राज्य के बिष्णुपुर जिले में असम राइफल्स के वाहन पर घात लगाकर किए गए हमले में दो जवान शहीद हो गए और पांच अन्य घायल हो गए। हालांकि, इस हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे किसी उग्रवादी संगठन का हाथ हो सकता है। यानी यह घटना राज्य में आपसी संघर्ष के मसले से हटकर क्षेत्र में शांति भंग करने की साजिश हो सकती है। यह आशंका इसलिए भी स्वाभाविक लगती है, क्योंकि इस हमले के विरोध में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। इससे साफ है कि अब वे क्षेत्र में किसी तरह की हिंसा नहीं चाहते और शांति कायम रखने के हिमायती हैं।

इसमें दोराय नहीं कि मणिपुर के लोगों की मूल समस्याओं का समय पर निपटारा न होने से वहां जातीय हिंसा भड़की और इसका असर आम लोगों के जीवन पर भी पड़ा। कई लोगों को अपना घर-बार छोड़कर शिविरों में शरण लेनी पड़ी और कुछ लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। यह भी सच है कि हिंसक घटनाओं के बाद सरकार ने राज्य में शांति बहाली को लेकर कई कदम उठाए। पिछले दिनों कुकी जो समुदाय से संबंधित दो संगठनों के साथ शांति समझौता और उसके बाद प्रधानमंत्री का मणिपुर दौरा इन्हीं प्रयासों की कड़ी का एक हिस्सा है। इससे पहले कुकी-जो और मैतेई समुदायों की ओर से आई प्रतिक्रिया से हालात सामान्य होने के संकेत मिले थे। मगर, अब अचानक सुरक्षाबल के वाहन पर हुए घातक हमले ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि स्थानीय लोग इस हमले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह के हमलों की पुनरावृत्ति न हो और राज्य के लोगों का शासन-प्रशासन पर भरोसा कायम रहे।

संतुलित विकास में हरा सोना है बांस

राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत बांस के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सतत विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बांस भविष्य में भारत के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है।

अरुणा व्यास

चीन के बाद भारत दूसरा बड़ा बांस उत्पादक देश है। मगर निर्यात के मामले में चीन हमसे अब भी बहुत आगे है। वह भारत, वियतनाम, जर्मनी, नीदरलैंड और तुर्की जैसे देशों में बांस का सर्वाधिक निर्यात करता है। एक दौर में ब्रिटिश हुकूमत ने बांस को एक पौधे की श्रेणी में रखते हुए इसकी खेती और कटाई पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लगाई थीं। दशकों तक इन दमनकारी नियमों के कारण बांस के बहुउपयोग पर कभी ध्यान दिया ही नहीं गया। बांस को खेती के रूप में स्थापित किए जाने, इससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और पर्यावरण संरक्षण में इसके महत्त्व को देखते हुए वर्ष 2017 में भारत में बांस को घास के रूप में दोबारा वर्गीकृत किया गया। इसका बड़ा लाभ यह हुआ कि देश भर में बांस को प्रतिबंधात्मक नियमों से मुक्ति मिल गई। किसानों को आसानी से इसकी कटाई और परिवहन की अनुमति मिलने लगी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इसका लाभ उठाते हुए बांस से विभिन्न तरह की वस्तुएं बनाने की दिशा में पहल की और देश से इनके निर्यात की संभावनाएं भी तेजी से बढ़ीं।

बांस की खेती बहुउपयोगी है। इससे अपशिष्ट जल का उपचार ही नहीं होता, बल्कि हवा भी शुद्ध होती है और मिट्टी का कटाव भी कम होता है। बांस तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। यह वातावरण से कार्बन डाईआक्साइड अवशोषित करने में मदद करता है। इसे कम लागत में अधिक उपज देने वाली घास कहा जा सकता है। जंगलों के साथ-साथ शुष्क क्षेत्रों में भी यह उगाया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, बांस आमतौर पर तीन से चार वर्ष में कटाई के लिए तैयार हो जाता है। एक बार लगाने के बाद यह चालीस-पचास साल तक पैदावार दे सकता है। कटाई के बाद यह फिर से बढ़ना शुरू कर देता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा और प्राकृतिक दवाओं में भी इसका इस्तेमाल होता रहा है। बांस के पाउडर का इस्तेमाल खांसी और अस्थमा जैसे रोगों के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में इसके रस का उपयोग बुखार और गर्मी कम करने के लिए किया जाता है।

दुनियाभर में कप, प्लेट, टूथब्रश, कंघे और कूड़ेदान आदि के निर्माण में बांस का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। बांस के रेशे प्राकृतिक रूप से जीवाणुरोधी होने के साथ ही नमी अवशोषित कर त्वचा को सुरक्षित और आरामदेह रखते हैं। इसलिए इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में भी किया जा रहा है। यह बल्ली, सीढ़ी, टोकरी और चटाई आदि बनाने में तो काम आता ही है, इससे बनने वाले फर्नीचर भी विविध रूपों में बाजार में अपना स्थान बनाने लगे हैं। खिलौने, कृषि यंत्र और कागज बनाने सहित अन्य साज-सज्जा का समान बनाने में बांस के बढ़ते उपयोग से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसकी खेती कारगर साबित हो रही है। देश-विदेश में बांस का उपयोग जैविक ईंधन तैयार करने के लिए भी किया जाने लगा है। बांस से निर्मित चारकोल का उपयोग पानी एवं वायु शोधन यंत्रों, दवाइयों और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में किया जा रहा है।

राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत बांस के उत्पादों को बढ़ावा देने के

लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने मनरेगा के तहत बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर सात लाख रुपए तक की अनुदान राशि देने की पहल की है। सतत विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बांस भविष्य में

> **दुनियाभर में कप, प्लेट, टूथब्रश, कंघे और कूड़ेदान आदि के निर्माण में बांस का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसके रेशे प्राकृतिक रूप से जीवाणुरोधी होने के साथ ही नमी अवशोषित कर त्वचा को सुरक्षित और आरामदेह रखते हैं। इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में भी किया जा रहा है। बांस बल्ली, सीढ़ी, टोकरी और चटाई आदि बनाने में तो यह काम आता ही है, इससे बनने वाले फर्नीचर भी विविध रूपों में बाजार में अपना स्थान बनाने लगे हैं। खिलौने, कृषि यंत्र और कागज बनाने सहित अन्य साज-सज्जा के समान में बांस के बढ़ते उपयोग से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसकी खेती कारगर साबित हो रही है।**

Join This Channel:- https://t.me/AllNewsPaperPaid1

भारत के लिए हरा सोना साबित हो सकता है। अभी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में ही बांस की खेती बड़े स्तर पर होती है। देश में इसकी खेती के प्रसार के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन कर बांस को पेड़ों की श्रेणी से हटा कर घास की श्रेणी में वर्गीकृत किया था। विषम परिस्थितियों में भी उग सकने वाले बांस की लगभग 136 प्रजातियां हैं, मगर इसकी बहु किस्मों के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण इसका व्यावसायिक उपयोग भारत में अभी सीमित है। बड़े भूमि क्षेत्र पर उगने के बावजूद इसके निर्यात का लाभ हमें नहीं मिल रहा है। जबकि बांस ऐसा पौधा है, जिसके हर एक भाग का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग प्रकार से किया जा सकता है। प्रशिक्षण के साथ इस संबंध में जागरूकता से किसानों की आय वृद्धि में यह महती भूमिका निभा सकता है।

वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि दूसरे पौधों की तुलना में बांस का पौधा तैंतीस फीसद अधिक कार्बन डाईडाक्साइड अवशोषित करता है और पैंतीस फीसद अधिक आक्सीजन प्रदान करता है। चीन में वर्ष 1980 के दशक में बांस की खेती के प्रयासों को गति मिली और आज इससे वह सर्वाधिक आर्थिक लाभ ले रहा है। वहां पचास लाख हेक्टेयर भूमि पर बांस की खेती हो रही है, जबकि भारत में एक करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बांस की खेती होने के बावजूद इसकी विविधता और उपयोगिता को लेकर जागरूकता का अभाव और विपणन में दिक्कतों के कारण हमें इसका यथोचित आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि जब से केंद्र सरकार ने बांस को घास के रूप में अधिसूचित किया है, तब से महाराष्ट्र में बांस की पैदावार को लेकर प्रभावी प्रयास हुए हैं। इससे बड़ी संख्या में किसानों का रुझान बांस की खेती की ओर हुआ है। वहां बांस से होटल उद्योग और दूसरे उद्योगों के सौंदर्यीकरण की दिशा में भी प्रयास हुए हैं। ऐसे ही प्रयास अगर दूसरे राज्यों में भी होते हैं, तो भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं।

बांस की खेती के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत बांस की कई किस्मों के उत्पादन को देशभर में प्रोत्साहन के साथ यदि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों की प्रसार शिक्षा के तहत बांस उत्पादन प्रशिक्षण वृहद स्तर पर आयोजित हों, तो किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण में भी बांस अहम योगदान दे सकता है। राजस्थान के राजसमंद जिले के पिपलांत्री गांव में चारागाह भूमि पर बांस लगाने और बांस उत्पादन में विविधता पर काफी काम हुआ है। राजस्थान का यह ऐसा गांव है जहां बांस की कई किस्में एक साथ उगाई जाती हैं। यहां बांस की खेती में अभिनव प्रयोग भी हुए हैं।

प्लास्टिक के बजाय बांस के पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों को यदि बंजर और चारागाह भूमि पर उगाने को बढ़ावा दिया जाता है, तो इसके बहुत अच्छे परिणाम भविष्य में मिल सकते हैं। किसानों के लिए आर्थिक लाभ के साथ बांस की खेती पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत अहम है। ग्रामीण आजीविका सृजन में बांस के उपयोग के लिए वातावरण बनाने की जरूरत है। चीन की तर्ज पर घास की खेती और इससे जुड़े उद्योगों की पारिस्थितिकी पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए हमारे यहां बड़े स्तर पर उपलब्ध बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करने, कटाव और मरुस्थलों से निपटने तथा ग्रामीण समुदायों की आय में सुधार के लिए बांस की खेती महत्त्वपूर्ण है।

शहर की तासीर

महेश परिमल

दुनिया मेरे आगे

हम अक्सर शहर-दर-शहर घूमते रहते हैं। कोई शहर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो कोई इतना प्यारा लगता है कि वहां से जाने का मन ही नहीं करता। कोई शहर हमें तुरंत भगा देता है, यानी हम वहां से चले जाना चाहते हैं तो कोई इसी अर्थ में बार-बार रुकने का आग्रह करता है। क्या कभी हमने सोचा है कि आखिर क्या है इन शहरों में जो बार-बार हमारे भीतर उथल-पुथल पैदा करते हैं।

वास्तव में हर शहर की अपनी एक तासीर होती है। जिस शहर से हमारे भीतर की संवदेना के तार जुड़ जाते हैं, वह शहर हमें अच्छा और भला लगने लगता है। संवेदना के तार आखिर क्या बला हैं? ये मन की वे कोमल भावनाएं होती हैं, जो हमारे दिल को दूसरों के दिलों से जोड़ती हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि किसी अजनबी शहर में गए, तो वहां जाते ही हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हो गया, जिसे नहीं होना चाहिए था। हमने बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ उस शहर में प्रवेश किया था, लेकिन किसी एक घटना ने हमारी आशाओं पर पानी फेर दिया, हमारे विश्वास को तोड़ दिया। हम उस शहर के लोगों पर विश्वास करना छोड़कर उस शहर को ही छोड़ देते हैं।

दूसरी ओर, कुछ शहर ऐसे होते हैं, जहां हमें हर जगह अपनापन मिलता है। वहां हर कोई अपना ही लगता है। अजनबी भी हमसे अपनों की तरह बात करते हैं। चारों ओर मुस्कराते चेहरे हमें भले लगते हैं। ऐसे में भला कौन चाहेगा, उस शहर को छोड़ना? पर सभी शहरों के साथ एक ही बात है। वह यही कि एक निश्चित समय बाद हमें उस शहर को छोड़कर जाना ही होता है, क्योंकि हमें भीतर से हमारा शहर पुकारता है। वास्तव में अपना शहर हमारे भीतर कुलांचें मारता है। हमें गोद में लेकर दुलारता है। बरसों से इसी दुलार को पाकर हम बड़े हुए। यह हमें अपनों की याद दिलाता है। एक उम्र के बाद हम दूसरे शहर में जाते हैं, जहां हमारी रोजी-रोटी जुड़ी होती है। पहले तो हमारे अतीत का शहर हमारे भीतर होता है, जिसे हम निकाल नहीं पाते। धीरे-धीरे हमारी रोजी-रोटी वाला शहर हमारे दिल में जगह बनाने लगता है। कुछ बरस बाद हम याद करते हैं कि इस शहर ने हमें क्या-क्या दिया। क्या लेकर आए थे इस शहर में और अब हमारे पास क्या नहीं है! एक संतुष्टि का भाव हमारे भीतर होता है।

इसके बाद हम तुलना करने लगते हैं अपने बचपन के शहर से। बचपन का शहर हमारे भीतर कहीं छिपा हुआ होता है। वह हमारे रोजी-रोटी वाले शहर से किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं करता। वह जानता है कि मैंने जिसे पाला-पोसा, जिसका लालन-पालन किया, उसे इस शहर ने खड़ा होना सिखाया। मैं इसका अतीत हूं, तो यह उसका वर्तमान है। इस तरह व्यक्ति के भीतर कई शहर समाए होते हैं। सब मिलजुल कर ऐसे रहते हैं, मानों एक ही शहर में रह रहे हों। कई शहर मिलकर एक महानगर की शक्ल ले लेते हैं।

अपना शहर छोड़ना एक त्रासद स्थिति है। पर दूसरा शहर चुनौतियों के साथ हमें बुलाता रहता है। अपने शहर में चुनौतियां नहीं होतीं। वहां के सारे काम हमारी जगहों और लोगों की पहचान के कारण आसानी से हो जाते हैं। दूसरा शहर हमें अपनाने से पहले परीक्षा लेता है। हमें अपने अनुकूल बनाता है। इसलिए नौकरी पर दूसरे शहर जाते ही दुश्वारियों का दौर शुरू हो जाता है। कदम-कदम पर परेशानियां हमारा इंतजार करती होती हैं। ये परेशानियां हमारी परीक्षाएं होती हैं, जिन्हें हमें पास करना ही होता है। यह दूसरा शहर हमें चैन से बैठने भी नहीं देता। एक के बाद एक बाधाएं आती ही रहती हैं।

> **अपना शहर छोड़ना एक त्रासद स्थिति है। पर दूसरा शहर चुनौतियों के साथ हमें बुलाता रहता है। अपने शहर में सारे काम हमारी जगह और लोगों की पहचान के कारण आसानी से हो जाते हैं। दूसरा शहर हमें अपनाने से पहले परीक्षा लेता है। हमें अपने अनुकूल बनाता है। इसलिए दूसरे शहर में जाते ही दुश्वारियों का दौर शुरू हो जाता है।**

शहरों में कौन-सा शहर प्यारा है, अगर इसकी सूची बनाएं, तो हमारे बचपन के शहर से कहीं ज्यादा हमें चुनौतियां देने वाला शहर प्यारा लगता है। यही शहर है, जिसने जीना सिखाया। यही शहर है, जिसने यह बताया कि भविष्य की अन्य चुनौतियों से भी तुम पार पाओगे। जीवन के तीसरे पड़ाव पर एक शहर और होता है, जहां हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद वाला यह शहर काफी सुकून देने वाला होता है। इस शहर तक पहुंचते-पहुंचते शरीर साथ देना छोड़ देता है। अब वैसी भाग-दौड़ नहीं हो पाती। कई कार्यों के लिए बच्चों का सहारा लेना होता है। यह वृद्धावस्था का शहर होता है। जहां सुकून होता है, अपनों का साथ होता है। हम अपनों के बीच रहते हैं, अपनापन बांटते हैं। इस तरह से जीवन के तीन शहर हुए। पहला दुलारने वाला, दूसरा रोजी-रोटी देने वाला और तीसरा सुकून देने वाला। इंसान की जिंदगी इन तीनों शहरों में सिमट कर रह जाती है।

चुनौतियां देने वाले शहर सदैव याद रखे जाते हैं। हम याद करें कि कौन-सा शहर हमें याद आता है। वही, जहां हम पग-पग पर मुश्किलें झेलते थे। आखिरी शहर जीवन के आखिरी पड़ाव की तरह होता है, जहां केवल निवृत्ति की बातें होती हैं। तब अपनों का घेरा बहुत बड़ा हो जाता है। पर अपनेपन का घेरा छोटा हो जाता है। पर्यटन वाले शहर क्षणिक याद आते हैं। बचपन का शहर कुलांचे मारता रह जाता है, लेकिन हमें गढ़ने वाला शहर हमारे भीतर ही बस जाता है। यही है शहर और शहरों की तासीर और उसमें गुंथे संवेदना के तार।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

चौपाल

प्रकृति के लिए

पिछले दिनों अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया गया। धरती के संरक्षण के लिए कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है, इन्हीं में से एक है ओजोन परत। इस परत का संरक्षण उसी तरह जरूरी है, जिस तरह बीमारियों से बचने के लिए हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। इसी तरह ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर यह परत न होती, तो सूर्य से आने वाली इन किरणों से धरती के प्राणियों का जीवन संकट में पड़ जाता। इस परत को सुरक्षित रखने के लिए दुनिया के हर देश के नागरिक को गंभीर रहने की जरूरत है। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है। धरती पर जिस तरह प्रदूषण बढ़ रहा है, जहरीला धुआं मुसीबत बन रहा है, उससे यह और भी खतरा बढ़ गया है कि यह ओजोन परत को पतला कर सकता है। इस परत को वातानुकूलन यंत्र और रेफ्रिजरेटर आदि से निकलने वाली गैसें नुकसान पहुंचाती हैं। आज प्रकृति हमारी गलतियों के कारण बीमार हो रही है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसके इलाज के लिए हम गंभीर नहीं है। दुनिया के सभी देशों को मिल कर ओजोन परत बचाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाने चाहिए।

– राजेश कुमार चौहान, जलंधर

सुधार की दिशा

जीएसटी में सुधार आर्थिक ढांचे को दीर्घकालीन मजबूती देने वाली रणनीति है। सवाल कराधान की जटिलता या पारदर्शिता भर का नहीं, बल्कि इस बात से जुड़ा है कि भारत अपने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में किस तरह स्थापित करता है। यहीं से यह सुधार 'एक कर नीति' से आगे बढ़ कर विकास नीति का रूप लेते हैं। वास्तविक समस्या यह रही है कि अब तक एमएसएमई क्षेत्र कर ढांचे की जटिलता, अनुपालन की ऊंची लागत और सीमित बाजार पहुंच से जूझता रहा। नतीजतन, रोजगार सृजन और निर्यात की क्षमता घटती गई। नए सुधारों का लक्ष्य कर आधार को विस्तारित करना, दरों को सरल बनाना और राजस्व नुकसान को रोकना है। किंतु जब तक इन प्रावधानों को व्यावहारिक स्तर पर लागू नहीं किया जाएगा, परिणाम सीमित रहेंगे। समाधान यही है कि सुधार को केवल राजस्व उगाही की दृष्टि से न देखा जाए, बल्कि इसे नवाचार का आधार बनाया जाए।

– अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़

मनमानी का नतीजा

'प्रकृति की चेतावनी' (संपादकीय, 18 सितंबर) महत्त्वपूर्ण है। देशभर में औसत से अधिक वर्षा प्रकृति के नाराज होने का संकेत है। वर्षों तक विकास के नाम पर प्रकृति के साथ किए जा रहे खिलवाड़ का ही यह नतीजा है कि सुखदायी बरसात, जीवनदायिनी नदियां और मनोहारी पहाड़ अब हमें डरा रहे हैं। हमने पहाड़ों को खोखला कर दिया। अपनी सुविधा के हिसाब से हमने नदियों का रास्ता बदला है। अपनी विलासिता के लिए जंगलों को बेरहमी से बर्बाद किया है। हमारी मनमानी के कारण जब प्राकृतिक जलवायु में विनाशकारी परिवर्तन दिखने लगा है, तो हम परेशान हो रहे हैं। हमारी यह तकलीफ स्वाभाविक भी है, पर हमें स्वीकार करना होगा कि यह सब देश की विनाशकारी विकास नीतियों का नतीजा है। देश के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को मिल कर समाधान के उपाय खोजना चाहिए, ताकि हम सफलतापूर्वक प्रकृति के प्रकोप का सामना कर सकें।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

राष्ट्रवाद बनाम खेल

एशिया कप में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय टीम को विजय भले मिल गई हो, लेकिन कई अनसुलझे सवालों में बीसीसीआइ घिरती दिख रही है। जब आतंकवाद के अनवरत पोषण के कारण आपरेशन सिंदूर की अनिवार्यता से उपजी तल्खी और तनाव व्याप्त है, तो क्रिकेट खेलना आखिर क्यों जरूरी हो गया। खेल के मैदान में दोनों देश के खिलाड़ियों के बीच द्वेष और परस्पर विरोध की देह भंगिमा स्पष्ट देखी जा रही थी। खेल के विज्ञापनों में अकूत धनराशि से बीसीसीआइ के खजाने भले लबालब हो गए हों, लेकिन पहलगाम में पाक प्रायोजित खूनी खेल ने इस विजय को फीका कर दिया। उस घटना के पीड़ितों ने आक्रोश भी जताया। नतीजा यह कि भारतीय टीम ने जीत के बाद पाक टीम से न्यूनतम शिष्टाचार दिखाने के बजाय प्रायश्चित की जरूरत महसूस की। अच्छा होता कि पाकिस्तान से खेलने से परहेज किया जाता।

– अशोक कुमार, पटना

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, सोमवार 22 सितम्बर 2025

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

ट्रंप का एक और झटका

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री एक-दूसरे के गहरे मित्र होने का दावा करते हैं, हालांकि उनकी दोस्ती कई नेताओं को समझ नहीं पड़ती और भारत में भी इस पर सवाल उठते हैं। दोनों के बीच सम्मान और दोस्ती का रिश्ता कितना गहरा है, यह तो वे ही सही-सही बता सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि सरकार चलाने के तौर-तरीके, लच्छेदार बातें और राष्ट्रवाद को राजनीति का केंद्र बनाना, इन सब में दोनों में जबरदस्त सामंजस्य दिखता है। शनिवार को जब नरेन्द्र मोदी गुजरात में आत्मनिर्भरता का पाठ देश को पढ़ा रहे थे और कह रहे थे कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी दूसरे देशों पर निर्भरता है। उसी वक्त ट्रंप सरकार अमेरिका फर्स्ट के नारे को बुलंद करते हुए एच-1 बी वीज़ा पर 1 लाख डॉलर (करीब 88 लाख) की फीस लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि यह अमेरिकी श्रमिकों की रक्षा करने, वीज़ा सिस्टम के ग़लत इस्तेमाल को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि केवल सबसे कुशल और सबसे अधिक वेतन पाने वाले विदेशी पेशेवर ही योग्य हों। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक ने कहा है, 'अगर आपको किसी को प्रशिक्षित करना है, तो आपको हमारे देश के बेहतरीन विश्वविद्यालयों से हाल ही में उत्तीर्ण हुए ग्रेजुएट को प्रशिक्षित करना चाहिए। अमेरिकियों को प्रशिक्षित करो। बाहर से लोगों को लाकर हमारी नौकरियां छीनना बंद करो।' व्हाइट हाउस ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है और कहा है कि संवेदनशील उद्योगों में विदेशी श्रमिकों पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता अमेरिका की क्षमता को कमज़ोर करती है।

फिलहाल भारत का विदेश मंत्रालय इस फैसले की समीक्षा कर रहा है, हालांकि इससे ज्यादा कुछ करने की स्थिति में वह है भी नहीं। क्योंकि मोदी सरकार की विदेश नीति इतनी कमजोर हो चुकी है कि ट्रंप जब चाहे भारत का अपमान कर सकते हैं। वे जानते हैं कि नरेन्द्र मोदी चुप ही रहेंगे। लेकिन नरेन्द्र मोदी खुद जितना आत्मनिर्भर होने, मेक इन इंडिया आदि की बातें करते हैं, और विदेश सामान खरीदने की आदत छोड़ने की बात कहते हैं, वे भी संभवत: इस फैसले से निजी हैसियत में सहमत ही होंगे। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक तो उनका कोई प्रतिवाद सामने नहीं आया है। अलबत्ता देश में इस पर हलचल मच गई है। खासकर आई टी इंडस्ट्री अब सोच में पड़ गई है कि कैसे इस चुनौती का सामना करे।

बता दें कि अमेरिका में एच 1 बी वीजा धारकों में भारतीयों की हिस्सेदारी 70 फीसदी से ज्यादा है, ऐसे में वीजा नियमों में बदलाव का सीधा असर भारत के टेक सेक्टर और प्रोफेशनल्स पर पड़ने वाला है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में शोध करने पहुंचे भारतीय शोधकर्ताओं को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिकी कंपनियां विदेशों से टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, फाइनेंस और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रतिभाशाली पेशेवरों को नौकरी पर रखती हैं। इनमें सबसे ज्यादा भारतीय नौकरी करते हैं। देश में इसी ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन पर बरसों से चिंता जताई गई, लेकिन ऐसा माहौल नहीं बना कि अच्छी नौकरी, बेहतर कार्य संस्कृति, अच्छा वेतन सब देश में ही उपलब्ध हो। लिहाजा लाखों भारतीय अमेरिका जाकर ही जीवन सुधारने के सपने देखते रहे। खुद नरेन्द्र मोदी ने 2014 में कहा था कि मेरा सपना है कि ऐसा भारत बने जिसमें अमेरिकियों को वीज़ा की लाइन में लगना पड़े। समय के साथ ये भी मोदीजी का एक और जुमला ही साबित हुआ। अब लाखों परिवार जब इस चिंता में हैं कि अमेरिका में रहें या नहीं, भविष्य में क्या और सख्ती बरती जाएगी, देश लौटेंगे तब नौकरी, पढ़ाई, की क्या सुविधा रहेगी, इन सब को नजरंदाज करते हुए मोदी चुप है।

इस वीज़ा नियम के 21 सितंबर को लागू होने से पहले ही कई उलझनें सामने आईं, जिन पर ट्रंप प्रशासन ने साफ किया है कि अमेरिकी कंपनियों को किसी विदेशी कर्मचारी के लिए हर नए एच-1बी आवेदन पर एक लाख डॉलर का शुल्क अदा करना होगा। जो भारतीय पहले से एच-1 बी वीजा पर काम कर रहे हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन नौकरी के नए अवसर तलाश रहे लोगों के लिए यह नई और एक बड़ी बाधा है। व्हाइट हाउस के मुताबिक यह फीस मौजूदा वीजा धारकों पर लागू नहीं होगी। नवीनीकरण पर भी यह शुल्क लागू नहीं है, बल्कि सिर्फ नए आवेदनों और आगामी लॉटरी साइकिल पर लागू होगा। हालांकि इस स्पष्टीकरण के बाद भी अफरातफरी मची।

सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ वीजाधारकों ने डर के चलते अमेरिका जाने वाली फ्लाइट छोड़ दी। वहीं दिल्ली से न्यूयॉर्क की सीधी उड़ानों के टिकट की कीमत महज दो घंटे में 37,000 से बढ़कर 70,000-80,000 तक पहुंच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक़ कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने विदेश में मौजूद अपने एच-1बी स्टाफ़ को सलाह दी है, 'जल्दी लौट आएं या तब तक अंतरराष्ट्रीय यात्रा से बचें जब तक नए नियम साफ़ न हो जाएं.'

अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल के पॉलिसी डायरेक्टर जॉर्ज लोवरी ने बीबीसी से कहा, 'यह पॉलिसी बिना किसी सूचना, बिना किसी दिशा-निर्देश और बिना योजना के लाई गई है।' हम देख रहे हैं कि भ्रम सिर्फ़ वीज़ा धारकों और उनके परिवारों में ही नहीं है, बल्कि एंप्लॉयर और यूनिवर्सिटीज़ भी समझ नहीं पा रहे कि उन्हें कैसे इसका पालन करना है। सरकार पर यह ज़िम्मेदारी है कि वह नियमों को साफ़ करे, ख़ासकर तब जब लोगों की ज़िंदगियां और करियर दांव पर हों।

ये तमाम बातें बताती हैं कि इस फैसले से अफरा-तफरी आगे बढ़ सकती है, लेकिन मोदी सरकार का रवैया इस आपदा को भी अवसर बताने का दिख रहा है। कई चैनलों ने इसी पर कार्यक्रम कर लिए कि अब हमारी प्रतिभा वापस आएगी, इसका लाभ हमें मिलेगा और अमेरिका का नुकसान होगा। अब तक यही मीडिया अमेरिका में मोदी-मोदी करने वाले प्रवासी भारतीयों की भक्ति पर कार्यक्रम करता था, तब सवाल नहीं होते थे कि मोदी के राज में देश में इतना विकास हुआ है, तो ये सब लोग विदेश में क्यों बने हुए हैं। अब देखना होगा कि प्रवासी भारतीयों का भक्त समुदाय क्या करता है और घर वापसी करने वाले कामगारों के लिए सरकार क्या प्रबंध करती है।

ट्रंप ने टैरिफ के बाद वीजा शुल्क बढ़ाया : मोदी कुछ भी नहीं रोक पा रहे!

जब नया नया सोशल मीडिया आया था तो लोग वहां हैप्पी बर्थ डे के मैसेज पाकर खुश हो जाते थे। केक फूल शैम्पेन की इमोजी देखकर खुद को मशहूर हस्ती समझने लगते थे। लेकिन अब सामान्य आदमी भी सच को समझ चुका है कि यह सारी मुबारकबादें ऐसी ही जिसे आज के युवा की भाषा में एवंई कहते हैं, होती है। मगर हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेशों से जन्मदिन की बधाइयां पाकर अभी भी यह समझते हैं कि वे कोई वाकई बड़ी अन्तरराष्ट्रीय हस्ती हैं। विश्व गुरु जो वे कहते हैं उसका गुमान और बढ़ जाता है। विदेश मंत्रालय में एक से एक काबिल अफसर हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी, मगर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह बता सके कि यह एक सामान्य औपचारिकता है। दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी ऐसी ही बधाइयां मिलती हैं। और भारत तो एक बड़ा देश है इसलिए यहां के प्रधानमंत्री को मिलना स्वाभाविक है। और यह तो कोई इशारों में भी नहीं बता सकता कि जैसे सोशल मीडिया पर जो ज्यादा ध्यान आकर्षण चाहता है लिख देता है कि नहीं दोगे बधाइयां उसे फिर लोग दे ही देते हैं। जन्मदिन की बधाइयां कोई पैमाना नहीं आपके महत्वपूर्ण होने का। मगर हमारे यहां जिस तरह से गोदी मीडिया ने खुशियां मनाईं, भक्त एक-एक बधाई गिनकर शोर मचाने लगे कि देखो कितना मानते हैं दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष हमारे मोदी जी को और फिर खुद मोदी जी ने एक एक राष्ट्राध्यक्ष को दिए धन्यवाद को जिस तरह प्रचारित किया गया वह ऐसा था जैसे इसके जरिए आप विश्व विजय की घोषणा कर रहे हों।

खासतौर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जन्मदिन की बधाई तो ऐसे बताई गई कि जैसे ट्रंप ने आत्म समर्पण कर दिया हो। जैसे राजा का जन्मदिन होता था तो खुश होकर कुछ दे या न दे मगर नाराज होने पर सज़ा जरूर दे देता था। वैसे ही पेश किया गया कि ट्रंप समझ गया कि अगर मोदी जी नाराज हो गए तो फिर बस समझ लेना खैर नहीं। डर कर ट्रंप ने फोन किया। मगर दो दिन भी नहीं बीते और ट्रंप ने फिर बता दिया कि वह अपने लिए नारे लगाने वाले मोदी को एक चुनाव प्रचार करने वाले से ज्यादा नहीं समझ रहा।

पचास प्रतिशत टैरिफ के बाद भारतीयों के लिए वीजा एच -1बी की फीस सौ गुना तक बढ़ा दी। एक लाख डालर। मतलब लगभग 90 लाख रूपए। और यह जब आप सुबह इन पंक्तियों को पढ़ रहे होंगे तो लागू हो चुका होगा। पहले इस वीजा के लिए छह लाख रुपए देना होता था। इसका सबसे ज्यादा असर भरतीयों पर पड़ेगा।

भक्त और अब उसी तरह का हो चुका मीडिया कई तर्क लेकर समाने आया है कि यह सब देशों को लिए है। वह यह नहीं बता सकता कि सबसे ज्यादा टेक्नोक्रेट भारत ने बनाए थे। और 2014 से पहले। नेहरू द्वारा स्थापित आईटीआई ने। अभी विदेश में रह रहे एक डाक्टर और लेखक प्रवीण झा ने बहुत अच्छा लिखा है कि एक अमेरिकी टीवी पत्रकार ने कहा कि 'हम सऊदी अरब से तेल मंगाते हैं, जापान से गाड़ियां, स्काटलेंड से व्हिस्की, लेकिन आपको मालूम है हम भारत से कौन सी बेशकीमती चीज मंगाते हैं? हम मंगाते हैं वहां के लोग। दुनिया के सबसे दिमागी और परिश्रमी इंजीनियर जो भारत से आते हैं।' और यह सारे इंजीनियर नेहरू द्वारा स्थापित आईआईटी से निकले हैं। मोदी जी ने इनका मजाक उड़ाने में भी कोई कसर नहीं रखी कहा आईआईटी नहीं आईटीआई चाहिए। वही खोल देते! लेकिन केवल बातें! नेहरू को नीचा दिखाने के लिए उनकी हर बात का विरोध। मगर अब शायद चलेगा नहीं!

शकील अख्तर

भारत का युवा बोलेगा। आज नहीं तो कब बोलेगा कि उसे भी वैसी शिक्षा और फिर उसके बाद नौकरी के ऐसे अवसर क्यों नहीं मिल रहे? उसे पकौड़े बेचने की अपमानजनक सलाह क्यों दी जा रही है? आईआईटी से इंजीनियर बनने के बदले उसे आईटीआई से मेकेनिक क्यों बनाया जा रहा है?

वीजा की यह नई फीस लाखों भारतीयों को अमेरिका छोड़ने पर मजबूर कर देगी। बता दें कि इस वीजा प्रणाली के अन्तर्गत 75 प्रतिशत वीजा भारतीयों को मिलते थे। इसलिए गोदी मीडिया के इस बचाव में कोई दम नहीं है कि शुल्क पूरी दुनिया के लिए बढ़ाया गया है। जहां नेहरू, इन्दिरा गांधी जैसे नेता ही नहीं हुए जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया है और खासतौर से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा में जिससे वहां ऐसे आईटी, हेल्थ, फाइनेंस इंजीनियरिंग, विज्ञान जैसे क्षेत्रों के प्रोफेशनल निकल पाए हों।

भारत का युवा बोलेगा। आज नहीं तो कब बोलेगा कि उसे भी वैसी शिक्षा और फिर उसके बाद नौकरी के ऐसे अवसर क्यों नहीं मिल रहे? उसे पकौड़े बेचने की अपमानजनक सलाह क्यों दी जा रही है? आईआईटी से इंजीनियर बनने के बदले उसे आईटीआई से मेकेनिक क्यों बनाया जा रहा है?

बातें बातें केवल बातें! इससे देश के लोगों को तो बेवकूफ बनाया जा सकता है। विदेश के लोगों को नहीं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कह दिया देश के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है।

बहुत बड़ा हमला। और राहुल ने कहा मैं रीपिट कर रहा हूं। मतलब चेतावनी। इससे पहले 2017 में राहुल ने मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री कहा था। विदेश नीति के साथ अमेरिका के इसी वीजा मामले में अमेरिका के सामने झुकने पर। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने इस मामले में और साफ बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी मोदी के नारे लगवाना विदेश नीति नहीं होती। सही है। पिछले 11 साल से मोदी जी केवल अपनी छवि चमका रहे हैं। जबकि इससे पहले यह होता था कि सरकार देश के हित के लिए काम करती थीं। अपनी व्यक्तिगत छवि की चिन्ता किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की। देश आगे बढ़ेगा, देश की जनता को फायदा होगा, युवा को रोजगार के अवसर मिलेंगे यही सब हर प्रधानमंत्री का उद्देश्य होता था।

यहां तो यह हुआ कि अपनी लकीर बढ़ी करने के चक्कर में प्रधानमंत्री बाकी सब प्रधानमंत्रियों की लकीरें छोटी करना शुरू कर दीं। देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि अपनी ही पार्टी के वाजपेयी तक का नाम नहीं लेते। भाजपा में वाजपेयी से बड़ा कोई नेता नहीं हुआ। भाजपा के पहले प्रधानमंत्री थे। मगर उनके नाम पर भी 11 साल में कुछ नहीं बनाया। ग्वालियर मध्य प्रदेश जहां के वे रहने वाले थे। उनका जन्म हुआ। पढ़े लिखे वहां भी उनके नाम पर कोई एक चीज नहीं बनाई गई।

एचडी देवगौड़ा तो अभी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री उनके समर्थन में हैं। मगर कभी उनकी तारीफ भी नहीं करते। बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति की वापसी में देवगौड़ा का महत्वपूर्ण रोल था। प्रसंगवश बता दें कि आतंकवादियों से हथियार डलवाने में और कश्मीर के युवकों को पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों से अलग करने में देवगौड़ा ने बड़ी भूमिका निभाई थी।

उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वाजपेयी सरकार ने हुर्रियत कान्फ्रेंस से पहली बार अधिकृत बातचीत की थी। अभी पुरानी सरकारों पर जबर्दस्ती सवाल उठाने के लिए यासिन मलिक को ले आए। इन्हें पता ही नहीं है कि यासिन मलिक जाने कितने सालों से हथियार छोड़कर खुद को गांधीवादी कहने लगा है। हुर्रियत से वह बातचीत गृह मंत्रालय के दफ्तर नार्थ ब्लाक में गृह मंत्री मंत्री आडवानी ने की थी।

मगर सारे इतिहास को खत्म करके सब कुछ अपने नाम से कर लेने की लिप्सा ने अब वह दिन ला दिया है कि सीधा उन्हीं से कहा जाने लगा है कमजोर प्रधानमंत्री।

देश तक 2014 में आजाद बता दिया गया। खुद बोल दिया कि 2014 से पहले भारत में जन्म लेना शर्म की बात थी।

हर चीज की एक हद होती है। लगता है अब वह आ गई। देश के नाम संबोधन हो रहा है। मगर अब देश की जनता और खासतौर से युवा, प्रोफेशनल या जिसे राहुल ने कहा है जेन जी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं!

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार है)

गांधीजी की लंगोटी : सादगी से स्वराज तक

■ अरुण कुमार डनायक

22 सितम्बर 1921, मदुरै—यह दिन गांधीजी के जीवन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक अनूठा मोड़ था। इसी दिन उन्होंने टोपी, कुर्ता और धोती त्यागकर सिर मुड़वा लिया और केवल लंगोटी पहनने का निश्चय किया। बुनकरों की सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा 'करोड़ों लोग इतने गरीब हैं कि छोड़े हुए विदेशी कपड़ों की जगह खादी खरीद ही नहीं सकते। उन्हें मैं सलाह देता हूं कि घुटनों तक की एक लंगोटी से ही संतोष करें।' उसी क्षण उन्होंने घोषणा की कि आगे से वे टोपी और सदरी भी नहीं पहनेंगे और केवल लंगोटी तथा आवश्यकता पड़ने पर शरीर ढकने के लिए एक चादर से काम चलाएंगे।

गांधीजी का यह निर्णय आकस्मिक नहीं था। इसके पीछे वर्षों की साधना, अनुभव और जनता के साथ आत्मीय एकता की भावना थी। दक्षिण अफ्रीका में वकालत करते समय मोहनदास करमचंद गांधी आधुनिक सभ्यता के प्रतीक सूट-बूट पहनते थे, लेकिन अदालत में पगड़ी पहनकर जाना चाहते थे। 1893 में डरबन की अदालत में जब उनसे पगड़ी उतारने का आदेश दिया गया तो उन्होंने इंकार कर दिया-यह उनके आत्मसम्मान की पहली उद्घोषणा थी।

भारतीय समाज में पगड़ी सम्मान का प्रतीक मानी जाती थी और नंगे सिर रहना शोक का चिह्न, किंतु गांधीजी ने यह दिखाया कि असली गरिमा वस्त्रों में नहीं, बल्कि सादगी और विनम्रता में है। गांधीजी के लिए वस्त्र परिवर्तन सुविधा नहीं, निर्धन जनता से एकात्मता का संकल्प था। वे कहते थे 'भारत के करोड़ों किसानों की पोशाक तो लंगोटी ही है, वे इससे अधिक कुछ पहनते ही नहीं हैं।' गांधीजी को विश्वास था कि जिस कार्य को वे स्वयं न कर सकें, उसकी सलाह वे दूसरों को भी नहीं दे सकते।

भारत लौटकर उन्होंने धोती, कुर्ता और पगड़ी वाली काठियावाड़ी वेशभूषा धारण की। चंपारण आंदोलन में भी वे इन्हीं वस्त्रों में नज़र आए। धीरे-धीरे उनका जीवन और अधिक सादा होता गया। 31 अगस्त 1920 को उन्होंने हाथ से काते सूत के वस्त्र पहनने की प्रतिज्ञा ली और पगड़ी त्यागकर टोपी धारण की। यही टोपी आगे चलकर 'गांधी टोपी' के नाम से प्रसिद्ध हुई, यहां तक कि ब्रिटिश सरकार ने अपने कर्मचारियों को इसे पहनकर दफ़्तर आने पर प्रतिबंध लगा दिया और शॉ वैलेस एंड कंपनी ने तो एक कर्मचारी कुशालकर को, जवाब देने का अवसर दिए बिना ही, गांधी टोपी पहनने का साहस दिखाने के कारण बर्खास्त कर दिया।

भारतीय समाज में पगड़ी सम्मान का प्रतीक मानी जाती थी और नंगे सिर रहना शोक का चिह्न, किंतु गांधीजी ने यह दिखाया कि असली गरिमा वस्त्रों में नहीं, बल्कि सादगी और विनम्रता में है। गांधीजी के लिए वस्त्र परिवर्तन सुविधा नहीं, निर्धन जनता से एकात्मता का संकल्प था। वे कहते थे 'भारत के करोड़ों किसानों की पोशाक तो लंगोटी ही है, वे इससे अधिक कुछ पहनते ही नहीं हैं।' गांधीजी को विश्वास था कि जिस कार्य को वे स्वयं न कर सकें, उसकी सलाह वे दूसरों को भी नहीं दे सकते।

1921 में दो अक्टूबर को नवजीवन में प्रकाशित लेख में उन्होंने स्वीकार किया कि खुलना के अकालग्रस्त लोग अन्न के बिना मर रहे थे और उसी समय विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के उनके अभियान पर कटाक्ष किए गए। उस क्षण उनके भीतर गहरा द्वंद्व उठा और बारिसाल में उन्होंने वस्त्र त्यागने का निर्णय लगभग ले ही लिया था। मौलाना मुहम्मद अली की वाल्टेयर में गिरफ्तारी के समय भी उनके मन में वस्त्र त्याग का विचार आया, किंतु उन्होंने सोचा कि उस समय ऐसा कदम भावुकता या दिखावे का प्रतीक लगेगा। इसलिए उन्होंने धैर्य रखा और उचित क्षण की प्रतीक्षा की।

मौलाना की गिरफ्तारी पर 22 सितम्बर 1921 को यंग इंडिया में उन्होंने लिखा 'विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कीजिए, चाहे लंगोटी में ही क्यों न गुज़ारा करना पड़े।' मद्रास यात्रा के दौरान भी आलोचना हुई-लोगों का कहना था कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि न तो पर्याप्त मात्रा में खादी उपलब्ध है और न ही निर्धन जनता के पास इतना धन है कि वह अपेक्षाकृत महंगी खादी खरीद सके। गांधीजी ने गहन विचार के बाद निश्चय किया कि यदि वे स्वयं वस्त्र त्याग का आदर्श प्रस्तुत करें तो ही यह आंदोलन सशक्त होगा। यही वह क्षण था जब उन्होंने अपने मित्र राजाजी के सामने लंगोटी धारण करने का संकल्प लिया। अपना पहनावा बदलने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि जब तक अमीर-गरीब सभी को पर्याप्त स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक वे केवल एक छोटा-सा कपड़े का टुकड़ा पहनेंगे। आरंभ में यह संकल्प 31 अक्टूबर तक सीमित था, किंतु बाद में उन्होंने इसे आजीवन स्वीकार कर लिया।

1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए जब वे लंदन गए, तो वहां की ठिठुरती सर्दी में भी वे केवल लंगोटी और चादर में पहुंचे। ब्रिटिश नेता विंस्टन चर्चिल ने कटाक्ष किया 'भारत का भविष्य एक आधे नग्न फकीर के हाथों में है।' परंतु गांधीजी अप्रभावित रहे। सबसे उल्लेखनीय क्षण तब आया जब वे बकिंघम पैलेस में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम से मिलने पहुंचे। पत्रकारों ने उनसे पूछा 'आप इतने कम कपड़ों में सम्राट के सामने कैसे पहुँच गए?' गांधीजी ने मुस्कराकर उत्तर दिया 'राजा ने तो इतना सब पहन रखा था कि हम दोनों की पोशाक मिलकर पूरी हो गई।' इस उत्तर में विनोद भी था और निर्भीक आत्मबल भी।

गांधीजी की लंगोटी केवल वस्त्र का टुकड़ा नहीं थी, स्वदेशी आंदोलन की सजीव व्याख्या थी। यह भारत की निर्धन जनता के साथ उनकी आत्मीयता और न्यूनतम आवश्यकताओं में जीवनयापन का आदर्श थी। टोपी और सदरी त्यागने का उनका संकल्प व्यक्तिगत था, इसे उन्होंने किसी अन्य कार्यकर्ता या साथी पर लागू नहीं किया था तथापि उनके आचरण से मौलाना आज़ाद और अली बंधु जैसे नेता भी वस्त्रों में सादगी अपनाने लगे। देशभर में स्वदेशी की लहर फैल गई। स्त्री-पुरुष, अमीर-गरीब सभी खादी पहनकर उनकी सभाओं में पहुंचने लगे। विवाह-समारोहों में नवदम्पत्ति खादी के वस्त्र पहनकर फेरे लेने लगे। गांधीजी की लंगोटी ने यह संदेश दिया कि भारत की स्वतंत्रता विलासिता से नहीं, बल्कि त्याग और आत्मबल से आएगी।

गांधीजी की यह यात्रा केवल बाहरी परिधान की नहीं, बल्कि आत्मा के शोधन और समाज के साथ आत्मीयता की यात्रा थी। आधुनिक सभ्यता के प्रतीक सूट से लेकर सादगी और स्वदेशी के प्रतीक लंगोटी तक पहुंचकर उन्होंने दिखाया कि नेतृत्व केवल विचारों से नहीं, बल्कि जीवन की प्रत्येक क्रिया से प्रकट होता है।

ब्रिटिश सम्राट के सामने लंगोटी में खड़े होकर वे संसार से यही कह रहे थे कि असली गरिमा वस्त्रों में नहीं, बल्कि आत्मबल में है। यही उनकी अमर विरासत है। गांधीजी की लंगोटी आज भी हमें स्मरण कराती है कि सादगी ही सबसे बड़ी शक्ति है और स्वदेशी ही स्वराज का पहला कदम।

(लेखक गांधी विचारों के अध्येता व समाजसेवी हैं)

Join This Channel:- https://t.me/AllNewsPaperPaid1

ललित सुरजन की कलम से

यदि भ्रष्टाचार रावण तो राम कहाँ ?

'यह बात हम जानते हैं कि रावण का निवास सोने की लंका में था। यदि भ्रष्टाचार से लड़ना है तो सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि यह सोने की लंका कहां है? इसे जानने के लिए बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। सोने की लंका सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। बल्कि उसका विस्तार नेता, अफसर और व्यापारी के त्रिलोक में है। जिन लोगों ने लाइसेंस परमिट राज्य खत्म कर बंधनमुक्त उद्यमशीलता (फ्री इंटरप्राइज) की वकालत की थी, वे ही उदारीकरण के इस युग में अपनी सोने की लंका में अपनी गगनचुंबी अट्टालिकाएं खड़ी कर रहे हैं। इस लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र लांघने की जरूरत है। पुल बांधने से पहले पुल बांधने की इच्छा शक्ति चाहिए। और उसके भी पहले रास्ता तलाश करने की दृष्टि भी। रावण से लड़ने राम अकेले नहीं गए थे, जनता अपना हृदय टटोलकर देखे कि क्या उसमें राम का कोई अंश है?'

(31 मार्च 2011 को प्रकाशित)

http://lalitsurjan.blogspot.com/2012/04/6_22.html

पावन प्रसंग

मातृशक्ति के जीवनचक्र का प्रतिबिंब है नवरात्रि पर्व

नवरात्रि केवल देवी पूजा का पर्व ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा समय है जब व्यक्तिगत जीवन में आने वाले परिवर्तनों को सकारात्मक रूप से अपनाने, व्यक्तिगत बाधाओं को दूर करने और एक बेहतर व्यक्ति बनने का दृढ़ निश्चय करता है, जिसे संकल्प कहा जाता है । नवरात्रि देवी मां के सम्मान में हमारे देश में मनाए जाने वाले सारे पर्वों में मुख्य पर्व माना जाता है । यह एक विशेष पर्व है जिसमें पारंपरिक पूजन, नृत्य व संगीत सभी शामिल रहते हैं। नवरात्रि का वास्तविक अर्थ है- हमारे जीवन के सभी तीन तत्वों को नौ दिनों तक विश्राम देना । नवरात्रि के पहले तीन दिन 'तामसिक दिन' होते हैं । उसके बाद 'राजसिक दिन' आते हैं और अंत के तीन दिन 'सात्विक दिन' होते हैं । हर दिन का अपना विशेष महत्व होता है । पूरे नौ दिन यज्ञ, पूजा और होम किए जाते हैं । अग्नि को अर्पित की जाने वाली सामग्री में विभिन्न जड़ी - बूटी, फल, वस्त्र और मंत्र शामिल होते हैं, जो मुग्ध कर देने वाले तेजोमय दैवीय वातावरण का निर्माण करते हैं। नवरात्रि की शुरुआत सर्वप्रथम मन की अशुद्धियों को दूर करने के लिए मां दुर्गा के आव्हान के रूप में की जाती है । कहा जा सकता है कि पहला कदम - लालसा, द्वेष, दंभ, लोभ आदि प्रवृत्तियों पर विजय पाना होता है । इसके पश्चात उत्कृष्ट मूल्यों व गुणों और समृद्धि को विकसित करने के लिए मां लक्ष्मी का आव्हान किया जाता है । अंत में आत्म के सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हेतु मां सरस्वती का आव्हान किया जाता है ।

नवरात्रि जैसे परम कल्याणकारी पर्व को मनाने का उद्देश्य जड़ता से प्रसन्नता की ओर, कामना से तृप्ति की ओर अग्रसर होना ही है । जिस प्रकार हम प्रतिदिन रात्रि के समय विश्राम करते हैं, ठीक उसी तरह भारतीय संस्कृति के अनुसार वर्ष में दो बार ध्यान साधना के द्वारा गहरे विश्राम में जाने और स्वयं का पुनर्नवीकरण करने की परंपरा है ध्यान दिया जाए तो मां दुर्गा की आरती के बाद हमेशा 'अर्गला स्त्रोत' का पाठ या उसके कुछ श्लोक बोले जाते हैं । यह एक पंक्ति बार - बार आती है-

रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि द्विषो जहि

अर्थात मां तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि व्याधियों का नाश करो । इन्हीं स्त्रोतों में ऐसी पंक्तियां भी आती हैं जो पुरुष द्वारा प्रार्थना के रूप में अच्छी पत्नी के लिए की जाती है:

पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारणिम ।
तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोदभवाम् ।।

अर्थात मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कल में उत्पन्न हुई हो ।

प्रति नवरात्र मे मां का आगमन किस वाहन मैं हो रहा है, यह भी महत्व रखता है । इस बार मां सोमवार को प्रकट हो रही है , जो हाथी वाहन के साथ आने की सूचना दे रहा है । मां के प्रकटोत्सव को लेकर कहा जाता है-

शशि सूर्य ग़जारूढ़ा , शशि भौमें तूरंगमें। गुरु शुक्रे च दोलायम बूधे नौका प्रकीरतिता ।। फ्लेंगज़े च जलदा देवी, छत्र भांग़ तूरंगमें । नौकायाम सर्वसिद्धिसयात दोलायम मरणम ध्रुवम ।।

श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के इस श्लोक के अनुसार मां दुर्गा का आगमन और प्रस्थान कि वाहन के साथ होगा इसका निर्धारण किया गया है । यदि नवरात्रि की प्रतिपदा सोमवार या रविवार को हो तो मन हाथी पर आरूढ होती है । शनिवार मंगलवार को घोड़े पर । गुरुवार या शुक्रवार को डोली और बुधवार को माता नौका पर सवार होकर आती हैं । हाथी पर सवार होकर आने से वर्षा अच्छी होती है, सुख समृद्धि बढती है ।

-डॉ. सूर्यकांत मिश्रा

आपके पत्र

संघ और मोदी शाह आमने-सामने!

आजकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत फुल पावर में नज़र आ रहे हैं क्योंकि मोदीजी ने खुद के बनाए उसूलों की अवहेलना की है। शायद यही वजह है मोदीजी को 75वीं सालगिरह पर शुभकामनाएं भी संघ प्रमुख ने नहीं दी। उन्होंने दो बार इशारों इशारों में उनके 75वें साल पर याद दिलाया कि उन्हें अपने पद से हट जाना चाहिए। पर वे डटे हुए हैं और अपने पसंदीदा चुनाव प्रचार कार्य में बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। दिलचस्प बात ये है कि कहीं से भी वे अपने अंदर के दर्द को प्रकट नहीं होने दे रहे हैं। इस बीच बिहार में उन्होंने अपने को दी गई मां की गाली पर जो नारी सम्मान का स्वांग रचा वह आपरेशन सिंदूर की तरह चकनाचूर हो गया। हाल ही में मां के पिंडदान हेतु गया में नौटंकी की बात सामने आई थी वे जन्मदिन पर वहां जाने वाले थे किंतु भाजपा के मोदी विरोधी सांसदों और संघ की दनादन हो रही बैठकों की वजह से उपजी चिंता के कारण वे पिंडदान करने नहीं जा पाए। उधर गुजरात से आई ख़बर ने यह साफ़ बता दिया कि उनके बड़े भाई मां का पिंडदान गया में कर आए हैं यानि गया की उनकी नौटंकी फ्लाप हो गई।

आजकल नितिन गडकरी पर लगे आरोप की पोल खोलने का इल्ज़ाम मोदी शाह पर लग रहा है क्योंकि ख़बरें बता रहीं हैं कि संघ ने भावी प्रधानमंत्री के रुप में उनका चयन कर लिया है इसकी भनक मोदी शाह को हो चुकी है। नितिन गडकरी को नीचा दिखाने के मोदी-शाह के इस कदम से संघ को ठेस पहुंची है।

इसी तरह भाजपाध्यक्ष पद पर जबरिया डटे जेपी नड्डा की हालत भी खराब है संघ बार-बार संजय जोशी के नाम पर अपनी अडिगता दिखा रहा है जो मोदीजी का शुरुआती राजनीतिक जीवन का नंबर वन शत्रु है। गुजरात मुख्यमंत्री बनने से मोदी ने उसे रोका था। यहां तक कि गुजरात से उसे बाहर कर ही दम लिया। आज उसी का नाम भाजपा अध्यक्ष पद पर संघ द्वारा चयनित हो चुका है।

ऐसी स्थिति में मोदी शाह जी जान से अपने को सही और योग्य साबित करने की चेष्टा में लगे हैं। उधर राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ नारे की धूम है।

मोदी शाह कई मामलों में फंसते नज़र आ रहे हैं। मोदीजी के चरित्र पर आक्षेप भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और सांसद कंगना रनौत खुल्लम खुल्ला लगा चुके हैं। फर्जी वाड़ा के शिरोमणि और अरबों की लूट का जीवंत किरदार तथा झूठ वा जुमलों का बादशाह अपने शाह के साथ बुरी तरह फंस चुका है।

इसलिए वह आज भी सत्ता के सम्मोहन में है क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है पद की शक्ति गई तो जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। इसीलिए लालकिले से संघ का यशगान किया झुक-झुक सलाम किया। उनको खुश रखने स्वावलंबन का उद्घोष किया और मणिपुर भी बेमन से जाना पड़ा जहां सरासर अपमान झेलना पड़ा। अब तो वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ संघ ने भी उन्हें गद्दी से हटाने की योजना बना रखी है अब देखना यह है कि भागवत अपनी इच्छा पूर्ण कर पाते हैं या मोदी के सर पर ताज कायम रहता है। किंतु यह बात तय है कि संघ भले ही सत्ता बचाने रहम कर दे किंतु आज नहीं तो कल गुजराती मोटा छोटा भाई की जुगल जोड़ी को हटना ही होगा और जेल की शोभा बढ़ानी होगी।

-सुसंस्कृति परिहार

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770

ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

चिंतन

भारत में नवाचार को रफ्तार देगा अमेरिका का फैसला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के साथ डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त बताते हैं, उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं और दूसरी तरफ एक के बाद एक भारत के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। दो दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान में भारत द्वारा बनाए जा रहे चाबहार पोर्ट पर 2018 में दी गई प्रतिबंधों से छूट को रद्द करने की घोषणा की है। यह फैसला 29 सितंबर 2025 से लागू होगा। भारत ने अभी तक वहां 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। भारत इस पोर्ट के साथ एक आर्थिक क्षेत्र बनाने व अफगानिस्तान तक रेल नेटवर्क तैयार करने पर भी काम कर रहा है। इस परियोजना को पाकिस्तान में चीन की तरफ से निर्मित गवादर पोर्ट की तुलना में भारत की महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी परियोजना के तौर पर देखा जाता है। इस प्रोजेक्ट के साथ उज्बेकिस्तान, तुर्केमिनस्तान व यूएई जैसे देशों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन अमेरिका का नया कदम पोर्ट परियोजना को लेकर अनिश्चितता पैदा कर देगा। अभी ये मामला ठंडा ही नहीं पड़ा था कि ट्रंप ने शुक्रवार को एच-1बी वीजा पर 100,000 डॉलर की एनुअल फीस लगाकर उन्होंने फिर भारत को झटका दिया। इससे यह प्रोग्राम लगभग खत्म हो जाएगा। इससे भारतीयों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। अमेरिका में एच-1बी वीजा की एवरेज एनुअल सैलरी 66,000 डॉलर है। यह कदम अमेरिका के संरक्षणवादी रवैये को दर्शाता है। ट्रंप ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की बातचीत धीरे-धीरे सामान्य होने की ओर बढ़ रही थी। हाल में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच की टीम भारत दौरे पर थी। उनकी भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता सकारात्मक रही। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अगले सप्ताह अमेरिका यात्रा पर जाने वाले हैं। वहां भारत-अमेरिकी व्यापार सरल बनाने पर चर्चा होनी है, लेकिन इससे पहले ही ट्रंप ने एच-1बी वीजा की फीस बढ़ाकर भारत पर एक बार फिर दबाव बनाने की कोशिश की है। अगर आंकड़ों को देखें तो अमेरिका हर साल 85,000 एच-1बी वीजा जारी करता है, जिनमें से लगभग 75 फीसदी भारत को मिलते हैं। ट्रंप के इस फैसले का असर भारत के आईटी इंजीनियर, डॉक्टर्स पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। ट्रंप ने कहा है कि अब कोई भी कंपनी विदेशी कर्मचारियों को ट्रेनिंग नहीं देगी। अगर देगी तो सरकार को 100,000 डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) देने होंगे। फिर कर्मचारी को भुगतान करना होगा। ऐसे में यह आर्थिक रूप से सही नहीं है। अगर आप किसी को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं तो आप अपने देश के बेहतरीन विश्वविद्यालयों से निकले हालिया ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग देंगे। कहा गया है कि एच-1बी प्रोग्राम के दुरुपयोग से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। इससे अमेरिकी नागरिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर बनाने से हतोत्साहित होते हैं, लेकिन ट्रंप ने सीधे-सीधे भारत को निशाने पर रखकर ये फैसला लिया है। वो किसी भी तरह से भारत पर दबाव बनाने की कोशिशों में लगे हैं। अनेक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ट्रंप का ये फैसला हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। ग्लोबल टैलेंट प्रतिबंध लगाने से लैब, पेटेंट, इनोवेशन और स्टार्टअप भारतीय शहरों की ओर चले जाएंगे, जिससे अमेरिका का नुकसान व भारत को फायदा होगा। ये कदम भारत के नवाचार को गति देगा। अब समय है कि हम अपने देश में विकास को गति दें ताकि अगली पीढ़ी को काम के लिए देश छोड़कर बाहर न जाना पड़े।

बिहार विस चुनाव

सुशील देव

नई पार्टियों की एंट्री बदलेगी गणित या बढ़ाएगी कंफ्यूजन

बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। इस बार की सबसे खास बात यह है कि कई नई राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। इससे न केवल राजनीतिक समीकरण बिगड़ सकते हैं बल्कि मतदाताओं के बीच असमंजस की स्थिति भी पैदा हो रही है। जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और महागठबंधन (राजद-कांग्रेस गठबंधन) चुनावी अखाड़े में प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं, वहीं इस बार नई पार्टियों की मौजूदगी ने पुराने दलों के लिए सिरदर्द बढ़ा दिया है। नई पार्टियों में सबसे ज्यादा चर्चा चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जन सुराज पार्टी की है जो इन दिनों बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है। जन सुराज को लंबे समय तक देशभर की राजनीति में चुनावी रणनीतियों के लिए डिजाइन किया है। अब वे खुद अपनी पार्टी के साथ मैदान में हैं। खास बात यह है कि उन्होंने बिहार की जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। गांव-गांव जाकर संवाद, पदयात्रा और जनता से सीधे संपर्क के जरिए उन्होंने साफ संदेश दिया है कि उनकी राजनीति जाति और धर्म के बंधनों से परे होगी। यही वजह है कि जन सुराज पार्टी को इस बार 'गंभीर खिलाड़ी' माना जा रहा है। वहीं पुरानी राजनीति को चुनौती देने वाली स्थिति भी रोमांचक है। बिहार की राजनीति पिछले पांच दशकों से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और दिवंगत रामविलास पासवान जैसे बड़े नेताओं के इर्द-गिर्द घूमती रही है। लेकिन इस बार तस्वीर बदलती नजर आ रही है। दो प्रमुख गठबंधनों के अलावा एआईएमआईएम (असदुद्दीन ओवैसी) और आजाद समाज पार्टी (चंद्रशेखर आजाद) भी सक्रिय हैं। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी और प्लूरल्स पार्टी (पुष्पम प्रिया चौधरी) जैसी पार्टियां भी वोट कटवा की भूमिका निभा चुकी हैं। इन नई पार्टियों की मौजूदगी से यह तय है कि पारंपरिक वोट बैंक पर सेंध लग सकती है। जातिगत राजनीति बनाम स्वच्छ राजनीति भी इन दिनों में बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। ध्यान रहे कि बिहार की राजनीति जातिगत समीकरणों से हमेशा प्रभावित रही है। इस बार भी कई छोटे दल ईबीसी (अति पिछड़ा वर्ग) और ओबीसी वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। महागठबंधन का पारंपरिक मुस्लिम-यादव वोट बैंक भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एआईएमआईएम जैसी पार्टियां उसी वर्ग को साधने की रणनीति बना रही हैं। दूसरी ओर एनडीए में भी पिछड़े वर्गों पर पकड़ बनाए रखने के लिए कड़ी चुनौती है। हालांकि, जन सुराज जैसी पार्टियां यह दावा कर रही हैं कि वे जाति-धर्म से ऊपर उठकर स्वच्छ राजनीति की नई शुरुआत करना चाहती हैं। यदि जनता ने इन दावों पर भरोसा किया तो यह बिहार की राजनीति के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी (आप) ने भी बिहार चुनाव को गंभीरता से लेने की तैयारी की है। भले ही राज्य में उसका कोई खास जनाधार न हो, लेकिन हर सीट पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान करके उसने संदेश दिया है कि वह सिर्फ मौजूदगी दर्ज कराने नहीं बल्कि सशक्त विकल्प बनने का प्रयास कर रही है। वहीं, चिराग पासवान भी इस बार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा जताया है। इससे न केवल एनडीए बल्कि महागठबंधन में भी असहजता है। जहां तक छोटे दलों की बात है, उनमें भी कई प्रकार से बदलाव देखे जा रहे हैं। अव्वल तो यह है कि ज्यादातर सभी सीटों से चुनाव मैदान में उतरने को आमादा हैं। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और लगभग हर सीट पर दर्जनों दावेदार नजर आते हैं। कई छोटे दल पहले से ही उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं, जबकि कुछ टिकट वितरण की प्रक्रिया में हैं। अक्सर छोटे दल चुनाव से पहले बड़ी पार्टियों के साथ अप्रत्याशित गठबंधन कर लेते हैं। कई बार उनका उद्देश्य सिर्फ एक या दो सीट जीतना नहीं बल्कि टिकट बंटवारे और गठबंधन की राजनीति से तवज्जो और पहचान हासिल करना होता है। कुछ दल तो चंदा जुटाने और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए भी मैदान में उतरते हैं। इन सबके बीच बड़ी पार्टियों को वोट कटवा की चिंता है। नई पार्टियों की एंट्री ने जहां पुरानी पार्टियों के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, वहीं मतदाताओं के लिए विकल्पों की भरमार से कंफ्यूजन बढ़ गया है। चुनावी परिणाम चाहे जो हो, इतना तय है कि इस बार का चुनाव राज्य की राजनीति की दिशा और दशा तय करने में निर्णायक साबित होगा। अगर नई पार्टियां जनता के विश्वास पर खरी उतरती हैं, तो बिहार की राजनीति में नई इबारत लिखी जाएगी। लेकिन अगर वे केवल वोट काटने तक सीमित रहीं, तो यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं होगा।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

समाजवाद, अहिंसा, लोककल्याण के अग्रदूत अग्रसेन महाराज

जयंती पर विशेष

ललित हीरालाल गर्ग

भारत भूमि में समय समय पर अनेकों महापुरुष अवतरित हुए है। महाराज अग्रसेन भारतीय सभ्यता के उन चिरस्थायी आदर्शों में से एक हैं, जिन्होंने समाज में समानता, अहिंसा और समुचित वितरण की भावना को जन्म दिया। युगाब्द से 22 वर्ष पूर्व (ईसापूर्व 3124) द्वापर युग के अंतिम चरण में आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को प्रतापनगर में सूर्यवंशी भगवान श्रीराम के बेटे कुश की 34वीं पीढ़ी के वंशज क्षत्रिय राजा वल्लभसेन व माता भगवतीदेवी के घर अग्रसेनजी का जन्म हुआ था। 15 वर्ष की आयु में अपने पिता राजा वल्लभसेन के साथ पांडवों की तरफ से कौरवों से महाभारत का युद्ध करते समय 10वे दिन भीष्म पितामह के बाणों से राजा वल्लभसेन को वीरगति मिलने से अग्रसेनजी प्रतापनगर के महाराज बनाये गये थे। नागकुमारी माधवी से विवाह कर उन्होंने द्वापर युग में 7 वर्षों तक प्रतापनगर में राज किया. द्वापर से कलयुग के परिवर्तन पर जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग किया था, तब 22 वर्षीय महाराज श्री अग्रसेन ने वर्तमान हरियाणा के अग्रोहा में सरस्वती नदी के तट पर नए राज्य की स्थापना कर 101 वर्षों तक राज करने के उपरांत कुलदेवी महालक्ष्मी से परामर्श करके अपने ज्येष्ठ पुत्र विभु को शासन सौंपकर तपस्या करने चले गए और वानप्रस्थ आश्रम में तपस्या के दौरान भौतिक शरीर का परित्याग किया. उन्हें व्यापार, कृषि और समानता पर आधारित व्यवस्था लागू करने हेतु याद किया जाता है। एकबार अकाल पड़ने पर वे वेश बदल कर राज्य भ्रमण के दौरान चार सदस्यों के परिवार में गये. जो भोजन करने ही वाले थे कि अतिथि को देखकर चारो ने अपनी अपनी थाली से एक अंश निकाल कर अतिथि को परोसा। इसी से प्रेरणा लेकर महाराज अग्रसेन ने 'एक ईंट और एक रुपया' की नीति से समाज में नवआगंतुकों को आत्मनिर्भर बनाकर सामूहिक सहयोग और सामाजिक सुरक्षा की मिसाल पेश की। उस समय समाज जाति व अस्पृश्यता विहीन था तथा एक कुल से दुसरे कुल में स्वयंवर द्वारा योग्य वर का चयन कर विवाह सम्पन्न होते थे। क्षत्रिय होते हुए भी उन्होंने यज्ञों में पशु बलि का विरोध करते हुए अहिंसा का मार्ग चुना और राज्य की समृद्धि के लिए हिंसा- रहित अग्रवंश (वैश्य वर्ग) खड़ा किया।

महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य को 18 जनपदों (गणराज्य/राज्यांश) में विभाजित किया था और प्रत्येक गणराज्य के प्रशासनिक प्रमुख को उन्होंने अपने पुत्रवत माना था। महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य में लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव भी रखी थी, जहाँ प्रत्येक जनपद से एक-एक प्रतिनिधि लेकर प्रशासन का संचालन होता था। प्रत्येक जनपद के अपने अपने गुरु थे जो ऋषि थे, वही आगे चल कर अग्रकुल कहलाए और उनके गोत्र उनके ऋषियों से ही बने।

गणराज्य प्रमुख	गोत्र नाम	महर्षि जी का नाम
1. विभु	गर्ग गोत्र	महर्षि गर्गाचार्य
2. भीमदेव	गोयल गोत्र	महर्षि गोभिल
3. शिवजी	गोयन गोत्र	महर्षि गौतम
4. सिद्धदेव	बंसल गोत्र	महर्षि वत्स
5. बासुदेव	कंसल गोत्र	महर्षि कौशिक
6. बालकृष्ण	सिंघल गोत्र	महर्षि शांडिल्य
7. धर्मनाम	मंगल गोत्र	महर्षि मंडव्य
8. अर्जुन	जिंदल गोत्र	महर्षि जैमिन
9. रणकृत	तुंगल गोत्र	महर्षि तांड्य
10. गुप्तनाम	ऐरन गोत्र	महर्षि और्व
11. पुष्पदेव	धारण गोत्र	महर्षि धौम्य
12. माधोसेन	मधुकुल गोत्र	महर्षि मुद्गल
13. केशवदेव	बिंदल गोत्र	महर्षि वशिष्ठ
14. भुजमान	मित्तल गोत्र	महर्षि मैत्रेय
15. कंवलदेव	कुच्छल गोत्र	महर्षि कश्यप
16. गुणराज	नांगल गोत्र	महर्षि नगेन्द्र
17. वासगी	भंदल गोत्र	महर्षि भारद्वाज
18. शिवजीभान	तायल गोत्र	महर्षि तैलंग

उक्त 18 गोत्र मूल ऋषियों के नामों पर आधारित हैं, जो अग्रवाल समाज की पहचान हैं. विचारणीय प्रश्न यह भी है कि यदि महाराजा श्री अग्रसेन जी के 18 पुत्र थे. तब तो सभी अग्रवाल आपस में पितृकुल से जुड़े भाई बहन हो जायेंगे तो अग्रवाल आपस में विवाह सम्बंध कैसे कर सकते है. संभव है कि हम सब महाराजा श्री अग्रसेन जी के आदर्शो पर चलने वाले भिन्न भिन्न जनसमूह से हो. लोकतांत्रिक शासन, न्यायप्रिय नीति, आर्थिक समानता और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएँ हर नागरिक के लिए सुलभ कराने वाले अग्रसेनजी ने अपने समय में प्रजाहित को सर्वोपरि स्थान दिया। महाराज अग्रसेन के नेतृत्व में अग्रोहा राज्य व्यापार, सामाजिक समन्वय, धर्म, न्याय और समृद्धि का केंद्र बन गया था। महाराज अग्रसेन के नाम से देशभर में अस्पताल, विद्यालय, सामुदायिक भवन, धर्मशालाएँ संचालित हैं, जो उनके लोकहितकारी दृष्टिकोण का जीवंत उदाहरण हैं।

उनकी 5100 वीं जयंती के पावन अवसर पर 1976 में भारत सरकार द्वारा, 2016 में मालदीव द्वारा तथा 2017 में भारतीय डाक विभाग द्वारा अग्रसेन की बावली पर एक स्मारक डाक टिकिट जारी किये गये है. छत्तीसगढ़ सहित अनेक राज्य-सरकारों द्वारा उनके आदर्शो को स्वीकार कर उनके नाम पर प्रतिवर्ष रु. दो

लाख से अधिक नगद पुरस्कार प्रदान किये जा रहे है. महाराज अग्रसेन न सिर्फ एक कालजयी शासक थे, बल्कि समता, उदारता व अहिंसा के ऐसे अनुकरणीय आदर्श हैं, जिनकी प्रेरणा आज भी सामाजिक उत्थान और सद्भाव की धुरी बनी हुई है। हर वर्ष हम अग्रसेन जयंती मनाते है, लेकिन अग्रकुल संस्थापक के इतिहास को अगली पीढ़ी तक नहीं पहुचा पाते है. कार्तिक अमावस्या को दीपावली, फाल्गुन पूर्णिमा को होली, चैत्र शुक्ल तेरस को महावीर जयंती, कार्तिक पूर्णिमा को गुरुनानक जयंती, चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी और आश्विन माह शुक्ल प्रतिपदा को श्री अग्रसेन जयंती इस बात के द्योतक हैं कि हमारे सभी व्रत त्यौहार तिथि आधारित हैं ना कि ग्रेगोरियन कलेंडर के दिनांक आधारित। इन्ही त्रुटियों को दूर करने हेतु देश के जानेमाने हिंदू चिंतक एवं विचारक अग्रकुल के ही सुनील गंगाराम गर्ग द्वारा संपादित व ललित हीरालाल गर्ग के बिलासपुर आवास से हिंदू दैनंदिनी न्यास द्वारा नववर्ष चैत्र प्रतिपदा युगाब्द 5127 के पावन अवसर पर बिलासपुर से विगत पांच वर्षो से लगातार हिंदू दैनंदिनी प्रकाशित कर अग्रवंश सहित हिंदु समाज को वास्तविकता से अवगत कराने हेतु विश्व में पहली बार हिंदू तिथि को अंको में लिखने की विधि सहित सरल भाषा में तिथि, व्रत, त्यौहार, ऋतु आदि एकसाथ उपलब्ध कराकर हिंदुत्व के विलुप्त होते सद्गुणों को सहेजने व नई पीढीयों को अपने वैभवशाली इतिहास से अवगत कराने हेतु उद्यम किया जा रहा है.

श्री श्री 1008 श्री महाराजा अग्रसेन की विशेषताए

दो युगों के दृष्टा : द्वापर के अंत से लेकर कलयुग में भी राज

जाति विहीन समाज : सूर्यवंशी होकर नागवंशी से विवाह

अहिंसा : पशुबलि/मांसाहार का त्याग कर शाकाहार अपनाया

वर्ण परिवर्तन : क्षत्रिय वर्ण को त्याग शुद्ध सात्विक वैश्य वर्ण अपनाया

समाजवाद : समाज से नवआगंतुकों को एक ईंट और एक रुपया दिलवाकर समकक्ष बनाना

धर्मार्थ कार्य : आमदनी का निश्चित हिस्सा धर्मार्थ समाज को वापस करना

समाजसेवा : उस दौर में वृक्षारोपण, कुएं, बावड़ी, धर्मशालाओ का निर्माण

गोत्र व्यवस्था : 18 पुत्रों को यज्ञ कर 18 ऋषियों के मूल गोत्र दिलवाना

सर्वाधिक न्यायपूर्ण राज : 7 वर्षों तक द्वापर युग में तथा 101 वर्षों तक कलयुग में कुल 108 वर्षों न्यायपूर्ण राज करने वाले एकमात्र शासक।

उपरोक्त विशेषताओं को ध्यान रखते हुए उनके वंशज (स्टेक होल्डर) होने के नाते आज हमें जाति व्यवस्था का त्याग कर केवल गोत्र उपयोग करना ना केवल ज्यादा प्रासंगिक होगा, अपितु समग्र हिंदू समाज के उत्थान में सहायक होकर पुरुष/महिला के अनुपात की कमी को दूर कर सभी के विवाह सम्बंध में सहायक भी होगा. उनकी 5149वीं जयंती पर हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों का त्याग कर उपरोक्त महर्षियों के गोत्र उपनाम अपनाकर जाति विहीन समरस समाज बनाकर उनके आदर्शो को अपनाना हीं उनके प्रति सही सम्मान होगा. यदि आपके मन में जाति व्यवस्था के अस्तित्व में आने के कारण, अस्पृश्यता के कारण, हिंदुत्व के वैज्ञानिक सद्गुण व काल गणना से सम्बन्धित कोई प्रश्न हो तो निसंकोच सम्पर्क करे यथासम्भव निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा।

नाम जप से मिट जाते हैं बुरे कर्म

संकलित

दर्शन

बुरे और अच्छे कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। आपने भी कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि इसके कर्म ही इसे ले डुबेंगे। दरअसल हर एक कर्म का फल यही इसी जिंदगी में भोगना है लेकिन क्या बुरे कर्म को कभी पूजा-पाठ या नाम जप से खत्म किया जा सकता है? इसका जवाब वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने दे दिया किया है। एक भक्त के पूछे जाने पर प्रेमानंद महाराज ने तीन तरह के कर्मों के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने समझाया कि नाम जप से कौन-कौन से बुरे कर्म खत्म किए जा सकते हैं और किन कर्मों का फल हमें किसी भी हालत में भुगतना ही पड़ता है। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि जप से बुरे कर्म तो नष्ट हो जाते हैं लेकिन वर्तमान के बुरे कर्म। जो कर्म प्रारब्ध बन गया है वो नहीं। वो भोगना पड़ेगा। इस शरीर की रचना के वक्त जो प्रारब्ध बन गया है, वो भोगना ही पड़ेगा। वो नहीं काटा जा सकता है। बड़े-बड़े संतों को भी वो भोगना पड़ता है। अब अगर हम इतना डटकर नाम जप करें तो पहले जो वर्तमान की जो गलतियां हुई हमारी इस जन्म में वो पवित्र हो जाए। फिर पूर्व जन्मों का जो संचित यानी गोदाम जमा है वो भस्म हो जाए और प्रारब्ध को भोग लें तो हम निष्पात हो जाएंगे। भोग बड़ा कार्य है। इसलिए पूरा जीवन पाप ना करते हुए, धर्म से चलते हुए एक-एक कदम सावधानी से नाम जप करते हुए तब वो निष्पात हो जाता है। निष्पात होना बहुत कठिन है क्योंकि जबसे सृष्टि हुई तबसे हमारा हिसाब-किताब चल रहा है और आज तक भजन नहीं हुआ।

लक्ष्य पर ध्यान लगाओ

संकलित

प्रेरणा

स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना [illegible] वह बिलकुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाये और सभी बिलकुल सटीक लगे। ये देख लड़के दंग रह गए और उनसे पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो, तो तम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। तब तुम कभी चूकोगे नहीं। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो, तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो. मेरे देश में बच्चों को यही करना सिखाया जाता है। इधर, एक और घटना है। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा पर गये थे। उनका भगवा वस्त्र और आकर्षक पगड़ी देख कर लोग अचंभित रह गये और वे यह पूछे बिना नहीं रह सके, आपका बाकी सामान कहां है? स्वामी जी बोले, मेरे पास बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने व्यंग्य किया, अरे! यह कैसी संस्कृति है आपकी? तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है। कोट-पतलून जैसा कुछ भी पहनावा नहीं है? इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराये और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है।

Join This Channel:- https://t.me/AllNewsPaperPaid1

महालय पर प्रभात फेरी

'दुर्गा पूजा' उत्सव की शुरुआत के प्रतीक 'महालय' के अवसर पर गुरुग्राम में निकाली गई 'प्रभात फेरी'।

आज की पाती

नाबालिग वाहन चालकों के लिए सख्ती हो

नाबालिग वाहन चालकों के लिए सख्ती होना चाहिए। अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पुलिस पकड़ लेती है तो इसके लिए सख्त कानून का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस कानून के तहत लगभग 25 हजार जुर्माना और लगभग तीन साल की सजा का भी प्रावधान है। हालांकि सरकार और प्रशासन इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए। स्कूलों में इसके लिए बच्चों को जागरूक भी किया जाए और स्कूलों से विद्यार्थियों के माता-पिता को इसके लिए नोटिस भी भेजे जाए कि वो अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न दें। दोपहिया वाहन एक्सीडेंट का आंकड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दोपहिया वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर या फिर एक्टिवा चलाते समय हैलमेट का प्रयोग अपनी जान की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, न कि चालान के डर से।

- विकास साहू, रायपुर

ट्रेंड

प्रगति की समीक्षा

लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की प्रगति की समीक्षा की। यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय होगा। यह भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं को प्रदर्शित करेगा और पर्यटन, अनुसंधान, शिक्षा और कौशल विकास का केंद्र बनेगा।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

हिंसा भड़का रहा विहिप

विश्व हिंदू परिषद कौन होता है यह तय करने वाला कि कौन गरबा में जाएगा और कौन नहीं? यह सलाह सिर्फ आयोजकों को निर्देश देने तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ कट्टरपंथी तत्वों को हिंसा भड़काने और बल प्रयोग करने का खुला निमंत्रण है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं!

- रामदास अठावले, केंद्रीय मंत्री

डल झील साफ

पिछले पांच वर्षों के दौरान, डल-निगीन झील और इसके जलग्रहण क्षेत्र के संरक्षण का काम मिशन मोड में किया गया है। डल झील साफ हुई है और बड़ी संख्या में घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित कर रही है।

-मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल, जम्मू-कश्मीर

भाजपा की मिलीभगत

मानव-वन्य जीव संघर्ष के लिए भाजपा सरकार की अवैध कटाई करवाने की मिलीभगत ज़िम्मेदार है। जब पशुओं के सामने 'भोजन और आश्रय' का संकट आएगा तो वो हिंसक होंगे ही।

- अखिलेश यादव, सांसद, सपा

करंट अफेयर

एक बार भारी आहार लेने से भी 'मेटाबॉलिज्म' व पाचन पर असर

नवरात्र शुरू हो रहे हैं और विशेषज्ञों की सलाह है कि इस दौरान उपवास करने वालों को रात्रि में अचानक भारी भोजन करने से बचना चाहिए। चिकित्सकों का मानना है कि ऐसा करना उनके 'मेटाबॉलिज्म' और पाचन तंत्र पर नकारात्मक असर डाल सकता है। आमतौर पर, नवरात्र में उपवास करने वाले श्रद्धालु दिन में फल और रात्रि में आलू-साबूदाना की खिचड़ी, सिंघाड़े के आटे का हलवा, लौकी, कद्दू, दूध, दही या पनीर इत्यादि चीजों का सेवन करते हैं। हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, नौ दिन तक खाने का यह पैटर्न नुकसानदायक साबित हो सकता है। दिनभर भोजन न करने से शरीर की ऊर्जा की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है और शाम या रात्रि में भारी भोजन लेने से पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है। इससे अपच, एसिडिटी और पेट में भारीपन की शिकायत हो सकती है। दिल्ली स्थित अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल के 'डायटिक्स एंड न्यूट्रिशन विभाग' की वरिष्ठ कंसलटेंट दिव्या मलिक ने कहा, नौ दिन के उपवास में दिनभर कुछ न खाना और रात्रि में एक बार भारी भोजन लेने से पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है। मेटाबॉलिज़्म भी धीमा पड़ सकता है क्योंकि भूखे रहने के बाद एक बार में ज्यादा खाना खाने से शरीर कैलोरी को सही तरीके से जलाने में मुश्किल महसूस करता है।

ऑफ बीट

मनोभ्रंश का कारण बन सकती है कम घंटों की नींद

देर रात तीन बजे आंख खुलने के बाद लगातार टकटकी लगाये छत पर लगे पंखे या घड़ी को देखते रहने से सिर्फ अगले दिन के लिए ऊर्जा कम होती है। अमेरिका में बुजुर्गों पर किए गए एक दीर्घकालिक अध्ययन में अब यह सामने आया है कि ज्यादा समय तक ये समस्या हमारे मस्तिष्क के अंदर होने वाले उन बदलावों से जुड़ी हुई है, जो मनोभ्रंश का कारण बनते हैं। अमेरिका के मेयो क्लिनिक के शोधकर्ताओं ने 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के 2,750 लोगों पर औसतन साढ़े पांच साल तक नजर रखी। अध्ययन में शामिल लोगों ने हर साल विस्तृत स्मृति जांच कराई और कई लोगों के मस्तिष्क स्कैन भी हुए, जिनसे भविष्य में संज्ञानात्मक समस्याओं के दो स्पष्ट संकेत मिले, जिनमें 'एमिलॉइड प्लेक' का निर्माण और मस्तिष्क के श्वेत पदार्थ में क्षति के छोटे-छोटे निशान शामिल हैं और इसे श्वेत पदार्थ 'हाइपरइंटेंसिटीज' भी कहते हैं। एक महीने के अंतराल पर कम से कम दो बार इस समस्या का निदान होने पर प्रतिभागियों को लंबे समय से इस समस्या से ग्रस्त माना गया। अध्ययन में पाया गया कि ये समस्या 16 प्रतिशत लोगों को प्रभावित करती थी। गहरी नींद में सोने वाले लोगों की तुलना में लंबे समय से अनिद्रा का शिकार लोगों की याददाश्त व सोचने की क्षमता में गिरावट देखी गई।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

पायनियर
नई दिल्ली, सोमवार, 22 सितंबर 2025

युवा क्रांति
दमित भावों का उबाल या बदलाव?

यह एक नई और प्रभावशाली घटना है। आज के युवा, जिन्हें जेन जेड के नाम से जाना जाता है, सड़कों पर उतरते हैं, सरकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं, कभी-कभी हिंसा और आगजनी का सहारा लेते हैं, और अचानक शासन व्यवस्थाएँ चरमरा जाती हैं, और उसके बाद भ्रम और अस्थिरता फैलती है। भारतीय उपमहाद्वीप में, यह पैटर्न चिंताजनक रूप से लगातार हो रहा है: सरकारें गिरती हैं, और अराजकता फैलती है। 2022 में कोलंबो की सड़कों से लेकर 2024 में ढाका और अब 2025 में काठमांडू तक, दक्षिण एशिया ने युवाओं के नेतृत्व में विद्रोह की एक असाधारण लहर देखी है जिसने अजेय प्रतीत होने वाली सरकारों को गिरा दिया है।

ये विद्रोह स्वतःस्फूर्त हैं, किसी विचारधारा या नेतृत्व के बिना, बल्कि एक पीढ़ीगत विस्फोट - उन युवाओं की हताशा का विस्फोट जो राजनीतिक व्यवस्था द्वारा अपने भविष्य के साथ छला हुआ महसूस करते हैं। अब स्वाभाविक प्रश्न यह है कि क्या भारत इस तरह के उथल-पुथल का अगला पड़ाव बन सकता है। पहली नजर में, समानताएं आश्चर्यजनक लगती हैं।

नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह, भारत में भी युवा आबादी है—इसकी 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र की है। कई लोग बेरोजगारी, बढ़ती शिक्षा लागत और बढ़ती असमानता से जूझ रहे हैं। वे डिजिटल रूप से भी कुशल हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लोगों को संगठित करने और अपनी राय बनाने में माहिर हैं।

फिर भी, ये अंतर भी उतने ही मायने रखते हैं। अपने पड़ोसी देशों के विपरीत, भारत में कहीं ज्यादा मजबूत चुनावी व्यवस्था और संस्थागत गहराई है। सरकारें बैरिकेडिंग के बजाय मतपत्रों के जरिए बदलती हैं। बांग्लादेश, जहाँ शेख हसीना के लंबे और सत्तावादी शासन ने लोकतांत्रिक विकल्प बहुत कम छोड़े थे, या श्रीलंका, जहाँ आर्थिक पतन के कारण सड़कों पर जाने का कोई विकल्प नहीं बचा था, के विपरीत, भारतीय व्यवस्था गुस्से को व्यक्त करने की गुंजाइश देती है।

अतीत में, भारतीय युवा बड़ी संख्या में बाहर आए थे—उदाहरण के लिए, सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान—लेकिन इससे सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। फिर भी, अचानक युवा अशांति की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय जेनरेशन जेड संकटों के बीच पली-बढ़ी है: आर्थिक तंगी और अब नौकरी की कमी। उनकी आकांक्षाएँ वैश्विक हैं, लेकिन उनके अवसर कम होते जा रहे हैं। और सुलगता असंतोष अक्सर सड़कों पर फूट पड़ता है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या ये तथाकथित क्रांतियां वाकई अपने नाम के लायक हैं? बिल्कुल नहीं।

इन विद्रोहों को क्रांतियों की संज्ञा देना निश्चित रूप से भ्रामक होगा। ये कोई सुव्यवस्थित जन आंदोलन नहीं हैं जिनका कोई सुसंगत एजेंडा, नेतृत्व या भविष्य के लिए कोई ढांचा हो। ये रोष के विस्फोट हैं, जो तात्कालिक कारणों से भड़क उठते हैं - कोलंबो में ब्लैकआउट, ढाका में नौकरियों में कोटा, काठमांडू में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध - लेकिन इनकी जड़ें किसी रोडमैप के अभाव में हताशा में हैं।

इसके बाद अक्सर अराजकता, अनिश्चितता और निराशा का माहौल होता है। भारत के लिए, सबक स्पष्ट है: युवा आक्रोश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे रोमांटिक भी नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके नेताओं के लिए चुनौती यह है कि इस ऊर्जा को लोकतांत्रिक तरीकों से सुधारों में लगाया जाए, इससे पहले कि यह विस्फोट अपरिहार्य हो जाए।

नेपाल में उपद्रव, भारत के लिए सबक

अनियंत्रित भीड़ की उपस्थिति, सड़कों पर खून-खराबा, व्यापक अराजकता, राष्ट्रपति भवन और संसद को जलाना, प्रधानमंत्री का इस्तीफा और नेपाली मंत्रिमंडल का सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन, एक खूबसूरत हिमालयी देश की बेहद निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं।

संजोए गौर बनर्जी
लेखक, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं।

पूर्वी हिमालय पर्वतमाला से आ रही हिंसक हलचलें, प्राइम-टाइम प्रसारणों और सोशल मीडिया के माध्यम से नेपाल में हो रहे खतरनाक घटनाक्रमों पर नजर रखने वालों के बीच व्यापक चिंता का विषय बन रही हैं। भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ 'जेनरेशन जेड' के विरोध प्रदर्शनों से शुरू हुआ आंदोलन अब अपहृत हो गया है और भयावह अराजकता और उत्पात में बदल गया है, जिसने नेपाल को उबलने और एक अकल्पनीय आपदा के कगार पर ला खड़ा किया है।

अनियंत्रित भीड़ की उपस्थिति, सड़कों पर खून-खराबा, व्यापक अराजकता, राष्ट्रपति भवन और संसद को जलाना, प्रधानमंत्री का इस्तीफा और नेपाली मंत्रिमंडल का सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन, एक खूबसूरत हिमालयी देश की बेहद निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं, जो आमतौर पर शांत, सुकून भरे पर्यटन स्थलों और शांत और सहज लोगों के लिए जाना जाता है।

स्थिति को गंभीर और चिंताजनक कहना कम होगा। निरंकुश राजतंत्र के दिनों से लेकर अंततः एक संवैधानिक राजतंत्र और अंततः एक संघीय गणराज्य में परिवर्तन तक, नेपाल के भारत के साथ संबंध पारंपरिक रूप से मधुर और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। राजनीतिक बदलावों के बावजूद - जिसमें हाल ही में बनी कम्युनिस्ट सरकार भी शामिल है, जिसका झुकाव स्वाभाविक रूप से चीन की ओर था - दोनों देशों ने सहयोग और आपसी सम्मान पर आधारित मजबूत, ऐतिहासिक रूप से अनूठे सैन्य संबंधों का आनंद लिया है। यह रक्षा साझेदारी व्यापक द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में सेवारत निडर नेपाली सैनिकों से लेकर एक-दूसरे के सैन्य नेताओं को मानद सेना प्रमुख की उपाधियाँ प्रदान करने की प्रथा तक, भारत-नेपाल रक्षा संबंध पौराणिक बने हुए हैं।

इस व्यापक अशांति के कारणों का, जिसकी परिणति अत्यधिक उत्तेजित और उत्तेजित भीड़ द्वारा की गई अत्यधिक हिंसा में हुई, जिससे जान-माल को गंभीर नुकसान पहुँचा, सावधानीपूर्वक विश्लेषण की आवश्यकता है, खासकर इसलिए क्योंकि ये घटनाएँ भारत के निकटवर्ती पड़ोस में घटित हो रही हैं। हालाँकि राजनीतिक विश्लेषक नीति निमार्ताओं, विपक्षी दलों या दोषपूर्ण सरकारी पहलों की ओर इशारा कर सकते हैं, लेकिन भारत की सुरक्षा पर इस उथल-पुथल के प्रभावों की जाँच करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

हालाँकि यह कहना अतिशयोक्ति हो सकती है कि भारत-नेपाल सीमा पर एक और मोर्चा खुल गया है, लेकिन पूर्वी भारत में अशांति फैलाने के लिए इस सीमा का दुरुपयोग किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वर्षों से, खुली सीमा नीति ने दोनों देशों के बीच वैध आवाजाही को सुगम बनाया है, लेकिन यह भारतीय अपराधियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह और दुर्भावनापूर्ण इरादे से भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों और राष्ट्र-विरोधी तत्वों के प्रवेश द्वार के रूप में भी कुख्यात रही है।

सशस्त्र सीमा बल की मौजूदगी के बावजूद, जिसे नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा का कार्यभार सौंपा गया है, भारत-नेपाल सीमा ने भारत-पाकिस्तान, भारत-चीन, या यहाँ तक कि भारत-बांग्लादेश और भारत-म्यांमार सीमाओं जितना सार्वजनिक या राजनीतिक ध्यान आकर्षित नहीं किया है।

फिर भी, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सिरे तक पूरी तरह से सुरक्षित नहीं किया जा सकता है, और भारत-नेपाल सीमा भी इसका अपवाद नहीं है। ऐतिहासिक रूप से यात्रा, व्यापार और व्यवसाय में लगे नागरिकों के लिए आवागमन की सुगमता के प्रतीक के रूप में देखा जाने वाला यह सीमांत क्षेत्र अब नेपाल में व्यापक अशांति, शासन की अचानक अनुपस्थिति और हिंसक विद्रोह के कारण खतरे में है। विश्लेषकों को नेपाल के वर्तमान संकट और श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान में हाल की घटनाओं के बीच समानताएँ स्थापित करनी होंगी और यह निष्कर्ष निकालना होगा कि सरकारों को गिराने के लिए हिंसक जन-विरोध प्रदर्शनों को संगठित करने से किन लोगों को लाभ होता है।

फिर भी, भारत के लिए यह जरूरी है कि वह सबक सीखे और अपनी सीमाओं के भीतर इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी बरते। पड़ोसी देशों में हाल ही में हुए लगभग सभी उथल-पुथल सोशल मीडिया पर दुर्भावनापूर्ण 'टूलकिट' के तेजी से प्रसार से प्रेरित हुए हैं। ये टूलकिट आमतौर पर सामाजिक शिकायतों - जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अराजकता, सत्ता का दुरुपयोग, भाई-भतीजावाद और धार्मिक विभाजन - के चित्रण के साथ-साथ विरोध को कैसे और कहाँ भड़काया जाए, इस बारे में सूक्ष्म निर्देश भी देते हैं। फिर ऐसी गतिविधियों को इतनी सावधानी से संचालित किया जाता है कि चिंगारी बेकाबू होकर आग में बदल जाती है और अधिकारियों के प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने से पहले ही पूरे राष्ट्र को अपनी चपेट में ले लेती है। सीमित भौगोलिक क्षेत्र और अधिक समरूप आबादी वाले छोटे देश विशेष रूप से असुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन भारत जैसे बड़े और अधिक विविध राष्ट्र भी इससे अछूते नहीं हैं। सुरक्षा की दृष्टि से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अधिक प्रभावी निगरानी की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि वे ऐसे टूलकिट को तेजी और बड़े पैमाने पर प्रसारित करने का प्राथमिक माध्यम बने हुए हैं।

सरकार को सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर नजर रखने, जनभावनाओं पर नजर रखने, प्रभावशाली लोगों की बयानबाजी का विश्लेषण करने और संभावित प्रदर्शनकारी नेताओं के धन स्रोतों का पता लगाने के लिए समर्पित विशेषज्ञ एजेंसियों की स्थापना करनी चाहिए। इसके लिए निरंतर सतर्कता और चौबीसों घंटे निगरानी की आवश्यकता है ताकि चिंगारी को असाध्य आग में बदलने से पहले ही बुझाया जा सके। इसी प्रकार, प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी, घुसपैठ का पता लगाने और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने के लिए ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के उदार उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर तैनाती के लिए कम तकनीक वाले सामरिक ड्रोनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन आवश्यक होगा, जिसके साथ मानवीय खुफिया जानकारी और निगरानी के अन्य तरीके भी होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में, किसी भी स्तर की सतर्कता को अत्यधिक नहीं माना जा सकता।

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों पर भी नजर रखने की आवश्यकता समान रूप से महत्वपूर्ण है, जो अक्सर प्रदर्शनकारियों की भर्ती के लिए उपजाऊ जमीन का काम करते हैं, जो बाद में बेपर्दा भीड़ के स्वेच्छा से सैनिक बन जाते हैं।

शैक्षणिक प्रशासकों को प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की पहचान करने और बाहरी प्रभावशाली लोगों को अस्थिरता पैदा करने के लिए छात्र आबादी का शोषण करने से रोकने के लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। हालाँकि नेपाल में हालात लगातार बदल रहे हैं और उम्मीद है कि अंततः शांति और स्थिरता बहाल हो जाएगी, लेकिन जो जानें गईं और शासन, कानून और संपत्ति का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती।

नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए काफी प्रयास और लचीलेपन की आवश्यकता होगी। भारत के लिए, सबक स्पष्ट है: जनता और सरकार को ऐसे किसी भी चेतावनी संकेत के प्रति सतर्क और संवेदनशील रहना चाहिए जो उसकी अपनी सीमाओं के भीतर इसी तरह की अशांति का पूर्वाभास करा सकता हो।

Join This Channel - https://t.me/AllNewsPaperPaid1

भारी पड़ सकती है स्वास्थ्य की अनदेखी

उस दौर के कई लोग लंबी उम्र जीते थे, और अपने आखिरी सालों में ही बीमारियों का शिकार हुए। आज, ऐसा लगता है मानो स्वास्थ्य हर जगह है, फिर भी, विडंबना यह है कि कहीं नहीं।

आशा अय्यर कुमार
लेखिका, स्वतंत्र पत्रकार हैं।

पिछले हफ़्ते, मैं और मेरा एक दोस्त, जैसा कि हम अक्सर करते हैं, व्हाट्सएप पर वॉइस नोट्स का आदान-प्रदान कर रहे थे। आमतौर पर, हम फिल्मों पर हंसते हैं, ऑफिस की गपशप करते हैं, या वीकेंड की योजनाएं बनाते हैं। लेकिन इस बार, हमारी बातचीत बदल गई थी। मजाकिया बातचीत की बजाय, हम कोलेस्ट्रॉल के स्तर, रक्तचाप, जोड़ों के दर्द, धीरे-धीरे बढ़ते वजन के बारे में बात कर रहे थे—मध्यम आयु के शांत लेकिन लगातार लक्षण जो किसी के न देखने पर भी अचानक उभर आते हैं।

कहीं न कहीं, मेरी बातचीत का केंद्र प्रेम और साहित्य से हटकर उस शरीर की कार्यप्रणाली पर आ गया है जो चरमराता है, खड़खड़ाता है और जिसे ठीक करने की जरूरत होती है। मेरे माता-पिता की पीढ़ी में, स्वास्थ्य एक सचेत प्रयास नहीं था। यह बस जीवन जीने का एक तरीका था। वे बाजार पैदल जाते थे, किराने का भारी बैग घर लाते थे, खुद से खाना बनाते थे, और अपने हाथों से काम करते थे। आहार सरल था, ज्यादातर घर पर बना होता था, और बिना सोचे-समझे मात्रा में लिया जाता था।

फिटनेस को प्रचार की जरूरत नहीं थी, यह रोजमर्रा की ज़िंदगी में समाया हुआ था। नियमित जांच दुर्लभ थी, दवाएं गंभीर बीमारियों के लिए थीं, और कोई भी कदमों की गिनती या प्रोटीन पाउडर के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था। उस दौर के कई लोग लंबी उम्र जीते थे, और अपने आखिरी सालों में ही बीमारियों का शिकार हुए। आज, ऐसा लगता है मानो स्वास्थ्य हर जगह है, फिर भी, विडंबना यह है कि कहीं नहीं।

ऐप्स, सप्लीमेंट्स, प्रभावशाली लोगों और सुडौल शरीर की अंतहीन फीड्स के साथ, वेलनेस एक तेजी से बढ़ता उद्योग बन गया है। जिम फल-फूल रहे हैं, फिटनेस के चलन बढ़ते-घटते रहते हैं, और फिट रहने का दबाव लगातार पृष्ठभूमि में गूंजता रहता है। हममें से जो लोग अब एक गतिहीन, तनावपूर्ण जीवनशैली के परिणामों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए खतरे की घंटी जोरदार और जरूरी है। बहुत लंबे समय तक, हम मानते रहे कि हम शुरूआती चेतावनियों को नकारते हुए, आराम से चल सकते हैं। जब तक दर्द और ऐंठन शुरू हुई, तब तक नुकसान शुरू हो चुका था। क्या यह अज्ञानता थी, या अहंकार जिसने हमें बुनियादी बातों को नजरअंदाज करने पर मजबूर किया? इसके विपरीत, आज के युवाओं को फिटनेस में इतना डूबा हुआ देखना आश्चर्यजनक है - जिम के लिए साइन अप करना, मैक्रोज गिनना, सप्लीमेंट्स पर जुनूनी होना। फिर भी मैं यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाती: क्या यह प्रेरणा वाकई स्वास्थ्य के बारे में है, या तस्वीरों में अच्छा दिखने के बारे में? सुंदरता के लिए व्यायाम करने और स्वास्थ्य को एक स्थायी निवेश के रूप में पोषित करने में बहुत बड़ा अंतर है। अगर पचास की उम्र में शरीर कमजोर पड़ने लगे, तो बीस की उम्र में एक परफेक्ट बॉडी का कोई मतलब नहीं रह जाता। असली इनाम एक ऐसी नींव बनाने में है जो गिरावट को रोके रखे, जिससे बाद के सालों में आजादी और स्फूर्ति बनी रहे। सच्चा स्वास्थ्य नाटकीय हाव-भावों से कम और समय के साथ छोटे-छोटे, स्थिर विकल्पों से ज्यादा जुड़ा है।

तेज चलना, ताजी सब्ज़ियों का भरपूर सेवन, सोने से पहले स्ट्रेचिंग, ध्यानपूर्वक साँस लेने के लिए रुकना—ये साधारण आदतें चुपचाप जमा होकर एक मजबूत शरीर और दिमाग बनाती हैं। मानसिक स्वास्थ्य, नींद और तनाव प्रबंधन उतने ही जरूरी हैं जितने कि गतिविधि और आहार। ये वो संसाधन प्रदान करते हैं जिनकी हमें दशकों बाद जरूरत पड़ेगी। जिस शरीर की आप बीस और तीस की उम्र में देखभाल करते हैं, वही शरीर आपको साठ और सत्तर की उम्र तक ले जाएगा। यही तय करता है कि आप स्वतंत्र, ऊजार्वान और गरिमामय बने रहेंगे या गोलियों और बैसाखियों पर निर्भर रहेंगे। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ. कपड़ों के साइज में फिट होना या पेट दिखाना नहीं है।

यह वह विरासत है जो हम अपने लिए बनाते हैं,पूरी तरह जीने और शान से बूढ़ा होने का आश्वासन। सुंदरता फीकी पड़ जाती है, जवानी ढल जाती है। लेकिन अच्छी तरह से देखभाल किया हुआ शरीर एक ऐसा साथी है जो आपको धोखा नहीं देगा। और इस सच्चाई को मैं अभी-अभी आत्मसात करना शुरू कर रही हूं।

आप की बात

सामरिक संतुलन की चुनौती

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ रक्षा समझौता भारत के लिए गहरी सामरिक चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें यह प्रावधान है कि किसी एक पर हमला दोनों पर माना जाएगा। यदि भारत भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद-रोधी कार्रवाई करता है, तो सऊदी अरब इसे पाकिस्तान पर हमला मान सकता है। यह स्थिति भारत की सैन्य स्वतंत्रता और रणनीतिक विकल्पों को सीमित करती है और भारत के लिए नई चुनौती खड़ी करती है। पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में सऊदी अरब का पाकिस्तान की ओर झुकाव भारत की कूटनीतिक चिंताओं को बढ़ाता है। इस परिस्थिति में भारत को आर्थिक, ऊर्जा और तकनीकी सहयोग के माध्यम से सऊदी अरब से अपने संबंध और गहरे करने चाहिए। यदि भारत इस क्षेत्र में रचनात्मक प्रभाव स्थापित करता है तो संभावित तनाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए भारत को स्मार्ट डिप्लोमेसी की राह अपनानी होगी, जहां कठोर रणनीति और लचीले संवाद का संयोजन हो। सऊदी अरब का यह कदम अमेरिका पर घटते भरोसे और क्षेत्रीय अस्थिरता का परिणाम है। भारत को जी-20, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर सऊदी अरब से संवाद बढ़ाना चाहिए।

– **अवनीश कुमार गुप्ता**, आजमगढ़

ट्रंप के निर्णय से चिंता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने हाल ही में एच-1बी वीजा की फीस में अप्रत्याशित वृद्धि का ऐलान किया। शुरूआत में यह संदेश गया कि वीजा शुल्क को अचानक एक हजार डॉलर से बढ़ाकर एक लाख डॉलर सालाना कर दिया गया है। इस खबर से भारतीय आईटी कंपनियों के साथ-साथ अमेरिकी कंपनियों में भी गहरी चिंता फैल गई, क्योंकि एच-1बी वीजा पर सबसे ज्यादा निर्भरता भारतीय पेशेवरों की ही रहती है। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि यह शुल्क सालाना नहीं बल्कि केवल एक बार ही देना होगा और यह भी कि यह नियम केवल नए आवेदनों पर लागू होगा, मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं। इस स्पष्टीकरण के बावजूद यह फैसला अमेरिका और भारत दोनों के हितों को चोट पहुंचाने वाला माना जा रहा है। आईटी सेक्टर ही नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों की अमेरिकी कंपनियां भी एच-1बी वीजा धारकों पर निर्भर हैं। अमेरिकी प्रशासन यदि यह सोच रहा है कि ऊंची फीस के कारण कंपनियां स्थानीय युवाओं को नियुक्त करने लगेंगी तो यह उनकी गलतफहमी है, क्योंकि अमेरिका में उतने प्रशिक्षित और सक्षम पेशेवर उपलब्ध ही नहीं हैं। यही कारण है कि अमेरिकी विकास में अप्रवासी पेशेवरों और श्रमिकों का योगदान लंबे समय से अहम रहा है। यदि इन्हें बाहर कर दिया जाए तो कई क्षेत्रों में कामकाज ठप हो सकता है।

– **सुभाष बुड़ावनवाला**, रतलाम

24 घंटे, 88 लाख और आम आदमी

गजब है अमरीकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रम्प का फरमान. दुनिया के किसी भी कोने में हों २४ घंटे में अमेरिका पहुंच जाएं एच १ बी वीजा धारक वरना भरना पड़ेंगे ८८ लाख रुपए। शायद आप तो पहुंच सकते हैं दुनिया के किसी भी दूरस्थ स्थान पर अपने निजी/सरकारी विमान सेवा से. पर क्या आम आदमी जो कि दूरस्थ गांव, फिर पास के शहर के एयरपोर्ट और उसमें भी विभिन्न विमानन कंपनी के भिन्न-भिन्न विमान की उड़ान के समय वहां पहुंच सकता है? और अपनी सम्बंधित फ्लाइट से इतनी जल्दी याने २४ घंटे में अमेरिका पहुंच सकता है क्या कोई भी शख्स ? इतने ऊँचे पद पर आसीन भी क्या सक्षम निर्णय लेने में असमर्थ हो सकते हैं? जैसा कि ट्रम्प ने निर्णय लिया. ये कोई युद्ध थोड़े ही था जो रॉकेट या मिसाइल से क्षण भर में किसी भी दुश्मन देश में पहुंचकर कर उसपर निशाना दागा जा सकता है. यह तो सामान्य व शांतिप्रिय नौकरी पेशा आम व्यक्ति के लिए लेने वाला निर्णय था. क्या इससे किसी भी आम आदमी के सामान्य अधिकारों पर कुठाराघात नहीं माना जा सकता ? फिर आसपास के स्थान की बात हो तो ठीक किन्तु हजारों मील दूर रहने वालों के लिए क्या २४ घंटे काफी हैं नियत स्थान तक पहुंच बनाने के लिए ? इसे बदला जाए और भविष्य में भी ऐसे विवेकहीन निर्णय कोई भी संस्था, राष्ट्र या राष्ट्राध्यक्ष न लें जिससे किसी भी देश के किसी भी नागरिक को परेशानी या आर्थिक दंड का भागी बनना पड़े।

– **शकुंतला महेश नेनावा**, इंदौर

अनुशासन और व्यवस्था की जरूरत

सड़कों पर जाम आज लगभग हर शहर की रोजमर्रा की समस्या बन चुकी है। चलते निर्माण कार्य, अव्यवस्थित ट्रैफिक और नियमों को ताक पर रखकर वाहन चलाना इसकी प्रमुख वजहें हैं। जाम केवल समय की बबार्दी नहीं करता बल्कि प्रदूषण, मानसिक तनाव और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ाता है। इस स्थिति से निपटने के लिए सबसे पहले सड़क मरम्मत, नालों की सफाई, फुटपाथ और किनारों का रख-रखाव नियमित होना चाहिए। कई जगहों पर सड़कें खुदी रहती हैं जो महीनों तक अधूरी पड़ी रहती हैं इससे जो जाम बढ़ता ही हैं। दूसरी ओर ट्रैफिक संकेतों और साइन बोर्ड की कमी, रात में पर्याप्त स्ट्रीट लाइट न होना भी समस्या को गहरा करता है। ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन और वाहन चालक का अनुशासन स्थिति को सुधार सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा, मेट्रो या ई-बस जैसे विकल्पों को सुलभ बनाकर निजी वाहनों का उपयोग सीमित हो। स्मार्ट सिग्नल और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों का उपयोग भी आवश्यक है।आखिर में जाम से निजात पाने के लिए सरकार, प्रशासन और नागरिक तीनों की साझा जिम्मेदारी बनती है।इसे अमल में लाकर ही जाम की लंबी लाइनें कम की जा सकती है।

– **अमृतलाल मारू 'रवि'**, इन्दौर मप्र

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 185

आईटी क्षेत्र को झटका

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में यह जता दिया है कि वह बिना किसी सार्वजनिक चर्चा या पूर्व सूचना के बड़े निर्णय लेने के लिए तैयार रहते हैं। एच-1बी वीजा के लिए फीस बढ़ाकर 1 लाख डॉलर तक करने के उनके निर्णय के साथ भी लगभग यही बात लागू होती है। ट्रंप के इस फैसले ने उन लोगों के मन में कुछ हद तक चिंता बढ़ा दी जिनके पास इस समय एच-1बी वीजा है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ट्रंप की घोषणा के बाद हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि नया एच-1 बी वीजा फीस केवल नए आवेदकों पर ही लागू होगा। मगर इस बात का कतई भरोसा नहीं किया जा सकता कि अमेरिकी सरकार इस आश्वासन पर कायम रहेगी। हालांकि, मौजूदा एच-1बी वीजा धारकों को निश्चित रूप से कुछ हद तक राहत महसूस होगी। अमेरिका प्रशासन का यह निर्णय किस तरह अमल में लाया जाएगा और किन पर लागू होगा इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप प्रशासन इस बात को लेकर गर्व महसूस कर रहा है कि उसे अपने निर्णयों पर किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है और बाहरी लोगों को तो बिल्कुल नहीं।

एच-1बी वीजा पर पर ट्रंप का निर्णय यह भी दर्शाता है कि वह अपने दूसरे कार्यकाल में अधिक अतिवादी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल में उनके अटॉर्नी जनरल ने एच-1बी वीजा कार्यक्रम सीमित करने एवं उसमें सुधार का प्रयास किया था मगर उनकी यह योजना आगे नहीं बढ़ पाई। दूसरे कार्यकाल के लिए ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक पहले बड़ी तकनीकी कंपनियों के प्रमुख लोगों और 'अमेरिका फर्स्ट' गुट के लोगों के बीच चर्चा में एच-1 बी वीजा का मुद्दा फिर उठा। उस समय निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने ईलॉन मस्क के प्रतिनिधित्व वाले गुट की बात मान ली थी। मगर अब मस्क राष्ट्रपति ट्रंप से दूर जा चुके हैं और अमेरिकी कंपनियों ने व्हाइट हाउस की इच्छाओं के आगे झुकने की अपनी रजामंदी भी दे दी है। इस गठबंधन के कारोबारी पक्ष पर 'अमेरिका फर्स्ट' समर्थक हावी हो गए हैं।

ट्रंप के इस निर्णय पर भारतीय अधिकारियों ने साहसिक रुख अख्तियार किया है। उन्हें लगता है कि भारत के अपने तकनीकी एवं स्टार्टअप क्षेत्र बड़ी संख्या में प्रतिभावान लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं मगर इस बात को लेकर भी संदेह नहीं कि भारत की कई सूचना प्रौद्योगिकी-समर्थित सेवा (आईटीईएस) कंपनियों के लिए गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। अमेरिका जितने एच-1 बी वीजा जारी करता है उनमें लगभग 70 फीसदी भारतीयों को मिलते हैं और कुछ खबरों के अनुसार एच-1बी लॉटरी में लगभग आधे स्लॉट आउटसोर्सिंग या स्टाफिंग कंपनियों द्वारा झटक लिए जाते हैं। उनके लिए स्वाभाविक रूप से यह एक बड़ा झटका होगा। इन कंपनियों ने जिन लोगों को एच-1बी वीजा पर बहाल किया उन्हें उनके काम के लिए औसत वेतन से भी कम रकम दी गई। उनके वेतन अल्फाबेट या मेटा द्वारा जा रही रकम से काफी होते हैं। इस तरह, स्पष्ट रूप से एक पुराना कारोबारी ढर्रा काम कर रहा था जिसमें ट्रंप की नई नीति के साथ खलल पड़ गई है।

आईटी, खासकर आईटीईएस कंपनियों को निश्चित रूप से अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना होगा। अमेरिका में उनके कारोबार प्रारूप को लेकर राजनीतिक माहौल बदल गया है। यूरोप सहित दूसरे क्षेत्रों में ऐसे बदलाव आ सकते हैं। वेतन लागत कम करना (वेज आर्बिट्राज) अब किसी कारोबारी योजना का ठोस हिस्सा नहीं रह गया है और न ही पहले की तरह प्रभावी ही है। उदाहरण के लिए उत्तरी इंगलैंड में आईटीईएस में किसी कर्मचारी के लिए औसत वेतन बेंगलूरु की तुलना में केवल दो या तीन गुना है। एजेंटिक एआई एवं अन्य नवाचारों के विकास से भी निचले एवं मध्यम स्तरों पर लोगों की जरूरत कम हो गई है। भारतीय आईटीईएस कंपनियों को अपने लिए कारोबारी माहौल तैयार करते वक्त इन बदलावों का अवश्य ध्यान रखना और एक नया रास्ता खोजना चाहिए जो उनके अंशधारकों के लिए अधिक लाभकारी हो। पलक झपकते ऐसा करना मुनासिब नहीं है मगर भारतीय कारोबारों को जल्द ही नए हालात के साथ तालमेल बैठाना होगा।

क्रिकेट-आतंक के खिलाफ जंग में फर्क करना जरूरी

कई समझदार लोग भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलने की हिमायत करने लगे हैं मगर यह सोच उनमें इस प्रतिस्पर्द्धी खेल की समझ की कमी उजागर करती है

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

औपचारिक रूप से देखें तो 'ऑपरेशन सिंदूर' अभी भी जारी है। हालांकि, सीमा पर शांति है और कहीं से कोई आहट नहीं दिख रही है लेकिन युद्ध क्रिकेट की दुनिया तक पहुंच गया है। यह अलग बात है कि यह मैदान से बाहर लड़ा जा रहा है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी सेना और सबसे बड़ी आबादी द्वारा छेड़े गए 'आतंकवाद के खिलाफ युद्ध' की दशा-दिशा इस बात से तय हो रही है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेले या नहीं। वास्तव में यह बहस क्रिकेट (सामान्य रूप से खेल) या यहां तक कि भारत-पाकिस्तान संबंधों के बारे में भी नहीं है। यह हमारे दोहरे मानदंड या ढोंग को उजागर कर रहा है।

इस दोहरे मानदंड को और उजागर करने के लिए मैं आपको टोकियो के विशाल नैशनल स्टेडियम में ले चलूंगा जहां एक ऐतिहासिक पल सामने आया जब भारतीय उपमहाद्वीप के चार एथलीट (दो भारत से, एक-एक पाकिस्तान और श्रीलंका से) विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंकने की प्रतिस्पर्द्धा में अंतिम12 खिलाड़ियों में शामिल थे।

अगर आपने पूरे दिन सभी सोशल मीडिया हैंडल पर नजर दौड़ाई हो और विशेष रूप से उस समय जब भाले फेंके जा रहे थे तो आपको कुछ विशेष ट्रेंड करता नहीं दिखा होगा। इस बात को लेकर कहीं कोई आक्रोश नहीं था कि नीरज चोपड़ा और सचिन यादव पाकिस्तानी अरशद नदीम के खिलाफ प्रतिस्पर्द्धा कर रहे थे। वर्ष 1896 में एथेंस में आधुनिक ओलिंपिक खेल शुरू होने के बाद से पिछले 130 वर्षों में भारतीय उपमहाद्वीप यानी दो अरब लोगों के समूह ने केवल तीन व्यक्तिगत ओलिंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। जी हां, ये आंकड़े बिल्कुल दुरुस्त हैं। उनमें से दो वही हैं नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम जो टोकियो में अंतिम 12 खिलाड़ियों में शामिल थे। आपको इस कार्यक्रम में लोगों की अधिक दिलचस्पी होने की उम्मीद जरूर होगी। मगर ऐसा नहीं था। अभी भी इस बात का जुनून लोगों के सिर पर सवार है कि भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए या नहीं। मैंने पाकिस्तानी मीडिया बहस भी देखी। उनके ओलिंपिक स्वर्ण पदक विजेता और विश्व रिकॉर्ड धारक अपने कट्टर भारतीय प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ प्रतिस्पर्द्धा कर रहे थे मगर बहुत कम उत्साह दिख रहा था क्योंकि हमारा जुनून तो क्रिकेट तक सीमित है। एक तरह से मैं कहूंगा कि यह अच्छी बात है। राहत मानिए कि इंटरनेट एवं समाचार चैनलों पर जमी भीड़ सेना में जेसीओ चोपड़ा को पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए परेशान नहीं कर रही थी, जबकि पहलगाम की विधवाएं तब भी शोक में डूबी हुई थीं। क्रिकेट और एथलेटिक्स के प्रति यह अलग-अलग भावनात्मक प्रतिक्रिया केवल आंशिक रूप से हमारे क्रिकेट के जुनून से आती है। बाकी मुख्य मकसद तो वही अधिक से अधिक सुर्खियों में रहना है। क्रिकेट दिन-रात आक्रोश पैदा करने के लिहाज से ओलिंपिक खेलों से कहीं अधिक प्रभावी रहा है।

मेरे लिए सबसे यादगार पल वह है जब कई नामी लोगों, विशेष रूप से पत्रकारों ने पहलगाम पीड़ितों के पिताओं की तस्वीरें पोस्ट कीं जो अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार कर रहे थे या उन शोक संतप्त विधवाओं की जिनका सुहाग उजड़ चुका था। वे पूछ रहे थे कि क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का मतलब है कि हमने उन्हें न्याय दिला दिया है? मेरा सवाल यह है कि क्या क्रिकेट नहीं खेलने और पाकिस्तान को अंक दिला देने से उन्हें न्याय मिलने का एहसास होगा?

क्या हमने अपनी वायु सेना, सेना और नौ सेना की संयुक्त और भयंकर मारक क्षमता का उपयोग कर उन्हें न्याय नहीं दिलाई? आप यह बात तभी नहीं मानेंगे जब आपको भी उन कई मूर्ख पाकिस्तानियों की तरह यह लगेगा कि जैश और लश्कर के तबाह हुए मुख्यालय, नेस्तनाबूद हुए एक दर्जन पाकिस्तानी वायुसेना अड्डे और धुएं से भरे रडार कोई खास बात नहीं है। भारतीय क्रिकेट आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में क्या हासिल कर सकता है जो हमारी सशस्त्र सेनाओं ने नहीं किया है, या अगर फिर ऐसी कोई जरूरत आन पड़ती है तो क्या फिर नहीं करेगी? हमारा खेल जुनून एकेश्वरवादी है, क्रिकेट ही एकमात्र भगवान है। इस मामले में उसी तरह आक्रोश जीतने को लेकर उतना नहीं है जितना खेलने या बहिष्कार करने के बारे में है।

बात केवल सोशल मीडिया तक होती इसे एक आक्रोश से भरी प्रतिक्रिया समझ कर नजरअंदाज किया जा सकता था। मगर हमारे न्यूज चैनलों पर भी यह बहस हावी रही। दोनों तरफ प्राइम टाइम में जहर उगला गया जिनमें कई बार तो अमर्यादित भाषाओं का भी इस्तेमाल हुआ।

उदाहरण के लिए पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ एक समाचार चैनल पर एक महिला एंकर के साथ हंसते हुए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के पहले नाम का 'गलत उच्चारण' करने का नाटक करते रहे। मैं यहां उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। आम तौर पर इस तरह की बदतमीजी अक्सर दोनों तरफ होती रहती है। अब कई समझदार लोग भी इस बात से सहमत दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना, यहां तक कि किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी, राजनीतिक, रणनीतिक और सबसे महत्त्वपूर्ण नैतिक रूप से गलत है। वे चाहते हैं कि भारत या तो टूर्नामेंट का बहिष्कार करे या मैच अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के पाले में जाने का मौका दे। ऐसी सोच एक प्रतिस्पर्द्धी खेल की समझ की कमी दर्शाती है। यह दुख की बात है कि भारत आतंकवाद का शिकार है। तो क्या उसे फिर सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पाकिस्तान को वॉकओवर देना चाहिए? यह किस तरह की पराजयवादी मानसिकता है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान, जिसके पास पिछले 20 वर्षों में किसी भी रूप में भारत को हराने की संभावना दस में से केवल एक रही है, उसे जीत तोहफे में दे दी जाए?

खेल से जुड़े कुछ आंकड़े काफी शिक्षाप्रद होते हैं। भारतीयों की दो पीढ़ियां पाकिस्तान के खिलाफ हमारी हार के पिछले रिकॉर्ड से अब भी आहत महसूस करती हैं। पिछले 25 वर्षों में स्थितियां बदल गई हैं। उदाहरण के लिए टी20 क्रिकेट में पिछले 20 वर्षों में खेले गए कुल 14 मैचों में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 11-3 से बढ़त बनाई है। पिछले एक दशक में हुए एकदिवसीय मुकाबलों में भारत 8-1 के साथ आगे है। इंगलैंड के द ओवल में 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 7-0 से आगे है। पाकिस्तान अब कभी जीतता भी है तो उसे अपवाद ही माना जाता है। क्या अब इसे यानी नियम बन जाने दें? क्या पहलगाम पीड़ितों को इस बात से न्याय मिलेगा कि हम पाकिस्तान को हमेशा हारने वाली टीम की बजाय स्थायी विजेता का दर्जा दे दें?

एकमात्र खेल जहां पाकिस्तान का दबदबा रहा है वह हॉकी है। क्रिकेट की तुलना में यहां तो समीकरण और अधिक बदल गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सभी सात मैच जीते हैं, जिसमें हांगचाऊ एशियाई खेल 2022 में दर्ज 10-2 की विशाल जीत भी शामिल है। पाकिस्तान 2012 से ही ओलिंपिक के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहा है।

पिछले महीने ही उन्होंने बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया कप से बाहर रहने का निर्णय लिया जहां विजेता अगले विश्व कप में स्वतः ही पहुंच जाता। पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं करने के लिए आईएचएफ को सोशल मीडिया का कोई दबाव, इन्फ्लुएंसर के शोर या टीवी कमांडो का सामना नहीं करना पड़ा। केवल बेवकूफ ही पाकिस्तान को खेल सौंपेंगे और उन्हें जीत उपहार में देना शुरू कर देंगे। किसी सरकार के लिए अपने समर्थकों की इच्छा के आगे झुकना एक ठीक नीति नहीं लगती। आप कह सकते हैं कि प्रतिबंध केवल कुछ दिनों के रहे क्योंकि पहलगाम का घाव अभी ताजा है। एक मजबूत एवं साहस रखने वाली सरकार ही कह पाएगी कि घाव भर गए हैं, इसलिए हम पाकिस्तान के साथ फिर खेल सकते हैं। हमें इसकी सराहना करनी चाहिए कि मोदी सरकार ने अपने समर्थकों से अधिक समझदारी दिखाई है।

भारत अब विश्व क्रिकेट का नेतृत्वकर्ता है और हॉकी पर उसकी पकड़ बढ़ रही है, खासकर हॉकी इंडिया लीग की वापसी के साथ। यह द्विपक्षीय मुद्दों को बहुपक्षीय खेल में नहीं घसीट सकता। अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) का हर दूसरा प्रमुख भारतीय होगा। जय शाह और राजीव शुक्ला को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी), एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के प्रमुख और पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन रज़ा नक़वी के साथ बातचीत करनी होगी। वास्तविक दुनिया की जरूरतों को स्वीकार करना होगा। आखिरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थ्यानचिन में शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के दौरान सामूहिक तस्वीर खिंचवाने से इसलिए मना नहीं कर सकते थे कि वहां शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। अतीत में हुए बहिष्कार या प्रतिबंध कोई मिसाल नहीं हैं। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत ने रंगभेद के कारण 1974 में डेविस कप फाइनल में नहीं खेलकर दक्षिण अफ्रीका को जीत थमा दी। 1988 में राजीव गांधी की सरकार ने इंतिफादा हत्याओं के कारण इजरायल को निर्वासन देना स्वीकार कर लिया। अमेरिका ने (1980 में) मॉस्को और रूस ने लॉस एंजिलिस (1984) ओलिंपिक का बहिष्कार किया था। यूक्रेन पर हमले के कारण रूस पर पेरिस ओलिंपिक, 2024 में प्रतिबंध लगा दिया गया। ये सभी बहुराष्ट्रीय कार्रवाइयां थीं।

एकतरफा बहिष्कार अब भारतीय क्रिकेट को नुकसान पहुंचाएगा और पाकिस्तान को जीत उपहार में देगा। इससे भी बुरी बात यह है कि हम नरम राज्य की तरह काम कर रहे होंगे। हमें 'ऑपरेशन सिंदूर' के साथ एक नई रेखा खींचने और सैन्य कार्रवाई की नई मिसाल पेश करने के बाद ऐसी बहिष्कार करने जैसी चीजों की जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले में भारतीय क्रिकेट को मुद्दा बनाने का कोई मतलब नहीं है।

Join This Channel:- https://t.me/AllNewsPaperPaid1

एआई बनाम मौलिक रचनात्मकता का संघर्ष

मीडिया मंत्र
वनिता कोहली-खांडेकर

कैंसर कोशिकाएं हमारे शरीर से ग्लूकोज और अन्य पोषक तत्वों का उपयोग करके फैलती हैं और आखिर में व्यक्ति को जान गंवानी पड़ती है। यदि इन कोशिकाओं को इन पोषक तत्वों से वंचित कर दिया जाए तो क्या यह बीमारी फैलाना बंद कर सकती हैं या इसका इलाज संभव हो सकता है? इसके आधार पर कैंसर को रोकने के लिए उपवास के इस्तेमाल को लेकर बहुत शोध हो रहा है। मीडिया एवं मनोरंजन कंपनियां भी एआई द्वारा उनके काम या सामग्री के इस्तेमाल के खिलाफ अपनी लड़ाई में बिल्कुल इसी तर्क का उपयोग कर रही हैं।

कैंसर की तरह ही, जेनरेटिव एआई अपनी 'बुद्धिमता' उन सभी चीजों से हासिल करता है जो चीजें प्रकाशित हैं, लिखी या रिकॉर्ड की गई हैं और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही जगहों पर उपलब्ध हैं। बिना ज्ञान, जानकारी, संगीत, फिल्मों, किताबों और समाचार पत्रों के एआई को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ भी नहीं होता। यही कारण है कि इसके चारों ओर बना उत्साह असाधारण लगता है। ऐसी दुनिया में जहां सूचना और ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं को चलाने के लिए ईंधन का काम करते हैं, वहां हम बिना किसी विरोध के पूरी मानवजाति के सामूहिक ज्ञान को चुनिंदा कंपनियों को सौंप रहे हैं। ये कंपनियां फिर उसी ज्ञान को अलग-अलग हिस्से में ऐप या किसी सारांश के माध्यम से हमें बेचती हैं या देती हैं। इसमें एक स्वाभाविक हितों का टकराव भी दिखता है। एआई उसी चीज को नष्ट कर रहा है जिस पर वह पल रहा है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां इंसान कोई भी मौलिक रचना करना या सृजन करना बंद कर चुका हो और ज्ञान के लिए तथा सोचने के काम के लिए पूरी तरह से एआई पर निर्भर हैं। यह 1999 में बनी 'द मैट्रिक्स' फिल्म की दुनिया की तरह है जिसमें मशीनों द्वारा शासित एक सर्वनाशी दुनिया में इंसानों को बैटरी सेल के रूप में दिखाया गया।

सच्चाई यह है कि एआई लोगों और कारोबारों के लिए बहुत उपयोगी और क्रांतिकारी साबित हो रहा है। डबिंग और सबटाइटल से लेकर किसी काम की स्पष्ट रणनीति बनाने तक वास्तव में इसने मीडिया उद्योग में लागत कम की है और इसकी क्षमता बढ़ाई है। यही बात अन्य कई उद्योगों पर भी लागू होती है।

अब खबरों की बात करते हैं। कॉमस्कोर के अनुसार, जून 2024 से जून 2025 तक, भारत के शीर्ष 10 अंग्रेजी भाषा के प्रकाशनों ने अपने ऑनलाइन पाठकों में 20 से 30 फीसदी की कमी देखी। कुल मिलाकर, 2024 में ऑनलाइन समाचार देखने वाले लोगों की संख्या 2023 की तुलना में लगभग पांच फीसदी कम हो गई जबकि खबरों के लिए दिया गया समय, एक-तिहाई कम हो गया। गूगल का एआई का सारांश, ओपनएआई का चैटजीपीटी या परप्लेक्सिटी मौजूद सूचनाओं और मीडिया वेबसाइटों से हासिल की गई जानकारी देते हैं, जिससे लोग समाचार के मूल स्रोत पर नहीं जाते। आप तर्क दे सकते हैं कि यदि समाचार कंपनियों को उनकी कॉपीराइट वाली सामग्री के उपयोग के लिए मुआवजा दिया जाता तब यह सही होता लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। एआई तंत्र स्टार्टअप से ही बना हुआ है ऐसे में भुगतान कैसे किया जा सकता है? यही तर्क कंपनियां और यहां तक कि नियामक भी देते हैं। ओपनएआई का मूल्यांकन अब 500 अरब डॉलर के करीब है और यह कंपनी अमेरिका में चैटजीपीटी की सेवाएं 20 डॉलर (1,760 रुपये) प्रतिमाह और भारत में 399 रुपये प्रति माह में देती है।

लेकिन भारत की प्रकाशन कंपनियों के लिए न्यूयॉर्क की इस कंपनी के साथ बातचीत करना भी मुश्किल रहा है ऐसे में मुआवजे की बात तो दूर की कौड़ी है। यह संयोग ही है कि यही कंपनी वॉल स्ट्रीट जर्नल, द टाइम्स और अन्य की सामग्री के उपयोग और उसे दिखाने के कारण अमेरिका की कंपनी न्यूजकॉर्प को पांच वर्षों के दौरान 25 करोड़ डॉलर का भुगतान करने जा रही है। गूगल का कहना है कि एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल वास्तव में 'उचित उपयोग' के कानूनी सिद्धांत पर आधारित है। इस बात से पूरी तरह से इनकार करना चिंताजनक है कि एआई मौजूदा कॉपीराइट डेटा पर बनाया जा रहा है, हालांकि इस रुख को सरकार और कारोबार भी समर्थन देते हैं।

भारत में लड़ाई अभी शुरू हुई है। पिछले साल, एशियन न्यूज इंटरनैशनल (एएनआई) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में ओपनएआई के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उसका आरोप है कि एआई कंपनी ने अपने मॉडल को प्रशिक्षण देने के लिए एएनआई की सामग्री का इस्तेमाल किया और न्यूज एजेंसी के नाम पर गलत जानकारी भी दी। इस मुकदमे में जल्द ही डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए) भी शामिल हो गया, जो 22 मुख्यधारा के प्रकाशकों (इसमें यह अखबार भी शामिल है) और म्यूजिक कंपनियों से जुड़े इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री (आईएमआई) का प्रतिनिधित्व करता है। कई अन्य प्रकाशक (जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स) और लेखक (जैसे जॉर्ज आरआर मार्टिन, जॉन ग्रिशम) भी कानूनी तरीके अपना रहे हैं। कानूनी लड़ाई के अलावा, रचनात्मक क्षेत्र तकनीक के जरिये भी पलटवार कर रहा है। क्लाउडफ्लेयर और टोलबिट जैसी कंपनियों की सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ रहा है जो एआई क्रॉलर/बॉट को वेबसाइटों से डेटा खंगालने से रोकती हैं। कई समाचार संस्थान भी अपनी सामग्री के लिए 'पेवॉल' पर जोर दे रहे हैं जिसके तहत बिना सबस्क्रिप्शन लिए सामग्री नहीं पढ़ी जा सकती है।

एक और दूसरी स्थिति यह है कि जब सारी मौलिक सामग्री का इस्तेमाल कर लिया जाएगा और मौजूदा कंपनियां खत्म हो जाएंगी, तब एआई, खुद एआई द्वारा बनाई गई सामग्री पर ही निर्भर हो जाएगा। ऐसे में यह पूछना दिलचस्प होगा कि तब एआई क्या बनाएगा और शायद खुद एआई से ही यह सवाल पूछा जा सकता है।

आपका पक्ष

जलवायु परिवर्तन से बढ़ रहा अनावश्यक बोझ

जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक संकट भी है। यदि वैश्विक स्तर पर अनुकूलन, हरित निवेश और स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो उत्पादकता का यह नुकसान भविष्य की आर्थिक स्थिरता को गंभीर रूप से चुनौती देगा। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की हालिया रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता का बड़ा कारण बन रहा है। अध्ययन के अनुसार, अगले 25 वर्षों में जलवायु से जुड़ी स्वास्थ्य और उत्पादकता संबंधी चुनौतियों के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को कम से कम 1.5 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट बताती है कि खाद्य एवं कृषि क्षेत्र में 740 अरब डॉलर तक का नुकसान वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। पर्यावरण क्षेत्र में 570 अरब डॉलर का नुकसान शहरी विकास और आधारभूत ढांचे को प्रभावित करेगा। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में 200 अरब डॉलर का नुकसान श्रम उत्पादकता और रोजगार के अवसरों को घटाएगा। यह संकेत है कि जलवायु जोखिम आर्थिक गणना तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता और मानव के लिए भी गंभीर खतरा है।

अमृतलाल मारू 'रवि' इन्दौर मप्र

डब्ल्यूईएफ और बीसीजी की रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जलवायु परिवर्तन आर्थिक व सामाजिक अस्थिरता का बड़ा कारण बन रहा है

दक्षिणी संघ की संकल्पना पर हो काम

पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन का लेख 'नेपाल में हुई उथल-पुथल और भारत के लिए सबक' और इसमें निष्कर्ष के रूप में दक्षिण एशिया के यूरोपीय संघ के समकक्ष संकल्पना प्रशंसनीय है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकारों और कट्टरपंथियों और विदेशी हस्तक्षेप की गिरफ्त में इन दोनों देशों के राजनीतिक ईकोसिस्टम के चलते भले ही यह दोनों देश भारत के साथ किसी दीर्घकालिक क्षेत्रीय संगठन का हिस्सा न बन सकें मगर नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, फिजी, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, लाओस और दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों के साथ सदर्न यूनियन या दक्षिणी संघ गठित करने पर विचार किया जा सकता है। इनमें आपसी आवागमन व यात्रा बिना वीजा, पासपोर्ट के संभव हो, आपसी व्यापार पर कोई व्यवधान या कोई टैरिफ न हो, विद्यार्थियों और व्यापारियों के लिए कोई बाध्यता न हो और सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से एक जैसी सैन्य सुरक्षा नीति हो, जहां आपसी सैन्य सहयोग और आपसी मुद्रा में व्यापार हो। यूरोपीय संघ एक सफल व्यवस्था है भले ही ब्रिटेन उससे अलग हो गया हो। यूरोपीय संघ को तभी समझा जा सकता है जब पूरे यूरोप में एक साथ यात्रा की जाए। इसी प्रकार दक्षिणी संघ कोई राजनीतिक व्यवस्था न होकर एक सामाजिक, शैक्षिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक सामंजस्य के साथ हो। 'पड़ोस प्रथम' नीति से सदर्न यूनियन की संकल्पना बहुत ऊपर है। यदि यह संभव हो सका तो भारत दक्षिण एशिया को अपने नेतृत्व में सुरक्षित भी कर सकेगा और विदेशी शक्तियों के चंगुल से दक्षिण एशिया मुक्त भी रहेगा।

विनोद जौहरी, दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पटना में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉ. कलाम की प्रतिमा को देखते आगंतुक। यह साइंस सिटी प्रदेश के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं नवाचार से जोड़ने का महत्त्वपूर्ण केंद्र बनेगा।